

मार्च १९४१ : १०००

मूल्य

बारह आना

प्रकाशक,
मार्तण्ड उपाध्याय,
मन्त्री, सस्ता साहित्य मण्डल,
कनाट सर्कस, नई दिल्ली

—मुद्रक,
एम० एन० हुल्लल,
फेडरल ट्रेड प्रेस,
देहली

विषय सूची

१. सोवियटरूस की राजनीतिक प्रणाली	१
२. टर्की की राजनीतिक प्रणाली	६६
३. जापान की राजनीतिक प्रणाली	८६
४. ब्रिटिशभारत की राजनीतिक प्रणाली	१६६

संसार की राजनीतिक प्रणालियां

[दूसरा भाग]

सोविएट रूस की राजनीतिक प्रणाली

अभी थोड़े ही दिन पहले सोविएट रूस में एक बहुत जबरदस्त, उग्र और हिंसापूर्ण राज्य-क्रान्ति हुई थी, जिसने सारे देश की काया पलट दी और इसके परिणाम अभी तक बराबर होते ही चलते हैं। यो तो महायुद्ध के बाद प्रायः सभी पराजित देशों में क्रान्तियाँ हुई थी; और खासकर इधरहाल में इटली और जर्मनी में भारी फैसिस्ट क्रान्तियाँ हुई हैं; परन्तु रूस की साम्यवादी क्रान्ति उन सभी क्रान्तियों से कई बातों में बहुत जबरदस्त हुई है, और उससे होनेवाले उलट-फेर भी बहुत बड़े हैं।

रूस की इस क्रान्ति ने वहाँ के केवल राजनीतिक यन्त्रों और राजनीतिक संस्थाओं में ही नहीं, बल्कि वहाँ की सारी आर्थिक तथा सामाजिक प्रणाली में भी बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया है।

रूस की प्रणाली की तुलना प्रायः इटली और जर्मनी की प्रणालियों के साथ की जाती है; और इसमें सन्देह नहीं कि बहुत सी बातों में इनमें बहुत कुछ समानता भी है। परन्तु इन सबको समान बतलाना कभी पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। हाँ, वह अर्द्ध सत्य अवश्य है। ये समानताये केवल इसीलिए हैं कि सभी देशों के निवासियों में बहुत कुछ समानताये हुआ करती हैं; फिर वे चाहे जिस प्रणाली के अधीन रहते हों। जब समाजों के सामने कुछ खास काम होते हैं, तब उन्हें बहुत कुछ समान उपायों से ही काम लेना पड़ता है। जिन समाजों को दूसरों के आक्रमणों से आत्म-रक्षा करनी पड़ती है या अपने देश की उपज और पैदावार जल्दी-जल्दी बढ़ानी पड़ती है, उन्हें प्रायः

ऐसे ही उपाय करने पड़ते हैं जिनसे सारी जनता इन उद्देश्यों की सिद्धि में मिल कर काम कर सके।

फैसिस्टों और कम्यूनिस्टों के सिद्धान्तों में भी कुछ बातें एक ही सी हैं। खासकर दोनों ही यह चाहते हैं कि राज्य की शक्ति और अधिकार बढ़ें। लेकिन इस प्रकार की मुख्य समानताये प्रायः राजनीतिक कार्रवाइयों और उपायों में ही होती हैं। यह ठीक है कि रूस की राजनीतिक कार्रवाइयाँ और कार्य-प्रणालियाँ बहुत से अंशों में फैसिस्टों की राजनीतिक कार्रवाइयों और कार्य-प्रणालियों से मिलती-जुलती हैं। परन्तु वास्तव में इन दोनों में बहुत बड़े और ऐसे भेद भी हैं जो इनके मूल सिद्धान्तों से सम्बन्ध रखते हैं, और जिन्हें हम तात्त्विक भेद कह सकते हैं।

रूस की राज्य-क्रान्ति—रूस की जिस राज्य-क्रान्ति ने आगे चल कर रूस की सोविएट शासन-प्रणाली को जन्म दिया था, उस का सूत्रपात सन १६१७ में उस समय हुआ था, जबकि यूरोप का महा-युद्ध ज़ोरों से चल रहा था। यह क्रान्ति वास्तव में क्रान्तिकारियों ने नहीं की थी, बल्कि वे एक प्रकार से इसके लिए विवश हो गये थे। उस साल रूस की ज़ार-शाही का इसलिए आप-से-आप अन्त हो गया था कि न तो वह युद्ध में ठहर ही सकती थी और न देश की आन्तरिक व्यवस्था ही कर सकती थी।

जिस समय ज़ार-शाही का अन्त हुआ, उस समय नये नेता बहुत फेर में पड़ गये थे। वे उस समय किसी तरह की क्रान्ति करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन ज़ार-शाही का अन्त हो जाने पर उन्हें विवश होकर उसके स्थान पर एक नई शासन-प्रणाली स्थापित करने का काम अपने हाथ में लेना पड़ा था। उस समय उन्होंने पश्चिमी यूरोप के ढंग पर पार्लामेण्टरी शासन-प्रणाली ही देश में स्थापित करने का प्रयत्न किया था, क्योंकि और किसी तरह की शासन-प्रणाली स्थापित करने के लिए वे तैयार ही

नहीं थे।

लेकिन वह पार्लमैण्टरी शासन-प्रणाली छः महीने से अधिक ठहर ही न सकी, और इस बीच में भी कभी शासन के वास्तविक अधिकार वहां की पार्लमैण्ट के हाथ में नहीं आये। बल्कि यह कहना चाहिए कि इन छः महीनों तक रूस में किसी तरह की सरकार भी ही नहीं। एक ओर तो बिल्कुल भयभीत और असहाय अस्थायी सरकार थी; और दूसरी ओर पसोपेश में पड़े हुए मजदूरों और कमकरो का आन्दोलन चल रहा था, जो ऐसी सोविएट या पंचायतें कायम कर रहे थे जो न तो स्वयं ही किसी की कोई आज्ञा मानने के लिए तैयार थीं और न किसी से अपनी आज्ञाओं का पालन ही करा सकती थीं।

जिस समय रूस के जार का पतन हुआ था, उस समय सारा पश्चिमी यूरोप और प्रायः सभी रूसी साम्यवादी यही समझते थे कि अब जल्दी ही यहां उसी तरह की पार्लमैण्टरी सरकार स्थापित हो जायगी, जिस तरह की सरकार और अनेक देशों में स्थापित है। लेकिन मुश्किल तो यह थी कि रूस में ऐसी जमीन ही नहीं थी जिसमें पार्लमैण्टरी प्रणाली का पौधा लग सकता। केरेन्सकी के समय में भी असली ताकत बहुत कुछ सोविएटों के हाथ में रहती थी; और जब वे सोविएट कोई काम कराने पर तुल जाती थीं, तो फिर वह काम कराके ही छोड़ती थीं। इसके बाद जब सोविएटें बोलशेविक नेताओं के हाथ में चली गईं और राज्याधिकार अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हो गईं, तब केरेन्सकी की सरकार भी उसी तरह सहज में टूट गई, जिस तरह जार-शाही टूटी थी। उस समय सारा अधिकार इस नई क्रान्ति के विधाता लेनिन के हाथ में आ गया जो मजदूरों और कमकरो की ओर से एक अधिनायक के रूप में देश का शासन करने लगा।

यूरोप के राजनीतिज्ञ अचानक अपने सामने एक बिल्कुल ही नई तरह की सरकार देख कर घबरा गये। यह नई सरकार ऐसी थी कि इसका शासन न तो प्रजा के चुने हुए पार्लमैण्टरी प्रतिनिधियों के ही हाथ में था और न किसी वंशानुक्रमिक स्वेच्छाचारी राजा के ही हाथ में था, बल्कि आप-से-आप बनी हुई ऐसी सभाओं और समितियों के हाथ में था जिसके सब सदस्य या तो कारखानों में काम करनेवाले मजदूर थे और या सैनिक; और इन सबका नेतृत्व तथा संचालन एक ऐसे क्रान्तिकारी दल के हाथ में था जो बहुत ही व्यवस्थित और मर्यादित रूप से काम कर रहा था। मार्क्स ने मजदूरों और कमकरो के जिस अधिनायक तन्त्र का विधान किया था, वह यदि किसी ऐसे देश में स्थापित होता जो शिल्प और उद्योग-धन्धों के विचार से यथेष्ट उन्नत होता और जहाँ के मजदूर और कमकर मिल कर काम करने की अच्छी शिक्षा पाये हुए होते तो शायद पाश्चात्य देशों को उतना आश्चर्य न होता। लेकिन कमकरो की यह सरकार उस पिछड़े हुए रूस में स्थापित हुई थी जहाँ कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों की अपेक्षा किसानों की संख्या ही कहीं अधिक थी, और जिस देश को किसी तरह के लोक-सत्तात्मक शासन का अबतक कोई अनुभव ही नहीं हुआ था। और पश्चिमी यूरोप के लिए यही सबसे अधिक आश्चर्य और भय की बात थी।

अक्तूबर १९१७ में रूस में जो राज्य-क्रान्ति हुई थी, उसने सबसे पहले सारे संसार को यह सिद्ध कर दिखलाया था कि पार्लमैण्टरी शासन के विकास के लिए पहले से किसी तरह की तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब यह कि साम्यवाद की विजय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि देश को पहले से प्रतिनिधि-सत्तात्मक या प्रजातन्त्री शासन-प्रणाली का अनुभव हो। अबतक यूरोपवाले यही समझते थे कि जिस देश में

एकतन्त्री या राजसत्तात्मक शासन-प्रणाली होती है—जहाँ का शासन किसी स्वेच्छाचारी राजा के हाथ में होता है—वहाँ उसका स्थान सबसे पहले प्रतिनिधि-सत्तात्मक या पार्लमैण्टरी शासन-प्रणाली ही ले सकती है।

लेकिन रूस के इन नये क्रान्तिकारियों ने यह सिद्ध कर दिखलाया था कि केवल पार्लमैण्टरी शासन-प्रणाली ही एकतन्त्री शासन-प्रणाली का स्थान ग्रहण करने की अधिकारिणी नहीं है, बल्कि उस से अधिक उन्नत और आगे बढ़ी हुई साम्यवादी शासन-प्रणाली भी सहज में उसका स्थान ग्रहण कर सकती है; और इसके लिए देश को पार्लमैण्टरी शासन-प्रणाली के अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन संसार इस प्रकार की शिक्षाये सहज में ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये शिक्षाये उसके प्रचलित विचारों और धारणाओं के बहुत विरुद्ध पड़ती थीं।

इसीलिए १९१७ के बाद भी बहुत दिनों तक लोग बराबर यही कहते चलते थे कि रूस की सोविएट सरकार का बहुत जल्दी पतन हो जायगा, और उसकी जगह या तो फिर कोई निकम्मा एकतन्त्री राजतन्त्र स्थापित हो जायगा या पुराने ढंग का पार्लमैण्टरी प्रजातन्त्र स्थापित हो जायगा। और अगर इन दोनों बातों में से एक भी बात न हुई, तो फिर रूस बहुत से छोटे-छोटे वैसे ही पिछड़े हुए कृषक राज्यों में विभक्त हो जायगा, जैसे कृषक राज्य पूर्वी यूरोप और दक्षिण-पश्चिमी एशिया में पहले से चले आ रहे हैं। यहाँ तक कि यूरोप के बहुत से साम्यवादी भी यह कहने लग गये थे कि रूस के क्रान्तिकारियों को इस समय बोल्शेविक क्रांति करने का इसलिए कोई अधिकार ही नहीं था कि रूस अभी तक साम्यवाद की स्थापना के लिए तैयार ही नहीं हुआ है। वह बहुत दिनों से जमींदारों के ही शासन में चला आ रहा था, और पूँजीदारों के

हाथ में रहने पर कोई देश कभी इतना विकसित हो ही नहीं सकता कि उसमें साम्यवाद की स्थापना हो सके।

जिन बोल्शेविक नेताओं ने शासन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया था, उनमें से भी अनेक ऐसे थे जो यह समझते थे कि इस समय हम लोगो ने अपने हाथ में अधिकार लेकर बुद्धिमत्ता का काम नहीं किया है; क्योंकि उन लोगों का भी यही दृढ़ विश्वास

कि साम्यवाद की स्थापना केवल उसी देश में हो सकती है जो ... और उद्योग-धन्धों में बहुत आगे बढ़ा हुआ हो। जो बोल्शेविक नेता राज्य का अधिकार अपने हाथ में लेने के पक्षपाती थे, उनमें से भी अधिकांश का प्रायः यही विश्वास था कि यदि हम सारे पश्चिमी यूरोप में इसी तरह की क्रांतियाँ न कर सकेंगे तो हमारी यह क्रान्ति भी अवश्य ही विफल हो जायगी। उन्हें भय था कि पश्चिमी यूरोप के पार्लमैण्टरी शासन-प्रणालीवाले देश हमारी इस नई शासन-प्रणाली को कभी जीवित न रहने देंगे; और इसीलिए वे सारे संसार में कमकरो और मजदूरोंवाली क्रांति करने का प्रयत्न करने लग गये। अक्टूबर १९१७ वाली क्रान्ति के कुछ दिन बाद तक सभी बोल्शेविक यही समझते थे कि हमारी यह क्रान्ति तभी सफल होगी, जब पश्चिमी यूरोप में भी इसी तरह की क्रान्तियाँ होंगी।

लेकिन सारे संसार में इस तरह की क्रान्तियाँ न तो होने को थीं और न हुई थी। हाँ, उल्टे पश्चिमी शक्तियाँ रूस का बहिष्कार करने लगीं और लगातार ऐसे लोगो को हर तरह की सहायता देने लगीं जो इस नई क्रान्ति को विफल और विनाश करने का प्रयत्न करते थे। लेकिन फिर भी वे लोग किसी तरह सोविएट प्रणाली का नाश नहीं कर सके। धीरे-धीरे दूसरे देशों के राजनीतिज्ञों को यह मानना ही पड़ा कि अब यह प्रणाली रूस में स्थायी रूप से प्रचलित हो गई है और अब, जबकि

साम्यवादियों के हाथ में पड़कर यह नया राज्य ठीक तरह से काम करता ही चलता है, तब यूरोप के प्रचलित राजनीतिक विचारों पर भी, और एशिया के कम विकसित देशों पर भी डम प्रणाली का प्रबल प्रभाव पड़े बिना न रहेगा, फिर चाहे पश्चिम के शिल्पी देशों की अपेक्षा रूस के साथ एशिया के देशों की कितनी ही कम समानता क्यों न हो। सभ्य जगत को अब विवश हो कर यह मानना ही पड़ता है कि संसार में एक नई तरह का राज्य भी स्थायी रूप से स्थापित हो हो गया है; और इस राज्य के मूल में एक ऐसी नई सामाजिक तथा आर्थिक प्रणाली चल रही है जो पूँजीदारीवाली प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन-प्रणाली से उसी प्रकार भिन्न है, जिस प्रकार खड़िया से मलाई भिन्न होती है। इस प्रकार रूस में जो साम्यवादी क्रान्ति हुई थी, उसने सभ्य जगत को कई ऐसे सिद्धान्त मानने के लिए विवश किया, जिन्हें वे कभी मानना नहीं चाहते थे।

अब रूस और दूसरे पाश्चात्य देशों के बीच में केवल यही प्रश्न नहीं है कि देश के राजनीतिक संघटन का क्या स्वरूप हो ? बल्कि उससे भी बढ़ कर बिकट प्रश्न यह है कि सब जगह किस प्रकार की सामाजिक प्रणाली का प्रचलन हो ? पुराने पार्लैमेंटरी देशों और यूरोप के नये राज्यों में वास्तविक अर्थ में प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन-प्रणाली की स्थापना नहीं हो रही थी, बल्कि असल में पूँजीदारों के प्रतिनिधियों की सत्ता स्थापित हो रही थी। जगह-जगह जो नये संघटन-विधान बन रहे थे, उनकी आड़ में पूँजीदारी की प्रथा को दृढ़ और स्थायी करने का प्रयत्न हो रहा था। अथवा कम-से-कम इस बात का प्रयत्न हो रहा था कि आज-कल हर जगह मजदूरों का जो जबरदस्त आन्दोलन होने लगा है, उसके आघात से पूँजीदारी की प्रथा जहाँ तक हो सके, बचाई जाय।

सन् १९१८ में जरमनी का यह विश्वास था और कदाचित् ठीक विश्वास था कि विजयी मित्र-राष्ट्र हमारा राजकीय शेष साम्राज्य बिना नष्ट किये न मानेंगे। लेकिन कदाचित् यह कहने में कोई हर्ज न होगा कि यदि मित्र राष्ट्र यह जानते होते कि रूस में सोविएट प्रजातन्त्र स्थापित हो जायगा तो वे शायद उस समय भी कैसर को जरमनी के सिंहासन पर रहने देते और सोविएट प्रजातन्त्र का नाश करने में उसकी सहायता लेने में भी किसी तरह का संकोच न करते। महायुद्ध के बाद ही हर जगह जो बहुत जल्दी-जल्दी पार्लमैण्टरी शासन-प्रणाली स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा था, उसका मूल कारण यह नहीं था कि लोग एकतन्त्री राजतन्त्र नष्ट करना चाहते थे, बल्कि उसका मुख्य कारण यही था कि लोगों के मन में साम्यवादी क्रान्ति का बहुत भय उत्पन्न हो गया था।

इन सब बातों से पाठको को यह पता चल गया होगा कि आजकल भी संसार के अधिकांश राज्य क्यों सोविएट प्रजातन्त्र के इतने अधिक विरोधी हो रहे हैं, क्यों हर तरह से उसे बदनाम करना चाहते हैं और क्यों उसे नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। इधर कई महीनों से यूरोप में जरमनी और इटली का इतना अधिक आतंक बढ़ जाने पर भी फ्रान्स और ब्रिटेन जल्दी रूम के साथ मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि अब तो हमारे लिए रूम की अपेक्षा जरमनी और इटली ही अधिक घातक सिद्ध होना चाहते हैं, तब लाचार हो कर वे रूस के साथ मिलने को तैयार हुए थे।

लेकिन इस राजनीतिक काल में भी जरमनी उनकी बाजी मार ले गया और उसने रूस के साथ समझौता करके फ्रांस और ब्रिटेन को चकित और विफल-मनोरथ कर दिया।

अस्तु। अब भी पश्चात्य प्रेक्षकों के लिए रूस की सभी बातें

परम आश्चर्य-जनक है। उन्हें ऐसा जान पड़ता है कि यह देश अपने पैरों पर नहीं खड़ा है, बल्कि उलटे ढंग से, मिर के बल खड़ा है। अनेक ऐसी संस्थाएँ हैं जिन्हें पाश्चात्य देशों के निवासी, जन्म से ही अभ्यस्त होने के कारण, अपने लिए केवल परम आवश्यक ही नहीं, बल्कि नितान्त अनिवार्य भी समझते हैं। परन्तु जब वे रूस में पहुँच कर देखते हैं कि हमारी वे सभी संस्थाएँ बिल्कुल नष्ट की जा रही हैं और उनकी जगह ऐसी नयी संस्थाएँ बन रही हैं जो उन पुरानी संस्थाओं के नितान्त विपरीत हैं और वे अपने सामने एक-से-एक नये विरोधाभास देखते हैं, तब उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रह जाता। उन्हें अपने सामने एक ऐसा देश दिखाई देता है जिसमें सभी सामाजिक सम्बन्ध बिल्कुल नये सिरे से स्थापित किये गये हैं और वह पेचीली वर्ग-व्यवस्था उन्हें कहीं दिखलाई ही नहीं देती जो और सभी पाश्चात्य देशों में है। वहाँ या तो सभी पुराने सामाजिक विभाग नष्ट होते जा रहे हैं और या जबरदस्ती खपाये जा रहे हैं और उनकी जगह सारी जनता का केवल एक ही वर्ग दिखाई देता है, जो सिर्फ पेशों और धन्यो के विचार से अलग-अलग दलों में बँटा हुआ है।

अन्यान्य पाश्चात्य देशों में भिन्न-भिन्न पेशों का जो सामाजिक मूल्य और महत्व समझा जाता है, उसकी अपेक्षा रूस में उन पेशों का बहुत ही भिन्न मूल्य और महत्व है। रूस में राज्य की तरफ से सब लोगो को भोजन बाँटा जाता है और सब लोगो को कुछ खास सुभीते भी दिये जाते हैं। पर किसी को साधारण और किसी को बढ़िया भोजन मिलता है, और किसी के साथ साधारण और किसी के साथ बहुत खास रिश्तायतों की जाती हैं। यदि केवल बँटनेवाले भोजन और की जानेवाली रिश्तायतों के ही विचार से देखा जाय और यह मान लिया जाय कि जिन्हें अधिक अच्छा भोजन और अधिक सुभीते मिलते हैं, वे उच्च वर्ग के लोग

हैं और जिन्हे साधारण भोजन और साधारण सुभीते मिलते हैं, वे निम्नवर्ग के लोग हैं, अर्थात् केवल भोजन और सुभीतो के तारतम्य से ऊँच-नीच का विचार किया जाय^१ तो पता चलता है कि रूस में मैनिक, ऊँचे दर्जे के सरकारी अफसर और बहुत बड़े-बड़े और खास तरह के कारखानों में काम करनेवाले मजदूर एक ही वर्ग में माने जाते हैं; और जो लोग काम नहीं करते, वे सबसे नीचे में माने जाते हैं। इसके सिवा वहाँ के लोगों और सामाजिक जीवन के विचार और उद्देश्य स्त्रियों और पुरुषों के सम्बन्ध वहाँ बिल्कुल बदल गये हैं और स्त्रियों की स्थिति में भी बहुत बड़ा अन्तर हो गया है।

पाश्चात्य देशों के प्रेक्षकों और विशेषतः अँगरेजों को वहाँ जाने पर पता चलता है कि और देशों में राजनीतिक तथा आर्थिक बातों में जो बहुत बड़ा और स्पष्ट भेद होता है, उसका भी रूसी राज्य में कहीं पता नहीं है। एक दृष्टि से रूस में प्रत्येक प्रश्न राजनीतिक प्रश्न माना जाता है, और हर एक कमकर राज्य का नौकर होता है। वे प्रेक्षक देखेंगे कि यहाँ सारे देश में केवल एक ही राजनीतिक दल है और वह दल ग्रेट ब्रिटेन या अमेरिका के संयुक्त-राज्यों के राजनीतिक दलों से उन्हे इतना अधिक भिन्न प्रतीत होगा कि वे उसका एक बिल्कुल अलग ही नाम रखना चाहेंगे। वे यह भी देखेंगे कि यहाँ एक ऐसी सरकार काम कर

१ इसका कारण यह नहीं है कि सोविएट रूस में लोगों को भोजन और दूसरे सुभीते मजदूरी या तनखाह के तौर पर मिलते हैं, बल्कि इसका कारण इस राज्य की वह आर्थिक नीति है जिसके अनुसार वहाँ उपयोगिता के विचार से प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य निश्चित किया जाता है। और मनुष्य की योग्यता का कदाचित् मजदूरी और वेतन की अपेक्षा इस प्रणाली से कुछ अच्छा ही पता चलता है।

रही है जो बिना दूसरी क्रान्ति के किसी तरह बदली ही नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी उस सरकार में, उस सरकार की नीति में और वहाँ के शासकों में नित्य ही परिवर्तन होते हुए दिखाई देंगे। वहाँ एक दृढ़ सिद्धान्त स्थापित हो चुका है और जितनी बातें आवश्यक समझी जाती हैं, उन सभी पर सरकार का पूरा-पूरा नियन्त्रण है। लेकिन फिर भी वहाँ की नीति और शासन बहुत कुछ लचीला है। वहाँ की बहुत बड़ी जनता राज्य की नीति और शासन-सम्बन्धी सभी बातों पर बराबर विचार और वाद-विवाद करती रहती है, और उसकी आलोचना करती रहती है। इसी विचार और आलोचना के अनुसार उसमें परिवर्तन भी होते रहते हैं। पर विचार और आलोचना करनेवाले सभी लोग सब काम बहुत ही मिलकर और नीति तथा शासन सफल करने के उद्देश्य से ही करते हैं। और जनता के इस तरह मिलकर सभी काम करने का उदाहरण शायद ग्रीस के नगर-राज्यों के बाद आज तक और कहीं नहीं मिलेगा। ये सब बातें विदेशियों को इतनी अधिक मात्रा में दिखाई देंगी कि वह दंग हो जायेंगे। इन सब बातों का प्रभाव नगरों के स्वरूप, लोगों के पहनावे और बातचीत, समाचारपत्रों के लेखों और नाटकों तथा फिल्मों के विषयों तक पर दिखाई देता है। इस नये शासन की कुछ बातें तो ऐसी हैं जो खास तौर पर साम्यवादी हैं; और कुछ पुरानी ऐसी बातें भी हैं जिन्हें सोविएट राज्य को केवल हमलिण अभी तक रक्षित रखना पड़ा है कि वह ऐसे संसार के बीच में पड़ा है जिनमें सब जगह पूँजीदारी की ही तृती बोल रही है। और इन सब बातों का ठीक-ठीक अन्तर साधारण प्रेक्षक की समझ में महज में नहीं आ सकता, और न वह जल्दी यही समझ सकता है कि सोविएट रूस के सामाजिक जीवन में कौन सी बातें स्थायी रूप से रह सकेंगी और किन बातों का अन्त हम बीच बातें

परिवर्तन-काल में हो जायगा ।

राज्य का आधार—जिन राजनीतिक संस्थाओं से सोविएट राज्य बना है और जिनका उसके संघटन-विधान में उल्लेख है, वे अपेक्षाकृत बहुत कुछ सीधी-सादी हैं । यहाँ हम उन्हीं संस्थाओं का संक्षेप में कुछ वर्णन देते हैं । परन्तु ये सब संस्थायें ऐसी ही हैं जो जब चाहे, तब बदली जा सकती हैं; इसलिए इन संस्थाओं का स्वरूप समझने से पहले स्वयं रूस को ही समझना अधिक महत्वपूर्ण है । और रूस का स्वरूप समझने के लिए यह आवश्यक है कि पहले वह सिद्धान्त समझा जाय जिस पर सोविएट रूस आश्रित है; और तब उन साधनों का स्वरूप समझा जाय जिनके द्वारा यह सिद्धान्त समाजिक कार्य के रूप में परिवर्तित किया जाता है । अंग्रेज अथवा अंग्रेजी सांचे में ढले हुए पाठको के लिए इसका महत्व समझना बहुत कठिन है; और अमेरिकन लोग इसका महत्व अपेक्षाकृत जल्दी और सहज में समझ सकते हैं । इसका कारण यही है कि अंग्रेजी राजनीतिक प्रणाली ऐसी नहीं है जिसकी सब बातें खूब समझ-बूझकर तैयार की गई हों । वह तो संयोग से ही धीरे-धीरे बनती चली आई है और उसकी एक परम्परा-सी स्थापित हो गई है । वह कभी किसी निश्चित सिद्धान्त के आधार पर नहीं बनाई गई है । अब यह बात दूसरी है कि जॉन लॉक सरीखे कुछ विचारशील समय-समय पर कोई ऐसा सिद्धान्त स्थिर करने का प्रयत्न कर लें जो वास्तविक तथ्यों के अनुरूप हो । अब यों तो ऐसा मालूम होता है कि फैसिस्ट इटली भी अपनी तरफ से एक ऐसा राजनीतिक सिद्धान्त गढ़ने का प्रयत्न कर रहा है, जिससे लोग यह समझने लगे कि वहाँ का संघटन भी एक राजनीतिक सिद्धान्त पर ही आश्रित है । और नहीं तो वास्तव में उसका स्वरूप भी किसी निश्चित सिद्धान्त के आधार पर स्थिर नहीं हुआ है । रूस का

राज्य वास्तव में कार्ल मार्क्स के उस समाजशास्त्रीय सिद्धान्त के अनुसार गढ़ा गया है जिसका विवेचन सबसे पहले सन् १८४८ में उसने अपने साम्यवादी एलान में किया था और जिसे निकोलाई लेनिन ने कार्य-रूप में परिणत किया है। रूस के क्रान्तिकारी नेताओं ने ठीक-ठीक उसी पथ पर चलने का प्रयत्न किया है जो आज से प्रायः अरसी-पचासी बरस पहले बतलाया गया था। इस बात का ठीक-ठीक पता उस समय चलता है, जब हम मार्क्स के बतलाये हुए क्रान्ति-कारी कार्यक्रम की तुलना उन कार्यों से करते हैं जो क्रान्तिकारी सरकार ने वास्तव में किये थे।

मार्क्स का सिद्धान्त यह बतलाता है कि जब किसी पूँजीदारी-वाले समाज को साम्यवादी समाज का रूप देना हो, तो पहले कमकरो का अधिनायक तन्त्र स्थापित करना चाहिए, और उन्हीं सामाजिक संस्थाओं से काम लेना चाहिए, जिनका विकास स्वयं कमकरो के समाज ने किया हो। असल में इसी ढंग से रूस में क्रान्ति की गई थी। सन् १९२३ में रूस का जो संघटन (विधान) बना था, यद्यपि उसमें इस सिद्धान्त का केवल कुछ ही अंश स्पष्ट रूप से देखने में आता है, पर फिर भी असल में वह संघटन उसी सिद्धान्त के अनुसार तैयार किया गया था। वह रूसी कमकरो का ही विद्रोह था जिसकी सहायता असन्तुष्ट सैनिकों ने की थी, और दोनों के मेल से वह क्रान्ति हुई थी। उसमें जिन संस्थाओं का विकास किया गया था, वे सोवियेट या कमकरो, सिपाहियों और खेतिहरों की कौन्सिलें या पंचायतें थीं। और कमकरो के अधिनायक तन्त्र का साधन उस समय भी साम्यवादी दल था और इस समय भी है।

यहाँ दो बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये दोनों ही बातें विशेष रूप से रूस की परिस्थिति के साथ सम्बन्ध रखती हैं। पहली बात तो यह है कि सन् १९१७ में रूस का जो कमकरो का

समाज था, वह यद्यपि रूस की विशाल जनता को देखते हुए संख्या में अपेक्षाकृत बहुत कुछ छोटा था, पर फिर भी वह मार्क्स की दृष्टि से पूरा-पूरा पीड़ित कमकरो का समाज था। एक तो उसका उत्पीड़न बहुत अधिक होता था और दूसरे वह बड़े-बड़े नगरों और बड़े-बड़े कारखानों में केन्द्रित था। फ्रान्स के मजदूरों की तरह वह सारे देश में छोटे-छोटे दलों में फैला हुआ नहीं था।

ग्रेट ब्रिटेन में मजदूरों आदि के जो संघ हैं, उनका तो देश के हानि-लाभ से बहुत बड़ा सम्बन्ध है, परन्तु जार-शाही के जमाने में रूस के मजदूरों और कमकरो का देश के हानि-लाभ के साथ उम तरह का कोई सम्बन्ध नहीं होता था। अमेरिकन मजदूरों को यह आशा रहती है कि हम किसी समय व्यक्तिगत रूप से अपनी यथेष्ट उन्नति भी कर सकते हैं; परन्तु रूसी मजदूरों को इस तरह की भी कोई आशा नहीं होती थी। वह शुद्ध रूप में पद-दलित और पीड़ित मजदूरों का समाज था; बल्कि यो कहना चाहिए कि उनकी अवस्था मजदूरी करनेवाले गुलामों की तरह थी और वे अपने मालिकों के हाथ में बिल्कुल जंजीरों से बंधे हुए गुलामों की तरह रहते थे। इसीलिए वे लोग उस तरह की कमकरोवाली क्रान्ति करने के लिए परम उपयुक्त थे, जिस तरह की क्रान्ति मार्क्स के लेखों में बतलाई गई है।

लेकिन—और यहीं से वह दूसरी बात आरम्भ होती है—जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, रूस के कमकर और मजदूर संख्या में अपेक्षाकृत बहुत ही कम थे और क्रान्ति करने में उन्हें खेतिहरों से तबतक सहायता नहीं मिल सकती थी, जबतक वे खेतिहरों को बदले में ज़मीन न देते। खेतिहर तभी उनकी सहायता कर सकते थे, जब बदले में उन्हें ज़मीन पर अधिकार मिलता। लेकिन वहाँ खेतिहरों का बहुत बड़ा वर्ग था; और यदि उन सब खेतिहरों को ज़मीनों का मालिक बना दिया जाता तो

सारी क्रान्ति ही व्यर्थ हो जाती। इसीलिए इधर बीस बरसों से वहाँ के क्रान्तिकारी नेता प्रचार-कार्य के द्वारा भी और बल-प्रयोग के द्वारा भी देश के समस्त खेतिहरों को कमकरो और मजदूरों की ही श्रेणी में लाने के लिए घोर परिश्रम कर रहे हैं।

परन्तु यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे लोग खेतिहरों को उस हैसियत में कमकर और मजदूर नहीं बना रहे हैं, जिस हैसियत में पूँजीदार देशों में कमकर और मजदूर होते हैं, क्योंकि रूस में अब पूँजीदारीवाली प्रथा रह ही नहीं गई है; बल्कि वे उन्हें उसी हैसियत में लाना चाहते हैं, जिस हैसियत में इस समय सोविएट रूस में कमकर और मजदूर हैं। मतलब यह कि वे नेता अपने देश के मजदूरों और खेतिहरों में सामंजस्य और एक रूपता स्थापित करना चाहते हैं। यही कारण है कि रूस के संघटन-विधान में देहाती सोविएटों या पंचायतों को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है, और यही कारण है कि वहाँ उन खेतिहरों का निर्दयता-पूर्वक अन्त किया जा रहा है जो वहाँ का पंचायती सिद्धान्त और पंचायती शासन मानने के लिए तैयार नहीं होते। वहाँ बहुत से जिले ऐसे थे जो यह नया शासन-विधान मानने के लिए तैयार नहीं थे; इसलिए उन नेताओं को उन जिलों की ही सफाई करनी पड़ी थी। लेकिन रूसी क्रान्तिकारी नेता सिर्फ बलपूर्वक अपने विरोधियों की सफाई करना ही नहीं जानते, बल्कि वे उनमें अपने सिद्धान्तों का प्रचार करना भी खूब अच्छी तरह जानते हैं; और जहाँ तक हो सकता है, उन्हें पहले समझा-बुझाकर, पंचायती शासन के लाभ बतलाकर और उनके सामने पंचायती शासन और व्यवस्था के शुभ उदाहरण रखकर उन्हें अपने पक्ष में मिलाना भी खूब जानते हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि इस नीति के अवलम्बन के कारण

देश में बहुत सी नई आर्थिक कठिनाइयाँ भी उत्पन्न हो गई हैं, और बहुत कुछ राजनीतिक दमन भी हुआ है। लेकिन फिर भी क्रान्ति के लिए इस नीति का अवलम्बन नितान्त आवश्यक था। परन्तु अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह नीति पूरी तरह से सफल हो ही गई है। इस समय तो केवल यही कहा जा सकता है कि रूसी क्रान्तिकारी नेता बहुत सी बड़ी-बड़ी कठिनाइयों और संकटों से पार पा चुके हैं और अभी तक उन्होंने अपनी कार्रवाइयों से अपने राजनीतिक राज्य को किसी बड़े संकट में नहीं डाला है। उल्टे अनेक दृष्टियों से उन्होंने अपने देश की अवस्था बहुत कुछ सुधारी ही है, और उसकी सभी प्रकार की शक्तियाँ बहुत कुछ बढ़ा ली हैं।

सा० सो० प्र० सं० का संघटन^१—सोविएट राज्य का संघटन अपेक्षाकृत बहुत कुछ सरल और सीधा-सादा है। साम्यवादी सोविएट प्रजातन्त्री संघ वास्तव में सात सोविएट प्रजातन्त्रों का संघ है। इनमें से सबसे बड़ा प्रजातन्त्र रूसी साम्यवादी फेडरल सोविएट का है जो पश्चिम में लेनिनग्राड से

१. अंग्रेजी में रूस के प्रजातन्त्री राज्य का पूरा नाम यूनियन आफ सोशलिस्ट सोविएट रिपब्लिक्स (Union of Socialist Soviet Republic) है, जिसका संक्षिप्त रूप (U. S S R) प्रायः काम में आता है। इसी का हिन्दी रूप साम्यवादी सोविएट प्रजातन्त्री संघ है जिसका संक्षिप्त रूप सा० सो० प्र० सं० है।—

२. उक्रेन की इसी अलग होनेवाली प्रवृत्ति से जर्मनी को यह आशा है कि वह कुछ दिनों में उक्रेन पर भी अधिकार कर लेगा। परन्तु इधर बहुत दिनों से प्रजातन्त्री शासन के अधीन रह चुकने के बाद वह जर्मनी के अधिनायकी तन्त्र में सम्मिलित होने के लिए तैयार होगा, इसमें सन्देह ही है।

पूर्व में व्लाडिवास्तक तक और उत्तर में वोल्गा से लेकर दक्षिण में कैस्पियन सागर तक विस्तृत है। बाकी छः प्रजातन्त्रों में से सबसे अधिक महत्व का उक्रेनियन साम्यवादी सोविएट प्रजातन्त्र है जिसकी राजधानी क्रियेफ नामक नगर है और जिसकी सभ्यता मास्को से भी कहीं अधिक पुरानी है। सोविएट प्रजातन्त्री संघ में उक्रेन सन् १९२० तक सम्मिलित नहीं हुआ था। सन् १९२० में भी उक्रेन केवल इसलिए इस संघ में सम्मिलित हुआ था कि उसे पोलैण्डवालों तथा कुछ ऐसे गोरे सेनापतियों का डर था जो उसे अपने अधीन करना चाहते थे।

सोविएट प्रजातन्त्री संघ में एक उक्रेन का प्रजातन्त्र ही ऐसा है जो अबतक संघ से अलग होना चाहता है^२ और इसके लिए सोविएट प्रजातन्त्री संघ को प्रायः चिन्तित रहना पड़ता है। सा० सो० प्र० सं० के सदस्य प्रजातन्त्रों में कुछ ऐसे भी हैं जिनके अन्तर्गत और भी छोटे-छोटे स्वराज्य-भोगी प्रजातन्त्र तथा स्वराज्य-भोगी प्रदेश हैं, जिनमें से तातार प्रजातन्त्र, वोल्गा का जर्मन प्रजातन्त्र, और जार्जिया, अरमेनिया तथा आज़रबायजान के प्रजातन्त्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

इस संघ के सभी सदस्य प्रजातन्त्रों का परस्पर बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है, क्योंकि सदस्य प्रजातन्त्रों की ओर से संघ सरकार को बहुत अधिक अधिकार दिये गये हैं। उदाहरणार्थ, संघ सरकार को ही यह अधिकार है कि वह सब सदस्य प्रजातन्त्रों की ओर से विदेशों के साथ व्यापार तथा अन्य प्रकार के सम्बन्ध स्थापित करे या तोड़े; दूसरे देशों के आक्रमणों से उनकी रक्षा करे; यदि किसी प्रजातन्त्र में कोई नई विरोधी क्रांति खड़ी हो तो उसे दबावे; सब प्रजातन्त्रों की राष्ट्रीय और आर्थिक नीति स्थिर करे; सब तरह के कर आदि लगावे और मजदूरों का संघटन तथा उनके सम्बन्ध में कानून आदि बनावे। इस प्रकार

आर्थिक और सामाजिक जीवन की प्रायः सभी मुख्य-मुख्य बातें संघ सरकार के हाथ में ही हैं। अलग-अलग प्रजातन्त्रों के अधिकार में तो प्रायः शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि की ही व्यवस्था है; और इन सब बातों में अधिकांश प्रजातन्त्रों ने अपने यहाँ की स्थानिक पंचायतों को बहुत अधिक स्वतन्त्रता दे रखी है।

परन्तु हम विषय में एक बहुत महत्व की और ध्यान रखने के योग्य बात यह है कि संघ सरकार ने सभी प्रजातन्त्रों को पूरी-पूरी सांस्कृतिक स्वतन्त्रता दे रखी है। सभी प्रजातन्त्र अपने यहाँ की भाषा में जो चाहे, वह लिख सकते हैं, जो चाहे वह कह सकते हैं और जो चाहे, वह छाप सकते हैं। जारशाही में अलग-अलग राष्ट्रों को इस प्रकार की कोई स्वतन्त्रता नहीं थी। उन दिनों तो इन सभी बातों में पूरा-पूरा दमन होता था। लेकिन अब सोविएट संघ सरकार ने वह सारी पुरानी नीति बिल्कुल उलट दी है और इस विषय में इतनी अधिक उदारता से काम लिया है, जितनी उदारता से अबतक बहुत ही कम यूरोपियन राष्ट्रों ने काम लिया है। इस प्रकार की उदारता से आस-पास के अनेक राज्यों के मन में भी इस संघ में सम्मिलित होने का लोभ उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, सोविएट संघ के आस-पास अफगानिस्तान और चीनी तुर्किस्तान आदि कुछ ऐसे राज्य हैं जो आगे चलकर इस उदाहरण से प्रेरित होकर अपने यहाँ साम्यवादी प्रणाली प्रचलित कर सकते हैं, और सोविएट संघ के सदस्य हो सकते हैं। यद्यपि सोविएट संघ के सब नेता रूसी ही हैं और उनकी भाषा भी मुख्यतः रूसी ही है, परन्तु यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो सिद्धान्ततः सोविएट संघ की कोई राष्ट्रीय इकाई नहीं है, बल्कि वह केवल ऐसे राज्यों का संघ है जिनमें एक ही तरह की साम्यवादी संस्थाएँ हैं, और जो एक ही सामाजिक सिद्धान्त—मार्क्सवाला साम्यवादी सिद्धान्त—

मानते हैं।

आज-कल के संसार में और जितनी राजनीतिक सत्ताये हैं, उनसे इस सत्ता में अनेक भेद हैं और उन्हीं भेदों में से एक भेद यह भी है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि रोम या इस्लाम के साम्राज्यों की तरह यह अपने शत्रुओं के बल पर अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं करना चाहता। 'कम-से-कम विधान में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि यदि कोई सदस्य-प्रजातन्त्र किसी समय इस संघ से अलग होना चाहे तो उसे अलग होने का भी पूरा-पूरा अधिकार है। यो चाहे अवसर पड़ने पर किसी सदस्य प्रजातन्त्र को भले ही सहज में अलग न होने दिया जाय, परन्तु फिर भी सिद्धान्ततः उसे अलग होने का अधिकार तो संघटन-विधान के अनुसार है ही।

सोविएट संघ में मत या वोट देने का अधिकार सब लोगों को समान रूप से प्राप्त है। उसमें पुरुष भी मत दे सकते हैं और स्त्रियाँ भी। हाँ, जो लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किराये या मजदूरी पर लोगों से काम लेते हैं, उन्हें अवश्य ही मत देने का अधिकार नहीं है। परन्तु खेती-बारी करनेवाले कृषक इससे बरी है। इसके सिवा जो लोग बिना परिश्रम किये और बिना कमाये अपनी जायदाद आदि से होनेवाली आय से अपना निर्वाह करते हैं, साधु-संन्यासी या धर्म-पुरोहित हैं, जो जड़-बुद्धि या मूढ़ हैं अथवा जो किसी समय जारशाही के गुमास्ते

१ पर इस बार जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके उसका विनाश आरम्भ किया, तब सोविएट रूस ने भी आगे बढ़कर पोलैंड के बहुत बड़े भाग में सोविएट तंत्र स्थापित कर दिया था; और कई छोटे-छोटे बाल्टिक राज्यों को अपने प्रभाव-क्षेत्र में ले लिया था। फिर फिनलैंड पर भी आक्रमण करके उसने उसका कुछ प्रदेश छीन लिया था। रा० चं० वर्मा

और कर्मचारी थे, उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। फिर सोविएट-प्रणाली का स्वरूप भी कुछ ऐसा ही है कि उसमें वोट या मत का कुछ बहुत अधिक महत्त्व नहीं है। नागरिकों को जो बहुत से अधिकार प्राप्त हैं, उन्हीं में वोट देने का भी एक अधिकार है।

नागरिकों को और भी अनेक प्रकार के अधिकार होते हैं। वे कमकरो और मजदूरों के संघों के सदस्य हो सकते हैं, उन्हें वह कार्ड या प्रमाणपत्र मिलता है जिसके अनुसार उन्हें सरकार की ओर से खाने-पीने आदि की तथा अन्य आवश्यक वस्तुये मुफ्त मिलती हैं, और बहुत सी ऐसी सामाजिक सेवायें भी मिल सकती हैं जो राज्य की ओर से परिचालित होती हैं, आदि-आदि।

अपने हाथ से नागरिकता के अधिकार गँवा देना भी वहाँ एक तरह का जुर्म या अपराध ही समझा जाता है; और यदि ऐसा अपराध भीषण हो तो उसके लिए सजा भी मिल सकती है।

ध्यान रखने के योग्य एक और बात यह है कि सभी सामाजिक और राजनीतिक विषयों में स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही अधिकार होते हैं। वहाँ बहुत सी ऐसी व्यवस्थाये भी हैं जिनसे स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि स्त्रियों को सबमुच पुरुषों के समान ही अधिकार हैं। अनेक देशों में ऐसे कानून तो बना दिये जाते हैं जिनसे स्त्रियों के समान अधिकार मान लिये जाते हैं, पर फिर भी जिनसे स्त्रियों को वास्तव में समानता के अधिकार प्राप्त नहीं होते। पर सोविएट सघ में यह बात नहीं है। वहाँ स्त्रियों को समानता के जो अधिकार दिये गये हैं, वे वास्तविक हैं। विवाह के सम्बन्ध में वहाँ जो कानून हैं, वे स्त्रियों और पुरुषों में कोई भेद नहीं करते। इसके सिवा वेंतन आदि में भी दोनों में कोई भेद नहीं किया जाता। रोग, गर्भ और प्रसव

आदि के समय स्त्रियों की देख-रेख आदि के लिए भी वहाँ बहुत ही विस्तृत व्यवस्था है। तात्पर्य यह कि इस प्रकार की बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे स्त्रियों को सचमुच पुरुषों के समान ही अधिकार होते हैं। यह समानता कोई दिखावटी नहीं है, बल्कि वास्तविक है।

रूस के नये संघटन-विधान में जो राजनीतिक प्रणाली स्थिर की गई है, वह एक प्रकार से कोणाकार है। नीचे की ओर तो उसका विस्तार बहुत अधिक है। ज्यों-ज्यों वह ऊपर की ओर बढ़ती है, त्यों-त्यों उसका विस्तार कम होता जाता है और अन्त में वह एक कोण या शिखर के रूप में जाकर समाप्त होती है। सबसे नीचेवाले तल में गाँवों और देहातों की छोटी-छोटी सोविएटें या पंचायतें हैं और उनके ऊपर उन्हीं की चुनी हुई दूसरी बड़ी पंचायतें हैं। छोटे-छोटे कस्बों में जो कल-कारखाने होते हैं, उनके कमकरो की भी इसी तरह की चुनी हुई पंचायतें होती हैं; और इन सब पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों की वे सोविएटें या पंचायतें होती हैं जो जिले भर के सब कामों की व्यवस्था करती हैं। जिले की पंचायतें अपने प्रान्त की पंचायतें चुनती हैं और प्रान्तों की पंचायतें उस केन्द्रीय संस्था के सदस्यों का चुनाव करती हैं जो पंचायतों की केन्द्रीय कांग्रेस (Central Congress of Soviets) कहलाती है। ऐसा नियम है कि इस कांग्रेस का अधिवेशन हर साल हुआ करे। संघटन-विधान के अनुसार सारे संघ के लिए सबसे बड़ा अधिकार इसी कांग्रेस के हाथ में होता है। इस कांग्रेस में जो निश्चय होते हैं, वे सारे संघ में समान रूप से माने जाते हैं। सोविएट कांग्रेसों में देहातों के प्रतिनिधियों की अपेक्षा नगरों और कस्बों के ही प्रतिनिधि अधिक होते हैं। इस सम्बन्ध में संघटन-विधान की नवी धारा में कहा गया है—

“साम्यवादी सोविएट प्रजातन्त्री संघ में सोविएटों की जो

क.प्रेस होगी, उसका निर्वाचन नगरों और वहाँ को सोविएटो के प्रतिनिधियों से इस आधार पर होगा कि प्रत्येक २,५००० निर्वाचको का एक डिप्टी प्रतिनिधि लिया जायगा, और सोविएटो की प्रान्तीय कांग्रेसों में आबादी के हर १,२५,००० आदमियों का एक डिप्टी प्रतिनिधि लिया जायगा।”

सोविएटो की कांग्रेस ही संघ की कौन्सिल का निर्वाचन करती है। इस कौन्सिल और राष्ट्रों अथवा स्वतन्त्र प्रजातन्त्रों के प्रतिनिधियों की कौन्सिल के योग से संघ की केन्द्रीय कार्य-कारिणी समिति बन जाती है। लेकिन इन दोनों कौन्सिलों के सदस्यों की संख्या इतनी अधिक होती है कि उनकी बैठक जल्दी-जल्दी नही हो सकती। इसलिए बीच में काम चलाने के लिए शासन का सब काम ‘प्रिसीडियम’ नाम की उस प्रतिनिधि सभा के हाथ में दे दिया जाता है, जिस में उक्त दोनों कौन्सिलों के चुने हुए इक्कीस सदस्य होते हैं। यही समिति केन्द्रीय कार्यकारिणी (Central Executive) कहलाती है। इस समिति की अधीनता में लोक प्रतिनिधियों की कौन्सिल होती है जिसमें राज्य के मुख्य-मुख्य विभागों के प्रधान अधिकारी रहते हैं।

यह सभा बहुत कुछ ब्रिटिश मन्त्रि-मंडल के ही समान होती है। साम्यवादी राज्य में सरकार के काम साधारणतः बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, इसलिए उन सब कामों के अलग-अलग विभाग संभालने के लिए वहाँ और भी बहुत सी कौन्सिलें, कमिशनर और कमेटियाँ होती हैं, जिनके स्वरूप और कार्य आदि बीच-बीच में बदलते रहते हैं। यद्यपि ये सब समितियाँ और इनके कार्य बहुत मनोरंजक होते हैं, पर फिर भी हमारे पास यहाँ इतना स्थान नहीं है कि इन सब का वर्णन किया जा सके। वहाँ संघ की सुप्रीम कोर्ट होती है; कमकर्मों और खेतिहरों की अवस्था का निरीक्षण करने के लिए कमसरियट होता है जो आर० के० आई०

कहलाता है और राज्य का राजनीतिक विभाग होता है जो जी० पी० यू० कहलाता है। इन सब का निर्वाचन भी प्रत्यक्ष रूप से संघटन-विधान के अनुसार होता है। इन सबके सम्बन्ध की कुछ बातें आगे चलकर यथा-स्थान बतलाई जायँगी। सोविएट संघ का कोई सभापति या राष्ट्रपति नहीं होता। हाँ, केन्द्रीय कार्य-कारिणी समिति के कई सभापति होते हैं, और कमिश्नों या विभाग मन्त्रियों की कौन्सिल का भी एक सभापति होता है। लेनिन बहुत दिनों तक इसी पद पर रहकर काम करता था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद से इस पद का महत्व बहुत ही कम हो गया है।

सोविएट संघटन का यह बहुत ही संचित्त वर्णन है। परन्तु यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि सोविएट संघ का संघटन-विधान कुछ बहुत पेचीला या कठिन नहीं है, और उसकी सब बातें बहुत सहज में समझ में आ जाती हैं। परन्तु इस संघटन-विधान का किसी तरह का सारांश जान लेने पर भी रूस के वास्तविक राजनीतिक जीवन की कोई कल्पना नहीं की जा सकती; और इसका सीधा-सादा कारण यही है कि उस जीवन की मुख्य-मुख्य बातों का उस संघटन-विधान में कोई उल्लेख ही नहीं है।

मार्क्स ने कमकरो के जो अनेक प्रकार के संघटन बतलाये हैं, उनमें से केवल एक ही, अर्थात् सोविएटो या पंचायतोवाले प्रकार को इस संघटन-विधान में स्थान दिया गया है। और ऐसा होना इसलिए बिल्कुल स्वाभाविक था कि जिन दिनों रूस में राज्य-क्रान्ति हुई थी, उन दिनों भी और उनसे पहले भी रूस में आप-से-आप बहुत सी सोविएटें बन गई थीं; और फिर आगे चलकर इन्हीं सोविएटों ने क्रान्तिकारी सरकार के हाथ में सब राजनीतिक तथा शासन-सम्बन्धी अधिकार सौंपे थे। जैसाकि संघटन-विधान में कहा गया है, रूस की सरकार सोविएटो की

ही बनाई हुई है, और उन्हीं के आधार पर बनी है। लेकिन सारे देश में कमकरो ने केवल सोविएट ही नहीं बनाई थी, बल्कि इनके अतिरिक्त शासन-सम्बन्धी कार्यों के लिए (कायदे-कानून बनाने के काम के लिए नहीं) और भी बहुत तरह की संस्थाएँ बनी थी, जिनमें सोविएटों की अपेक्षा कहीं ज्यादा ज्ञान दिखलाई देती थी। यहाँ इन संस्थाओं को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए।

इस सम्बन्ध में हमें एक बात बराबर याद रखनी चाहिए। वह यह कि साधारणतः किसी पूँजीदारीवाले देश में शासन का जितना क्षेत्र होता है, उसकी अपेक्षा साम्यवादी देश या समाज में शासन का क्षेत्र कहीं अधिक बड़ा और विस्तृत होता है। पूँजीदारीवाले देशों में सारा शिल्प, उद्योग-धन्धे और व्यापार आदि बहुत से काम निजी रूप से कुछ व्यक्तियों के हाथ में होते हैं। यातायात के बहुत से साधन भी उन्हीं के हाथ में होते हैं और उनका केवल कुछ अंश सरकार की अधीनता में काम करता है। परन्तु साम्यवादी देश या समाज में ये सभी बातें सरकार या राज्य के अधीन होती हैं और इसीलिए उनके शासन का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत होता है। तात्पर्य यह कि पूँजीदारीवाले देशों में जितनी बातें सरकार के हाथ में होती हैं और जितने क्षेत्रों में उसे शासन की व्यवस्था करनी पड़ती है, उन सबकी तो व्यवस्था साम्यवादी सरकार को करनी ही पड़ती है, पर उसके साथ-ही-साथ उसे और भी बहुत सी बातों की व्यवस्था करनी पड़ती है और इसीलिए उसका शासन-क्षेत्र स्वभावतः बहुत बड़ा होता है।

सामूहिक व्यवस्था—एक हद तक सोविएट शासन ऊपर से ही होता है। अन्यान्य बहुत से देशों की तरह वहाँ भी बहुत सी बातों में विभागों के प्रधान अधिकारियों की ही आज्ञाएँ चलती हैं। परन्तु जैसा कि समय-समय पर और अनेक देशों ने भी

किया है, ये विभाग और उनके प्रधान अधिकारी कमकरो की और भी कई ऐसी संस्थाओं से सहायता लेते और उनका उपयोग करते हैं जो वहाँ क्रान्ति के पहले से ही चली आ रही हैं। वहाँ पहले से मजदूरों और कमकरो के जो बहुत से संघ या ट्रेड-यूनियन और सहकारी सोसाइटियाँ चली आ रही हैं, उनसे भी सरकार शासन आदि के बहुत से काम लेती है। विशेषतः जब से वहाँ के सरकारी श्रम-विभाग का सारा काम ट्रेड-यूनियनों या मजदूरों और कमकरो के संघों को सौंप दिया गया है, तब से वे संघ सरकारी यन्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग बन गये हैं। परन्तु अन्यान्य सभी देशों से बढ़ कर एक विशेष बात वहाँ यह है कि वहाँ के अधिकांश कार्यों के सम्बन्ध में नीचे-वाले स्तर ही निर्णय करते हैं और उन्हीं के हाथों में उन कामों की व्यवस्था भी रहती है। ऊपर से उनके लिए केवल वही आज्ञायें आती हैं जो उनके लिए मार्गदर्शक का काम देती हैं। वहाँ अलग-अलग हर एक काम में जितने आदमी लगे रहते हैं, वे सब अपनी-अपनी सभायें और समितियाँ बना लेते हैं, और अपने अधिकांश सामाजिक कार्यों की सारी व्यवस्था आप ही कर लेते हैं।

उदाहरण के लिए कोई कारखाना ले लीजिए। उस कारखाने में जितने आदमी काम करते हैं, वे सब मिल कर एक कमेटी बना देते हैं। उस कारखाने में काम करनेवालों के सामाजिक जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली जितनी बातें होती हैं, उन सब की व्यवस्था वही कमेटी करती है। कारखाने के सभी कमकरो के लिए एक भोजनालय और एक क्लब होता है, और सब लोगो के रहने के लिए मकान होते हैं, और इन सब की सारी व्यवस्था उसी कमेटी के हाथ में होती है।

कारखाने में जो म्त्रियाँ काम करती हैं, उनके बच्चों के लिए

तरह करने चाहिए। आरम्भिक काल के साम्यवादी कहा करते थे कि जहाँ किसी प्रकार का उत्पादन होता हो या कोई चीज तैयार होती हो, वहाँ वह चीज तैयार करनेवाले सब लोगों को मिलकर उस उत्पादन पर नियन्त्रण रखना चाहिए। इसलिए इस सम्बन्ध में हम इतना तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस कमेटी का उत्पादन पर नाम को भी नियन्त्रण नहीं होता। सन् १९१८-१९ में कुछ दिनों तक इस प्रकार का प्रयोग किया गया था और कारखानों में बननेवाली चीजों या उनके उत्पादन पर इस तरह की कमेटियों का ही नियन्त्रण रक्खा गया था। परन्तु उसका परिणाम बहुत ही बुरा हुआ था। इसलिए वह व्यवस्था उसी समय उठा दी गई थी। अब तो किसी कारखाने में बननेवाली चीजों या उनके उत्पादन पर उन्हीं लोगों का नियन्त्रण रहता है, जिनके हाथ में उस कारखाने की व्यवस्था होती है। उनकी देख-रेख वे सरकारी कर्मचारी करते हैं जो इसी काम के लिए नियुक्त होते हैं।

परन्तु यह बात उस 'कोलखोजी' खेती के सम्बन्ध में नहीं है जिसकी कुछ बातें हम आगे चलकर बतलावेगे। इस कमेटी को यह भी निश्चय करने का कोई अधिकार नहीं रहता कि कमकरो को क्या पारिश्रमिक दिया जाय या उन्हें किस प्रकार तथा किस अवस्था में रक्खा जाय। ये सब बातें भी ऊपर के अधिकारी ही निश्चित करते हैं। एक बहुत बड़ी हद तक ये कमेटियाँ आलोचनायें भी करती हैं और शिकायतें भी करती हैं। यदि कोई रूसी कमकर अपने कारखाने की किसी बात से असन्तुष्ट होता है तो उसके पास अपना वह असन्तोष प्रकट करने के बहुत अधिक साधन होते हैं। लेकिन फिर भी यह नहीं समझना चाहिए कि ये संस्थाएँ केवल शिकायत और आलोचना करने लिए ही होती हैं। कारखाने की चीजें तैयार करने में भी और

इस सम्बन्ध में आगे के लिए योजनाये बनाने में भी इन संस्थाओं से निश्चित रूप से बहुत बड़ी सहायता मिलती है। रूस में जो पहली पंच-वार्षिक योजना बनी थी, उससे पहले सारे रूस के कमकरो की इन संस्थाओं में बहुत अधिक वाद-विवाद हुआ था और उस योजना को सफल करने में भी, और समय-समय पर आवश्यकतानुसार उस में सुधार करने में भी, इन संस्थाओं ने कुछ कम सहायता नहीं की थी।

ये संस्थाये मजदूरों के लिए सभी तरह के सामाजिक और सांस्कृतिक काम तो करती ही हैं, पर साथ ही ये अदालत का भी कुछ काम करती हैं। यदि कोई कार्यकर्ता कोई अपराध करता है या कारखाने के नियमों की अवज्ञा करता है तो उसका विचार भी पहले इसी संस्था में होता है और यहीं से उसे दंड भी मिलता है।

इस प्रकार कलेक्टिव या कारखाने की कमेटी लोकल बोर्ड का भी काम करती है, स्थानीय अदालत का भी काम करती है और क्लब का भी काम करती है। इसके सिवा वह कारखाने के सुधार के उपाय भी बतलाती है और अच्छी-अच्छी योजनायें भी सुझाती है। तात्पर्य यह कि एक छोटे क्षेत्र में वह एक छोटी सी सरकार के ही अधिकांश कार्य करती है। इस सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि इस तरह की संस्थाये संसार के और किसी देश में नहीं होतीं। -

इस कलेक्टिव का रूप चाहे जो हो और इसका संघटन चाहे जिस प्रकार होता हो, परन्तु फिर भी इसमें कोई सन्देह नहीं कि आजकल के रूस में यह सबसे अधिक महत्व की, सबसे अधिक आवश्यक, और सब से अधिक मनोरंजक संस्था है। यही एक ऐसी संस्था है जो सब में नई जान डालती है और जो प्रजातन्त्र के प्रत्येक नागरिक के सभी अच्छे-अच्छे गुणों को एक सूत्र में

बाँधकर उनसे ठीक तरह से काम लेती है, और उनका पूरा-पूरा उपयोग करती है। जो साम्यवादी समाज चारों ओर से पूँजीदार समाजों और देशों से घिरा हुआ हो, उसे अपने यहाँ सब लोगों से बहुत ही कठोरतापूर्वक मर्यादा और नियमों का पालन कराना पड़ता है। रूस में यही एक ऐसी संस्था है जो सब लोगों से उस मर्यादा और नियमों का ठीक तरह से पालन कराती है और यह कठोरता किसी को खलने नहीं देती। जिन देशों में रूस की तरह बहुत दिनों से गरीबों पर बड़े-बड़े अत्याचार न होते आये हो, उनमें इन संस्थाओं की स्थापना और इनके नियमों का ठीक-ठीक पालन किसी प्रकार सम्भव ही नहीं है। लेकिन इस में कोई सन्देह नहीं कि प्रतिनिधिसत्तात्मक सामाजिक जीवन की विकट स्थायी समस्या की मीमांसा में इन संस्थाओं से बहुत ही बहुमूल्य सहायता मिलती है।

साम्यवादी दल—परन्तु सोविएट संघटन-विधान में इन कलेक्टिवों या सामूहिक संस्थाओं का कहीं कोई जिक्र नहीं है। और न उसमें उस साम्यवादी दल का ही कहीं कोई जिक्र है, जिसका इस प्रणाली में और विशेषतः इस क्रान्ति के काल में इतना अधिक महत्व है।

प्रायः व्यंग्य और उपहासपूर्वक कहा जाता है कि और सब प्रकार के दलों से और साम्यवादी दल में सब से बड़ा अन्तर यही है कि इस दल में सम्मिलित होना तो बहुत कठिन होता है और इससे अलग होना बहुत ही सहज होता है। परन्तु वास्तव में अन्यान्य राजनीतिक दलों से इस दल में इसके सिवा और भी कई बड़े अन्तर हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से यह साम्यवादी दल उसी पुराने रूसी साम्यवादी प्रतिनिधिसत्तात्मक दल का बहुमत-वाला या बोलशेविक अंग है, जो सन् १९०३ में सिद्धान्त-सम्बन्धी कुछ मत-भेदों के कारण विभक्त हो

गया था। परन्तु सन् १९१७ की ग्रीष्म ऋतु में रूस की पहली राज्य-क्रान्ति के बाद और दूसरी राज्य-क्रान्ति से पहले इस दल ने उन सब शक्तियों का नेतृत्व ग्रहण करना निश्चित किया था जो अस्थायी सरकार का विरोध करती थी। इस दल ने उस समय सब जगह यही पुकार मचाई थी कि सारी शक्ति सोविएटो या पंचायतो के हाथ में रहनी चाहिए, अर्थात् सारा अधिकार मजदूरो की संस्थाओं और संघटनों को मिलना चाहिए; और तभी से यह दल वास्तव में मजदूरो और कमकरो के अधिनायकत्व का साधन बना है।

यहाँ हमें इस बात का विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जिस समय देश में राज्य-क्रान्ति हो रही थी, उस समय यह दल अपने आपको उस अधिनायकत्व का साधन समझता था या नहीं, परन्तु यह बात बहुत ही स्पष्ट है कि थोड़े ही दिनों में सब लोगों का समझ में बहुत अच्छी तरह आ गया था कि जबतक कोई मजबूत, व्यवस्थित और समझदार दल नेतृत्व न ग्रहण करेगा, तबतक क्रान्ति ठीक तरह से न हो सकेगी, और इस के बदले में सारे देश में अव्यवस्था फैल जायगी तथा भीषण गृह-युद्ध छिड़ जायगा। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने ही यह दल बनाया था।

रूस के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो संस्थायें, कानून बनाने और शासन करने का काम करती हैं, वे वही हैं जिनका ऊपर वर्णन किया गया है। परन्तु कानून बनाने और शासन करने के सम्बन्ध में जो नीति है, वह साम्यवादी दल ही स्थिर करता है। इसका मतलब यही है कि नीति के सम्बन्ध में वास्तव में जो महत्वपूर्ण वाद-विवाद होते हैं, वे

सोविएटो की कांग्रेस में नहीं होते, बल्कि समय-समय पर होने-वाली साम्यवादी दल की कांग्रेसों में होते हैं।

संघटन-विधान में चाहे जो कुछ कहा गया हो, लेकिन असल में सारा अधिकार साम्यवादी दल की कांग्रेस के ही हाथ में है। और एक कांग्रेस हो जाने के बाद जबतक दूसरी कांग्रेस नहीं होती, तबतक सारा काम इस दल की कार्यकारिणी समिति करती है, जिसका मन्त्री स्टालिन है।

साम्यवादी दल ने जो सारा अधिकार अपने हाथ में कर रक्खा है, उसका कारण यही है कि जितने महत्व के पद हैं, वे सब इस दल के सदस्यों के ही हाथ में रहते हैं, अथवा कम-से-कम ऐसे लोगों के हाथ में रहते हैं जो साम्यवादी सिद्धान्तों को पूरी तरह से मानते हैं। इसके सिवा स्थानीय सोविएटो तथा महत्वपूर्ण क्लेक्टिवों में भी इस दल के इतने काफी आदमी रहते हैं कि वे सोविएटो और क्लेक्टिव इस दल के सिद्धान्तों और निश्चयों के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकते।

हमारे कहने का यह मतलब नहीं है कि सारे रूस में काम करने वाले अधिकारियों के जितने पद हैं, उन सब पर इस दल के सदस्य ही हैं। वास्तव में इस दल की सदस्यता के नियम ही कुछ इतने कठोर हैं कि सब लोग सहज में इसके सदस्य नहीं हो सकते। इस समय भी सारे देश में इस दल के शायद पच्चीस लाख से अधिक सदस्य न होंगे; और इस दल के नेताओं की निश्चित नीतिक कारण यह संख्या भी प्रायः घटती-बढ़ती रहती है। इसके सिवा देश में और भी ऐसे लाखों करोड़ों आदमी हैं जो इस दल की नीति पर तो पूरा-पूरा विश्वास रखते हैं, परंतु फिर भी जो किसी-न-किसी कारण से इस दल में सम्मिलित नहीं होते, अथवा नहीं हो सकते। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि सारे देश में जितने बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारी हैं, वे सब इस दल के सदस्य ही हैं। और

सोविएटों में भी वही सोविएट या पंचायत अधिक महत्व की समझी जाती है जिसमें इस दल के सदस्य ही अधिक होते हैं।

जिस ढंग से इस दल ने सब जगह अपना प्रभुत्व स्थापित कर रक्खा है, वह ढंग भी बिल्कुल सीधा-सादा कहा जाता है, और वह ढंग बतलाया भी बहुत सहज में जा सकता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं समझना चाहिए कि इस ढंग से काम लेना भी उतना ही सहज है। इस में सब से बड़ी आवश्यकता इस बात की होती है कि दल के जितने सदस्य हों, वे बहुत ही व्यवस्थित और मर्यादित रूप से सब काम करें, दल की सभी आज्ञाओं का पूरी तरह से पालन करें, और दल के निश्चयों तथा सिद्धान्तों पर पूरी-पूरी निष्ठा और श्रद्धा रखें, और उनमें यथेष्ट कार्य-कुशलता, बुद्धि और योग्यता हो। दल के सदस्यों में इन सब गुणों की इसलिए और भी अधिक आवश्यकता होती है कि रूस आजकल आर्थिक दृष्टि से दिन-पर-दिन बहुत अधिक विकसित होता जा रहा है। देश ज्यों-ज्यों इस उन्नति की ओर अग्रसर होता जाता है, त्यों-त्यों यह बात और भी अधिक स्पष्ट रूप से सिद्ध होती जाती है कि केवल पुराने ढंग के आदर्श विचारों से ही कोई काम नहीं हो सकता।

यदि कोई व्यक्ति पुराने आदर्श सिद्धान्तों को पूरी तरह से मानता हो, परंतु उसमें योग्यता, बुद्धिमत्ता और कार्य-कुशलता न हो तो इस प्रणाली में उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता। साम्यवादी दल के सिद्धान्तों पर आस्था रखना तो आवश्यक है ही, लेकिन किसी ऊँचे पद पर पहुँचने के लिए साम्यवादियों को और भी अनेक प्रकार की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना पड़ता है। इसके विपरीत यदि उसमें सब गुण तो हों, परंतु साम्यवादी सिद्धान्तों पर उसका पूरा-पूरा विश्वास न हो, तो वह व्यक्ति रूस की वर्तमान शासन-प्रणाली के लिए किसी काम का नहीं है।

इसीलिए साम्यवादी दल में सिर्फ ऐसे ही चुने हुए लोग रह सकते हैं जो हर तरह से योग्य होने के अतिरिक्त दल के सिद्धान्तों पर पूरा-पूरा विश्वास रखते हों और उन सिद्धान्तों के लिए अपना सर्वस्व तक त्यागने के लिए तैयार रहते हों। और इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए कठोर-से-कठोर उपायो तक का अवलम्बन किया जाता है।

राज्य-क्रांति से पहले लोग केवल बाह्य परिस्थितियों से ही विवश होकर इस दल की मर्यादा और नियमों का पालन करते थे। उस समय उन्हें भय रहता था कि यदि हम मर्यादा भंग करेंगे तो या तो हमें देश-निकाला ही मिलेगा और या हमें अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ेगा। जो दल सरकार की तरफ से गैर-कानूनी ठहरा दिया गया हो, उसमें कभी कमजोर और निकम्मे आदमी नहीं शामिल हो सकते। अगर कभी किसी तरह ऐसे कुछ आदमी उसमें पहुँच भी जाते हैं तो या तो वे जल्दी ही काम के आदमी बन जाते हैं और या दल में से निकाल बाहर कर दिये जाते हैं। लेकिन राज्य-क्रांति के बाद से अब वहाँ बिल्कुल ही नये प्रकार की मर्यादा और नये प्रकार के नियम बने हैं। ये नियम स्वयं भी बहुत कठोर हैं और इनका पालन भी बहुत ही कठोरतापूर्वक किया और कराया जाता है।

पहली बात तो यह है कि साम्यवादी दल के सदस्यों की सूची पर सदा पूरा ध्यान रखा जाता है, और समय-समय पर उस में काट-छाँट होती रहती है। यह काट-छाँट इसी उद्देश्य से की जाती है कि जिसमें शिल्प और उद्योग-धन्धों में काम करनेवाले मजदूरों और कमकरो का अनुपात इस सूची में सदा बढ़ा रहे, जिसमें दल का मजदूरों और कमकरोवाला स्वरूप नष्ट न होने पावे। और तरह के काम करनेवालों के लिए तो नहीं, लेकिन उद्योग-धन्धों में काम करनेवाले लोगों के लिए इस दल में

सम्मिलित होना अपेक्षाकृत कुछ सहज होता है ।

लेकिन समय पर दल की सूची में जो काट-छोट होती रहती है, उसमें भिन्न-भिन्न वर्गों के शिल्पियों, कारीगरों और कमकर्मों के बहुत से नाम एकदम से बढ़ा दिये जाते हैं ।

दूसरी बात यह है कि साधारणतः जबतक बहुत सी बातों में किसी की पूरी-पूरी परख नहीं कर ली जाती, तबतक उसे दल में सम्मिलित नहीं किया जाता । इस परख के बाद भी पहले वह कुछ दिनों तक इसलिए उम्मीदवारी में रक्खा जाता है जिसमें उसकी योग्यताओं और गुणों की और भी पूरी तरह से जाँच हो जाय । ये सब उपाय इसी आशा से किये जाते हैं कि दल का काम सँभालने के लिए जो नये सदस्य आवें, वे चरित्र, योग्यता और बुद्धिमत्ता आदि सभी बातों के विचार से पूर्ण-रूप से उपयुक्त हों ।

तीसरी बात यह है कि जो लोग दल के सदस्य हो जाते हैं, उन्हें अपने दल और देश की व्यक्तिगत रूप से बहुत अधिक सेवा भी करनी पड़ती है, और अपना व्यक्तिगत आचरण भी बहुत उच्च रखना पड़ता है । उनसे यह भी आशा की जाती है कि वे या तो स्वयं अपनी ही इच्छा से और या दल की आज्ञा से स्वेच्छापूर्वक अपने ऊपर बहुत तरह के काम लेंगे । उनसे यह भी आशा की जाती है कि वे अपने व्यक्तिगत सुख और मनोविनोद आदि में इस दृष्टि से बहुत कुछ कमी करेंगे जिस में उनकी सार्वजनिक सेवाओं में अधिक विघ्न न पड़ने पावे; और वे साम्यवादी सिद्धान्तों के अनुसार अपना आचरण और अपने कार्य इतने उच्च तल पर रक्खें कि समाज के और लोगों के लिए वे आदर्श हों । यहाँ हमें इस बात का भी स्मरण रखना चाहिए कि रूस में सदाचार पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता । वहाँ आचरण अच्छा

रखने का मतलब यही है कि मनुष्य कभी अपने काम में सुस्ती न करे और सदा समाज को उन्नत, सुखी और सम्पन्न बनानेवाले अधिक-से-अधिक काम किया करे। पहले कुछ दिनों तक यह भी नियम था कि उसे औरो की अपेक्षा कुछ कम वेतन लेना पड़ता था, और यह नियम था कि साम्यवादी दल के सदस्य को किसी अवस्था में इतने से अधिक वेतन न दिया जाय। लेकिन कई कारणों से वह चल नहीं सकता था, इसलिए यह नियम कुछ शिथिल कर दिया गया। पर फिर भी इसका मूल सिद्धान्त अभी तक नष्ट नहीं होने पाया है।

यहाँ तक तो उस बड़े दल की बात हुई जो देश-व्यापी है और जिसकी कांग्रेसों में सारे देश के प्रश्नों का पिचार और निर्णय होता है। इसके सिवा वहाँ साम्यवादियों की एक प्रकार की छोटी सभायें भी होती हैं जिन्हें 'कोमसोमोल' कहते हैं। इन संस्थाओं के प्रायः पचास लाख सदस्य हैं जिनकी अवस्था १६ से २४ वर्ष तक होती है। और जो नवयुवक स्कूलों में पढ़ने वाले बालकों के लिए मार्ग-दर्शक का काम देते हैं, उन्हें 'पायनियर' कहते हैं। इन दोनों संस्थाओं की सदस्यता के सम्बंध में भी बहुत कुछ उन्हीं नियमों और सिद्धान्तों का पालन किया जाता है जिनका साम्यवादी दल की सदस्यता के लिए पालन होता है। जो नवयुवक 'कोमसोमोल' के सदस्य होना चाहते हैं या 'पायोनियर' बनना चाहते हैं, उन्हें पहले कुछ दिनों तक उम्मीदवारी करनी पड़ती है और उस समय कई तरह से उनकी जाँच भी होती है।

अन्य देशों में जिम प्रकार स्काउटों की संस्था होती है, बहुत कुछ उसी प्रकार की यह पायनियर वाली संस्था भी है; पर बहुत सी बातों में यह स्काउटवाली संस्था से बहुत कुछ आगे बढ़ी हुई है। इन पायनियरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि ये राज्य के सामाजिक ढाँचे का एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं।

अन्य देशों के स्काउटों को यों ही सिखला दिया जाता है 'रोज एक अच्छा काम करना चाहिए।' पर कोई स्काउट रोज एक अच्छा काम नहीं करता। हाँ, जब कभी किसी स्काउट से कोई अच्छा काम हो गया, तब हो गया। परन्तु पायनियरों के लिए यह नितांत आवश्यक और अनिवार्य है कि वे नियमित रूप से नित्य एक अच्छा काम करें ही। और हर एक पायनियर को नित्य सामाजिक सेवा का एक-न-एक अच्छा और बड़ा काम अवश्य ही करना पड़ता है। कोमसोमोल में केवल नवयुवक ही सदस्य रहते हैं और क्रांतिकारी देश में नवयुवकों से बहुत बड़ी-बड़ी आशाएँ की जाती हैं; और इसी-लिए शासन के क्षेत्र में इनसे इतनी अधिक सहायता मिलती है, जितनी यूरोप के और किसी देश में इस तरह की संस्थाओं से कभी मिल ही नहीं सकती। बहुत से उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर प्रायः कोमसोमोल ही काम करते हुए दिखाई देते हैं।

इस दल को उसके सिद्धान्तों के अनुसार चलाने का काम नेताओं के हाथ में रहता है। इस दल की कांग्रेसों में जो निश्चय होते हैं, उनका ठीक-ठीक आशय लोगों को बतलाना और उन्हें उन सिद्धान्तों के अनुसार चलाना नेताओं का ही काम है। वास्तव में लेनिन ने ही आरम्भ में सन १९२३ तक इस दल की सारी नीति पूरी तरह से स्थिर कर दी थी। उसके बाद यद्यपि नेताओं में सिद्धान्तों के सम्बन्ध में बहुत कुछ वाद-विवाद होता रहा है, परन्तु नीति स्थिर करने का काम अधिकतर स्टालिन के ही हाथ में रहा है। परन्तु देश में लेनिन के प्रति लोगों का जो आदर था और स्टालिन के प्रति जो आदर है, उसका कारण यह नहीं है कि वे ऊँचे-ऊँचे राजकीय पदों पर रहते आये हैं या उन्होंने बड़े-बड़े अधिकार अपने हाथ में ले रखे थे। लेनिन जनता के कमिषरो की कौन्सिल का सभापति था और स्टालिन दल का मंत्री है। परन्तु

केवल इन पदों पर पहुँच जाने से ही कोई नेता नहीं हो जाता। नेतृत्व तो दल की कॉंग्रेसों में विजयी होने से प्राप्त होता है। ट्रास्की के समय स्टालिन को कई बरसों तक उसके अनुयायियों के साथ काफी लड़ना-झगड़ना पड़ा था, और तब स्टालिन को नेतृत्व प्राप्त हुआ था। इन लड़ाई-झगड़ों का अन्त सन् १९२७ में उस समय हुआ था, जब ट्रास्की देश से निकाल दिया गया था। तब से अब तक रूस में नेताओं का इस तरह का कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ है। अब तो यही होता है कि जो लोग दल की नीति से सहमत नहीं होते, वे चुपचाप दल से अलग कर दिये जाते हैं।

इस दल में असन्तुष्ट और विरोधी वर्गों के लिए कोई स्थान नहीं है। दल के अन्दर किसी तरह की गुटबंदी करना बहुत बड़ा अपराध समझा जाता है। इसलिए ऊपर से देखनेवालों के मन में स्वभावतः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह दल कहाँ तक प्रतिनिधिसत्तात्मक सिद्धान्तों के अनुसार चलता है और इसके सदस्यों को इसकी नीति स्थिर करने का कहाँ तक अधिकार है। यह ठीक है कि इस प्रश्न का पूरा और संतोषजनक उत्तर वही दे सकता है, जिसने बहुत दिनों तक इस दल में रह कर इसकी सेवा की हो। परंतु यह स्पष्ट है कि ट्रास्कीवाले झगड़े के सम्बन्ध में सारे रूस में बहुत बड़ा वाद-विवाद छिड़ गया था, और सभाओं में भी तथा समाचारपत्रों में भी कुछ दिनों तक उसकी खूब चर्चा होती थी। इस झगड़े का निर्णय होने में भी बहुत दिन लग गये थे। इन सब बातों का यही मतलब निकलता है कि दल यही

१. ट्रास्की एक प्रसिद्ध रूसी राजनीतिज्ञ है जो क्रान्तिकारी होने के कारण कई बार गिरफ्तार और निर्वासित हो चुका है। सन् १९१७ वाली क्रान्ति के बाद वह रूस में विभाग मन्त्री था। आज-कल वह फिर निर्वासित है।

चाहता है कि हमारा जो निश्चय हो, उसे सब लोग पूरी तरह से माने। यूरोप के अन्यान्य उदार देशों में यही कहा जाता है कि अल्प-संख्यकों के लिए भी क्षेत्र में कुछ स्थान होना चाहिए। परन्तु रूसवाले अल्प-संख्यकों का होना किसी तरह पसंद नहीं करते। फिर भी यह मानना ही पड़ता है कि रूस की अन्यान्य संस्थाओं की तरह साम्यवादी दल में भी बहुत सी बातों में लोगों को स्थानिक और व्यक्तिगत रूप से ऐसे विषयों में अपना स्वतन्त्र मत रखने का अधिकार होता है, जो प्रजातंत्री संघ की रक्षा और कल्याण के लिए विशेष आवश्यक नहीं समझे जाते। मतलब यह कि बहुत सी बातों में वहाँ लोगो को अपना स्वतंत्र मत रखने का भी अधिकार होता है और विरुद्ध पक्ष को उस प्रकार दमन या नाश नहीं होता, जिस प्रकार जर्मनी या इटली में होता है। इस सम्बन्ध में एक बात यह भी ध्यान रखने की है कि जो लोग विरोधी होने के कारण देश से निर्वासित कर दिये जाते हैं, वे भी चाहे स्टालिन और उसके मित्रों के सम्बन्ध में जो कुछ कहा करे, परन्तु फिर भी वे स्वयं साम्यवादी दल या उसके सिद्धान्तों के विरुद्ध कभी कोई आक्षेप नहीं करते। अर्थात् वहाँ जो झगड़े होते हैं, वे व्यक्तिगत होते हैं, दल या उसके सिद्धान्तों के सम्बन्ध में नहीं होते।

कुछ लोग साम्यवादी दल की तुलना फैसिस्ट और नाजी दलों के साथ करते हैं, और कुछ लोग उसे ईसाइयों के जेसुइट सम्प्रदाय के समान बतलाते हैं। परन्तु ये दोनों ही तुलनाये ठीक नहीं हैं। यह ठीक है कि साम्यवादी लोग इस बात में फैसिस्टों और नाजियों के समान हैं कि वे अपने सदस्यों से दल की व्यक्तिगत रूप से सेवा कराते हैं और समाज के सभी अंगों का अपने ही सिद्धान्त और नीति के अनुसार चलाना चाहते हैं। कम-से-कम एक और बात में फैसिस्ट भी नाजियों की अपेक्षा साम्यवादियों से अधिक

मिलते हुए हैं। नाजी लोग अपने दल में चुने हुए लोगों की अपेक्षा कुछ और लोगों को भी ले लेते हैं; परन्तु साम्यवादी और फैसिस्ट बहुत ही सोच-समझ कर और सिर्फ खास-खास चुने हुए आदमियों को ही अपने दल में लेते हैं। नाजी नेता प्रायः जोशीले व्याख्यान देकर लोगों को उत्तेजित करने का प्रयत्न करते रहते हैं, परन्तु साम्यवादी और फैसिस्ट लोगों को अपने सिद्धान्त अच्छी तरह समझा कर उन्हें अपने साथ मिलाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार दोनों का प्रचार का ढंग बहुत कुछ समान है।

साम्यवादी और फैसिस्टों में यह तो एक बहुत बड़ा और स्पष्ट अन्तर है ही कि साम्यवादियों लोग साम्यवाद के सिद्धान्त मानते हैं और फैसिस्ट उन सिद्धान्तों को बिल्कुल नहीं मानते; लेकिन इसके सिवा साम्यवादी की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि वे सिर्फ बहुत ही चुने हुए लोगों को अपने दल का सदस्य बनाते हैं और जो व्यक्ति बहुत दिनों से खूब समझ-बूझकर उनके सिद्धान्तों को मानता आता है, केवल उसी को अपने दल में मिलाते हैं। यह बात नाजियों में तो बिल्कुल है ही नहीं, पर फैसिस्टों में भी बहुत कम है।

जेसुइटों के साथ साम्यवादियों की जो तुलना की जाती है, उसके सम्बन्ध में इतना ही कह देना पर्याप्त है कि साम्यवादियों का कोई संसार-त्यागी सम्प्रदाय नहीं है। साम्यवादी दल के सदस्यों को समाज के दूसरे नवयुवकों से अलग रखकर विशेष प्रकार की कोई शिक्षा नहीं दी जाती। साधारण बालकों और युवकों को जिस प्रकार की शिक्षा मिलती है, उसी प्रकार की शिक्षा साम्यवादियों को भी मिलती है। इसके अलावा साम्यवादी लोग न तो जेसुइटों की तरह ब्रह्मचारी ही रहते हैं और न किसी विशेष प्रकार के आचार-विचार का पालन करते हैं।

साम्यवादी दल कोई याजकों और धर्म-पुरोहितों का दल

नहीं है। इस दल के कुछ निश्चित सिद्धान्त हैं और जो कोई वे सिद्धान्त पूरी तरह से मानता है, वही इसमें सम्मिलित हो सकता है। उन सिद्धान्तों का केवल उपदेश देनेवालों के लिए इस दल में कोई स्थान नहीं है।

सोविएट शासन के दो अंग—सोविएट शासन में एक ओर तो पूरा-पूरा प्रकाश और ज्ञान दिखलाई देता है और दूसरी ओर उसके बिल्कुल विपरीत घोर अन्धकार और अज्ञान नजर आता है। जो लोग रूसी राजनीति का अध्ययन करते हैं, वे इन दोनों विरोधी बातों को एक साथ देखकर चकर में पड़ जाते हैं। सोविएट रूस में एक ओर तो यह नियम है कि बालकों से कल-कारखानों में किसी तरह का काम न लिया जाय। और दूसरी ओर सोविएट शासन के विरोधी उन कृषकों पर, जो पुराने ढंग से निजी रूप से खेती-बारी करते और कुलकी कहलाते हैं, अनेक प्रकार के अत्याचार होते हैं। साधारण अपराधियों को तो वहाँ हर तरह से सुधारने और अच्छा नागरिक बनाने का प्रयत्न किया जाता है; परन्तु जो लोग इस क्रान्ति के विरुद्ध आन्दोलन करते करते हैं या जिन पर राज्य के किसी प्रकार के विरोध का सन्देह होता है, उनके साथ जेलखानों में बहुत ही कठोर व्यवहार होता है। इस प्रकार एक ओर तो सोविएट शासन बहुत अधिक उदारता से काम लेता है और दूसरी ओर बहुत कठोरता और संकीर्णता से। यही विरोध लोगों की सम्झ में जल्दी नहीं आता। इसलिए यहाँ इस प्रकार की कुछ बातों का स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक जान पड़ता है।

सोविएट रूस एक ऐसा देश है जिसके दो रुख हैं। इसका एक रुख तो वह है जो साम्यवादी समाज का है। यह समाज चारों ओर पूँजीदारों से घिरा हुआ है और उन्हीं के बीच में—बत्तीस दाँतों में जीभ की तरह—रहकर उसे इस बात का निरन्तर

प्रयत्न करना पड़ता है कि किसी प्रकार हमारा अस्तित्व नष्ट होने पावे। यह समाज पूरी तरह से तो मार्क्स के सिद्धान्तों के अनुसार नहीं चलता, लेकिन फिर भी बहुत कुछ उसी के दिखलाये हुए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता है। अबतक इस समाज ने जो काम किये हैं, उनकी यह हर प्रकार के आक्रमणों और आघातों से रक्षा करने का सदा प्रयत्न करता रहता है। इसके विरुद्ध इसका जो दूसरा रुख है, उसमें एक ऐसा देश है जिसमें बहुत दिनों से साम्यवाद के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के प्रयोग होते आये हैं। इन प्रयोगों में कुछ तो सफल हुए हैं और कुछ विफल। परन्तु ये सब प्रयोग प्रायः ऐसे ही सिद्धान्तों और विचारों के आधार पर हुये हैं, जिनका मार्क्स के साथ प्रायः नहीं के समान सम्बन्ध रहा है। इसका कारण यही है कि मार्क्स के लेखों आदि में कहीं साफ तरह से यह नहीं बतलाया गया है कि साम्यवादी राज्य में जनता का जीवन किस प्रकार का होना चाहिए।

वर्तमान रूस का संघटन पहले रुख से सम्बन्ध रखता है, और उसके सब काम सोविएटों या पंचायतों के आधार पर होते हैं। इसीलिए अधिकारियों को सारे देश में उसी कलेक्टिववाली संस्था का खूब जोरों से पचार करना पड़ता है, क्योंकि वे लोग चाहते हैं कि किसानों का कोई ऐसा वर्ग न रह जाय जो इस कलेक्टिववाली संस्थाओं के सिद्धान्त न मानता हो। उन्हें डर है कि यदि देश में इस तरह के थोड़े बहुत किसान रह जायेंगे जो व्यक्तिगत और निजी रूप से खेती-बारी करते रहेंगे और सामूहिक सिद्धान्तों के विरोधी होंगे, तो वे आगे चलकर किसी समय एक और नई क्रान्ति खड़ी कर देंगे जिसके फल-स्वरूप रूस की भी बहुत कुछ आज-कल के फ्रान्स की सी ही अवस्था हो जायगी। इसीलिए उन्हें उन बाहरी शत्रुओं का भी दमन करना पड़ता है जो सोविएट शासन का नाश करना चाहते हैं और देश में रहनेवाले देश-द्रोहियों

को भी दबाना पड़ता है। रूस की लाल सेना भी और राजकीय राजनीतिक विभाग भी इसी प्रकार के दमन और शासन के लिये हैं। और इसी के अनुसार सोविएट सरकार को अपनी वह पर-राष्ट्रीय नीति भी स्थिर करनी पड़ी है जिसका मार्क्स के सिद्धान्तों के साथ बहुत ही कम मेल है। और इसका मुख्य कारण यही है कि मार्क्स के दर्शन में कहीं यह नहीं बतलाया गया है कि पूँजी-दारीवाले संसार में साम्यवादी सरकार का आचरण और व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए।

मार्क्स ने अपने सिद्धान्त बहुत कुछ यही मान कर स्थिर किये हैं कि सारे संसार में साम्राज्यवादी पूँजीदारी की प्रथा पूरी तरह से नष्ट हो जायगी और हर जगह साम्यवाद का ही राज्य दिखाई देगा। उस में यह तो नहीं कहा गया है कि सारे संसार में सभी देशों में एक साथ ही साम्यवाद स्थापित हो जायगा; लेकिन फिर भी यह जरूर समझा गया है कि थोड़े ही समय के अन्दर सब देश साम्यवादी हो जायेंगे। अक्टूबर १९१७ में रूस में जो राज्य-क्रान्ति हुई थी, उसके बाद कुछ दिनों तक रूस के क्रान्तिकारी नेता यही समझते थे कि यह भविष्यद्वाणी शीघ्र ही पूरी होगी और रूस की देखा-देखी संसार के और सब देशों में या कम-से-कम यूरोप के सभी देशों में साम्यवादी राज्यों की स्थापना हो जायगी। उसी समय के लगभग जर्मनी में भी एक राजनीतिक क्रान्ति हुई थी और यह समझा जाता था कि वहाँ भी शीघ्र ही साम्यवाद के सिद्धान्तों का बोल-बाला होगा।

बेवेरिया और हंगरी में तो साम्यवादी सरकारें स्थापित भी हो गई थीं। यहाँ तक कि ग्रेट ब्रिटेन में भी कारखानों के मजदूरों और युद्ध से लौटे हुए सिपाहियों ने कुछ समय के लिए एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी जिसने वहाँ के अधिकारियों और शासकों को बहुत कुछ चिन्तित कर दिया था। इन सब बातों से

रूसी यही समझते थे कि अब बहुत जल्दी सारे संसार में साम्यवादी क्रान्ति होना चाहती है। वे यह भी समझते थे की बिना आस-पास के देशों के साम्यवादी हुए हमारा काम किसी तरह चल ही नहीं सकेगा। आस-पास के देश साम्यवादी हो कर जब हमारी सहायता करेंगे, तभी हमारी क्रान्ति भी सफल हो सकेगी। उन्हें यह आशा ही नहीं थी कि अ-साम्यवादी देशों से घिरे रह कर हम अपनी क्रान्ति की रक्षा कर सकेंगे।

इसीलिए कई बहुत बड़ी-बड़ी समायें करके यह निश्चय किया था कि दूसरे पूँजीदार देशों की प्रजा को भी इसी तरह की साम्यवादी क्रान्ति करने के लिए उत्साहित करना चाहिए और इसके लिए हर तरह से उनकी सहायता करनी चाहिए। परन्तु ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, त्यों-त्यों उन्हें यह मालूम होता गया कि संसारव्यापी साम्यवादी क्रान्ति अभी बहुत दूर है, और अभी कोई देश रूस के आदर्श पर चलने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच में रूस में कुछ गृह-युद्ध भी छिड़ गया था, और कई विदेशी सेनापतियों ने उस पर सैनिक आक्रमण भी कर दिया था।

जब रूस ने इन दोनों ही विपत्तियों से छुटकारा पाया, तब उसके सामने यह प्रश्न आया कि अब हम दूसरे देशों में भी क्रान्ति करने का प्रयत्न करें या पूँजीदार संसार के साथ किसी तरह का समझौता कर लें। ट्रास्की का मत था कि हमें अपने पूर्व निश्चय के अनुसार सारे संसार के देशों में क्रान्ति करने का प्रयत्न करना चाहिए; और स्टालिन कहता था कि हमें अन्यान्य देशों के साथ समझौता करके और अपने देश की अवस्था सुधार कर सारे संसार के सामने साम्यवादी राज्य का एक अच्छा आदर्श उपस्थित करना चाहिए, जिसे देख कर और देश आप-से-आप हमारा अनुकरण करना चाहेंगे।

यदि ट्रास्की की नीति मान ली जाती तो सम्भवतः रूस को सारे संसार के साथ अकेले ही लड़ना पड़ता और उस लड़ाई में शायद रूस का नाश ही हो जाता। ट्रास्की और स्टालिन में नीति के सम्बन्ध में जो यह झगड़ा हुआ था, इसने बहुत उग्र रूप धारण किया था; परन्तु इसमें अन्त में स्टालिन की ही विजय हुई और ट्रास्की को देश छोड़ कर भागना पड़ा। वस उसी समय से रूस के उस दल की पूरी हार हो गई जो सारे संसार में साम्यवादी क्रान्ति करना चाहता था। तब से जब जैसा भौका आता था, तब रूस अपनी वैसी ही पर-राष्ट्रीय नीति स्थिर करता था। इसमें उसका मुख्य उद्देश्य यही होता था कि हमारे साम्यवादी सिद्धान्तों की किसी प्रकार हत्या न होने पावे, और जहाँ तक हो सके, दूसरे देशों के साथ कोई नया झगड़ा भी न खड़ा होने पावे।

जिन देशों के सम्बन्ध में रूसी सरकार अच्छी तरह यह जानती है कि ये हमारे विनाश से ही प्रसन्न होंगे, उनके साथ भी वह अपनी ओर से रूसी क्रान्तिकारी कोई वैर नहीं करती। और जिस राष्ट्र-संघ की किसी समय बहुत अधिक निन्दा करते थे, उसके कामों और अधिवेशनों में भी अब वे सहर्ष सम्मिलित होते हैं। जिन देशों के सम्बन्ध में वे यह समझते हैं कि ये हमारा आर्थिक कार्य-क्रम आगे चल कर मान सकते हैं, उनके साथ वे विशेष मित्रता का व्यवहार रखते हैं और उन्हें अनेक प्रकार से साम्यवाद की ओर प्रवृत्त होने के लिए प्रोत्साहित भी करते रहते हैं। वे उन्हें यह बतलाते रहते हैं कि बिना बीचवाली सीढ़ियों पर पैर रखे भी यदि कोई देश चाहे तो वह साम्यवाद के शिखर पर पहुँच सकता है। इसके लिए उन बीचवाली अवस्थाओं को पार करने की आवश्यकता नहीं है जिन अवस्थाओं में अनेक पाश्चात्य देश पड़े हुए हैं।

अब इसका वह दूसरा रुख लीजिए जिसमें सोविएट शासन-काल के वे सब सामाजिक प्रयोग आते हैं जो अबतक हुए हैं। हमारे पास यहाँ इतना स्थान नहीं है कि उन सब का पूरा-पूरा विवेचन किया जाय। हम केवल यही बतलाना चाहते हैं कि इस बात में प्रायः सभी लोग सहमत हैं कि स्त्रियो, बच्चों, शिक्षा, संस्कृति तथा जीवन की इसी प्रकार की और बातों के सम्बन्ध में क्रांति के बाद से जितने क़ानून और संस्थाये बनी हैं, वे सब बहुत ही प्रशंसनीय हैं; या कम-से-कम जिन विचारों से प्रेरित हो कर वे क़ानून और संस्थाये बनाई गई हैं, उनके उत्तम होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता।

एक दूसरी विशेषता यह है कि सारे रूस में शिल्प और उद्योग-धन्धे बढ़ाने का बहुत अधिक प्रयत्न किया गया है, परंतु वे अमानुषिक अत्याचार और विकट यातनाये वहाँ नहीं आने पाई हैं जो यूरोप के सभी शिल्पी देशों में शिल्पी क्रांति के बाद से बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देने लगी हैं। रूस में शिल्प तो बहुत अधिक बढ़ा है, पर उसके कारण कमकरो और मजदूरों पर किसी तरह का अत्याचार नहीं होता, न कहीं उनके साथ निर्दयता का ही कोई व्यवहार होता है और न इन शिल्पों तथा उद्योग-धन्धों से जो लाभ होता है, वह साम्यवादी सिद्धांतों के अनुसार अधिक-से-अधिक लोग को बहुत कुछ समान रूप से पहुँचाने का प्रयत्न किया जाता है। जहाँ तक हो सकता है, सब के दुःख दूर करने का और सब को सुखी करने का समान रूप से प्रयत्न किया जाता है।

ये सब देश के आन्तरिक प्रयोगों से सम्बन्ध रखनेवाली बातें हैं। जो लोग हर तरह के साम्यवाद के घोर विरोधी नहीं हैं, वे लोग भी और बहुत से दूसरे लोग भी, आधुनिक रूस का दमनवाला अंग बहुत ही नापसंद करते हैं। वे यह बात अवश्य ही मानते हैं कि

पाश्चात्य जगत रूस की सब बातों की भले ही नक़ल न करे, लेकिन फिर भी वह बहुत सी अच्छी बातें सीख सकता है। रूस में जो कानूनी और अदालती कार्रवाइयाँ होती हैं, वे हृद से ज्यादा सीधी-सादी होती हैं और उनमें फिजूल की रस्मों और पावनन्दियों का कहीं नाम भी नहीं है। वहाँ न तो अदालती कार्रवाइयाँ पेचीदा होती हैं और न कानूनी दाव-पेच होते हैं। वहाँ कानून-पेशा लोगो का कोई अलग वर्ग भी नहीं होता।

वहाँ जज भी दो तरह के होते हैं—एक तो स्थायी और दूसरे ऐसे लोग जो अदालत के काम के सिवा और तरह के पेशे भी करते हैं। जब उन्हें अदालत में कोई काम नहीं होता, तब वे अपना पेशा या काम करते हैं; और जब जरूरत होती है, तब स्थायी जजो के साथ न्यायालय में बैठकर मुकदमों सुनते हैं। उन्हें न तो कानून का बहुत अधिक ज्ञान ही होता है और न उसकी विशेष आवश्यकता ही होती है। वहाँ बहुत ही सीधे-सादे मुकदमों होते हैं और बहुत ही सीधी तरह से उनका विचार होता है।

वहाँ वकीलो को किसी तरह की फीस नहीं मिलती। सरकार की तरफ से उनका बँधा हुआ वेतन होता है, जिससे वे अपना निर्वाह करते हैं। इसलिए व्यर्थ के मुकदमों लड़ाने में उनका कभी कोई स्वार्थ नहीं होता। किसी अभियुक्त को बचाने के लिये उसके पक्ष में जितनी बातें कही जा सकती हैं, वे सब साफ-साफ कह दी जाती हैं, और उन्हें जबर्दस्ती कानून के चंगुल में फँसाने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। अगर वह दोषी ठहरता है तो उसे वही उचित दण्ड दिया जाता है जो उसके अपराध को देखते हुए उपयुक्त होता है। वहाँ सजाये भी बहुत हलकी दी जाती हैं, और इस बात का भी पूरा-पूरा उद्योग किया जाता है कि जेलखानों में

रह कर आदमी बिल्कुल सुधर जाय और उसके दोष दूर हो जायँ। उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता जो उसे अपराधी का अभ्यस्त बनावे और उसे “जेल की चिड़िया” बना दे।

इस तरह की सभी बातों में रूस में जितने कायदे-कानून हैं, वे केवल आदर्श उपस्थित करने के विचार से बनते हैं, जिनको देखकर पाश्चात्य देशों के निवासी चकित होते हैं। पाश्चात्य देशों में यही समझा जाता है कि कायदे-कानून में कहीं कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। वे यह भी समझते हैं कि जो कानून काम में नहीं लाया जाता, वह या तो खराब कानून है या उससे कानून का दुरुपयोग होता है।

लेकिन आधुनिक रूस की कानून के सम्बन्ध में कुछ और ही धारणा है। वहाँ कानूनों के द्वारा सिर्फ लोगों को यह बतलाया जाता है कि साधारणतः कोई काम किस प्रकार होना चाहिए। और जिस कानून का जितना महत्त्व होता है, प्रायः उसका उतना ही प्रयोग किया जाता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रक्खा जाता है कि कोई कानून कहाँ तक काम में आ सकता है, और उसकी कहाँ तक पाबन्दी हो सकती है? जब कहीं किसी कानून की पाबन्दी कराने की जरूरत होती है, तब इस बात का भी खयाल रक्खा जाता है कि इसकी पाबन्दी करने में लोगो को कहाँ तक दिक्कत होती है। वहाँ कानून बना कर रख दिये जाते हैं और इस बात का विचार कलेक्टिव पर छोड़ दिया जाता है कि किसी कानून की कहाँ तक पाबन्दी होनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रक्खा जाता है कि व्यर्थ और कष्टदायक रूप में किसी कानून की पाबन्दी न कराई जाय। इस बात की भी देख-रेख रक्खी जाती है कि कानून ने लोगो को जो सुभीते दे रक्खे हैं, उनका कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है।

इसीलिए रूस में कानून बनाये तो बहुत बड़े-बड़े इरादों से

जाते हैं, लेकिन उनकी पाबन्दी बहुत ही समझ-बूझ कर कराई जाती है। और कानून तथा उसकी पाबन्दी से यही बहुत बड़ा अन्तर देख कर पाश्चात्य देशों के निवासी बहुत घबराते हैं। वहाँ हर एक कानून सिर्फ इसी इरादे से बनाया जाता है कि वह साधारण अवस्थाओं में लोगों के लिए आदर्श का काम दे और जब आवश्यकता हो, तब ठीक तरह से काम में भी लाया जा सके। यही कारण है कि साधारण अपराधियों के साथ तो वहाँ बहुत अच्छा और ऐसा व्यवहार होता है जिससे उनका सुधार हो सके और राजनीतिक अपराधियों के साथ बहुत ही कठोर व्यवहार होता है।

दूसरी ओर एक राजकीय राजनीतिक विभाग है जिस पर संघटन-विधान के अनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी कमेटी का नाममात्र का नियन्त्रण है। सारे प्रजातन्त्री संघ में जिन लोगों पर इस क्रान्ति के विरुद्ध प्रयत्न करने का सन्देह होता है, उन सब लोगों पर और समस्त पुलिस-विभाग पर इसी विभाग का पूरा नियन्त्रण होता है। राजद्रोह के अपराधियों को यही विभाग दण्ड देता है। इसे सर्व-साधारण के सामने कभी अपनी कोई कैफियत देने की आवश्यकता नहीं होती।

सारे देश में इसके वर्दीवाले कर्मचारी तो रहते ही हैं, पर साथ-ही-साथ बिना वर्दी के भी इतने गुप्तचर रहते हैं, जिनकी संख्या किसी को मालूम नहीं हो सकती।

एलन मान्कहाउस नामक एक सज्जन हैं जो साम्यवादी तो नहीं हैं, पर फिर भी साम्यवादी रूस के साथ कुछ सहानुभूति अवश्य रखते हैं। उनका कहना है कि यह विभाग वास्तव में उतना अधिक भीषण तो नहीं है, लेकिन यह ऐसे ढंग से काम करता है कि लोग इसे बहुत अधिक भीषण समझते हैं। यह बात अवश्य ही बिल्कुल ठीक है कि लाल सेना के सदस्यों की तरह इस विभाग के

सदस्य भी साधारण पुलिस कर्मचारियों की अपेक्षा जनता के हित के बहुत बड़े-बड़े सामाजिक काम करते हैं। लेकिन फिर भी जो संस्था गुप्तचरो से काम लेती हो और देश में आतंक फैलाती हो, उसे स्वतन्त्रता-प्रेमी कभी अच्छी दृष्टि से नहीं देख सकते।

अभी कुछ दिन पहले यह कहा गया था कि यह विभाग तोड़ दिया जायगा। मालूम नहीं कि अभी तोड़ा गया था नहीं। यदि इस समय यह तोड़ भी दिया जाय तो भी सहज में यह विश्वास नहीं होता कि आजकल के ज़माने में इसके स्थान पर इसी तरह का कोई और विभाग न बनेगा।

कोई यह नहीं कह सकता कि रूस के राजनीतिक जीवन में इन दोनों तत्त्वों का क्या भविष्य होगा। इसका उत्तर मुख्यतः दो बातों पर निर्भर होता है। उनमें से एक बात तो यह है कि रूस को साम्यवादी उपायों से अपनी आर्थिक अवस्था सुधारने में कहाँ तक सफलता होती है। दूसरी बात यह है कि बाहरी जगत् का रूस के साथ कैसा व्यवहार होता है। इस प्रश्न का मार्क्स का सनातनी उत्तर तो यही है कि जिस देश में साम्यवाद के सिद्धान्तों के अनुसार पूरी तरह से काम होने लगता है, उस देश में "राज्य" अर्थात् दमन करनेवाले यन्त्र की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती, और वह आप-से-आप नष्ट हो जाता है। लेकिन साम्यवाद के पूरी तरह से स्थापित हो जाने का यह मतलब ज़रूर है कि यदि सारे संसार में साम्यवाद पूरी तरह से स्थापित न भी हो, तो भी कम-से-कम ऐसी अवस्था तो अवश्य ही उत्पन्न हो जाय जिसमें साम्यवादी देशों या राज्यों को यह खटकना न रह जाय कि हमारे पड़ोसी हम पर आक्रमण करेंगे।

रूस की संस्थाओं ने अबतक कम-से-कम इतनी उन्नति तो अवश्य कर ली है कि सब लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं

कि वर्तमान परिस्थितियों में भी साम्यवाद क्या-क्या कर सकता है। लेकिन अभी तक विदेशी राष्ट्र जिस दृष्टि से रूसी प्रणाली को देखते हैं, उससे कभी यह आशा नहीं की जा सकती कि रूस में दमन करनेवाले उस यन्त्र का, जो “राज्य” कहलाता है, जल्दी अन्त होगा। जो राज्य रूस पर किसी प्रकार का आक्रमण नहीं करना चाहते, उनका रुख भी कुछ ऐसा ही है कि उसे देखते हुए अभी रूस को अपने यहाँ यह यंत्र प्रचलित रखना पड़ेगा। आज अगर कोई रूसी साम्यवादी यह कहे कि हमें अपने शत्रुओं की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए और सारे अस्त्र-शस्त्रों तथा सेनाओं का अन्त कर देना चाहिए तो वह राजनीतिक दृष्टि से बहुत बड़ा बेवकूफ माना जायगा।

दमनकारी संस्थाओं का जीवन दो प्रकार का हुआ करता है—एक मुख्य और दूसरा गौण। अपने मुख्य जीवन में तो वे दमन का पूरा-पूरा काम करती ही हैं। परन्तु इतिहास हमें बतलाता है कि उनके गौण जीवन का वह समय भी आ जाता है जबकि उन्हें दमन करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती और वे एक कोने में निकम्मी होकर पड़ी रहती हैं; और यहाँ तक कि लोगों की निगाहों में खटकने भी लगती हैं। लेकिन यह अवस्था तभी आती है जबकि उन्हें अपने पड़ोसियों से किसी तरह का भय नहीं रह जाता। जब कोई राज्य चारों ओर से निश्चिन्त रहता है, तभी वह अपना शासन-यन्त्र ढीला कर सकता है। अभी वर्तमान संसार में किसी राष्ट्र को इस अवस्था तक पहुँचने में बहुत देर लगेगी।

अभी तो सारे संसार पर अस्त्रीकरण का भूत सवार है, और इधर साल भर से तो राष्ट्रों के भय और आतंक की मात्रा इतनी बढ़ गई है, जितनी शायद आज तक कभी नहीं बढ़ी थी। रूस के बाहर अन्यान्य देशों में भी बहुत से ऐसे आदमी हैं जो

यह चाहते हैं कि दमन और शामन करनेवाली संस्थाओं का अन्त हो जाय और साम्यवादी संस्थाओं को अपना प्रयोग और विकास करने का अवसर दिया जाय। परन्तु इस प्रकार का अवसर प्राप्त करना स्वयं रूस के हाथ में नहीं है; उसे इस तरह का अवसर देना केवल दूसरे राज्यों के हाथ में है।'

साम्यवादी रूस की सफलता—यह प्रकरण सम्भवतः बहुत कुछ अधूरा रह जायगा, यदि यहाँ संक्षेप में यह भी न बतला दिया जाय कि रूस में इधर थोड़े दिनों से जो साम्यवादी प्रयोग हो रहा है, उसमें रूस को कहाँ तक सफलता हुई है, और उससे वह कहाँ तक उन्नत तथा अप्रसर हुआ है। यहाँ सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कम-से-कम इस समय रूस ने अपनी उस पुरानी नीति का परित्याग कर दिया है, जिसके अनुसार वह सारे संसार में साम्यवादी क्रान्ति करना चाहता था। अब तो उसका उद्देश्य केवल यही है कि सारे संसार के सामने साम्यवादी तन्त्र का एक ऐसा अच्छा आदर्श उपस्थित किया जाय कि लोग यदि सचमुच उसे अच्छा समझे तो आप-से-आप उसे ग्रहण करें। वह फैसिस्टों और नाज़ियों की तरह बलपूर्वक सारे संसार में अपने सिद्धान्तों का प्रचार और प्रस्थापन नहीं करना चाहता। किसी देश पर अकारण आक्रमण करना भी उसके सिद्धान्त के विरुद्ध है।

परन्तु कठिनता यह है कि संसार की वर्तमान परिस्थिति उसे तरह-तरह के सैनिक आयोजन करने के लिये विवश करती है। फैसिस्ट और नाज़ी सिद्धान्ततः उसके कट्टर शत्रु हैं। उन का कहना है कि यह साम्यवादी नीति वर्चस्वपूर्ण है और यदि

१. कोल की मूल पुस्तक में यह प्रकरण यही समाप्त होता है। इस प्रकरण की इससे आगे की पंक्तियाँ स्वयं मेरी लिखी हुई हैं। इन के लिए मूल लेखक उत्तरदायी नहीं समझे जाने चाहिए। १०० चं० वर्मा।

इसका नाश न किया जायगा तो यह यूरोप की सभ्यता और संस्कृति का नाश कर डालेगी; मानो वे लोग यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति के ठेकेदार हैं और किसी दूसरे को कोई नई सभ्यता या संस्कृति स्थापित नहीं करने देंगे। इन्हीं की देखा-देखी जापान भी केवल स्वार्थवश उनके साथ मिल गया है। स्वार्थवश इसलिए कि वह कभी यूरोप की सभ्यता और संस्कृति का ठेकेदार होने का दम नहीं भर सकता। अभी हाल में वह स्पेन भी इन्हीं लोगों के दल में मिल गया था जिसमें इटली और जर्मनी की सहायता से जनरल फ्रैंको ने सारा अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। कुछ दिन पहले इटली और जर्मनी की ओर से इस बात का भी प्रयत्न हो रहा था कि हंगरी भी खुल कर इस बात की घोषणा कर दे कि हम रूस की साम्यवादी प्रणाली के केवल विरोधी ही नहीं हैं, बल्कि शत्रु भी हैं।

यह तो हुई उन लोगों की बात जिन्होंने हर तरह से साम्यवादी रूस का नाश करने का बीड़ा-सा उठा रक्खा था। उधर इंग्लैंड और फ्रांस भी रूस को कभी अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। वे जर्मनी और इटली का अत्याचार चुपचाप देखने के लिए तैयार थे, लेकिन उनका विरोध करने के लिए रूस से मिलना नहीं चाहते थे।

सन् १९३६ के आरम्भ में जब जर्मनी आसपास के छोटे-छोटे राष्ट्रों पर बलपूर्वक अधिकार करने लगा, तब बिल्कुल लाचारी की हालत में इंग्लैंड और फ्रान्स ने रूस के साथ मिलने का विचार किया।

दोनों महीनों तक रूस को अपनी तरफ मिलाने का प्रयत्न करते रहे। पर रूस की जो शर्तें थीं, वे उन्हें मंजूर नहीं थीं। इसलिए कुछ भी फल न हुआ। उधर जर्मनी भी गुप्त रूप से रूस को अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न कर रहा था। जर्मनी की

बहुत बड़ी राजनीतिक जीत यह हुई कि उसने रूस की सभी शर्तें मानकर उसके साथ समझौता कर लिया। इस समझौते के अनुसार यह निश्चय हुआ था कि जर्मनी और रूस आपस में एक-दूसरे पर आक्रमण न करेंगे। इस प्रकार अपने पूर्वी शत्रु की ओर से बिल्कुल निश्चिन्त होकर जर्मनी ने पोलैण्ड पर चढ़ाई कर दी। लेकिन जब दो-ढाई सप्ताह के अन्दर ही 'प्रायः आधा पोलैण्ड तहस-नहस करके जर्मन सेनायें वहाँ की राजधानी वारसा में जा पहुँचीं, तब रूसी सेनाओं ने तुरन्त आगे बढ़कर पोलैण्ड के बाकी सभी हिस्सों पर बिना किसी प्रकार के रक्तपात के अधिकार कर लिया। इसके बाद जब रूस ने देखा कि अब जर्मनी पश्चिम की रियासतों की तरफ बढ़ना चाहता है, तब उसने बाल्टिक सागर के तट के लैट्विया, एस्टोनिया और लिथुआनिया आदि छोटे-छोटे देशों पर अपना प्रभाव बढ़ाना आरम्भ किया। इसी प्रयत्न में उसे फिनलैण्ड के साथ कुछ लड़ाई भी करनी पड़ी जो ग्रीच में जाड़ा आ जाने के कारण कोई तीन-चार महीने चलती रही। इस लड़ाई के अन्त में फिनलैण्ड को लाचार होकर रूस की सभी शर्तें माननी पड़ीं और अपने देश का कुछ अंश उसे देकर राजी करना पड़ा।

फिनलैण्ड सरीखे छोटे से देश के साथ रूस को जो कई महीनों तक लड़ना पड़ा, इससे कुछ लोग यह समझने लगे हैं कि रूस की युद्ध-शक्ति वास्तव में नगण्य है। परन्तु यह उनका भ्रम है। वास्तव में रूस कभी किसी देश पर जल्दी इतनी बुरी तरह से और उस भीषण रूप से आक्रमण नहीं कर सकता, जिस तरह से इस युद्ध में जर्मनी ने बेलजियम और फ्रान्स आदि पर किया था। इस प्रकार के आक्रमणों का प्रजा पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। रूस कभी किसी प्रजा पर इस प्रकार का बुरा प्रभाव डालकर उसे अपना शत्रु नहीं बना सकता। उसे तो

वास्तव में प्रजा को सन्तुष्ट रखना और अपनी तरफ मिलाना पड़ता है। इसीलिए वह ऐसे अवसरों पर उग्र उपायों से काम नहीं ले सकता।

इस सम्बन्ध में ध्यान रखने की दूसरी बात यह है कि रूस जिन देशों पर विजय प्राप्त करता है, उनमें वह जर्मनी की तरह लूटमार नहीं मचाता। वह वहाँ केवल अपनी शासन-प्रणाली और अपनी राजनीतिक संस्थाओं का ही प्रचार करता है और उन्हें सोविएट संघ का सदस्य बनाकर अपने संरक्षण में ले लेता है। यह संरक्षण उस प्रकार के संरक्षण से बिल्कुल अलग है, जिस प्रकार के संरक्षण का ढोल पीटकर जर्मनी ने हालैंड और बेल्जियम आदि पर अधिकार किया है।

इधर हाल में जब जर्मनी को फ्रांस पर पूरी विजय प्राप्त हो गई, तब रूस ने समझ लिया कि शक्तिशाली जर्मनी अब शायद बालकन की तरफ निगाह फेरेगा। इसलिए उसने रूमानिया से उसके बेसरेबिया और बोकोविना नाम के दो प्रदेश ले लिये। जर्मनी ने भी अवसर देखकर रूस के इस काम में कोई बाधा नहीं दी। उल्टे रूमानिया से कह दिया कि तुम रूस की माँग पूरी करके उसे सन्तुष्ट करो। लेकिन इन सब बातों का यह मतलब नहीं समझना चाहिए कि रूस और जर्मनी में गहरी मित्रता हो गई है। जान पड़ता है कि वास्तव में दोनों अभी तक उसी तरह एक-दूसरे के जानी दुश्मन हैं, जिस तरह पहले थे। और सम्भव है कि बालकन के प्रश्न पर ही आगे चलकर रूस और जर्मनी में युद्ध हो; क्योंकि उस पर दोनों की निगाहे—तेज निगाहे—हैं। उस समय ससार को पता चलेगा कि वास्तव में जर्मनी की युद्ध-शक्ति प्रबल है या रूस की। इस समय एक ही बात स्पष्ट है। वह यह कि वर्तमान युद्ध से लाभ उठाकर रूस भी आस-पास के छोटे-छोटे देशों में सोविएट शासन-प्रणाली

का प्रचार कर रहा है और इसके लिए एक फिनलैंड को छोड़कर बाकी और कहीं उसे कोई रक्तपात नहीं करना पड़ा है।

फ्रांस का तो इस समय एक प्रकार से अस्तित्व ही मिट सा गया है। पर इंग्लैंड अब फिर से रूस का प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहा है। और इसका कारण है केवल जर्मनी का आतंक, नहीं तो वस्तुतः इंग्लैंड भी रूस का वैसा ही शत्रु है, जैसा जर्मनी है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि यूरोप का बहुत बड़ा अंश किसी-न-किसी रूप में साम्यवादी रूस का विरोधी है। ऐसी अवस्था में यह किस प्रकार आशा की जा सकती है कि रूस में शासन और दमन-सम्बन्धी यन्त्रों का जल्दी अन्त होगा? हाँ, यदि यूरोप के वर्तमान युद्ध के परिणाम-स्वरूप वहाँ की सारी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक इमारत ढह जाय और नई सृष्टि का आरम्भ हो, तब शायद लोगो को इतनी समझ आवे कि वे शान्तिपूर्वक स्वयं भी कालयापन करें और दूसरों को भी करने दें। यही कारण था कि रूस को भी अन्यान्य सभी राष्ट्रों की तरह बहुत ज़बर्दस्त फौजी तैयारियाँ करनी पड़ी थी। और-और बातों में रूस ने जो उन्नति की है, उसका वर्णन करने से पहले हमें यह आवश्यक जान पड़ता है कि रूस की सैनिक तैयारियों का यहाँ थोड़ा-सा वर्णन कर दिया जाय।

सन् १९३० से अबतक रूस ने जितनी सैन्य-सामग्री प्रस्तुत की है, उतनी शायद और किसी देश ने नहीं की है। बड़े-बड़े ज्ञानकारों का कहना है कि आजतक किसी राष्ट्र ने अपनी रक्षा के लिए उतनी ज़बर्दस्त तैयारी नहीं की जितनी रूस ने की है। वहाँ २५ लाख आदमियों की तो ऐसी स्थायी सेना है जो हर दम युद्ध-क्षेत्र में जाने के लिए नैयार रहती है। इसके सिवा १८ लाख ऐसे नागरिक सैनिक हैं जो

आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त युद्ध-क्षेत्र में बुलाये जा सकते हैं। इसके सिवा १३ लाख ऐसे आदमी भी हैं, जिन्हें युद्ध की थोड़ी बहुत शिक्षा मिली है और जो थोड़े ही समय में सैनिक रूप में परिवर्तित हो सकते हैं।

कोई दो साल पहले वहाँ सिर्फ २० लाख सैनिक थे। लेकिन जब जर्मनी ने एक ही दिन में सारे आस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया, तब स्टालिन ने अपनी सेना में ५ लाख आदमी और भी बढ़ा लिये थे। उसके लड़नेवाले हवाई जहाजों की संख्या ४० हजार के लगभग है।

स्टालिन कई बार कह चुका है कि इस बात की बहुत बड़ी सम्भावना है कि जर्मनी, इटली और जापान एक साथ मिलकर सोविएट रूस पर चढ़ाई करे। इन तीनों की सम्मिलित शक्तियों का मुकाबिला करने के लिए ही रूस को ये सब तैयारियाँ करनी पड़ी हैं। इधर बीस बरस की सोविएट शिक्षा ने रूस के अधिकांश निवासियों को युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार कर रखा है।

दो साल पहले रूसी सरकार की जितनी आय हुई थी, उसका पाँचवाँ हिस्सा उसे सैनिक तैयारियों में ही खर्च करना पड़ा था। रूस पर उक्रेन, फिनलैण्ड, पोलैण्ड और मंचुको की तरफ से ही चढ़ाइयाँ हो सकती हैं, इसलिए अधिकांश सेनाये भी इन्हीं सीमाओं पर रक्खी गई हैं। रूस के हवाई जहाज भी जर्मनी और इटली के हवाई जहाजों से बहुत तेज उड़ते हैं और बहुत दूर तक जा सकते हैं। आज से चार-पाँच बरस पहले रूस के पास जितने जंगी जहाज और सब-मेरीन आदि थे, उन सबकी संख्या अब चौगुनी हो गई है और अपना समुद्री बेड़ा भी उसने अजेय कर लिया है। रूस के सैनिकों की संख्या इटली के सैनिकों से चौगुनी और जर्मनी के सैनिकों से

तिगुनी है।

समाचार-पत्रों में प्रायः यह प्रकाशित होता रहता है कि आज रूस में इतने गुप्तचर पकड़े गये और आज इतने विद्रोही मारे गये। इस तरह संसार को यह दिखलाने का प्रयत्न किया जाता है कि रूस में शान्ति नहीं है और वहाँ की जनता साम्यवादी सरकार की विरोधी है। पर असल में दूसरे देश ही धन देकर वहाँ लोगो को इस प्रकार के उपद्रव करने के लिये भेजा करते हैं और रूसी सरकार के लिए उनसे अपनी रक्षा करना आवश्यक हो जाता है।

अभी थोड़े ही दिन पहले साम्यवादी दल की जो कांग्रेस क्रैमलिन में हुई थी, उसमें स्टालिन ने यह बतलाया था कि इस तरह की कार्रवाइयों से रूस दिन-पर-दिन और भी मजबूत होता जाता है। उसने यह भी बतलाया था कि अगस्त १९३८ में जब जापानियों ने हमारी मंचुकोवाली सीमा की एक पहाड़ी पर बलपूर्वक अधिकार करना चाहा था, तब हमारे सैनिकों ने कितने सहज में आक्रमणकारियों को परास्त करके पीछे हटा दिया था। उसने यह भी कहा था कि सन् १९३७ वाले निर्वाचन में, जो कई सेनापतियों को प्राण-दण्ड देने के बाद हुआ था, देश के साढ़े अठानवे (६८%) प्रतिशत से भी अधिक जनता ने हमारे दल के पक्ष में वोट दिया था। इसी से मालूम हो सकता है कि रूस में सोविएट शासन लोगो को कितना पसन्द है ?

कहा जा सकता है कि जर्मनी और इटली में भी हिटलर और मुसोलिनी को प्रायः इतने ही वोट मिलते हैं। पर जब हम देखते हैं कि जर्मनी और इटली में लोक-मत कितनी जबरदस्ती से दबाया जाता है और रूस में लोक-मत को कहाँ तक उदारतापूर्वक स्वतन्त्र रहने दिया जाता है, और जब हम इस बात का ध्यान करते हैं कि हिटलर और मुसोलिनी को तो सिर्फ

जर्मनों और इटालियनों के ही वोट मिलते हैं, लेकिन रूस में सोविएट दल को बहुत सी भिन्न-भिन्न जातियों के वोट मिलते हैं, तब हमें दोनों के अन्तर स्पष्ट रूप से विदित हो जाते हैं। स्टालिन ने अपने क्रैमलिनवाले व्याख्यान में यह भी कहा था कि दूसरे देशों के गुप्तचर-विभाग इसी तरह हमारे यहाँ अपने गुप्तचर और हथियारों तथा हमारी प्रणाली का विनाश करनेवाले आदमी भेजते रहेगें; और इसीलिए हमें अपने यहाँ का गुप्तचर-विभाग भी इतना मजबूत रखना चाहिए कि जिसमें हम अपनी जनता के समस्त शत्रुओं का समूल नाश कर सकें।

इस व्याख्यान के अन्त में स्टालिन ने यह भी कहा था कि हमारे देश में जो लोग पूँजी की सहायता से अनुचित लाभ उठाते थे, उनमें से अधिकांश का अन्त हो चुका है और अब सारी सोविएट जनता में पूरी-पूरी एकता स्थापित हो चुकी है। फिर भी कई शिल्पों और उद्योग-धन्धों में हमारा देश अभी ब्रिटेन और अमेरिका के संयुक्त राज्यों से बहुत पिछड़ा हुआ है, और अभी हमें निरन्तर सुधार और उन्नति करने की आवश्यकता है।

यह ठीक है कि अभी औद्योगिक दृष्टि से कई बातों में रूस अन्य कई देशों से बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी यह ध्यान रखना चाहिए कि इधर बीस-बरसों में उसने अपने यहाँ के उद्योग और शिल्प की जो उन्नति की है, वह आश्चर्यजनक है। बल्कि हम कह सकते हैं कि संसार के इतिहास में उसकी वह उन्नति अनुपम और अभूतपूर्व है। असल में उसकी औद्योगिक उन्नति का आरम्भ सन् १९२० से हुआ था। तीन बरस तक तो लेनिन ने देश की बागडोर अपने हाथ में रक्खी थी; और जब जनवरी सन् १९२४ में उसका देहान्त हो गया, तब प्रायः सारा भार स्टालिन पर आ पड़ा। तब से आज तक रूस ने जो उन्नति की है, उसका सारा श्रेय प्रायः स्टालिन को ही है।

रूस में प्राकृतिक सम्पत्ति तो अनन्त थी, पर उसका उपयोग बहुत कम होता था। जो कुछ होता भी था, उसका लाभ विदेशियों को पहुँचता था। साम्यवादियों ने सारा काम बहुत ही बे-सरो-सामानी की हालत में शुरू किया था।

इस बीच में वहाँ दो बार पंच-वार्षिक योजनाये हुई हैं और दोनों ही बहुत अधिक सफल हुई हैं। हर योजना में खास-खास शिल्प और उद्योग बहुत अधिक बढ़ाये गये हैं। अब तीसरी पंच-वार्षिक योजना सन् १९३८ से आरम्भ हुई है। जहाँ पहले कुछ भी नहीं था, वहाँ अब जगह-जगह काराज, सेल्यूलायड, कपड़े, रबर, लोहे, दियासलाई, चाय, सिनेमा और मशीनों आदि के बहुत बड़े-बड़े सैकड़ों-हजारों कारखाने खुल गये हैं। जिन उजाड़ देहातों में जहाँ कभी तेल का दीया भी नहीं जलता था, वहाँ सैकड़ों कारखाने चल रहे हैं और बिजली की लाखों बत्तियाँ जगमगा रही हैं। खासकर बिजली, मिट्टी का तेल, लोहा और कोयला तो वहाँ इतना ज्यादा बनने और निकलने लगा है कि देश की सारी आवश्यकताये पूरी करने के बाद और देशों में भी बहुत अधिक मात्रा में भेजा जाने लगा है।

बिजली तैयार करने के देश में सैकड़ों बहुत बड़े-बड़े कारखाने बन गये हैं जो सैकड़ों-हजारों मील दूर तक बहुत ही सस्ती बिजली पहुँचाते हैं और जिनसे नये-नये कारखाने खोलने और चलाने में बहुत बड़ी सहायता मिलती है। यदि उन सबका वर्णन किया जाय तो एक बड़ी पुस्तक तैयार हो सकती है। इसलिए हम सिर्फ एक बहुत ही छोटी चीज—दियासलाई—के सम्बन्ध की कुछ बातें बतलाते हैं। सन् १९१४ में वहाँ ४॥ अरब दियासलाई की डिवियाँ तैयार होती थीं। पर सन् १९३५ में ११ अरब तैयार हुई थीं और इस प्रकार दियासलाई तैयार करने में वह सारी दुनिया में अग्रवर्ती हो गया था। वस यही, बल्कि

इससे भी कुछ बढ़कर और सैकड़ों शिल्पो तथा उद्योगों का हाल समझ लेना चाहिए। और फिर इन सब कारखानों में वही कलेक्टिववाली व्यवस्था है। हर जगह के मजदूर और सब कर्मचारी मिलकर अपने कारखाने और अपने रहने आदि की जगहों और खाने-पीने, पहनने और मनोविनोद आदि की अच्छी-से-अच्छी सारी व्यवस्था आप ही कर लेते हैं।

इन सब बातों का परिणाम यह हुआ है कि रूस की प्रायः सारी प्रजा परम सुखी और सन्तुष्ट है और आशा नहीं है कि किसी और प्रकार की शासन-प्रणाली और व्यवस्था कभी उन्हे अच्छी लग सकेगी।

जब से रूस में सोविएट शासन प्रचलित हुआ है, तब से वहाँ के प्रत्येक प्रान्त, प्रत्येक नगर और प्रत्येक गाँव की इतनी अधिक उन्नति हुई है कि मानो एकदम से उनकी काया-पलट ही हो गई है। अब हर जगह पुरानी दरिद्रता की जगह सम्पन्नता और वैभव, कष्ट और दासता की जगह सुख और स्वतन्त्रता और वीरानी की जगह रौनक दिखाई देती है।

वहाँ का साइबेरिया प्रदेश प्राकृतिक सम्पत्ति के विचार से था तो बहुत अधिक सम्पन्न, लेकिन वह सारी सम्पत्ति अछूती पड़ी थी और उसका कुछ भी उपयोग नहीं होता था। उपयोग यही होता था कि जिन लोगों को लम्बी-लम्बी सजायें दी जाती थी, या जिन्हे देश-निकाला मिलता था, वे वहाँ कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए भेज दिये जाते थे। परन्तु सोविएट शासन ने उसे शिल्प और उद्योग का एक बहुत बड़ा केन्द्र बना दिया है। वहाँ बहुत से लोहे के कारखाने बन गये हैं जिनमें से एक-एक कारखाने में हर साल दस-दस लाख टन लोहा तैयार होता है। उस प्रदेश में कोयला भी बहुत था, लेकिन बहुत ही कम खाने थीं। सोविएट शासन के आरम्भ में वहाँ मुश्किल से छः-सान

लाख टन कोयला निकलता था। लेकिन अब वहाँ डेढ़ करोड़ टन से भी अधिक कोयला हर साल निकलने लगा है। इस प्रकार वहाँ की यह उपज चौबीस गुनी हो गई है। आशा की जाती है कि अभी इसकी मात्रा और भी बढ़ेगी। इसके सिवा वहाँ अनाज भी खूब पैदा होने लगा है और वहाँ के जंगलों की लकड़ियाँ भी बहुत अधिक माँग में बाहर जाने लगी हैं। इसके सिवा वहाँ के निवासी माँस और मक्खन आदि तैयार करके जो बाहर भेजने लगे हैं, वह अलग।

यही हाल सोविएट-संघ के बाकी सभी प्रान्तों का है। सब जगह बिजली की रोशनी है, मोटरे हैं, रेडियो हैं, सिनेमा और नाटकशालायें हैं, बड़ी-बड़ी मशीनें और कल-कारखाने हैं, मजदूरों के रहने के लिए आलीशान मकान हैं, आमोद-प्रमोद की अच्छी-से-अच्छी व्यवस्था है, लड़कों और लड़कियों के लिए ही नहीं, बल्कि वयस्क स्त्री-पुरुषों के लिए भी पाठशालाएँ और पुस्तकालय तथा अजायबघर हैं, जच्चेखाने हैं, अपाहिजों के रहने के स्थान हैं और आजकल की सभ्यता और संस्कृति की उन्नति के लिए जितने प्रकार की प्रयोगशालाएँ और दूसरी संस्थाएँ हो सकती हैं, वे सभी हैं। यह सारी उन्नति इधर पन्द्रह-बीस बरसों के अन्दर ही हुई है। रूस सरीखे पिछड़े हुए देश ने इतने थोड़े समय में जितनी अधिक उन्नति की है, उतनी अधिक उन्नति आज तक इतने थोड़े समय में शायद और किसी ने नहीं की है। सबसे बढ़कर बात यह है कि रूस की सारी प्रजा में एक नवीन जीवन, एक नवीन उत्साह, एक नवीन स्वतंत्रता और एक नवीन देश प्रेम का संचार हो गया है।

रूस की इस सारी उन्नति का एकमात्र रहस्य वहाँ का 'स्तखानोवी आन्दोलन' है। साम्यवाद का यह एक सिद्धान्त है कि श्रम जितना ही अधिक उपजाऊ होगा, समाज भी साम्यवाद के

उतना ही समीप पहुँचेगा। आलस्य और वैयक्तिक स्वार्थ ही साम्यवाद के लिए सबसे अधिक घातक है। इसलिए सोविएट नेताओं ने लोगों के सामने श्रम का महत्त्व रक्खा और उन्हें बतलाया कि जो जितना ही अधिक श्रम करता है, उसका सम्मान और सम्पत्ति भी उतनी ही बढ़ती है। इसके फल-स्वरूप जो लोग खूब जो लगाकर बहुत अधिक काम करते थे, वे उदारिक या तूफानी कमकर कहलाते थे।

इसके बाद वहाँ स्तखानोफ नामक एक व्यक्ति ने शारीरिक श्रम के साथ अपना बुद्धि-बल भी लगाया और अपनी उपज को कई गुना बढ़ाया। तभी से श्रम की उपज बढ़ानेवाले प्रयत्न को 'स्तखानोवी आन्दोलन' कहते हैं। इस आन्दोलन के कारण ही रूस की दोनों पंचवार्षिक योजनाये इतनी अधिक सफल हुई हैं, जिसका कभी किसी को स्वप्न में भी अनुमान नहीं था।

पहली और दूसरी दोनों ही योजनाओं के समय सारे कारखाने, सारे नगर और प्रान्त, और सारे कमकर खूब होड़ लगाकर काम करते थे और हरएक यह चाहता था कि हम अपने काम में अपने दूसरे सहयोगियों से आगे बढ़ जायें। योजना के अनुसार जिस कारखाने को जितना काम करना चाहिए था, उससे हरएक ने सचाया और झुँड़का काम कर दिखलाया।

१२ दिसम्बर १९३७ को नये विधान के अनुसार सोविएट पार्लमैण्ट के निर्वाचन के उपलक्ष्य में सारे प्रजातन्त्र में १० दिन के लिए स्तखानोवी होड़ हुई थी। इसका फल यह हुआ कि जिस कारखाने को रोज ५०० मोटरे तैयार करनी थी, वह छः सौ के लगभग मोटरे तैयार करने लगा और जिस कारखाने को १०० टन लोहा तैयार करना होता था, वह १३० और १४० टन

लोहा तैयार करता था। मास्को के मशीन बनाने के एक कारखाने में एक दिन एक कारीगर ने ७ घण्टे में ११५२ पुरजे तैयार किये थे और कोई ११०० रूबल कमाये थे। एक और कमकर ने २६ घण्टों में ३३८ घण्टों का काम किया और ८०० रूबल कमाये। एक मिस्त्री ने ५॥ घण्टे में १६८ गुना काम किया और प्रायः १२०० रूबल कमाये। हर आदमी यही चाहता था कि जल्दी-से-जल्दी, ज्यादा-से-ज्यादा और अच्छे-से-अच्छा काम करके दूसरों के सामने एक आदर्श उपस्थित करे। जहाँ इस तरह होड़ लगाकर सारा देश अधिक-से-अधिक काम करने में लग जाय, उस देश की सम्पत्ति और उन्नति का क्या पूछना है !

अब हम सोविएट-संघ की खेती-बारी के सम्बन्ध में कुछ बातें बतलाकर यह प्रकरण समाप्त करेंगे। वहाँ खेती तीन प्रकार की होती है। पहले प्रकार में तो वही पुराने ढंग की खेती है, जो संसार में सब जगह होती है और जिसमें अलग-अलग किसान अपनी-अपनी व्यक्तिगत जमीन मनमाने ढंग से जोतते और बोते हैं। लेकिन दिन-पर-दिन इस तरह के किसानों की संख्या बराबर घटती जाती है; और अब बहुत थोड़े से ऐसे स्थान रह गये हैं जहाँ के लोग व्यक्तिगत रूप से खेती-बारी करते हो। अधिकतर किसानों को कोलखोजी प्रणाली अपनाने के लिए विवश किया जाता है। यह प्रणाली है भी इतनी अच्छी कि बहुत से गाँव स्वयं ही अपने यहाँ यह प्रणाली प्रचलित कर लेते हैं। खेती का दूसरा प्रकार सोवखोज कहलाता है और इसमें स्वयं सरकार की ओर से खेती होती है।

ज़ारशाही के पहले यूरोपीय रूस में २८ हजार जमींदारों के पास इतनी अधिक भूमि थी कि उसे एक करोड़ किसान जोतते-बोते थे। परन्तु क्रान्ति के बाद जमींदारों की सारी

जर्मादारी जव्त कर ली गई और उसमे से कुछ तो किसानो को दे दी गई और कुछ मे सरकार स्वयं खेती-बारी करने लगी। अब वहाँ जितने सोवखोज हैं, वे सब मानो अनाज पैदा करने के सरकारी कारखाने ही हैं। इनमें लोगो को वतन देकर उनसे काम कराया जाता है।

सन् १९३६ मे सोवखोजो ने जितना अनाज पैदा किया था, उससे सन् १९३७ में डेढ़ गुना अधिक अनाज पैदा किया था। वहाँ हर साल सोवखोजो के लिए योजना बनती है और हरएक सोवखोज अपनी योजना से कहीं अधिक अनाज पैदा करने का प्रयत्न करता है। अब वहाँ सोवखोजो और कोलखोजों मे भी बहुत अधिक काम मशीनो से ही होने लगे हैं। मशीनों से काम लेने में वहाँ के कमकर बहुत दक्ष भी हो गये हैं; और स्तखानोवी कमकरो ने मशीनो के काम की मात्रा भी बहुत बढ़ा दी है।

जहाँ-जहाँ सरकार ने सोवखोज स्थापित किये हैं, वहाँ-वहाँ अच्छे खासे शहर बस गये हैं। उनमे बड़ी-बड़ी सड़के, बगीचे और बीसियों प्रकार की सांस्कृतिक संस्थाये हैं। वहाँ खेती-बारी के सिवा पशु-पालन का काम भी खूब जोरों से होता है और चौपायों की नसल मे खूब तरक्की की जाती है। गौओं, बकरियों, भेड़ों और सूअरो की संख्या भी खूब बढ़ाई जा रही है और उनकी नसल भी सुधारी जा रही है। कई तरह के नये सॉड़ और भेड़े आदि भी पैदा की गई हैं।

खेती का तीसरा प्रकार वह है जो कोलखोजी कहलाता है। इसका आरम्भ सन् १९२८ मे स्टालिन ने किया था। इसमें पहले गाँवों को समझा-बुझाकर नये और वैज्ञानिक ढंग से पंचायती खेती करने के लाभ बतलाये जाते थे और उन्हें इसकी ओर आकृष्ट किया जाता था। जो लोग कोलखोजी या पंचायती

खेती करने के लिए तैयार होते थे, उन्हें सरकार से खाद, हल, बीज और मशीनों आदि की अच्छी सहायता दी जाती थी। इसका परिणाम यह हुआ है कि अब रूस की अधिकांश खेती इसी कोलखोजी सिद्धान्त के अनुसार होने लगी है।

कोलखोज में गाँव भर के सब लोग मिलकर सहयोग समितिवाले सिद्धान्त के अनुसार पंचायती खेती करते हैं। समिति जिस प्रकार सारे गाँव की और सब बातों की व्यवस्था करती है, उसी प्रकार सारी खेती-बारी की भी व्यवस्था करती है। सौ-डेढ़सौ आदमियों की अलग-अलग टोलियाँ बना दी जाती हैं और उन सबको अलग-अलग काम सौंप दिये जाते हैं। उन्हीं में से कुछ लोग रसोइये, लुहार, बढ़ई, धोबी और ग्वाले आदि बना दिये जाते हैं। गाँव भर की खेती-बारी की सारी उपज और दूसरी समस्त सम्पत्ति पर सारे गाँव के लोगों का समान अधिकार होता है और सबको उनकी योग्यता और आवश्यकता के अनुसार घर बैठे सब चीजें मिलती रहती हैं। हर कोलखोज के साथ एक प्रयोगशाला भी होती है जिसमें धीज, मिट्टी, खाद और उपज आदि की परीक्षा की जाती है और उनमें सुधार तथा उन्नति का प्रयत्न किया जाता है।

जब मौसम खराब होने को होता है या टिड्डियो अथवा दूसरे कीड़े-मकोड़ों का उत्पात होने को होता है, तब लोग पहले से सचेत कर दिये जाते हैं। समय समय पर इस बात की भी व्यवस्था की जाती है कि एक कोलखोज के किसान दूसरे उन्नत तथा श्रेष्ठ कोलखोजों में जाकर देखें कि वहाँ किस प्रकार उन्नति हुई है और तब वे अपने यहाँ आकर उसी प्रकार की उन्नति करने का प्रयत्न करें। सोवखोजों की तरह कोलखोजों में भी पशु-पालन आदि होता है। इन सब बातों की पूरी-पूरी व्यवस्था गाँव की सोविएट या पंचायत करती है। जिसे यह

देखना हो कि साम्यवादी गाँव कैसा होता है और उसके काम किस तरह चलाये जाते हैं, उसे रूस का कोई कोलखोज गाँव देखना चाहिए।

कोलखोज प्रथा ने रूस के गाँवों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया है। हर कोलखोज में स्कूल, अस्पताल, सांस्कृतिक भवन, वाचनालय, क्रीड़ा-क्षेत्र, प्रसूतिगृह और स्नानागार होते हैं। अक्सर स्थानों में नाट्यशालायें, सरकस और सिनेमा भी होते हैं। टेलीफोन और डाकखाने भी हैं। रेडियो से खाली तो वहाँ शायद कोई गाँव न होगा। भोपड़ियों की जगह अब कोलखोजी किसान बड़ी-बड़ी इमारतों में रहते हैं। सभी बातों में कोलखोजों में आपस में सदा एक होड़-सी लगी रहती है। यही कारण है कि कोलखोजों की संख्या वहाँ दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है और व्यक्तिगत रूप से खेती-बारी करनेवाले गाँव बहुत ही थोड़े रह गये हैं।^१

: २ :

टर्की की राजनीतिक प्रणाली

सन् १९१८ से अबतक जितने अधिनायक तन्त्र स्थापित हुए हैं, उनमें से टर्की का अधिनायक तन्त्र दो बातों में सबसे आगे है। पहली बात तो यह है कि वहाँ पूरी तरह से अधिनायक का ही राज्य है और दूसरा यह कि वहाँ जितने उग्र उपायों से

१. जो लोग सोविएट रूस के सम्बन्ध में पूरी बातें जानना चाहते हों, उन्हें श्री राहुल सांकृत्यायन की लिखी और नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी से प्रकाशित 'सोविएट भूमि' नामक पुस्तक देखनी चाहिए।

—रा० चं० वर्मा।

विरोधियों का दमन किया गया है, उतने उग्र उपायो से और कहीं नहीं किया गया है। वास्तव में वही ऐसा अधिनायक तन्त्र स्थापित हुआ है जिसमें सारे अधिकार एक ही आदमी ने अपने हाथ में ले लिये थे। वह व्यक्ति कमाल पाशा था, जिसका कुछ ही दिन पहले देहान्त हुआ है। पर वास्तव में सारा देश कमाल का इतना अधिक आदर करता था और वह इतना अधिक लोक-प्रिय था कि उसे समस्त संघटित विरोधों को जड़मूल से उखाड़ फेंकने और विशुद्ध राष्ट्रीय नीति के अनुसार सब काम करने में पूरी-पूरी सफलता हुई थी। उसने अपनी सारी प्रजा का रहन-सहन और व्यवहार इतना अधिक बदल दिया, जितना एक रूस को छोड़कर शायद और कोई देश नहीं बदल सका था। इस एक व्यक्ति के अधिनायक तन्त्र ने टर्की में अपने साथ एक बहुत बड़ा और संघटित राजनीतिक दल तैयार कर लिया था, जो उसके बाद भी ठीक तरह से काम कर रहा है और आशा है कि भविष्य में भी बहुत दिनों तक काम करता रहेगा। अब वस्तुतः एक ही दल सारे देश में है। अब वहाँ कुछ छोटे-मोटे विरोधी दल फिर कुछ तैयार होने लगे हैं, लेकिन ये दल भी ऐसे ही हैं कि जो नवीन शासन-प्रणाली की आधार-भूत संस्थाओं पर किसी प्रकार का आघात नहीं करना चाहते। परन्तु इस अधिनायक तन्त्र का स्वरूप भी बहुत कुछ प्रतिनिधिसत्तात्मक है और निर्वाचन में देश के बहुत अधिक निवासियों को वोट देने का अधिकार है। सन् १९३१ से वहाँ की स्त्रियों को भी वोट देने का अधिकार मिल गया है। इन्हीं निर्वाचकों की चुनी हुई वहाँ केवल एक असेम्बली होती है। यही असेम्बली कानून भी बनाती है और राष्ट्रपति भी चुनती है। जिस मुस्तफा कमाल ने सारे टर्की का स्वरूप ही बदल दिया था, वह प्रतिनिधिसत्तात्मक आधार पर बनी हुई असेम्बली का निर्वाचित सभापति और राष्ट्रपति था और उसके मरने पर इसी असेम्बली

ने उसका उत्तराधिकारी भी चुना था । लेकिन वास्तव में असेम्बली के सब सदस्य एक ही दल के हैं और वह दल स्वयं मुस्तफा कमाल का संघटित किया हुआ है । इटली, जर्मनी और रूस की तरह टर्की में भी इधर कुछ बरसों से एक ही दल का राज्य है ।

मुस्तफा कमाल अपने देश का परित्राण करनेवाला समझा जाता है और इसीलिए सारे देश में उसका बहुत अधिक आदर था । यही कारण था कि बहुत ही थोड़े समय में वह राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर पहुँच गया था और सारे देश का राष्ट्रीय जीवन विलकुल नये सौच में ढाल सका था । महायुद्ध के बाद टर्की पराजित और दुर्बल तो था ही, पर साथ ही इस बात की भी आशंका हो रही थी कि स्वतन्त्र राज्य के रूप में कहीं उसका कोई अस्तित्व ही न रह जायगा । उसकी पुरानी राजधानी कुस्तुनतुनिया पर मित्र-राज्यों ने अधिकार कर लिया था और वहाँ का सुलतान मित्र-राज्यों के हाथ की कठ-पुतली बन गया था । मित्र-राष्ट्र उसके साम्राज्य के भिन्न-भिन्न अंगों का आपस में बँटवारा कर रहे थे और नाम के लिए जो प्रदेश टर्की के सुलतान के अधिकार में छोड़ दिया गया था, उसके अनेक अंशों पर भी मित्र-राष्ट्र अपना प्रभुत्व और प्रभाव स्थापित करना चाहते थे । लेकिन टर्की के सौभाग्य से मित्र-राष्ट्रों में ही आपस में फूट पैदा हो गई थी और वे यह नहीं निश्चित कर सकते थे कि टर्की-राज्य के किस अंश पर किसका प्रभाव रहे और कौनसा प्रदेश कौन ले । अंग्रेजों, फ्रान्सीसियों और इटैलियनों में इस सम्बन्ध में प्रायः झगड़े-बखेड़े होते रहते थे; और इन्हीं सब झगड़ों से टर्की को लाभ उठाने का अवसर मिल गया । इस तरह के झगड़े-बखेड़े खड़े करने और बढ़ाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार ब्रिटेन कहा जाता है । इसका कारण यह है कि अंग्रेजों ने ही ग्रीस को

उभारकर उससे एशिया माइनर पर आक्रमण करा दिया था; और इसी अनुचित आक्रमण का यह परिणाम हुआ था कि सारे टर्की में राष्ट्रीयता की एक ऐसी लहर उठी जो किसी के रोके रुक नहीं सकी। उस समय टर्की की राष्ट्रीय सेना का सेनापति मुस्तफा कमाल था, जिसने ग्रीको को एशिया माइनर से मारकर भगा दिया और टर्की में नया राज्य स्थापित किया। मित्र-राष्ट्रों को विवश होकर मानना पड़ा कि युद्ध में तुर्कों की विजय हुई है। सेवरेस की जिस सन् १९२० वाली सन्धि ने तुर्कों पर बहुत ही ऐसी शर्तें और पाबन्दियाँ लगा रखी थीं, जो उनके लिए बहुत ही हानिकारक भी थीं और अपमानकारक भी, उसके सन्धिपत्र को इस युद्ध ने रद्दी के टोकरे में डाल दिया था। इसके बाद सन् १९२३ में लासेन में जो नई सन्धि हुई थी, उससे टर्की की नई सीमायें निश्चित हुई और उन सीमाओं के अन्दर उसे पूरी-पूरी स्वतन्त्रता भी मिल गई। तभी से वहाँ राष्ट्रीय एकता के आधार पर एक नवीन राज्य का निर्माण होने लगा।

नवीन टर्की—नवीन टर्की के सम्बन्ध में सबसे पहली ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वह पुराने टर्की से बिल्कुल भिन्न है। नवीन टर्की एक राष्ट्रीय राज्य है और उसमें मुख्यतः एक ही प्रकार की जनता बसती है। वहाँ पहले बहुत सी और जातियों के लोग भी बसते थे। लेकिन वे लोग ग्रीस और बल्गेरिया को दे दिये गये थे, और उनके बदले में तुर्क जनता उनसे ले ली गई थी। अब भी वहाँ कई जातियों के थोड़े-थोड़े लोग हैं और इस प्रकार अल्प-संख्यकों की कुछ समस्याएँ उसके सामने रह गई हैं। लेकिन प्रजा का बहुत बड़ा हिरसा तुर्क ही है। उदाहरण के लिए एशिया माइनर में थोड़े से कुर्द जाति के लोग रहते हैं और कुस्तंतुनिया में अधिकतर बहुत सी जातियों की मिली-जुली बस्ती है। लेकिन इन सब अल्प-संख्यक जातियों के रहते

हुए भी अब टर्की एक राष्ट्रीय राज्य हो गया है। लेकिन पुराने टर्की साम्राज्य में कभी यह बात नहीं होने पाई थी। उसमें बहुत सी जातियों के बहुत से लोग रहते थे और उनके कारण प्रायः उपद्रव भी होते रहते थे। पुराने टर्की में जो एकता थी, वह जबरदस्ती कायम की गई थी, और उसकी प्रजा में आन्तरिक एकता का कोई भाव नहीं था। इससे उसे वह एकता नहीं प्राप्त हुई थी जो किसी साम्राज्य में होती है, बल्कि वह एक ऐसे धार्मिक आन्दोलन का केन्द्र था जो राज्य की सीमाओं के बाहर भी दूर-दूर तक काम करता था। टर्की का सुलतान केवल बादशाह या सुलतान ही नहीं होता था, बल्कि वह सारे इस्लामी जगत का आध्यात्मिक प्रधान या खलीफा भी होता था। लेकिन कमाल पाशा की अधीनता में आकर तुर्की ने इस धार्मिक आधार का समूल नाश कर डाला। पहले सन् १६२२ में वहाँ के तख्त से सुलतान हटाया गया और फिर सन् १६२४ में खिलाफत का भी खात्मा कर दिया गया। कमाल ने धार्मिक आधार का नाश कर के केवल लौकिक आधार पर नवीन टर्की का संघटन किया। वहाँ राज्य के तत्वावधान में सब को केवल लौकिक विषयों की शिक्षा दी जाने लगी और पुराने धार्मिक कानूनों की जगह स्वीटजरलैण्ड की तरह का ऐसा नया कानून बना जिसका आधार विशुद्ध लौकिक था। सन् १६८८ वाली क्रान्ति के बाद भी उस समय के नवयुवक तुर्कों ने एक बार टर्की को पश्चिमी सौँचे में ढालने का प्रयत्न किया था, जो कई कारणों से बिल्कुल विफल हुआ था। लेकिन जब कमाल ने यह प्रयत्न फिर से आरम्भ किया, तब इस कारण उसे पूरी सफलता हुई कि उसने सारा नव-निर्माण एक राष्ट्रीय सीमा के अन्दर और बिल्कुल राष्ट्रीय आधारों पर किया था। अब उसके सिर पर उस साम्राज्य का कोई बोझ न रह गया था, जिसकी पहले ठीक तरह से कोई

व्यवस्था ही नहीं हो सकती थी और जिसके कारण अधिकारियों को सदा तंग होना पड़ता था।

युद्ध के बाद कुछ दिनों तक टर्की में दो सरकारें थी। इनमें से पहली सरकार तो स्वयं सुलतान की थी जिसकी राजधानी कुस्तुनिया में थी। इस सरकार पर मित्र-राष्ट्रों का सैनिक नियन्त्रण था, परन्तु वास्तव में देश पर इस सरकार का कोई अधिकार नहीं था। यह नाम-मात्र की सरकार थी। दूसरी सरकार एंगोरा में राष्ट्रीय असेम्बली की थी, जिसके सब काम कमाल की आज्ञा से होते थे। कमाल की अधीनता में पहली असेम्बली की बैठक सन् १९१६ में एर्ज़रूम में हुई थी। परन्तु वास्तव में नवीन टर्की की स्थापना सन् १९२० में उस समय हुई थी, जिस समय एंगोरा में पहली राष्ट्रीय असेम्बली की बैठक हुई थी। इसी असेम्बली के निश्चय के अनुसार कमाल ने ग्रीको के साथ युद्ध किया और उसमें विजय प्राप्त की थी। फिर भी सन् १९२२ तक सुलतान की सरकार जैसे-तैसे बनी रही। लेकिन १९२२ में मित्र-राज्यों ने उस पर से अपना संरक्षण हटा लिया जिससे लाचार होकर सुलतान को देश छोड़कर भागना पड़ा और एंगोरा की सरकार ने आकर कुस्तुनिया पर अधिकार कर लिया। सन् १९२० में ही एंगोरा वाली असेम्बली ने यह घोषणा कर दी थी कि देश का सारा अधिकार हमारे हाथ में है और टर्की राष्ट्र की मालिक इस देश की जनता है। परन्तु सुलतानी शासन का जो नाम-मात्र का अधिकार था, उसका अन्त सन् १९२२ में ही हुआ था। उस समय तक खिलाफत का अन्त नहीं हुआ था, और खलीफा का पद उस्मानी राज-वंश के एक व्यक्ति को दे दिया गया था जिसे लौकिक विषयों में कोई अधिकार नहीं था। परन्तु सन् १९२४ में खिलाफत का भी अन्त कर दिया गया और वह पद ही तोड़

डाला गया^१। इससे पहले सन् १९२३ में ही यह घोषणा कर दी गई थी कि तुर्की में प्रजातन्त्र स्थापित हो गया है और मुस्तफा कमाल उस प्रजातन्त्र का पहला राष्ट्रपति चुना गया था।

उस समय तक यह निश्चय नहीं हुआ था कि इस नये राज्य की सरकार का क्या स्वरूप होगा। सन् १९२१ में एंगोरा की राष्ट्रीय असेम्बली ने अपने मूल सिद्धान्तों और अधिकारों आदि के सम्बन्ध में जो बुनियादी कानून (Fundamental Law) बनाया था, उसमें यह घोषणा कर दी गई थी कि जनता की एक-मात्र प्रतिनिधि यह असेम्बली ही है और यह नियम बना दिया गया था कि इस का चुनाव हर दूसरे वर्ष हुआ करेगा। इस असेम्बली का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक कालेजों या निर्वाचित संस्थाओं के द्वारा हुआ करता था। निर्वाचन करने का अधिकार केवल पुरुषों को ही दिया गया था, परन्तु उनकी संख्या बहुत अधिक रक्खी गई थी। सन् १९२४ में संघटन-विधान में जो सुधार हुआ था, उसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन वाली पुरानी प्रणाली तो रहने दी गई थी, परन्तु असेम्बली का कार्य-काल दो वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष कर दिया गया था। आगे चलकर अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जगह प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा चलाई गई। परन्तु सन् १९३१ तक का निर्वाचन उसी पुरानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन-प्रणाली से ही हुआ था। कमाल का दल लोकप्रिय दल (Popular Party) कहलाता था और असेम्बली के सभी सदस्य इसी दल से चुने गये थे।

पहले टर्की में शिक्षा का बहुत ही कम प्रचार था और

१. सन् १९३८ के अन्त में मिस्र के नये बादशाह ने स्वयं ही खलीफा का पद ग्रहण कर लिया था और अब इस्लामी जगत् उसी को अपना खलीफा मानने लगा है—रा० चं० वर्मा।

वहाँ पढ़े-लिखे लोगो की संख्या बहुत ही थोड़ी होती थी। परन्तु अब वहाँ शिक्षा का बहुत अधिक प्रचार हो गया है और देश में शिक्षितो की संख्या बहुत बढ़ गई है। कुछ तो देश में शिक्षितों की संख्या बढ़ जाने के कारण और कुछ राज्य के सब काम एक ही दल के हाथ में चले जाने के कारण अप्रत्यक्ष निर्वाचन-वाली प्रणाली ही निकम्मी और बेकार हो गई है। सन् १९३० में स्त्रियों को म्यूनिसिपल निर्वाचन में और सन् १९३१ में राष्ट्रीय निर्वाचन में वोट देने का अधिकार मिला था। स्थानीय शासन पर केन्द्रीय सरकार का बहुत अधिक नियन्त्रण रक्खा गया है। सारा टर्की ६३ विलायतों या प्रदेशों में बँटा है और हर एक विलायत को व्यवस्था करने के लिये सरकार की ओर से एक बली नियुक्त होता है। हमारे यहाँ की तहसील की तरह वहाँ जो सबसे छोटा स्थानिक विभाग होता है, वह 'नहिया' कहलाता है और कई नहियों के योग से एक 'करा' होता है जो हमारे यहाँ के जिले के बराबर होता है। और कई करों का एक विलायत या प्रान्त होता है। प्रत्येक कर में राज्य की ओर से नियुक्त एक अधिकारी रहता है। प्रत्येक विलायत और प्रत्येक नहिया में जनता की चुनी हुई एक कौन्सिल भी होती है। परन्तु विलायत की कौन्सिल के हाथ में शासन-सम्बन्धी विशेष अधिकार नहीं होते और वह प्रायः परामर्श देनेवाली संस्था ही होती है।

सन् १९२४ तक तो नये टर्की राज्य को अधिकतर वही सब अव्यवस्थाये दूर करनी पड़ी थी, जो महायुद्ध के बाद से वहाँ उत्पन्न हो गई थीं। मुस्तफा कमाल ने स्वयं ही राष्ट्रीय सेना का संघटन किया था और स्वयं ही उसका संचालन करके ग्रीकों पर विजय प्राप्त की थी, जिससे देश में उसका सम्मान बहुत बढ़ गया था। और इसीलिए सारा देश सदा उसकी आज्ञा के

अनुसार चलने के लिए तैयार रहता था। अपने देशवासियों और अपनी सेना की निष्ठा और भक्ति पर वह पूरा-पूरा भरोसा कर सकता था। पहले तो वह राष्ट्रीय असेम्बली का ही सभापति था; आगे चलकर सन् १९२४ वाले नये संघटन-विधान के अनुसार वह तुर्की प्रजातन्त्र का राष्ट्रपति भी चुन लिया गया था। सन् १९२३ से ही उसने अपने लोकप्रिय दल का निर्माण भी आरम्भ कर दिया था। इस दल के संघटन का जो विधान बना था, उसके आरम्भ में ही कहा गया था : “इस दल का उद्देश्य यह रहेगा कि देश का शासन जनता के हित के लिए, स्वयं जनता के ही द्वारा हो और टर्की को उन्नत करके एक आधुनिक राज्य की हैसियत तक पहुँचा दिया जाय।” इसी विधान में यह भी कहा गया था कि धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग रक्खा जाय ; कुछ विशिष्ट वर्गों को अभी तक जो विशेष अधिकार और सुभीते प्राप्त हैं, उन सबका अन्त कर दिया जाय, सब नागरिकों को नागरिकता के समान अधिकार रहे और इन अधिकारों के सम्बन्ध में स्त्रियों और पुरुषों में कोई भेद न रहे। उसमें यह भी कहा गया था कि प्रजातन्त्र का आधुनिक रीतियों से संघटन किया जाय और उसका वही वैज्ञानिक और रचनात्मक आधार रक्खा जाय जो सबसे अधिक उन्नत तथा अग्रसर देशों के संघटन का है। इस प्रकार इस दल ने सन् १९२३ में अपना वह सारा कार्यक्रम तैयार कर लिया था जिसके अनुसार अबतक टर्की को पाश्चात्य सॉचे में ढाला गया है।

यद्यपि सन् १९२४ में देश में मुस्तफा कमाल का बहुत अधिक आदर और सम्मान था, वह सबसे बड़ा राष्ट्रीय नेता माना जाता था, और वह अपने देश को उन्नत तथा विकसित करने का अपनी ओर से पूरा-पूरा प्रयत्न कर रहा था, परन्तु

फिर भी तबतक राजनीतिक क्षेत्र में वह अधिनायक या डिक्टेटर की हैसियत तक नहीं पहुँचा था। इसका कारण यह था कि उस समय तक देश में एक और दल भी मौजूद था जिसका उसे मुकाबिला करना पड़ता था। यह वही दल था जिसने सन् १९०८ में टर्की से राज्य-क्रान्ति की थी। इसमें पुराने ढंग के कुछ-कुछ प्रगतिशील नेता थे जिन्होंने देश में एकता और प्रगति की समिति (Committee Of Union And Progress) स्थापित कर रखी थी। अपनी युवावस्था में कमाल भी इस आन्दोलन में बहुत कुछ काम कर चुका था। उन दिनों वह सैलोनिका में एक नवयुवक अफसर के तौर पर काम करता था। लेकिन उस राज्य-क्रान्ति के बाद जिन राजनीतिक नेताओं के हाथ में तुर्की का शासन था, वे लोगो की निगाह से इसलिए बहुत गिर गये थे कि बाल्कन युद्धों में भी और महायुद्ध में भी उनकी अधीनता में देश बराबर परास्त होता आ रहा था और उसकी अनेक प्रकार से हानि हो रही थी। फिर जब महायुद्ध समाप्त हो गया, तब सेबरेस वाली सन्धि के अनुसार टर्की पर जो अपमानजनक शर्तें लादी गई थीं, उन्हें भी उन लोगों ने चुपचाप मान लिया था और वे मित्र-राष्ट्रों की आज्ञा के अनुसार ही सब काम करते थे। इस के सिवा जब मित्र-राष्ट्रों ने कुस्तुंतुनिया पर अधिकार कर लिया था, तब वही लोग वह नाम-मात्र की सरकार चलाते थे, जिसके हाथ में कोई वास्तविक अधिकार नहीं था। उनके इन्हीं सब दोषों के कारण उन पर से नवयुवक टर्की का विश्वास और श्रद्धा हट गई थी। कमाल के सभी विरोधी नेता तो नहीं, पर फिर भी उनमें से बहुत से नेता वही थे जो देश की इन सब दुर्दशाओं के कारण थे। परन्तु केवल वही नेता उसके विरोधी नहीं हुए थे, जो उसके विरुद्ध खड़े होने का साहस नहीं कर सकते थे। कमाल के ये सब विरोधी नेता और प्रतिद्वन्द्वी देश

में पार्लमैण्टरी शासन स्थापित करना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि देश में भिन्न-भिन्न विरोधी और प्रतिद्वन्द्वी दल बने रहे और जिस तरह से पाश्चात्य पार्लमैण्टरी देशों में शासन के सब काम होते हैं, उसी तरह तुर्की में भी हुआ करे। कमाल का बहुत बड़ा मित्र और अनुयायी इस्मत पाशा था, जिसे इन विरोधियों ने कुछ दिनों के लिए प्रधान-मन्त्री के पद से हटा भी दिया था। कमाल चाहता था कि देश में एक केन्द्रित और व्यवस्थित राज्य स्थापित हो। पर फहती बे के नेतृत्व में उसके प्रगतिशील विरोधी नेता कुछ दिनों के लिए इतने प्रबल हो गये थे कि उन्होंने राज्य का बहुत कुछ अधिकार भी अपने हाथ में ले लिया था। इस पर कमाल ने सारी असेम्बली को अपने अधिकार में कर लिया और अपने विरोधियों पर यह इल्जाम लगाया कि इन्हीं लोगों की नीति के कारण एशिया माइनर में कुर्दों का विद्रोह हुआ था। इसके बाद उसने बहुत उग्र उपायों से उस विद्रोह का दमन करके फहती बे को प्रधान-मन्त्री के पद से हटा दिया और उस स्थान पर फिर इस्मत पाशा को नियुक्त करके शान्ति-रक्षा के लिए एक नया कानून बनाया। इस नये कानून की सहायता से उसने अपने समस्त विरोधियों का बहुत जल्दी और पूरा-पूरा दमन किया। उसने कुछ नई अदालतें बना दीं जिनमें विरोधी नेताओं का विचार होता था। इन्हीं अदालतों ने कमाल के बहुत से विरोधियों को प्राण-दण्ड की आज्ञा दी और बहुतों को देश से निर्वासित कर दिया। इस प्रकार वह और उसका लोक-प्रिय दल, जिसका संघटन उसने सन् १९२३ में किया था, दोनों सारे देश के पूरे-पूरे मालिक हो गये और कोई उनका विरोध करनेवाला न रह गया।

कमाल का अधिकार—परन्तु अपनी इस विजय के उपरान्त भी कमाल जान-बूझकर एक अधिनायक या डिक्टेटर

की हैसियत से सब काम करने से बचता रहा ; और मरते वक्त तक कभी उसने खुलकर डिक्टेटरी नहीं की। वह बराबर तुर्की प्रजातन्त्र का राष्ट्रपति ही बना रहा। हर चार बरस के बाद जब नई राष्ट्रीय असेम्बली चुनी जाती थी, तब वह उसे भी चार वर्षों के लिए राष्ट्रपति चुन लेती थी। वहाँ का विधान ही ऐसा था कि राष्ट्रपति को बार-बार चुने जाने का अधिकार होता था। राष्ट्रपति की हैसियत में उसके अधिकार भी कुछ बहुत अधिक नहीं होते थे। वहाँ राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि असेम्बली के बनाये हुए किसी कानून को अगर वह नापसन्द करे या अच्छा न समझे तो उसे दुबारा विचार करने के लिए असेम्बली के पास भेज सकता है। लेकिन असेम्बली को भी यह अधिकार होता है कि वह वही कानून फिर से पास कर दे। राष्ट्रपति ही प्रधान-मन्त्री की नियुक्ति करता है और प्रधान-मन्त्री को यह अधिकार होता है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार और मन्त्रियों को चुन ले। परन्तु मंत्रि-मण्डल के लिए यह आवश्यक होता है कि असेम्बली का बहुमत उसके पक्ष में हो। राष्ट्रपति को कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं होता। और यदि वह कोई कानून बनावे भी तो उसके लिए यह आवश्यक होता है कि प्रधान-मन्त्री भी उस पर हस्ताक्षर करे और वह विभाग मन्त्री भी उस पर हस्ताक्षर करे, जिसके विभाग से वह कानून सम्बन्ध रखता है।

लेकिन कमाल केवल राष्ट्रपति ही नहीं था, बल्कि वह सेना का प्रधान सेनापति और लोकप्रिय दल का सभापति भी था। और इन तीनों पदों के एक साथ मिल जाने के कारण ही देश पर उसे इतना अधिक अधिकार प्राप्त हुआ था। परन्तु असल बात यह है कि उसका सारा अधिकार उसके किसी पद के कारण नहीं, बल्कि इसलिए था कि देश उसे बहुत ही सम्मान

की दृष्टि से देखता था और उस पर पूरा-पूरा भरोसा रखता था। और इसीलिए यह आवश्यक नहीं है कि ये सब बातें उसके उत्तराधिकारी को भी प्राप्त हो ही।

टर्की में सुधार—सन् १६२५ में विजयी होने के बाद से कमाल पाशा टर्की को नये राष्ट्रीय राज्य के साँचे में ढालने का प्रयत्न करने लगा। उसने राज्य के धार्मिक स्वरूप का नाश करके पाश्चात्य यूरोप के ढंग पर केवल लौकिक आधारवाली संस्थाएँ ही बनाई थी। यहाँ के स्कूलों में पहले लौकिक विषयों के साथ-ही-साथ धार्मिक विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। परन्तु कमाल ने धार्मिक शिक्षा हटा कर केवल उच्च कोटि की और आधुनिक प्रणाली की लौकिक शिक्षा की ही व्यवस्था की और देश के सब बालकों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य कर दी। इस विषय में उसने एक सबसे बड़ा सुधार यह किया था कि टर्की लिपि को हटाकर उसके स्थान पर रोमन लिपि का देश में प्रचार किया था। इसके सिवा देश की भाषा भी पहले से बहुत सरल कर दी गई थी। टर्की की पुरानी लिपि और भाषा ऐसी पेचीली थी कि वह शिक्षा के प्रचार में बहुत बाधक होती थी और इसीलिए उसे इन दोनों में सुधार करना पड़ा था। स्त्रियों को केवल राजनीतिक विषयों में ही नहीं, बल्कि शिक्षा-सम्बन्धी और सामाजिक बातों में भी पुरुषों के समान ही अधिकार दिये गये थे। अब व्याह-शादियाँ भी वहाँ बिल्कुल पश्चिमी ढंग से होने लगी हैं और उनका वह पुराना निकाही रूप हटा दिया गया है। स्त्रियों का परदा भी दूर कर दिया गया है। यूरोपीय ढंग की पोशाक पहनना सब लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है और दाढ़ियाँ भी जबरदस्ती मँड़वा दी गई हैं। सब जगह पाश्चात्य ढंग की

अदालते कायम हो गई है । बहुत से लोग यह समझते थे कि प्राचीन सांस्कृतिक और धार्मिक विषयों में कमाल जो जबरदस्ती कर रहा है, उसके कारण उसका बल बहुत कुछ घट जायगा । लेकिन अपनी मजबूत सरकार की सहायता से उसने बहुत ही सफलतापूर्वक ये सारे सुधार कर डाले थे और इससे उसका सम्मान तथा बल बढ़ा ही था । इन सब सुधारों में उसके लोकप्रिय दल ने भी बहुत ही तत्परतापूर्वक उसकी पूरी-पूरी सहायता की थी । इस में सन्देह नहीं कि उसके इन सब कार्यों से देश में कुछ लोग अप्रसन्न और असन्तुष्ट हुए थे । लेकिन जबसे उसने कुर्द विद्रोहियों और प्रगतिशील दल का दमन किया था, तब से फिर किसी को खुलकर उसका विरोध करने का साहस नहीं हुआ ।

टर्की की परराष्ट्रीय नीति—कमाल ने अपने देश के लिए जो नई आर्थिक और सार्वराष्ट्रीय नीति ग्रहण की थी, उससे उसे अपने इन प्रयत्नों की सफलता में बहुत बड़ी सहायता मिली थी । कमाल के समय में तुर्कों ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि न तो हम अपने खोये हुए प्रदेशों पर फिर से अधिकार करने की आकांक्षा ही रखते हैं और न उन पर अधिकार करने की हमारी इच्छा ही है । और इसी नीति के कारण देश में कमाल की स्थिति बहुत दृढ़ हो गई थी । आगे चलकर तुर्की ने और राष्ट्रों से प्रजा का जो परिवर्तन किया था, और विशेषतः एशिया माइनर से बहुत से ग्रीकों को निकालकर उनके बदले में ग्रीक सीमाओं में से जो बहुत से तुर्क ले लिये थे, उसी से यह सिद्ध होता है कि उसने अपना उक्त सिद्धान्त कितने शुद्ध हृदय से स्थिर किया था और वह अपने वादों को कितनी ईमानदारी के साथ पूरा करना चाहता था । फिर अपनी इसी नीति के अनुसार उसने अपने सभी पड़ोसियों से यह समझौता भी कर लिया था

कि न तो हम किसी के प्रदेश पर आक्रमण करेंगे और न कोई हमारे प्रदेश पर आक्रमण करे। और ये सब बातें निश्चित करने के बाद सन् १९३२ में वह राष्ट्र-संघ का भी सदस्य बन गया था। फिर सन् १९३४ में उसने ग्रीस, युगोस्लेविया और रूमानिया के साथ मिलकर प्रसिद्ध बालकनवाला समझौता किया था। लेकिन यह समझौता कर लेने पर भी उसने कभी बल्गेरिया के साथ विगाड़ नहीं किया। इस नवीन तुर्की प्रजातन्त्र को सबसे पहले सोवियट रूस ने मान्य किया था। अब रूस के साथ इसलिए उसका कोई झगड़ा नहीं रह गया था कि सन् १९२१ में ही उसने एक सन्धि के द्वारा सीमा-सम्बन्धी सब झगड़े तै कर लिये थे। तब से अबतक सोवियट रूस के साथ टर्की की मित्रता ही चली आती है और कभी दोनों में अनबन नहीं हुई। रूस ने अपने यहाँ जो नई आर्थिक योजना और व्यवस्था की थी, उसका कमाल पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था और इसीलिए वह भी बहुत सी बातों में रूस का ही अनुकरण करता था। और सन् १९३४ के आरम्भ में तुर्की ने अपने लिए एक पंच-वार्षिक योजना भी तैयार की थी जिसमें उन्हें बहुत कुछ सफलता भी हुई है।

टर्की की आर्थिक समस्याएँ—महायुद्ध के बाद व्यापार की जो दुर्दशा हुई थी, उसके कारण टर्की की भी बहुत कुछ आर्थिक हानि हुई थी। टर्की में पहले बहुत सी ऐसी दस्तकारियाँ होती थीं, जिनका सारे संसार में बहुत आदर होता था। मशीनों की सहायता से नहीं, बल्कि सिर्फ हाथ से तुर्क लोग ऐसी बहुत सी बढ़िया-बढ़िया चीजें तैयार करते थे जिनकी खपत दुनिया भर में हुआ करती थी। परन्तु अब उस तरह की चीजें पाश्चात्य देशों में मशीनों की सहायता से बहुत अधिक मान में तैयार होने लग गई थीं। इसलिए अब टर्की को अधिकतर अपनी खेती का

पैदावार का ही सहारा रह गया था। वह खेती-बारी से ही बहुत सी चीजें और खासकर तम्बाकू पैदा करके दूसरे देशों को भेजा करता था। लेकिन जब दुनिया भर में इन सब चीजों के दाम बहुत गिर गये, तब तुर्की की आर्थिक परिस्थिति बहुत विकट हो गई। अब टर्की सरकार के सामने यह प्रश्न आया कि खेतिहरों को नष्ट होने से किस प्रकार बचाया जाय ? इसके लिए उसने यह व्यवस्था की कि बाहर से आनेवाले माल पर बहुत काफी चुंगी लगा दी और इस चुंगी से उसे जो आमदनी होती थी, उसी से वह उन लोगों की सहायता करती थी, जो देश का बना हुआ माल विदेश भेजते थे। इसके सिवा वहाँ यह भी व्यवस्था हुई थी कि जो कच्चा माल बाहर से मँगाना पड़ता है, वह भी जहाँ तक हो सके, देश में ही पैदा किया जाय। पहले खासकर चीनी और रुई के लिए उसे दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब टर्की को जितनी चीनी की जरूरत होती है, वह सब वह आप ही पैदा कर लेता है। अब रुई भी वहाँ होने लगी है और बढ़िया रुई तैयार करने के लिए वहाँ बहुत अच्छा प्रयत्न हो रहा है। इसके सिवा ब्रिटेन से मशीनें मँगाकर तुर्क लोग अब बहुत से कपड़े भी खुद ही तैयार करने लगे हैं। स्वयं राज्य की देख-रेख में अब वहाँ के किसानों को यह भी सिखलाया जाता है कि खेती-बारी के कामों में मशीनों का किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए और नये-नये तरीकों से किस तरह खेती की पैदावार बढ़ानी चाहिए।

टर्की प्रजा का एक बड़ा अंश इस समय एशिया-माइनर में है, पर वहाँ अच्छी सड़के, रेलें और यातायात के दूसरे साधन नहीं हैं। और तुर्कों के सामने अबतक यह भी एक बड़ी समस्या रही है। पुराने टर्की में तो यूरोपियन ढंग की अच्छी-अच्छी रेलें हैं, लेकिन एशिया-माइनर के भीतरी भागों तक रेलें पहुँचाने का

टर्की की राजनीतिक प्रणाली

अभी तक बहुत ही थोड़ा प्रयत्न हुआ है। इस समय की परिस्थिति यह है कि यूरोप में तो केवल दस लाख तुर्की प्रजा चसती है और एक करोड़ चालीस लाख तुर्की प्रजा एशिया में है। अब राजधानी भी कुस्तुंतुनिया से हटकर एंगोरा में आ गई है। अब टर्की मुख्यतः एशियाई राज्य हो गया है, यूरोपीय राज्य नहीं रह गया है। कमाल पाशा की यही इच्छा थी कि देश का आर्थिक विकास और उन्नति करने के लिए एशियाई प्रदेश के भीतरी भागों में ऐसे नये बाजार तैयार किये जायँ जिनमें तुर्क खेतिहरो की पैदावार बिक सके। साथ ही वहाँ अच्छी सड़कें और रेलें भी बन जायँ, जिसमें नई प्रणालियाँ और नये विचार भी दूर-दूर तक पहुँच सकें। इसीलिए इधर कुछ दिनों से तुर्की सरकार नई-नई रेलें बनाने पर बहुत जोर देती रही है। अवश्य ही उसे यह सारा काम विदेशी कोठियों और विदेशी इंजीनियरों से कराना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसने इसके लिए कभी किसी विदेशी सरकार से कोई ऋण नहीं लिया है। हाँ, इन सब बातों के कारण देश पर जो भारी बोझ पड़ा है, उससे वहाँ की प्रजा को जीवन-निर्वाह में अवश्य ही कुछ कठिनता हुई है।

इस समय तक इस नीति के बहुत शुभ परिणाम देखने में आये हैं। सन् १९२८ में टर्की ने जितना माल तैयार किया था, सन् १९३२ में उसका ढाई गुना तैयार किया था। सन् १९३३ में वहाँ सिर्फ १४४० मील रेल थी, लेकिन सन् १९३२ में ४००० मील से भी अधिक रेल की लाइनें थीं। पहले टर्की में बहुत सा शिल्प-सम्बन्धी काम विदेशी पूँजीदारों के हाथ में रहता था, परन्तु अब वह सब तुर्कों के हाथ में आ गया है। अब टर्की में जिन विदेशी कंपनियों को कोई काम करने का ठेका या कारबार करने का अधिकार दिया जाता है, उन्हें अपने डाइरेक्टरों के बोर्ड में तुर्क डाइरेक्टर भी रखने के लिए विवश

किया जाता है। इसके सिवा उन कम्पनियों को अपने यहाँ तुर्क काम करने वाले भी रखने पड़ते हैं और तुर्की भाषा का भी व्यवहार करना पड़ता है। अब टर्की के समुद्र-तट पर केवल तुर्क जहाज ही चलने पाते हैं और वही एक जगह का माल दूसरी जगह पहुँचाते हैं, जिससे वहाँ जहाजरानी का काम भी खूब बढ़ गया है। अब शिल्प और उद्योग-धन्धो पर सरकार का बहुत कुछ नियन्त्रण रहता है, उन्हें सरकार की तरफ से रुपये-पैसे की मदद दी जाती है और उन्हें तुर्कों के ही हाथ में रक्खा जाता है। तात्पर्य यह कि टर्की की आर्थिक नीति भी और राजनीतिक नीति भी बिल्कुल राष्ट्रीयता की दृष्टि से स्थिर की जाती है। परन्तु यह तुर्की राष्ट्रीयता साम्राज्यवादी ढंग की नहीं है। वह दूसरों पर आक्रमण करके उन्हें अपने अधीन नहीं करना चाहती, बल्कि उसका उद्देश्य केवल आत्म-रक्षा करना ही होता है। अब टर्की केवल यही चाहता है कि हमारे अधिकारों पर दूसरे लोग आक्रमण न करने पावे और हमें चुपचाप शान्तिपूर्वक अपनी उन्नति तथा विकास करने का अवसर मिले।

टर्की की राजनीतिक स्थिति—यदि हम टर्की के एकदलीय राज्य की, जिसका विकास कमाल की देख-रेख में हुआ है, सोविएट रूस के श्रमिक अधिनायक तन्त्र अथवा इटली और जर्मनी के फ़ैसिस्ट अधिनायक तन्त्र के साथ तुलना करें तो सबसे पहले हमें यह पता चलेगा कि केवल टर्की की ही यह नवीन प्रणाली ऐसी है, जिसकी स्थापना शुद्ध राष्ट्रीय विचारों से हुई है—उसके मूल में राष्ट्रीयता की भावनाओं को छोड़कर और किसी प्रकार की भावना नहीं है। इटली और सोविएट संघ ने राष्ट्रीयता को मान्य किया है, परन्तु फिर भी वहाँ उसकी स्थापना सार्वराष्ट्रीय तथा वर्गीय विचारों के आधार पर हुई है। इटली और जर्मनी के फ़ैसिस्टवाद में भी राष्ट्रीयता के बहुत से तत्त्व हैं,

परन्तु फिर भी उन देशों में उसका उदय और विकास शुद्ध राष्ट्रीय रूप में नहीं हुआ था, बल्कि साम्यवाद के विरोध के रूप में हुआ था। परन्तु टर्की में ऐसा कोई साम्यवादी आन्दोलन था ही नहीं, जिसका उसे मुकाबिला करना पड़ता। मुस्तफा कमाल को तो केवल इसीलिए नेतृत्व और अधिकार प्राप्त हुआ था कि मित्र-राष्ट्र टर्की राज्य के टुकड़े-टुकड़े करके उसे अपने अधीन करना चाहते थे, और कमाल ने केवल राष्ट्रीयता के विचार से मित्र-राष्ट्रों के विरुद्ध विद्रोह किया था। सुलतान को सिर्फ इसलिए तख्त छोड़ना पड़ा था कि वह मित्र-राष्ट्रों के हाथ की कठपुतली हो रहा था। और कमाल इसलिए टर्की का भाग्य-विधाता बना था कि उसने ग्रीको को परास्त किया था और मित्र-राष्ट्रों को सेवरेस वाली सन्धि का परित्याग करने के लिए विवश किया था। कमाल को सारा अधिकार अपने सैनिक बल और राष्ट्रीय सम्मान के कारण प्राप्त हुआ था। टर्की की सारी सेना उसके प्रति पूरी निष्ठा रखती थी और इसीलिए वह अपने उन राजनीतिक विरोधियों का निर्दयतापूर्वक नाश करने में समर्थ हुआ था जो उसके अधिनायक या डिक्टेटर बनने में बाधा खड़ी करना चाहते थे। अन्त तक उसका सारा बल सेना के आधार पर ही रहा। अब जो कोई टर्की में जाता है, उसे सीमा पार करते समय जिस कठोर सैनिक नियन्त्रण का सामना करना पड़ता है, उसी से उसे पता चल जाता है कि कमाल ने सेना के बल पर ही सारा अधिकार अपने हाथ में लिया था। परन्तु आगे चलकर उसने अपना एक बहुत बड़ा और जवर्दस्त राजनीतिक दल भी बना लिया था। सारे देश में इस दल के सदस्यों की संख्या भी बहुत अधिक है और उसका संघटन भी बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। इसी दल ने अपने अधिनायक के द्वारा सारे देश को अपने राजनीतिक प्रभाव में कर रक्खा है और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का

बहुत बड़ा काम किया है। कमाल ने अपने समस्त विरोधियों का पूरा-पूरा नाश करके बाकी सभी तरह के लोगो को अपनी तरफ मिला लिया था, जिनमे बहुत सी स्त्रियाँ भी थीं। अब टर्की की सारी प्रजा मिलकर अपने देश की पूरी-पूरी आर्थिक तथा सांस्कृतिक उन्नति करना चाहती है और यूरोप की अच्छी तथा लाभदायक संस्थाओं का अपने यहाँ प्रचार करना चाहती है। इसके सिवा यूरोप के ज्ञान से भी वह पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहती है। सभी लोगो को यह मानना पड़ता है कि कमाल की अधीनता मे टर्की ने थोड़े ही दिनों में आश्चर्यजनक उन्नति की और आजकल टर्की मे जैसा अच्छा शासन होता है, वैसा पहले कभी नहीं होता था। यह ठीक है कि मुस्तफा कमाल ने अपना उद्देश्य सिद्ध करने के लिए बहुत ही भीषण और ठीक उसी प्रकार के उग्र उपायो का अवलम्बन किया था जिन उपायों से जर्मनी मे हिटलर ने काम लिया था। लेकिन फिर भी इस मे कोई संदेह नहीं कि उसने और उसके दल ने अपनी शक्ति का उपयोग केवल अपने देश-भाइयो की अवस्था सुधारने मे किया है। उमी के प्रयत्नो का यह फल है कि आजकल तुर्क किसान दिन-पर-दिन सभ्य भी होते जा रहे हैं और उन की आर्थिक अवस्था भी बराबर अच्छी होती जा रही है। टर्की किसी जमाने मे “यूरोप का मरीज” कहा जाता था और उसे यूरोप वाले बहुत ही घृणा तथा उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। परन्तु अब वह बात नहीं रह गई है। अब टर्की स्वस्थ और सबल हो रहा है और पश्चिमी एशिया में बहुत अच्छा प्रजातन्त्र माना जाता है। रूस तथा बालकन पड़ोसियो के साथ उसका बहुत अच्छा और मित्रता का व्यवहार है। उसमें राष्ट्रीयता का भाव तो बहुत प्रबल है, परन्तु उसकी राष्ट्रीयता ऐसी नहीं है जो दूसरे राज्यों के मन मे किसी प्रकार का भय या आतंक उत्पन्न करती हो। और

एक ऐसे देश के लिए ये सब बातें अवश्य ही बहुत अधिक अभिमान की हैं जो आज से केवल बीस वर्ष पहले कब्र में पैर लटकाये हुए पड़ा था ।

वर्तमान यूरोपीय युद्ध में अभी तक टर्की पूर्ण रूप से तटस्थ बना हुआ है। पर यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी यह तटस्थता कब तक निभेगी; और न यही कहा जा सकता है कि समय पड़ने पर वह किस पक्ष में सम्मिलित होगा । तो भी अभी तक उसकी सहानुभूति प्रजातन्त्रात्मक पक्ष के ही साथ है; और जर्मनी ने उसे अपने पक्ष में मिलाने के जो प्रयत्न किये हैं, वे विफल ही हुए हैं ।

: ३ :

जापान की राजनीतिक प्रणाली

यदि आप किसी अच्छे सन्दर्भ-ग्रन्थ के द्वारा यह जानना चाहेंगे कि जापान का संघटन-विधान कैसा है, तो आपको पता चलेगा कि वह पश्चिमी यूरोप के पार्लियामेण्टरी राज्यों के संघटन-विधान से बहुत कुछ मिलता-जुलता है । वहाँ एक सम्राट् होता है जो देखने में बिल्कुल वैधानिक रूप से अपने मन्त्री-मंडल के द्वारा शासन करता है । वहाँ दो हाउसों की एक पार्लियामेण्ट भी है जिनमें से बड़े हाउस में तो अधिकतर वंशानुक्रमिक सदस्य हैं और दूसरे हाउस में सब चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं । सन् १८२५ से वहाँ के सभी वयस्क पुरुषों को निर्वाचन का अधिकार मिल गया है और निर्वाचन गोटी डालकर होता है । यही पार्लियामेण्ट सब कानून बनाती है जिन पर सम्राट् के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है । लोक-प्रतिनिधियों की चेम्बर ठीक ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स की तरह सालाना बजट पास करती है ।

मन्त्रियों की अधीनता में एक सिविल सर्विस भी है और केन्द्रीय नियन्त्रण में स्थानिक शासन की भी ऐसी व्यवस्था है जो देखने में बहुत-कुछ फ्रान्स के ढंग की जान पड़ती है। वहाँ दो बड़े राजनीतिक दल भी हैं जो प्रायः बारी-बारी से अधिकारारूढ़ होकर शासन के सब काम अपने हाथ में लेते हैं। इनके सिवा कुछ दूसरे छोटे-छोटे दल भी हैं जो समय-समय पर मन्त्री-मंडल में दिखाई देते हैं। इधर कुछ दिनों से वहाँ का सारा अधिकार एक राष्ट्रीय सरकार के हाथ में था जिसमें अधिकतर सरकारी अफसर और विशेषतः नौ-सेना विभाग के अफसर थे। पर हाल में वहाँ की सरकार केवल सैनिक अफसरों के हाथ में चली गई है और वहाँ भी बहुत कुछ फैसिस्ट ढंग से शासन-प्रणाली प्रचलित होगई है।

तात्पर्य यह कि पार्लमेण्टरी प्रतिनिधिसत्तात्मक शासन में जितने लवाजमे होते हैं, वे सभी वहाँ दिखाई देते हैं। परन्तु वास्तव में जापान की राजनीतिक प्रणाली नाम को भी पार्लमेण्टरी देशों की शासन-प्रणाली के समान नहीं है। नाजी जर्मनी या फैसिस्ट इटली की शासन-प्रणाली जितनी पार्लमेण्टरी कही जा सकती है, उससे जापानी शासन-प्रणाली अधिक पार्लमेण्टरी नहीं है। वहाँ का सारा पार्लमेण्टरी शासन केवल नाम का है। और फिर पाश्चात्य उदार मत के सिद्धान्तों से आज-कल के जर्मनी और इटली का शासन जितना दूर है, शायद उससे भी कुछ और ज्यादा दूर आज-कल के जापान का शासन पड़ता है। और इसका कारण यही है कि जापान की संस्थाओं का आधार बिल्कुल भिन्न प्रकार की सामाजिक परम्पराओं और विचार-शैलियों पर है। किसी देश की संस्थाओं की केवल बनावट देखने से यह पता नहीं चल सकता कि वहाँ की राजनीतिक प्रणाली का सच्चा स्वरूप क्या है? इसके लिए तो

यह देखना पड़ेगा कि वास्तव में वे संस्थायें किस प्रकार काम करती हैं।

लेकिन फिर भी इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जापानी प्रणाली बहुत सी बातों में पाश्चात्य प्रणालियों की नकल है। सन् १८६७ के प्रसिद्ध “पुनरुद्धार” के उपरान्त पाश्चात्य राजनीतिक संस्थाओं का भी ठीक उसी प्रकार अनुकरण किया गया था, जिस प्रकार उसने पाश्चात्य शिल्प और उद्योग-धन्धों, पाश्चात्य महाजनी या बैंकिंग, पाश्चात्य विज्ञान और पाश्चात्य अस्त्र-शस्त्रों का अनुकरण किया था। लेकिन शिल्प, महाजनी, विज्ञान और अस्त्र-शस्त्र आदि ऐसी बातें हैं जिनमें पाश्चात्य उपायों का अवलम्बन बिना उन्हींकी तरह काम किये हो ही नहीं सकता; और इन सब बातों में वह बिल्कुल पाश्चात्य देशों के ही रास्ते पर चलता है। लेकिन जापान की पार्लमेण्टरी शासन-प्रणाली सदा केवल नाम के लिए ही पार्लमेण्टरी रही है; और वास्तव में न तो वहाँ कभी आज तक उत्तरदायी पार्लमेण्टरी सरकार स्थापित हुई ही है और न इस समय ही है।

पार्लमेण्ट और स-शस्त्र शक्तियाँ—जापानी पार्लमेण्टरी शासन-प्रणाली की इस दुर्बलता का कारण केवल यही नहीं है कि संघटन-विधान के अनुसार पार्लमेण्टरी नेताओं को जो अधिकार मिले हैं, उनका वे ठीक तरह से उपयोग नहीं करते; बल्कि इसका कारण यह है कि ठीक तरह से पार्लमेण्टरी सरकार चलाने के लिए जिन अधिकारों की आवश्यकता होती है, वे जान-बूझकर पार्लमेण्टरी नेताओं के हाथ में नहीं जाने दिये जाते। जापान में ऐसा मन्त्री-मंडल और पार्लमेण्ट तो जरूर है जो सालाना बजट पास करती है, पर वास्तव में मन्त्री-मंडल पार्लमेण्ट के सामने उत्तरदायी नहीं है, बल्कि स्वयं सम्राट् के सामने उत्तरदायी है। और इसका मतलब यही है कि सारा बजट वही लोग मंजूर

करते हैं जो सदा सम्राट् के आस-पास रहते हैं। पार्लमैण्ट में जिस दल के सदस्यों का बहुमत होता है, प्रायः उसी दल के लोग मन्त्री बनाये जाते हैं। परन्तु यह बात उन मन्त्रियों के सम्बन्ध में नहीं है जिनके हाथ में युद्ध-विभाग रहते हैं; क्योंकि युद्ध विभाग पार्लमैण्ट के नियंत्रण में नहीं है, बल्कि स्वयं सम्राट् के अधिकार में है। युद्ध विभाग में जितने आदमी हैं, वे सब सम्राट् के सामने उत्तरदायी हैं और वे लोग अपने खर्च के लिए अपनी माँगें पेश करते हैं और मन्त्री-मंडल को वे माँगें हर हालत में मंजूर करनी पड़ती हैं। फिर अधिकारारूढ़ दल के मन्त्री-मंडल में जल और स्थल सेना विभाग के ऐसे मन्त्री भी जबरदस्ती रखे जा सकते हैं, जिन्हें दल के मन्त्री बिलकुल ना-पसन्द करते हों या जिनकी नीति से वे तनिक भी सहमत न हों। पार्लमैण्टरी-नियंत्रण का खास मतलब यही समझा जाता है कि राज्य की “थैली” पर पार्लमैण्ट का अधिकार हो और जापान की थैली पर वहाँ की पार्लमैण्ट का अधिकार शायद सिवा मज्जाक के और कुछ भी नहीं है। सेना विभाग को तो जाने दीजिए, स्वयं सिविल सर्विस के सम्बन्ध में भी पार्लमैण्ट को इस तरह का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, उसे इतना अधिकार जरूर है कि जो बजट उसके सामने पेश किया जाय, उसे वह मंजूर करने से इन्कार कर दे। लेकिन उसके इस इन्कार का भी कोई खास मतलब नहीं निकल सकता। पार्लमैण्टरी देशों में कायदा यह होता है कि जब पार्लमैण्ट बजट नामंजूर कर देती है, तब सब विभागों के खर्च भी बन्द हो जाते हैं। लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। वहाँ यह नियम है कि यदि पार्लमैण्ट किसी साल बजट ना-मंजूर कर दे तो पिछले साल का पास किया हुआ बजट ही बराबर तब-तक काम देता रहता है, जब-तक नया बजट मंजूर न हो। इसका मतलब यह है कि अगर पार्लमैण्ट पुराने कगो को नामंजूर करना

चाहे तो भी वे कर बराबर लगे ही रहते हैं और उनकी वसूली होती चलती है। फिर कोई ऐसा बन्धन भी नहीं है जो घाटे के दिनों में सम्राट् को ऋण लेने से रोक सके; इसलिए सेना-विभाग सदा हाथ में डंडा लिये पार्लमैण्ट के सिर पर भी और नागरिक-मन्त्रियों के सिर पर भी सवार रहता है। सेना-विभाग के प्रधान सदा यही कहते हैं कि हमें स्वतन्त्र रूप से सब काम करने का पूरा अधिकार है; और वे प्रायः मन्त्रियों के विचारों और सिद्धान्तों के विरुद्ध भी अपनी नीति के अनुसार सब काम बराबर मजे में करते रहते हैं। अभी कुछ ही वरस पहले जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण करके वहाँ मंचुको का नया राज्य स्थापित किया था और वहाँ नाम-मात्र का एक सम्राट् सिंहासन पर बैठा दिया था। सेना-विभाग ने यह आक्रमण बिना मंत्री-मंडल से पूछे ही कर दिया था।

जापान की राजनीतिक परिस्थिति में खास बात यही है कि वहाँ के सभी युद्ध-विभाग बिल्कुल स्वतन्त्र हैं। इधर कुछ दिनों से जापान की सार्वराष्ट्रीय नीति वहाँ का प्रधान-मन्त्री या पर-राष्ट्र मन्त्री नहीं स्थिर करता, बल्कि वह युद्ध-मन्त्री करता है जो सेना विभाग का एक बड़ा अधिकारी है। पहले यहाँ जनरल अराकी युद्ध-मन्त्री के पद पर था। पर जब बीमार होने के कारण उसे इस्तीफा देना पड़ा, तब उसने बतला दिया कि मेरे स्थान पर कौन व्यक्ति युद्ध-विभाग का मन्त्री बनाया जाय; और वही व्यक्ति युद्ध-मन्त्री बनाया भी गया। इस प्रकार युद्ध-विभाग के मन्त्री पर मन्त्री-मंडल का कोई नियन्त्रण नहीं होता। यदि उस पर कोई नियंत्रण है तो वह एक ऐसे सरदार का है जिसका जापान के संघटन-विधान में कहीं नाम तक नहीं है। यह वृद्ध राजनीतिज्ञ कहलाता है जो आज-कल प्रिन्स सैओन्जी है। पहले वहाँ कई वृद्ध राजनीतिज्ञ हुआ करते थे। बहुत दिनों से वहाँ जो प्रथा

चली आ रही है, उसके अनुसार सम्राट् के लिए यह आवश्यक होता था कि सभी महत्त्वपूर्ण विषयों में, उनसे परामर्श ले लिया करे; और बहुधा उसी परामर्श के अनुसार सब काम होते थे। लेकिन अब तो उन वृद्ध राजनीतिज्ञों में से एक मात्र प्रिन्स सैओन्जी ही बच रहा है और वह भी अब सचमुच बहुत वृद्ध हो गया है। वह सेना-विभाग के कार्यों पर बहुत कुछ नियंत्रण रखता है और उन्हें उग्र रूप नहीं धारण करने देता। यदि वह न होता तो बहुत सम्भव था कि जापान की सैनिक नीति अब-तक बहुत उग्र रूप धारण कर लेती। कहा जाता है कि बहुत कुछ उसी के जोर देने पर कुछ दिनों तक जापान राष्ट्र-संघ का सदस्य बना रहा था। अभी कुछ दिन पहले सेना-विभाग के नेताओं ने यह माँग पेश की थी कि पार्लमेण्ट में मंत्री-मंडल के स्थान पर सरकारी अफसरों का एक ऐसा मंत्री-मंडल रखा जाय जिस का किसी राजनीतिक दल से कोई सम्बन्ध न हो; और जो सेना-विभाग की सब माँगों का बराबर समर्थन करता रहे। लेकिन प्रिन्स सैओन्जी के विरोध के कारण ही उस समय उनकी वह माँग पूरी नहीं हो सकी थी। सेना-विभाग के अधिकारी चाहते थे कि इस समय नाम के लिए जो प्रतिनिधिसत्तात्मक शासन प्रणाली है, उसका भी अन्त कर दिया जाय और ठीक उसी तरह की फ़ैसिस्ट शासन-प्रणाली स्थापित की जाय जिस तरह की यूरोप के कई देशों में है। डेढ़-दो साल पहले ही उन्होंने अपना यह विचार बहुत से अंशों में पूरा भी कर लिया था। और जुलाई १९४० में तो वहाँ पूरी-पूरी फ़ैसिस्ट शासन-प्रणाली प्रचलित हो ही गई है।

पुनरुद्धार और उसके बाद—जापान की राजनीतिक अवस्थायें तब तक अच्छी तरह समझ में नहीं आ सकती, जब तक यह न जान लिया जाय कि सन् १८६७ में वहाँ जो प्रसिद्ध पुनरुद्धार हुआ था, उसका स्वरूप क्या था और उसमें क्या-क्या

बाते हुई थीं। वास्तव में इसी पुनरुद्धार के समय से ही जापान का अभ्युदय आरम्भ हुआ था और तभी से उसकी गिनती महाशक्तियों में होने लगी थी। यह बात प्रायः सभी लोग जानते हैं कि पिछली शताब्दी के मध्य तक जापान एक सामंती राज्य (Feudal State) था, जिसमें सारा अधिकार बड़े-बड़े सामंतों और जागीरदारों के हाथ में था। उस समय वहाँ कुछ ऐसे नियम थे कि कोई विदेशी वहाँ पहुँचने ही नहीं पाता था और बाहरी जगत के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं था। वहाँ बराबर इसी बात का प्रयत्न किया जाता था कि देश पर किसी प्रकार का विदेशी प्रभाव न पड़ने पावे। लेकिन जब अमेरिका के नौ-सेना विभाग के सेनापति पेरी ने जापानी तटों पर पहुँचकर गोले-बारी की और जापानियों को यह बतलाया कि पाश्चात्य सभ्यता बहुत सी बातों में तुम्हारी सभ्यता से बहुत बढ़कर है, तब जापानियों को विवश होकर अपने बन्दरगाह सारे संसार के लिए खोल देने पड़े और अपनी पुरानी एकान्ततावाली नीति का परित्याग करना पड़ा। फिर इसके बाद भी कई और घटनाएँ हुईं, जिनसे जापानियों को अच्छी शिक्षा मिली। जापानी लोग प्रायः विदेशी नाविकों पर आक्रमण कर बैठते थे और इसलिए ब्रिटिश जहाजों ने भी कई बार जापानी तटों पर गोला-बारी की थी। इन सब बातों से जापानियों ने अच्छी तरह समझ लिया था कि पाश्चात्य देशों का मुकाबला करने के लिये हमें भी उन्हीं की तरकीबों से काम लेना चाहिए। फिर जिस तेजी के साथ और जिस पूरी तरह से उन्होंने अपना जीवन पाश्चात्य सौँचे में ढाला, वह सचमुच आश्चर्यजनक है। सब से पहले तो वहाँ एक राजनीतिक क्रांति हुई, जिसका उद्देश्य यह था कि सम्राट् के हाथ से जो राजनीतिक अधिकार निकल कर जागीरदारों और मन्सबदारों या सामंतों के हाथ में चले गये हैं, वे उसे फिर से प्राप्त हों।

१८६७ से सैकड़ों बरस पहले से धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों में सम्राट् ही सर्व-प्रधान अधिकारी माना जाता था। पर बाद में उसके हाथ से सारा राजनीतिक अधिकार निकलकर एक ऐसे वंशानुक्रमिक अधिकारी के हाथ में चला गया था जो शोगुन कहलाता था। इस शोगुन का एक अलग दरबार होता था, जिसमें आकर जागीरदार और मन्सबदार मुजरा करते थे। स्वयं शोगुन भी एक बहुत बड़ा मन्सबदार था और देश का एक बहुत बड़ा भाग प्रत्यक्ष रूप से उसके शासन और नियंत्रण में था। देश का बाकी अंश दूसरे बड़े-बड़े जागीरदारों और मन्सबदारों के हाथ में था। तात्पर्य यह कि वहाँ भी बहुत कुछ उसी प्रकार की व्यवस्था थी, जिस प्रकार की व्यवस्था मध्य युग में यूरोप में थी। परन्तु सन् १८६७ में बहुत बड़ा आन्दोलन होने पर अन्तिम शोगुन को अपने अधिकार छोड़ देने पड़े और वे सब अधिकार फिर से सम्राट् के हाथ में चले गये। इस आन्दोलन का एक उद्देश्य यह भी था कि जापान बिल्कुल आधुनिक ढंग का राज्य हो जाय और यूरोप के देशों की तरह वहाँ भी शिल्प और उद्योग-धन्धे और अस्त्र-शस्त्र हो और यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान का वहाँ भी प्रचार हो।

यहाँ कदाचित् यह बतलाने की आवश्यकता न होगी कि इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए जापान में जो आन्दोलन हुआ था, उसमें क्या-क्या बातें हुई थीं और उसने कब कैसा रूप धारण किया था। शोगुन के अधिकार में जितनी जागीरें थीं, वे सब सरकार के हाथ में आ गईं ! फिर थोड़े ही दिन बाद और सब जागीरदारों ने भी अपनी सब जागीरें और सब अधिकार सम्राट् को अर्पित कर दिये। देश के कुछ भागों में थोड़े से जागीरदारों ने इस नई व्यवस्था के विरुद्ध जो विद्रोह किया था, वह भी पूरी तरह से दबा दिया गया। सभी बड़े-बड़े जागीरदारों के यहाँ कुछ

बड़े-बड़े योद्धा रहते थे जो समूराई कहलाते थे। इन्हीं समूराइयो के योग से वहाँ एक नौकरशाही बन गई जिससे जापान ने एक ऐसे राज्य का रूप धारण किया, जिसमें सारा नियन्त्रण एक केन्द्रित सरकार के हाथ में आ गया। पुराने सरदारों और समूराइयो को कुछ खास अस्त्रियार होते थे और उनके साथ कुछ खास रिआयतें की जाती थी। लेकिन उन लोगों ने भी अपनी वे रिआयतें और वे अधिकार छोड़ दिये जिसके बदले में उन सब लोगों को पेन्शन देना निश्चित हुआ था। लेकिन इन पेन्शनो के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत होती थी जिससे नये राज्य को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इसलिए सरकार को दूसरे देशों से ऋण लेकर ये पेन्शन देनी पड़ती थी। आरम्भ में वहाँ का संघटन मुख्यतः गणतन्त्री था। वहाँ बड़े-बड़े सरदार ही मन्त्रियों के पद पर नियुक्त होते थे, जिनकी सहायता के लिए काउन्सिले भी होती थीं; पर उन काउन्सिलों के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते थे, बल्कि सम्राट् और दूसरे बड़े अधिकारियों के नियुक्त किये हुए होते थे। फिर इन काउन्सिलो का स्वरूप भी प्रायः बदल दिया जाता था। इसके बाद सन् १८८६ में वहाँ एक नया संघटन-विधान बना जिसका स्वरूप कुछ-कुछ पार्लमैण्टरी था, पर जो वास्तव में विस्मार्क के जर्मनी के अनुकरण पर था। यही संघटन-विधान वहाँ अबतक चल रहा है। सन् १९२५ में उसमें सिर्फ एक सुधार हुआ था जिसके अनुसार अब वहाँ के सभी वयस्क पुरुषों को मत देने का अधिकार मिल गया है।

हम ऊपर कह आये हैं कि समूराई लोग जागीरदारों के साथ रहनेवाले योद्धा होते थे। यदि उनकी हैसियत केवल इतनी ही होती तो आधुनिक जापान का स्वरूप कुछ और ही होता।

जिस समय समूराइयों ने अपने अधिकारों और सुभीतों का परित्याग करके देश को पश्चिमी साँचे में ढालने का काम शुरू किया था, उस समय उनका वह पुराना वर्ग या जाति ज्यों-की-त्यों रह गई थी; और उसके साथ ही उनका वह आचार-विचार भी लगा रह गया था, जिसकी शिक्षा उन्हें बाल्यावस्था से ही मिली थी। उनका यह आचार-शास्त्र जुशीदो कहलाता है। संक्षेप में यह बतलाना प्रायः असम्भव ही है कि जुशीदो क्या है और उसमें कौन-कौन सी बातें हैं। यह एक प्रकार का नैतिक विधान है जो योद्धाओं का ही बनाया हुआ है और उन्हीं के वर्ग या जाति के लिए है। इसमें वे गुण सबसे अधिक श्रेष्ठ बतलाये गये हैं जो योद्धाओं या क्षत्रियों में होते हैं, अथवा होने चाहिएँ। इस विधान के अनुसार वे लोग कुछ धृष्टा की दृष्टि से देखे जाते हैं जो व्यापार आदि करते हैं। इसमें राज्य के हितों के प्रति आदर्श श्रद्धा और भक्ति रखना आवश्यक होता है। पुनरुद्धार के समय से राज्य के सब अधिकार सम्राट् के हाथ में चले गये हैं, इसलिए वह सारी आदर्श श्रद्धा और भक्ति सम्राट् के प्रति ही रक्खी जाती है। एक और विशेषता यह है कि यद्यपि इन समूराइयों ने देश की सभी सामाजिक बातें पूरी तरह से बदल दी हैं और उन्हें बिलकुल नया स्वरूप दिया है, परन्तु फिर भी अपने वर्ग या जाति की सब बातें इन लोगों ने बिलकुल ज्यों-की-त्यों रक्खी हैं और उनमें कहीं कोई परिवर्तन या सुधार नहीं होने दिया है। अनिवार्य रूप से इसका परिणाम यही होता है कि राज्य की जितनी योद्धा-शक्तियाँ हैं, वे सब समूराइयों के ही अधिकार में हैं। इसके सिवा शिल्प और व्यापार के साथ तो उनका कोई सम्बन्ध है ही नहीं, सारा सम्बन्ध सिर्फ जमीन के साथ है; इसलिए वे सदा बड़े-बड़े पूँजीदारों को छोड़कर गरीब किसानों का ही पक्ष लेते हैं। यही कारण है कि जब कृषि और कृषकों से

सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्न उठते हैं, तब जापान के जल और स्थल-सेना के नेता अपनी विकट सैनिक प्रवृत्ति का ही प्रदर्शन करते हैं और अपने यहाँ की पुरानी सामाजिक व्यवस्था को बदलना नहीं चाहते। समूराई अफसर और कृपको के नेता सदा फैसिस्ट आन्दोलनों का ही साथ देते हैं और मौका मिलने पर सैनिक अफसर बड़े-बड़े महाजनो और रोजगारियों की हत्या कर डालते हैं और कल-कारखानों के मजदूरों के आन्दोलन हर तरह से दबा देते हैं। और इन सब बातों का सारा रहस्य यही है कि सारा अधिकार वास्तव में समूराइयो के ही हाथ में है।

जापानी संघटन—जापान में दो हाउसों की एक पार्लमैण्ट है। ऊपरी या बड़े हाउस में चार तरह के लोग हैं। पहले तो वे बड़े-बड़े सरदार हैं जिन्हें हाउस में बैठने का जन्म-सिद्ध अधिकार प्राप्त है और जो उसके आजीवन सदस्य होते हैं। दूसरे, कुछ ऐसे पुश्तैनी सरदार और रईस हैं जो छोटे-बड़े बहुत से सरदारों और रईसों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। तीसरे, सम्राट् के नियुक्त किये हुए कुछ ऐसे आदमी होते हैं जो राज्य की बहुत अच्छी और बड़ी-बड़ी सेवाएँ करते हैं या कर चुके होते हैं। और चौथे वर्ग में प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र के सबसे अधिक कर देनेवाले पंद्रह अमीरों का चुना हुआ एक प्रतिनिधि होता है। महायुद्ध से पहले प्रशिया में इस प्रकार की निर्वाचन की प्रथा थी और वहीं से जापान ने भी सीधे यह प्रथा ली है। दूसरे या नीचेवाले हाउस में सन् १९२५ तक कुछ ऐसे ही लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि लिये जाते थे, जिनके पास कुछ सम्पत्ति होती थी। परन्तु सन् १९२५ से वहाँ के सभी वयस्क पुरुषों को निर्वाचन में मत देने का अधिकार मिल गया है और उन लोगों का चुनाव गोटी डालकर होता है। यह प्रणाली अब जापान में इसलिये ठीक तरह से काम करती है कि राज्य की ओर से सब लोगों

को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाती है, जिससे देश में अशिक्षित लोग रह ही नहीं गये हैं। मंत्री-मण्डल का चुनाव प्रायः इस बात का ध्यान रखकर किया जाता है कि नीचेवाले हाउस में बहुमत उसके पक्ष में रहे। लेकिन सम्राट् जब चाहे, तब मंत्री-मंडल को तोड़ सकता है और छोटे हाउस को भी भंग कर सकता है। और कार्य रूप में प्रायः यह भी देखने में आता है कि सम्राट् जिस दल के लोगो को मंत्री-मंडल बनाने के लिए बुलाता है, और दलो के मुकाबले में उस दल का बहुमत भी हो जाता है। ऊपरी या बड़ा हाउस कभी भंग नहीं किया जा सकता, और उसमें जितनी जगह निर्वाचन से भरी जाती है, उन जगहों के लिए हर सातवें वर्ष चुनाव होता है। जिन सरदारों को उसमें बैठने का जन्म-सिद्ध अधिकार है, वे तो उसके आजीवन सदस्य होते ही हैं। इसके सिवा जिन्हे सम्राट् अपनी ओर से नियुक्त करता है, वे भी आजीवन सदस्य होते हैं। सभी तरह के कानूनी मसौदों के लिए यह आवश्यक है कि वे दोनों हाउसों में स्वीकृत हो और अन्त में उन्हें सम्राट् की स्वीकृति भी प्राप्त हो। लेकिन वजह पर छोटे हाउस में ही विचार होता है। इस छोटे हाउस की अवधि चार वर्ष होती है, परंतु कभी-कभी वह बीच में ही भंग कर दिया जाता है।

जैसा कि हम ऊपर बतला चुके हैं, ये सब पार्लमैण्टरी यंत्र बहुत कुछ दिखावटी ही हैं। ऊपर से देखने में इनका स्वरूप तो बहुत भव्य है, परंतु वास्तव में इनके हाथ में कोई विशेष अधिकार नहीं है। जितने सैनिक-विभाग हैं, उन सब पर पार्लमैण्ट का कोई नियंत्रण नहीं है, और न आमदनी और खर्च ही उसके हाथ में है। फिर जापान में जो प्रतियोगी राजनीतिक दल हैं, उनमें भी नीति या सिद्धान्त सम्बन्धी कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं होता। इधर हाल के दलो में दो दल

प्रधान थे जिनमे से एक सेयूकाई कहलाता है और दूसरा मिन्सेइटो^१ लेकिन इन दलों की भी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि इनके अंदर भी बहुत पोल थी और तरह-तरह की खराबियाँ थीं। भिन्न-भिन्न आर्थिक हितों के साथ भी इनका घनिष्ठ सम्बन्ध था और प्रायः इन्हीं बातों के लिए इनमें प्रतियोगिता चलती रहती थी। राजनीतिक सिद्धांतों के सम्बन्ध में इनके झगड़े बहुत ही कम होते थे। साधारणतः सेयूकाई दल के सम्बन्ध में यह माना जाता था कि वह राजनीतिक क्षेत्र में कृपकों के हितों की रक्षा करनेवाला प्रतिनिधि दल है। इसके सिवा मित्सुई कम्पाइन नाम की एक बहुत बड़ी ऐसी व्यापारिक कम्पनी के साथ भी उसका सम्बन्ध था जो महाजनी या बैंकिंग का भी बहुत बड़ा काम करती है और प्रायः सभी प्रकार के मुख्य-मुख्य शिल्पो और व्यापारों में भी जिसका बहुत-कुछ हाथ रहता है। और इन सबसे बढ़कर सेयूकाई दल का सम्बन्ध देश के भीतरी व्यापार और अस्त्र-शस्त्र बनानेवाले कारखानों के साथ था। परन्तु मिन्सेइटो दल का सम्बन्ध अधिकतर ऐसे व्यापारियों के साथ था, जो माल तैयार करके विदेशों में बेचने के लिए भेजते हैं; और यही कारण है कि यह दल प्रायः इसी बात पर जोर देता था कि पर-राष्ट्रीय नीति का स्वरूप ऐसा रक्खा जाय जिसमें दूसरे देश नाराज न होने पावे। लेकिन अस्त्र-शस्त्र बनानेवाले कारखानों के साथ इसका भी घनिष्ठ सम्बन्ध था। अगर सेयूकाई दल मित्सुई कम्पाइन नामक कम्पनी का आश्रित है, तो मिन्सेइटो दल उसकी प्रतिद्वन्द्विनी

^१पर देश में फैसिस्ट शासन-प्रणाली प्रचलित हो जाने पर अगस्त १९४० में इस दल ने भी अपनी बैठक करके उसमें अपने आपको भंग कर डाला है। दूसरा दल अभी मौजूद है और वह शासक दल के साथ है। रा० च० वर्मा।

मित्सुबिशी नाम की कम्पनी पर निर्भर रहता था; और मित्सुबिशी कम्पनी के हाथ में भी अस्त्र-शस्त्र बनाने के बहुत बड़े-बड़े कारखाने हैं। इसके सिवा इंजीनियरिंग, जहाज बनाने और कोयले, फौलाद तथा बिजली के सामान बनाने और लड़ाई के जहाज तैयार करने के बहुत से काम भी उसके हाथ में हैं। इसलिए इनमें से हर एक दल प्रायः इसी बात का प्रयत्न करता रहता था कि बड़े-बड़े ठेके और काम उसी कम्पनी को मिले, जिस पर हमारा भाग्य निर्भर रहता है। और इन्हीं सब बातों के कारण प्रायः ऐसा भंडा-फोड़ होता रहता था, जिससे इन दलों की भी बढ़नामी होती रहती थी और उन कम्पनियों की भी, जिनके साथ इनका सम्बन्ध था।

इन दोनों ही मुख्य दलों का सम्बन्ध अस्त्र-शस्त्र बनानेवाले कारखानों से था, और इसी लिए सैनिक नेता प्रायः इन दोनों दलों से बिल्कुल अलग रहते थे और इस प्रकार राज्य में उनका एक ऐसा तीसरा दल बन गया था जो सबसे अधिक प्रबल था। जापानी सैनिक नेताओं और उनके दल के सम्बन्ध में एक मुख्य और महत्व की बात यह है कि वे पूँजीदारों के प्रायः बहुत विरोधी रहते हैं। जापान की पुरानी सामाजिक व्यवस्था में योद्धाओं या क्षत्रियों का स्थान सबसे ऊँचा माना जाता था। वहाँ दूसरे दरजे में किसान और कारीगर माने जाते थे और व्यापारियों का स्थान सबसे नीचा समझा जाता था। सैनिक वर्ग के लोगों में यह भाव अभी तक बहुत प्रबल है। यद्यपि सारे देश में शिल्प और उद्योग-धन्धों का बहुत अधिक विकास और विस्तार हो चुका है, लेकिन फिर भी योद्धाओं के मन में उनके प्रति जो पुराना घृणा का भाव था, वह अभी तक कम नहीं हुआ है। और बहुत से राष्ट्रों की अपेक्षा जापानियों को अपने राज्य का बहुत अधिक अभिमान है, और उनका यह अभिमान सबसे

बढ़कर इस रूप में प्रकट होता है कि उनमें सैनिकों के प्रति असीम श्रद्धा और भक्ति होती है। जैसा कि हम ऊपर बतला चुके हैं, पुरानी योद्धा जाति समूराइयों के लोग, जिनका अभी तक देश पर पूरा-पूरा प्रभुत्व है, व्यापारियों और महाजनों को उसी प्रकार तुच्छ समझते हैं, जिस प्रकार उनके पूर्वज समझा करते थे। और उनका यही भाव राजनीतिज्ञों के सम्बन्ध में भी है जिन्हें वे व्यापारियों और महाजनों के हाथ की कठ-पुतली समझते हैं। एक तो इसी कारण से और दूसरे इसलिए भी कि बहुत से समूराई बहुत दरिद्र हैं, वे चरम सीमा के सैनिकवादी किसानों के साथ साधारणतः बहुत अधिक सहानुभूति रखते हैं और पूँजीदारों तथा राजनीतिज्ञों के साथ उनकी बहुत ही कम सहानुभूति होती है। इसके सिवा कल-कारखानों में काम करने वाले उन मजदूरों के साथ भी उनकी थोड़ी-बहुत सहानुभूति होती है जो साम्यवादी विचारों के प्रभाव से दूर रहते हैं। पहले इनमें से कुछ लोग साम्यवादी सिद्धान्तों के भी कुछ समर्थक थे। परन्तु अब वे लोग भी सैनिकतावादियों के साथ मिल गये हैं और पुराने पार्लमैण्टरी दलों के मुकाबले में उन्होंने अपना एक फैसिस्ट दल भी बना लिया है और आज-कल इसी दल ने वहाँ की सरकार अपने हाथ में कर रखी है। वहाँ जो साम्यवादी प्रतिनिधिसत्तावादी दल था, वह जब सन् १९३२ में टूट गया, तब उसके प्रायः आधे सदस्य जाकर उस नये राष्ट्रीय साम्यवादी दल में मिल गये जिसका कार्यक्रम बहुत कुछ फैसिस्टों के ढङ्ग का था।

जापान में इधर कुछ दिनों में जो राजनीतिक विकास हुए हैं, उनमें सबसे अधिक महत्त्व की बात यह है कि वहाँ राजनीतिक दल दिन-पर-दिन बढ़ते जाते थे और प्रायः लोग एक दल छोड़-कर दूसरे दल में मिलते रहते थे। अभी चार-पाँच बरस पहले

की बात है कि वहाँ की पार्लमैण्ट के मिन्सेटो दल में मतभेद हो गया। उस समय इस दल के १४६ सदस्य थे। उनमें से एडाची नाम के एक नेता ने प्रायः तीस सदस्यों को अपने साथ लेकर एक नया फ़ैसिस्ट दल खड़ा कर लिया जो वहाँ की भाषा में कोकमिन डोमेई कहलाता है। अब यह दल कहता था कि जापान में भी फ़ैसिस्ट ढंग का वैसा ही राज्य होना चाहिए, जिसमें देश भर में केवल एक ही दल हो। उधर दक्षिण पक्ष में रईसों और सरदारों का कोकूहोन्सका नाम का एक और दल था जिसका नेता हिरानुमा था। इसके सिवा वहाँ सेइसान्तो नाम का एक और दल था, जिसका मतलब होता है—“पैदावार करनेवाला दल”; और यह दल भी फ़ैसिस्ट कहा जाता था। यह दल इस दृष्टि से और भी विलक्षण था कि इसमें अधिकतर वही लोग थे जो पहले कम्युनिस्ट दल में थे। यह दल कट्टर सैनिकतावादी था और इसका यह विश्वास था कि केवल जापान ही सुदूर पूर्व को पाश्चात्य शक्तियों के चंगुल से छुड़ा सकता है। यह सदा सैनिक नेताओं के साथ मिलकर ही काम करता था। इसके सिवा वहाँ इसे जाइगो गनजिनकाई नाम की उस संस्था से भी बहुत सहायता मिलती थी, जिसमें अधिकतर वही नागरिक थे जो सैनिक शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और आवश्यकता होते ही तुरन्त सेना में भरती हो सकते थे। लेकिन इसकी आर्थिक नीति विलकुल वही थी जो वाम पक्ष के दलों की होती है; बल्कि शायद उनसे भी कुछ बढ़ कर थी। यह दल कहता था कि देश में जितने शिल्प और उद्योग-धन्धे हैं, उन सब की व्यवस्था सम्राट् स्वयं ही साम्यवाद के सिद्धान्तों पर करे, क्योंकि सम्राट् पर यह दल पूरी-पूरी निष्ठा और भक्ति रखता था। यह दल यह भी कहता था कि सन् १८६८ में पुनरुद्धार के बाद सम्राट् ने जागीरदारों और मन्सबदारों से जो सब अधिकार ले लिये थे, उसका तर्क-संगत परिणाम

यही होना चाहिए कि देश के सब काम साम्यवाद की नीति और सिद्धान्तों के अनुसार ही हो। जापान में सारे एशिया को एक में मिलाकर जो एक राजनीतिक संघटन करने का आन्दोलन चल रहा है, उसका भी यह बहुत बड़ा पक्षपाती था।

इधर कुछ वर्षों में साम्यवाद भी जापान में बहुत से ऊँच-नीच देख चुका है। महायुद्ध के बाद जापान में और विशेषतः वहाँ के पढ़े-लिखे और समझदारों में साम्यवाद की एक खासी लहर उठी थी और सन् १९२२ के बाद वहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलन ने बहुत जोर पकड़ा था। लेकिन सन् १९२८ के बाद से कम्युनिस्ट दल का दमन होने लगा और उसके प्रायः तीस हजार सदस्य गिरफ्तार कर लिये गये। यह दल अब भी वहाँ है, लेकिन खुलकर नहीं, बल्कि अन्दर-ही अन्दर, अपना काम करता है। इधर इसके बहुत से अनुयायी सेईसान्तो दल में मिल गये थे। वहाँ जो सनातनी ढंग का साम्यवादी दल है और जो शाकाई जाइशुटो कहलाता है, उसका अभी तक दमन नहीं हुआ था और उसके कुछ सदस्य पार्लमैण्ट में भी थे। इसके सिवा वाम पक्ष में कृषकों का भी एक दल था, जो रोमोटो कहलाता था। लेकिन अब इसका भी उसी प्रकार दमन कर दिया गया था, जिस प्रकार कम्युनिस्ट दल का दमन किया गया था। लेकिन अब भी शायद इस दल के कुछ लोग अन्दर ही अन्दर काम कर रहे थे, क्योंकि यह भी गैर-कानूनी ठहरा दिया गया गया था।

जापानी किसान और कमकर—जापान में कृषकों की समस्या बहुत महत्त्व की है। जापान पहाड़ी देश है और उसका बहुत बड़ा अंश ऐसा ही है जिसमें खेती-बारी नहीं हो सकती। जिन भागों में खेती-बारी हो सकती है, वे भाग बहुत ही घने बसे हुए हैं। फिर वहाँ कहीं तो बहुत ज्यादा गरमी पड़ती है और कहीं बहुत ज्यादा सर्दी होती है। जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती

है, वहाँ बस्ती भी कम है। वहाँ कुछ और लोग जाकर बस जरूर सकते हैं। लेकिन गरम जगहों में रहनेवाले लोगो के लिए ठढी जगहों में जाकर रहना बहुत मुश्किल होता है। जापान ने अभी हाल में मंचूरिया पर अधिकार कर लिया है और कुछ दूसरे स्थान भी अपने अधिकार में कर लिये हैं। परन्तु इसी लिए जापानी लोग उन देशों में भी जाकर नहीं बस सकते। इसके सिवा दूसरे देशों में जापानियों के जाकर बसने में एक और कठिनता है। जिन देशों के लोग जापानियों की अपेक्षा बहुत ही थोड़े खर्च में अपना काम चला लेते हैं, उन देशों में जापानी इसलिए जाकर नहीं बस सकते कि वे वहाँ के मूल निवासियों के मुकाबले में कम खर्च में गुजर नहीं कर सकते। इन्हीं सब बातों का परिणाम यह है कि जापान के मध्यवाले प्रदेशों में तो बस्ती बहुत गुंजान हो गई है और वहाँ किसानों के पास इतनी थोड़ी जमीन है कि उसकी पैदावार से उनका किसी तरह गुजारा ही नहीं हो सकता। वहाँ की खास पैदावार चावल है। परन्तु देश के कुछ भागों में गेहूँ और कुछ दूसरे अनाज भी होते हैं।

जापानी कृषकों की अवस्था सुधारने के लिए इधर कुछ दिनों से इस बात पर बहुत जोर दिया जाता है कि वे कच्चा रेशम पैदा करें जो अमेरिकन संयुक्त राज्यों में बहुत अधिक मात्रा में भेजा जाता है। लेकिन जब से व्यापार मन्दा पड़ा, तब से अमेरिका में रेशम और रेशमी माल की माँग बहुत ही कम हो गई, जिससे जापानी कृषक और भी संकट में पड़ गये। इससे कृषकों में बहुत अधिक असन्तोष भी फैल गया। इस असन्तोष की वृद्धि में उन्हें सैनिक नेताओं से भी कुछ सहायता मिलती थी। उधर जो दो मुख्य राजनीतिक दल थे और जिनका सम्बन्ध बड़े-बड़े व्यापारियों और पूँजीदारों से था, वे कृषकों के इन कष्टों से बहुत कुछ लाभ उठाते थे। इससे उन्हें कारखानों

में काम करने के लिए बहुत सस्ते मजदूर मिल जाते थे और इसी लिए वे दूसरे देशों के मुकाबिले में खूब सस्ता माल तैयार करके बाजार भर रहे थे। वहाँ की सरकार ने जापानी सिक्कों की दर जान-बूझकर घटा दी थी और देश के अन्दर चीजों की दर बहुत बढ़ा है। इन सब बातों के कारण कृषकों की कठिनाइयाँ और भी बढ़ गई थी और उनका असन्तोष भी बढ़ता जाता था। कारखानेदारों का इससे यह लाभ होता था कि उन्हें बहुत किरायेत में काम करने के लिए मजदूर मिल जाते थे। खासकर लड़कियाँ तो वहाँ और भी किरायेत में मिलती हैं। गरीब किसान बहुत ही थोड़ा धन लेकर अपनी लड़कियों कारखानों में काम करने के लिए भेज देते हैं, जहाँ उन्हें ठेके के तौर पर कई-कई वर्ष तक काम करना पड़ता है।

कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों में भी बहुत कुछ असन्तोष फैला हुआ है। कुछ स्थानों में तो मजदूरों को कम्युनिस्ट और साम्यवादी सिद्धान्त बहुत ही पसन्द आते हैं। लेकिन जापान में चरम सीमा के जितने आन्दोलन होते हैं, वे सब और विशेषतः वे आन्दोलन जिनका सम्बन्ध सार्वराष्ट्रीयता से होता है, बहुत कड़ाई के साथ दबाये जाते हैं। जापान में भी मजदूरों और कमकरो के संघ हैं जो बिल्कुल कुचल तो नहीं डाले गये हैं, लेकिन फिर भी जो बहुत कमजोर हैं। इसके सिवा उनमें आपस का भी बहुत कुछ मत-भेद चलता रहता है। उनमें कई दल हैं जिनके विचार और सिद्धान्त अलग-अलग हैं। यहाँ यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हिन्दोस्तान या चीन की बनिस्वत जापान में मजदूरी की दर कुछ ज्यादा है और मजदूरों तथा कमकरो के संघों की सुदूर पूर्व के और देशों की अपेक्षा जापान में इसलिए ज्यादा मजबूती से जड़ जमी हुई है कि वहाँ की सारी प्रजा पढ़ी-लिखी है।

जापानी फैसिस्टवाद—यह तो हम बतला ही चुके हैं कि जापान में जो दो मुख्य राजनीतिक दल थे, उनका कारखानेदारों और पूँजीदारों के दो विरोधी और प्रतियोगी वर्गों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था और वहाँ की योद्धा जाति से इन दोनों ही दलों का घोर विरोध था। इसके सिवा वहाँ का सैनिक व्यय दिन-पर-दिन बढ़ता जाता है और उसकी पूर्ति के लिए नये-नये करो की सम्भावना बनी ही रहती है। जिन लोगों के हाथ में राज्य का अधिकार है, उन्हें सदा यह भय भी बना रहता है कि कहीं पार्लमैण्ट हमारा बजट नामंजूर न कर दे। इसलिए जापान में बराबर एक तरह की खींचा-तानी और वैमनस्य चलता ही रहता है। शासकों की ओर से प्रायः कहा जाता है कि राजनीतिज्ञ लोग देश की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और वैभव का बहुत कम ध्यान रखते हैं; और जिन व्यापारियों के साथ उनका सम्बन्ध है, उन्हींको और अधिक सम्पन्न बनाने की ओर ही उनका सबसे अधिक ध्यान रहता है। सैनिक दल में जो नवयुवक अफसर और दूसरे पक्षपाती हैं, उनमें देश-हित का भाव बहुत ही प्रबल है। ऐसे लोगों ने अपनी गुप्त सभाये बना रखी हैं जिनके सदस्यों को इस बात की दृढ़ प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि राज्य के हित के लिए हम जो बात अच्छी समझेंगे, उसे पूरा करने में अपनी तरफ से कोई कसर न करेंगे। जिन बड़े-बड़े नेताओं की नीति इन्हें पसन्द नहीं है, उनकी अब ये लोग हत्यायें भी करने लगे हैं। जापान के जन-साधारण में से हारा ही ऐसा पहला व्यक्ति था, जो प्रधान मन्त्री के पद पर पहुँच सका था। यह सेयूकाई दल का नेता भी था। लेकिन सन् १९२१ में इसकी भी हत्या कर डाली गई थी। जापान में यमुदा बंक बहुत बड़ा समझा जाता है। उसके प्रेसिडेंट को भी इन लोगों ने उसी समय के लगभग मार डाला था। हामागुची नाम का एक और प्रधान मन्त्री सन् १९३० में

एक चरम राष्ट्रवादी के द्वारा सख्त धायल हुआ था। और सन् १९३२ में इनुकाई नाम के एक तीसरे मन्त्री को सामरिकता-वादियों ने मार डाला था। इस प्रकार सैनिक दल के पक्षपाती प्रायः बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों की हत्याये करते रहते हैं। अदालतों में इस तरह के हत्यारों के साथ यह कहकर बहुत रिआयत की जाती है और उन्हें बहुत हलका दंड दिया जाता है कि ये लोग देश-हित के भावों से प्रेरित होकर ये सब काम करते हैं। नौ-सेना विभाग के जिन अफसरों ने इनुकाई की हत्या की थी, उन्हें पहले तो अदालत से सजाएँ मिल गई थीं। लेकिन सैनिकतावाद के पक्षपातियों के प्रार्थना करने पर सम्राट् ने उन्हें बिलकुल क्षमा कर दिया था। और जब वे लोग जेलखाने से छूटकर आये थे, तब बाहर उनका बहुत अधिक सम्मान तथा अभ्यर्थना की गई थी।

यूरोप के अधिनायक-तन्त्री देशों में जो बहुत सी खास बातें हैं, वे सब बहुत से अंशों में जापान में भी पहले से ही मौजूद हैं। स्थानिक शासन वहाँ बहुत अधिक केन्द्रित है और थोड़े से ऐसे अफसरों के नियन्त्रण में है, जिन्हें केन्द्रीय अधिकारी नियुक्त करते हैं; और स्थानिक निर्वाचित काउन्सिलों का स्थानिक व्यवस्था पर बहुत ही कम नियन्त्रण रहता है। केन्द्रीय शासन-प्रणाली भी बिलकुल नौकर-शाही के हाथ में है; और सब काम थोड़े से बड़े-बड़े अधिकारियों की आज्ञा और इच्छा के अनुसार ही होते हैं। राष्ट्रीय जीवन के सभी अंगों पर उनका पूरा नियन्त्रण रहता है और खुलकर कोई इनकी अलोचना नहीं करने पाता। यदि किसी अच्छे पद पर कोई ऐसा आदमी होता है जो केन्द्रीय अधिकारियों की आँखों में खटकता है, तो वह तुरन्त उस पद से हटा दिया जाता है। देश के शिल्प और व्यापार को यद्यपि राज्य की ओर से अच्छा प्रोत्साहन मिलता है, पर साथ ही केन्द्रीय

अधिकारियों का उन पर पूरा-पूरा नियंत्रण भी रहता है। बहुत से नये कामों में सरकार की तरफ से अच्छी आर्थिक सहायता भी मिलती है। जापान के रोजगारियों को जब दूसरे देशों के रोजगारियों से काम पड़ता है, तब उन्हें इस बात का पूरा विश्वास रहता है कि किसी तरह का झगड़ा होने पर राज्य के अधिकारी हर तरह से हमारी मदद करेंगे। अवसर पड़ने पर जापानी व्यापारी राज्य के अफसरों की सब आज्ञायें भी चुपचाप मान लेते हैं। वहाँ की मुद्रा-प्रणाली और व्यापारिक सम्बन्धों पर भी राज्य का पूरा नियंत्रण रहता है और इनका संचालन ऐसे ढंग से किया जाता है कि राष्ट्र के हितों पर किसी तरह का आघात न होने पावे। देश के आर्थिक जीवन के सभी अंगों का और यहाँ तक कि खेती-बारी का भी ऐसे ढंग से संघटन किया गया है कि मालूम होता है कि सभी आर्थिक विषयों की पहले से ही योजना कर रखी गई थी। एक रूस को छोड़कर और किसी दूसरे देश में इस प्रकार की पूर्व-निश्चित आर्थिक योजना नहीं दिखाई देती।

युरोपीय देशों के फ़ैसिस्टवाद में यद्यपि अधिकतर सैनिकता की ही बातें दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के सारे फ़ैसिस्ट आन्दोलन नागरिकों के ही चलाये हुए हैं। लेकिन जापान में चरम सोमा की राष्ट्रीयता की जितनी शक्तियाँ हैं, वे सब सेनाओं और सैनिकों पर ही आश्रित हैं; और उस पर पार्लमैण्ट का किमी प्रकार का नियन्त्रण नहीं है। इधर कुछ दिनों से वहाँ के नागरिकों में एक प्रकार का ऐसा फ़ैसिस्टवाद चलने लगा है जो कृपकों के कष्ट दूर करने के लिये बहुत बड़ी-बड़ी माँगें पेश करता है। लेकिन इसे सैनिक तथा नौ-सैनिक नेताओं की जितनी सहायता मिल सकती है, उतना ही यह आन्दोलन सफल हो सकता है। आरम्भ में जिस समय जापान पाश्चात्य देशों की राजनीतिक संस्थाओं का अनुकरण करने लगा था, उस समय

कुछ दिनों के लिए थोड़ा जाति का प्रभुत्व और प्रभाव कुछ कम हो गया था। लेकिन अब वहाँ केवल पार्लमैण्टरी शासन प्रणाली ही आदर्श और अनुकरणीय नहीं समझी जाती और इसी लिए अब वहाँ फिर से थोड़ा जाति की फैसिस्ट शासन-प्रणाली स्थापित हो गई है। जब जापानियों ने पाश्चात्य संस्थाओं को अपनाना शुरू किया था, उन्होंने फ्रान्स, ग्रेट ब्रिटेन या अमेरिकन संयुक्त राज्यों का आदर्श अपने सामने नहीं रक्खा था, बल्कि जर्मनी को ही अपने आदर्श के रूप में चुना था; और बहुत सी बातों में उसी का अनुकरण किया था। और इसका कारण यही था कि जर्मन प्रणाली में सब बातों में थोड़े से बड़े-बड़े अधिकारियों की आज्ञाओं का ही पालन होता था; और वहाँ और देशों की अपेक्षा सैनिक वर्ग का सम्मान भी अधिक था और उनके हाथ में अधिकार भी बहुत था। लेकिन जब सन् १९१८ में जर्मनी महायुद्ध में हार गया और यूरोप में पार्लमैण्टरी प्रतिनिधिसत्तात्मक शासन-प्रणाली की विजय होती हुई दिखाई दी, तब जापान में भी कुछ दिनों के लिए पार्लमैण्टरी शासन-प्रणाली का विकास होने लगा था। लेकिन जब रूस में कम्यूनिस्टों के पैर अच्छी तरह जम गये, तब फिर लोगों के विचार कुछ-कुछ बदलने लगे। जिस समय यूरोप के राज्य रूस के कम्यूनिस्टों को दबाना चाहते थे, उस समय जापान ने भी साइबेरिया में घुसने का प्रयत्न किया था। लेकिन न तो पाश्चात्य शक्तियों को ही और न जापान को ही अपने इन प्रयत्नों में कोई सफलता हुई थी; और इसी लिए जापानियों के विचार पार्लमैण्टरी शासन-प्रणाली की ओर से और भी हटने लग गये थे। फिर जब साम्यवादियों के हाथ में पड़कर रूस उन्नति करने लगा, तब फिर लोग साम्यवादी विचारों और सिद्धान्तों की ओर प्रवृत्त होने लग गये थे। और ऐसा जान पड़ता था कि जापान के पड़े-

लिखे और समझदार भी अपने यहाँ साम्यवादी राज्य स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन जब यह बात स्पष्ट हो गई कि बोल्शेविक लोग सारे संसार में जो साम्यवादी राज्य-क्रान्ति करना चाहते थे, वह अब नहीं होगी, या कम-से-कम अभी कुछ दिनों तक इस प्रयत्न के सफल होने की कोई आशा नहीं है, तब फिर लोगो का मत बदलने लगा। ठीक उसी समय जापान में कम्यूनिस्ट दलों का दमन भी आरम्भ हो गया था। आगे चलकर जब फैसिस्टवाद यूरोप में एक नया आदर्श खड़ा करने लगा, तब जापानी भी उसी को अच्छा समझने लगे और वहाँ बहुत से लोग उसके पक्ष में हो गये। और जब दूसरे महायुद्ध में जर्मनी ने फ्रान्स को पूरी तरह से दबा लिया, तब तो जापान में फैसिस्ट राज्य स्थापित ही हो गया।

जब जर्मनी में फैसिस्ट शासन-प्रणाली स्थापित हुई, तब भी अधिकांश जापानी इसी प्रणाली के भक्त हो गये थे। बात यह है कि जर्मनी के साथ जापान का कई बातों में बहुत मेल मिलता है। जापानी भी यही चाहते हैं कि राष्ट्र के हितों पर सबसे अधिक ध्यान रहे; और यदि आवश्यकता हो तो व्यक्तिगत हित उसके सामने दबाये भी जा सके। और ठीक यही बात जर्मनी में भी है। यो तो जापानी पहले से ही कई बातों में जर्मनी की नकल करते आते थे। पर जब जापानियों ने देखा कि फैसिस्ट शासन-प्रणाली की अधीनता में ही आकर जर्मनी अपने वे सब कलंक और अपमान धोने में समर्थ हुआ है, जो पिछले युद्ध में पराजित होने के उपरान्त उसके सिर पड़े थे, तब वे इस प्रणाली के और भी अधिक समर्थक हो गये थे। इसी लिए स्वभावतः जापान और जर्मनी बहुत सी बातों में मिल कर एक हो गये थे। दोनों ने ही प्रतिनिधिसत्तात्मक शासन-प्रणाली की सभी बातें अपने यहाँ से हटा दीं और दोनों ने ही राष्ट्र-संघ के सिद्धान्तों को मानने से

हन्कार कर दिया। दोनों ने ही यह घोषणा कर दी कि रूस की कम्युनिस्ट शासन-प्रणाली बहुत ही हानिकारक है और संसार से उसका उठ जाना ही अच्छा है। दोनों ने ही यह घोषणा कर दी कि हमारा उद्देश्य अपनी राष्ट्रीयता का विस्तार करना है और हम अपनी-अपनी सभ्यता का प्रसार करना चाहते हैं। उधर जर्मनी ने यह निश्चय कर लिया कि हम यूरोप में, रूसी "बबरता" का किसी तरह प्रचार नहीं होने देंगे; और इधर जापान ने यह निश्चय कर लिया कि न तो हम एशिया में रूसी मार्क्स-भक्तों को हाथ-पैर फैलाने देंगे और न यहाँ पाश्चात्य पूँजीदारों का प्रभुत्व रहने देंगे। जापान जो अब चारों तरफ हाथ-पैर फैलाना चाहता है, उसका कारण भी यही है कि उसकी राष्ट्रीयता में सैनिकता भी मिली हुई है। और साथ ही वह यह भी कहता है कि हम एशिया के लोगों को पाश्चात्य पूँजीदार लुटेरों के हाथ से छुड़ाना चाहते हैं।

जापानियों की प्रसार-वृत्ति—जापानियों में चारों ओर अपना प्रसार करने की वृत्ति और अनेक कारणों से तो है ही, पर साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि उनकी इस प्रवृत्ति का एक कारण उनकी आन्तरिक आर्थिक कठिनाइयाँ भी हैं। जापानी राष्ट्रीयता के नेताओं की आकांक्षाएँ तो बहुत बड़ी-बड़ी हैं, परन्तु उन आकांक्षाओं को देखते हुए उनके देश में कृषि और शिल्प दोनों के लिए ही बहुत थोड़ा क्षेत्र है। जापान पहाड़ी देश है और उसका बहुत बड़ा भाग ऐसा ही है, जिसमें खेती-बारी बिल्कुल नहीं हो सकती। जिन जगहों में खेती-बारी हो सकती है, वहाँ आबादी बहुत ही घनी होती जा रही है। कुछ जगहें ऐसी भी हैं, जहाँ की आबादी कम है और वहाँ खेती-बारी भी हो सकती है। लेकिन वहाँ की आबहवा कुछ ऐसी है कि लोग वहाँ जाकर

बसना नहीं चाहते। जिन जगहों में ज्यादा आबादी है और जो आबहुता के खयाल से रहने के लायक हैं, उनमें किसानों की हालत इसलिए बहुत खराब है कि उनके पास जमीन इतनी थोड़ी है कि उससे उनका अच्छी तरह गुजारा हो ही नहीं सकता। जापान शिल्प और उद्योग-धन्धों में भी बहुत आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इनके लिए जिस कच्चे माल की जरूरत होती है, वह उस देश में पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ जमीन की कमी है। वहाँ जो नदियाँ और जल-प्रपात आदि हैं, उनसे काफी बिजली पैदा की जाती है, जिसका शिल्प आदि में अच्छा उपयोग होता है। जापान में कोयला भी है, लेकिन वह अच्छा नहीं होता, घटिया दर्जे का होता है। लोहा और रुई आदि वहाँ बिल्कुल नहीं होती। हाँ, रेशम बहुत काफी होता है। इसी लिए जापान यह चाहता है कि कुछ ऐसे देश हमारे हाथ में आवें, जिनमें हमारी दिन-पर-दिन बढ़ती हुई प्रजा जाकर बस सके और खेती-बारी कर सके और जहाँ से हमें काफी कच्चा माल भी मिल सके। अभी हाल में मंचूको पर इसीलिए उसने अत्यन्त रूप से अधिकार किया है कि वहाँ बहुत सा कच्चा माल पैदा हो सकता है और वहाँ के निवासी अपने देश के इन साधनों का कोई विशेष उपयोग नहीं करते। इसके सिवा मंगोलिया के भीतरी भाग और उत्तरी चीन में भी बहुत-सा कच्चा माल तैयार हो सकता है; और इन दोनों प्रदेशों पर मंचूको की ओर से सहज में आक्रमण और अधिकार किया जा सकता है। लेकिन इन प्रदेशों में जापानी खेतिहरों की बस्ती बसना इसलिए कठिन है कि वहाँ जापानियों को ऐसे लोगों का मुकाबला करना पड़ेगा जो उनकी अपेक्षा बहुत ही थोड़े में अपना निर्वाह कर सकते हैं। कनाडा और अमेरिकन संयुक्त राज्य अपने यहाँ जापानियों को बसने नहीं देते; इसलिए जापानी चाहते

हैं कि बोरनियो, न्यू गिनी, आस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रदेश और डच ईस्ट इन्डोज में हम अपने उपनिवेश स्थापित करें। और वर्तमान युद्ध के समय वे अपनी यही इच्छा पूरी करने के फेर में पड़े हुए हैं।

लेकिन जिन देशों में जापान अपने उपनिवेश स्थापित करना चाहता है, उनपर पहले से ही यूरोप के अनेक साम्राज्यों ने अधिकार कर रक्खा है। ग्रेट ब्रिटेन कहता है कि हम आस्ट्रेलिया में गोरों के सिवा और किसी को बसने ही नहीं देंगे; और आस्ट्रेलिया के सब राजनीतिज्ञ भी उसकी इसी नीति के पूरे-पूरे समर्थक हैं। अगर ईस्ट इंडोज में जापान अपना सिक्का जमाना चाहता था, तो अंगरेज और डच दोनों ही मिलकर उसका घोर विरोध करते थे। हालैंड पर जर्मनी का अधिकार हो जाने पर वह ईस्ट इंडोज पर अधिकार करने के लिए, और भी उतावला हो रहा है। अभी अरबों रुपये खर्च करके ब्रिटेन ने सिंगापुर में अपने सैनिक बेड़ों का जो बहुत बड़ा अड्डा बनाया है, उसमें उद्देश्य यही है कि भारतीय महासागर और ईस्ट इंडोज के टापुओं पर जापानियों का राजनीतिक प्रभाव न पड़ सके। फिलिप्पाइन्स^१ आज-कल अमेरिकन साम्राज्य के अन्तर्गत है। लेकिन सम्भव है कि आगे चलकर उस पर जापान का सहज में

१ फिलिप्पाइन बहुत से छोटे-छोटे टापुओं का एक समूह है, जो बोरनियो के उत्तर में चीन और इंडोचीन के पास है। यह सन् १८६६ में स्पेन से अमेरिकन संयुक्त राज्यों को मिला था। यहाँ चावल, नारियल चीनी, सन, तम्बाकू और इसी तरह की और कई चीजों की बहुत अच्छी पैदावार होती है, और यहाँ के जंगलों में इमारती लकड़ी भी बहुत अधिक होती है। रा० च० वर्मा।

अधिकार हो सके। अमेरिकन संयुक्त राज्यों ने निश्चय कर लिया है कि फिलिपाइन्स को स्वराज्य दे दिया जाय; और इसका कारण यही है कि वह अमेरिका से बहुत दूर और चीन के बिलकुल पास पड़ता है; और अमेरिका इतनी दूर से उसकी रक्षा की यथेष्ट व्यवस्था नहीं कर सकता। लेकिन अगर यह मान भी लिया जाय कि फिलिपाइन्स पर से अमेरिका अपना प्रभाव हटा लेगा और वह जापान के हाथ में चला जायगा, तो भी जापान का उससे इसलिए कोई बहुत ज्यादा काम नहीं निकलेगा कि उसकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को देखते हुए वह कोई चीज ही नहीं है। जापान के नेता समस्त सुदूर पूर्व पर अधिकार करना चाहते हैं; और इसीलिए उन्होंने कोरिया तथा फारमोसा पर अधिकार कर लिया है; और अब वे चाहते हैं कि चाहे समग्र चीन पर और चाहे उसके भिन्न-भिन्न खंडों पर हमारा राजनीतिक अधिकार हो जाय^१ परन्तु वे यह नहीं चाहते कि पूर्वी एशिया में रूस का किसी प्रकार का अधिकार हो या वहाँ रूस के कम्युनिस्ट सिद्धान्तों और शासन-प्रणाली का प्रचार हो; इसी लिए वे मंगोलिया और मंचूको पर भी अपना पूरा-पूरा अधिकार रखना चाहते हैं। रूसियों के मार्ग में बाधा खड़ी करने के लिए वे अपनी

१ अपने इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए जापान ने प्रायः तीन वर्षों से चीन के साथ विना घोषणा किये युद्ध छेद रक्खा है। इस युद्ध में जापान के अबतक पाँच-छः लाख आदमी मरे और घायल हुए हैं और ७५ करोड़ पाउण्ड खर्च हो चुके हैं। इस बीच में उसने चीन के दो-तिहाई प्रदेश पर अधिकार कर लिया है और वहाँ के १६ लाख सैनिकों को मारा और घायल किया है और वहाँ के शिल्प तथा व्यापार का बुरी तरह से नाश किया है। अब चीनियों ने जापानियों के साथ जमकर युद्ध करना कम कर दिया है और वे अधिकतर लुक-छिपकर

सैनिक शक्तियों का उपयोग करने में नहीं चूकते। वे यह भी समझते हैं कि रूस अपनी पूर्वी सीमा पर इसलिए जल्दी लड़ाई छेड़ने के लिए तैयार नहीं होगा कि उसे डर रहेगा कि कहीं पश्चिमी सीमा पर जर्मनी का आक्रमण न हो जाय। वर्तमान युद्ध में फ्रांस पर जर्मनी का प्रभुत्व स्थापित हो जाने पर वह फ्रांसीसी इंडो-चाइना पर भी अधिकार जमाने का प्रयत्न करने लगा है। ईस्टइंडियन टापुओं और भारत में अभी वह अपना केवल व्यापार ही बढ़ा रहा है और दूसरे देशों के मुकाबले में बहुत सस्ता माल बेच रहा है। इन देशों में वह अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने से पहले व्यापारिक आधार दृढ़ करना चाहता है। जापानी नेताओं का यह विश्वास है कि ज्योंही हम इन देशों से यूरोपियन व्यापारियों को हटावेंगे, त्योंही हम इन देशों पर से यूरोपियनों का राजनीतिक प्रभाव भी हटा देंगे, और जब सुदूर पूर्व का सारा व्यापार हमारे हाथ में आ जायगा, तब एशियावाले स्वभावतः हमारा नेतृत्व मान लेंगे और यूरोपियन साम्राज्यवाद के विरुद्ध हम जो युद्ध छेड़ेंगे, उसमें ये एशियावाले हमारा साथ देंगे।

जापान की सब संस्थायें ऐसी ही हैं, जिनमें सारा अधिकार एक ही स्थान में केन्द्रित है और सभी जगह वहाँ सैनिक उपायों

जापानी छावनियों पर छापा मारने लगे हैं। इधर उन्होंने जापानियों से अपने कुछ नगर तथा प्रदेश वापस भी ले लिये हैं, जिससे जापान आज-कल और भी परेशान हो रहा है। इसके सिवा जबसे चीन-जापान युद्ध छिड़ा है, तबसे जापान का विदेशी व्यापार भी प्रायः एक-चौथाई कम हो गया है। और इसका कारण यह है कि कुछ लोगों ने जापानी माल का बहिष्कार आरम्भ कर दिया है। अभी यह युद्ध चल ही रहा है।

का अवलम्बन किया जाता है। उधर बाहर की ओर जापान अपना खूब प्रसार करना चाहता है और अपना साम्राज्य खूब बढ़ाना चाहता है। जापान की संस्थाये उसके इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए परम उपयुक्त भी हैं। लेकिन जापान में अन्दर-ही-अन्दर कुछ ऐसी शक्तियाँ भी काम कर रही हैं जो इस उपद्रवी और आक्रमणकारी नीति के विरुद्ध हैं। यद्यपि इधर कुछ दिनों में शिल्प और व्यापार में जापान ने बहुत अधिक उन्नति कर ली है, लेकिन फिर भी वह एक बहुत ही गरीब देश है। वहाँ ज्यादा आबादी ऐसे ही गरीब किसानों की है जो बहुत ही थोड़े में बड़ी कठिनता से जीवन-निर्वाह करते हैं। चारों तरफ हाथ पैर फैलाने के लिए जिस पूँजी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, उसका जापान में बहुत अभाव है। तरह-तरह की सैनिक शक्तियाँ रखने और अस्त्र-शस्त्र बढ़ाने में भी उसे बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है। साथ ही वहाँ की सरकार को गरीब खेतिहरो की भी कई तरह से सहायता करनी पड़ती है और शिल्प तथा उद्योग-धन्धों के विकास के लिए लोगों को खासी पूँजी भी देनी पड़ती है। वहाँ का सैनिक व्यय बहुत बढ़ा-चढ़ा है और अर्थ-विभाग के मन्त्रियों को उस व्यय को रोकने या कम करने का कोई अधिकार नहीं होता; और इसलिए उन्हें आय और व्यय बराबर रखने के लिए सदा बहुत चिन्तित रहना पड़ता है; और कभी-कभी भगीरथ-परिश्रम करना पड़ता है। यदि कभी वे सैनिक मँगों का किसी प्रकार का विरोध करते हैं तो प्रायः उन्हें अपने प्राणों तक से हाथ धोना पड़ता है। अर्थ-शास्त्र के ज्ञाता सदा यही कहा करते हैं कि जिस देश का व्यय उसकी आय की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। लेकिन अगर यह बात ठीक होती तो शायद जापान का अबसे बहुत दिन पहले ही सर्वनाश हो चुका होता। इधर जबसे उसने चीन के साथ युद्ध

छेड़ा है, तबसे प्रायः लोग यही कहते हैं कि इससे जापान का आर्थिक सर्वनाश होना अवश्यम्भावी है। लेकिन फिर भी अभी तक जापान जैसे-तैसे चला ही चलता है। शायद आरम्भ में उसने यही आशा की थी कि जिस तरह इटली ने सहज में एबीसीनिया पर अधिकार कर लिया है, उसी प्रकार चीन पर सहज में हमारा भी अधिकार हो जायगा। और उसने दो-तिहाई चीन पर अधिकार कर भी लिया है। लेकिन चीन के जिन प्रदेशों पर उसने अधिकार कर लिया है, उन प्रदेशों में भी वह अभी तक शान्ति और अपना शासन स्थापित करने में समर्थ नहीं हुआ है। चीनवाले जापानियों को किसी तरह दम नहीं लेने देते। और कई चीनी नेताओं का यह दृढ़ विश्वास है कि हम जापान को अन्त में परास्त करके ही छोड़ेंगे और इस युद्ध के कारण जापान का सर्वनाश हुए बिना न रहेगा। जो हो, लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि चीन-जापान युद्ध ने जापान को सभी प्रकार से बहुत त्रस्त कर रक्खा है। वह चीन को अपने वश में करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा रहा है, परन्तु अभी तक उसे इस प्रयत्न में सफलता नहीं हो रही है। इस समय जो परिस्थिति चल रही है, उसे देखते हुए यदि दो-चार या छः महीने में जापान निराश होकर चीन के साथ लड़ना छोड़ दे तो किसी को आश्चर्य न होगा।

कहा जाता है कि इस युद्ध का जापान की आर्थिक अवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वहाँ बेकारी भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और चीजों का भाव भी बहुत बढ़ता जा रहा है। बेकारी तो इसलिए बढ़ रही है कि वहाँ सब चीजों के उत्पादन का व्यय घटाने का इतना अधिक प्रयत्न किया जाता है और कारखानों आदि की मजदूरी इतनी घटाई जा रही है कि उससे लोगों का काम किसी तरह नहीं चलता; और कई

विभागों में लोगो ने सिर्फ इसीलिए काम करना छोड़ दिया है कि उन्हें उचित से बहुत ही कम वेतन मिलता है। चीजों के भाव पर नियन्त्रण रखने के लिए सरकार ने जो कानून बनाये हैं, उनका लोग ठीक तरह से पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे पुलिस का काम बहुत बढ़ गया है। चीन की लड़ाई में सरकार को जो व्यय करना पड़ रहा है और साथ ही नये-नये कल-कारखाने खोलने के लिए उसे जो धन चाहिए, उसके लिए सरकार ने कई वर्ष पहले कहा था कि जापानी जनता को ४७ करोड़ पाउंड की बचत करनी चाहिए। वहाँ जनता जो धन बचाती है, वह सब सरकार उससे ऋण के रूप में ले लेती है। दो वर्ष पहले की जनता की बचत ४२ करोड़ पाउंड के लगभग हुई थी। गत वर्ष सरकार चाहती थी कि जनता ६० करोड़ पाउंड बचाकर सरकारी कागज खरीदे। कुछ लोगो का विश्वास है कि इस वर्ष शायद उसे इससे भी अधिक धन की आवश्यकता होगी। वहाँ कुछ ऐसे उपाय भी सोचे जा रहे हैं जिनसे सारे देश के वयस्क पुरुष जबरदस्ती सेना में भर्ती किये जा सकें और देश की पैदावार बढ़ाकर युद्ध के काम में लगाई जा सके। कुछ दिनों तक वहाँ यह भी आन्दोलन चल रहा था कि इस प्रकार के कार्यों के लिए प्रधान मन्त्री के अधिकार और भी बढ़ाये जायें। अबतक वहाँ के अधिकांश कारखानों में मजदूरों को १५ और १६ घन्टे तक नित्य काम करना पड़ता था। लेकिन देश की बढ़ती हुई बेकारी कम करने के लिए यह व्यवस्था की गई कि कुछ विभागों में वयस्क पुरुषों से दिन में केवल १२ घन्टे काम लिया जाय। उसका राष्ट्रीय ऋण भी दिन-पर-दिन बहुत बढ़ता जा रहा है। १३ मार्च १९३६ को यह ऋण एक अरब पाउंड से भी ऊपर था।

यद्यपि इधर बहुत दिनों से जापान अपनी आमदनी से बहुत

ज्यादा खर्च करता चला आ रहा है, तो भी वह साथ ही साथ अपना उत्पादन और व्यापार भी बराबर बढ़ाता आता है। उसके उत्पादन और व्यापार की यह उन्नति ऐसे समय में हुई है जब कि और-और देशों का व्यापार बराबर घटता रहा है और उनके यहाँ बेकारी बढ़ती रही है। लेकिन जापान ने व्यापारिक क्षेत्र में जो यह उन्नति की है, उसका उसे कहीं अधिक मूल्य देना पड़ा है; और विशेषतः अपने यहाँ के गरीबों और किसानों के हितों का बहुत कुछ बलिदान करना पड़ा है। यो तो जापान के सैनिक नेता जब चाहते हैं, तब वहाँ के राजनीतिज्ञों को दवा लेते हैं और उनसे जो चाहते हैं, वह करा लेते हैं। लेकिन फिर भी अपने देश के गरीब कृषकों की अवस्था देखते हुए उन्हें अपने बहुत से हौसले मन ही मन दबा रखने पड़ते हैं और जहाँतक हो सकता है, अपने बहुत से काम सस्ते में ही निपटाने पड़ते हैं। चीन के शांघाई नामक बन्दरगाह पर एक बार जापान ने जो चढ़ाई की थी, उसमें उसका खर्च तो बहुत अधिक पड़ गया था, पर उससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था। अब वह फिर शांघाई से यूरोपियनों को निकालने के प्रयत्न में लगा है और अंग्रेजों ने तो वहाँ से अपनी सेना हटा भी ली है (अगस्त १९४०)। हाँ, मंचूको को अपने अधिकार से लाने के लिए उसने जो कुछ व्यय किया था, उससे अवश्य ही उसे कुछ आर्थिक लाभ हुआ है। रूस-जापान युद्ध में जापान का जितना धन व्यय हुआ था, उससे सत्तर गुना अधिक वह अबतक इधर तीन वर्षों में चीन के साथ लड़ने में खर्च कर चुका है। यद्यपि शांघाईवाली चढ़ाई में जापान को जो कटु अनुभव हुआ था, उसके कारण बहुत दिनों तक जापानियों को चीन के साथ लड़ने की जल्दी हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन इधर यूरोप की राजनीतिक परिस्थिति ढाँवाडोल देखकर ही उसने यह सोचा था कि यह समय चीन पर से यूरोपियों का

प्रभुत्व हटाने के लिए बहुत अनुकूल है; और इसीलिए उसने इस बार फिर चीन पर चढ़ाई की है। और यदि इस बार भी उसे वैसा ही अनुभव हुआ, जैसा कि शांघाईवाली चढ़ाई के समय हुआ था, तो सम्भव है कि बहुत दिनों के लिए उसे ऐसी शिक्षा मिल जाय कि वह इस प्रकार का दुस्साहस न कर सके।

सन् १९१५ में जिस समय यूरोप में भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय जापान ने चीन के सामने अपनी इक्कीस जबरदस्त माँगें पेश की थी। लेकिन उस समय अमेरिका के संयुक्त राज्यों ने ही बीच में पड़कर किसी तरह चीन का छुटकारा कराया था। सन् १९१८ के बाद जापान ने जब साइबेरिया की तरफ बढ़ने का प्रयत्न किया था, तब भी अमेरिकन संयुक्त राज्यों ने ही उसका वह प्रयत्न विफल किया था। लेकिन उसके बाद जो बहुत दिनों तक जापान चुपचाप रहा और उसने चीन पर आक्रमण करने का कोई प्रयत्न नहीं किया था, उसका कारण यह नहीं था कि उसे संयुक्त राज्यों का अथवा राष्ट्र-संघ का कोई भय था, बल्कि उसका कारण यही था कि उसकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी। और इस बार भी कदाचित् उसने अपनी दिन-पर-दिन गिरती हुई आर्थिक अवस्था सुधारने के ही मुख्य उद्देश्य से चीन पर चढ़ाई की थी। जापानी नेताओं के मन में सारे एशिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की जो इच्छा है, वह बराबर स्पष्ट शब्दों में प्रकट करते रहते हैं। अप्रैल सन् १९३४ में तो जापान की एक सरकारी घोषणा तक में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई थी और मानो पाश्चात्य शक्तियों को साफ तौर पर चुनौती ही दी गई थी। इस घोषणा में जापान ने साफ-साफ कह दिया था कि सुदूर पूर्व के सम्बन्ध में हमारा भी वही मनरोवाला-सिद्धान्त है। हम यहाँ किसी विदेशी शक्ति को कोई हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहते। उसमें यह भी

कहा गया था कि चीन के मामले में यूरोपियन शक्तियों को नहीं पड़ना चाहिए और चीन को ऐसी कोई सहायता नहीं देनी चाहिए, जिससे वह जापान का आक्रमण रोकने में समर्थ हो सके। जब अमेरिका में घरेलू झगड़े बहुत बढ़ गये और अमेरिका अपनी आर्थिक अवस्था के सुधार में लग गया, तब जापान को अपना दुष्ट उद्देश्य सिद्ध करने का और भी अच्छा अवसर मिला गया और वह एक-एक करके चीन के कुछ अंशों पर अधिकार करने लगा। पहले तो उसने मंचूकी पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में किया और वहाँ एक ऐसे व्यक्ति को सिंहासन पर बैठाया, जो हर तरह से उसके हाथ का खिलौना था; और तब वहाँ की सारी आर्थिक व्यवस्था अपने हाथ में कर ली। और जब वहाँ उसके पैर अच्छी तरह जम गये, तब उसने उत्तरी चीन पर आक्रमण कर दिया। और इधर तीन बरसों से चीन के साथ उसकी जबरदस्त लड़ाई चल रही है। इस बीच में उसने चीन के बहुत बड़े हिस्से पर अधिकार तो कर लिया है, लेकिन उस हिस्से में भी चीनवाले अभी तक बराबर लड़ ही रहे हैं।

इस दूसरे यूरोपीय युद्ध के समय उसने अंगरेजों पर दबाव डालकर बर्मा के रास्ते चीन में माल पहुँचना बन्द कर दिया; और हारे हुए फ्रांस पर दबाव डालकर चीन के लिए इंडो-चीन वाला रास्ता भी बन्द कर दिया। अब चीन को जो थोड़ी-बहुत सामग्री मिलती है, वह प्रायः सोवियट रूस से ही मिलती है।

जापान के नेताओं को वहाँ की प्रजा पर इतना अधिक विश्वास है कि वे समझते हैं कि जिस समय राज्य पर कोई संकट आवेगा या कोई विकट परिस्थिति उत्पन्न होगी, तब प्रजा अपने सभी स्वार्थों का त्याग करके केवल वही काम करेगी, जिससे देश का हित होगा। पाश्चात्य देशों के निवासियों और

विशेषतः ब्रिटिश तथा फ्रान्सीसी व्यक्ति-म्वान्तन्यवादियों को यह बात बहुत ही विलक्षण मालूम होती है और यह जल्दी उनकी समझ में ही नहीं आता कि कोई प्रजा अपने देश के हित के लिए इतना अधिक स्वार्थ-त्याग किस प्रकार कर सकती है। परंतु वास्तव में ऐसा जान पड़ता है कि संसार का कोई काम ऐसा नहीं हो सकता, जो जापानी प्रजा अपने देश और राज्य के लिए न कर सकती हो। इसी प्रकार की कुछ भावना नाजी जर्मनी में भी देखने में आती है और मुसोलिनी भी बराबर इटैलियनों को अपना भाव इसी प्रकार का रखने की शिक्षा देता रहता है। यूरोप के अन्यान्य देशों के निवासियों में किसी विशेष अवसर पर तो कुछ समय के लिये अवश्य ही ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ के अधिकांश निवासियों को यही जान पड़ता है कि इस प्रकार का भाव बिलकुल कृत्रिम होता है, वह मनुष्यों पर जबरदस्ती लादा जाता है और उसका प्रभाव चिर-स्थायी नहीं होता। परन्तु जापान में बहुत दिनों से जो प्रबल राष्ट्रीयता की परम्परा चली आई है, उससे देश-हित के लिए चरम सीमा के स्वार्थ-त्याग का भाव जापानियों में बिलकुल स्वाभाविक हो गया है। उसमें कभी-कभी जो न्यूनता हो जाती है, वह केवल इसी लिए कि वे बीच-बीच में पाश्चात्य देशों की पार्लैमेंटरी शासन-प्रणाली और उसके विधानों का अनुकरण करने लगते हैं। लेकिन जब से वहाँ फैसिस्ट विचारों की प्रबलता होने लगी थी, तब से जापानियों में फिर वही स्वार्थ-त्यागवाला भाव प्रबल होने लग गया था। अब तो उसका स्वरूप इसलिए और भी अधिक उग्र तथा भयंकर हो गया है कि उसकी आर्थिक और सैनिक व्यवस्था भी बिलकुल पाश्चात्य ढंग की हो गई है। और आशा है कि अब वहाँ फैसिस्ट शासन स्थापित हो जाने पर वह स्वरूप और भी उग्र तथा भयंकर हो जायगा।

युरोप में फैसिस्टवाद का उग्र और भीषण स्वरूप उसी समय देखने में आता है, जब कि वहाँ कोई विकट संकट सामने दिखाई देता है; और यदि उस संकट की विकटता कम हो जाय, तो वह स्वार्थ-त्यागवाला भाव भी ढीला पड़ जाता है। लेकिन जापानी फैसिस्टवाद के लिए इस प्रकार के किसी उत्तेजक तत्त्व की कोई आवश्यकता नहीं होती। और अब तो जापान ने स्वयं ही अनेक प्रकार के नये वैज्ञानिक अस्त्र-शस्त्र बना लिये हैं और इसीलिए वह पहले-पहल युरोपियन सभ्यता का मुकाबला ऐसी निर्भीकता से करने के लिए तैयार हो गया है जो सिर्फ जंगली फिरकों में ही देखने में आती है।

लेकिन फिर भी इसमें एक बात संतोष की अवश्य है। जापान के निकटतम पड़ोसी चीन और रूस हैं। और इनमें से कोई ऐसा मुलायम चारा नहीं है, जिसे जापान सहज में हजम कर सके। जापानियों के आक्रमण करने पर चीनी सेनाये तितर-बितर हो सकती हैं, लेकिन फिर भी चीन इतना बड़ा और विस्तृत देश है कि जापान अपनी सारी सैनिक शक्ति लगाकर भी न तो उसे पद-दलित ही कर सकता है और न उसकी व्यवस्था तथा संघटन ही कर सकता है। रूस के लिए कुछ कठिनता अवश्य है और वह सहज में अपने सुदूर पूर्व के प्रदेशों की रक्षा नहीं कर सकता। अब मंचूको भी जापानियों के हाथ में चला गया है, इसलिए वह केवल आकाश-मार्ग से ही आक्रमण करके व्लाडिवोस्टक और आमूर रेल्वे की रक्षा कर सकता है। और नहीं तो साधारणतः सैनिक दृष्टि से वह किसी प्रकार उनकी रक्षा नहीं कर सकता। सन् १९१५ और १९१६ में भी जापान ने साइबेरिया में घुसने का प्रयत्न किया था और उन दिनों सोविएट रूस आज-कल की अपेक्षा बहुत ही दुर्बल था। लेकिन उस समय भी रूसियों ने साइबेरिया में जापान की दाल नहीं गलने दी थी।

फिर अब तो वह उस समय की अपेक्षा कहीं अधिक बलवान् हो गया है। ऐसी अवस्था में भला कैसे यह आशा की जा सकती है कि जापान सहज से साइबेरिया में प्रवेश कर सकेगा? इस समय तो पाश्चात्य देशों के लिए सन्तोष की यही बात है कि जापान के साधन बहुत ही परिमित हैं और उसे बहुत दिनों तक मंचूको के आस-पास के प्रदेशों तथा चीन में ही उलझे रहना पड़ेगा। जो प्रदेश पाश्चात्य शक्तियों के हाथ में हैं, उन पर न तो जापान को आक्रमण करने का साहस ही होगा और न जल्दी-अवसर ही मिलेगा। रूस भी इस समय अपनी आर्थिक अवस्था सुधारने और अपने देश का राजनीतिक संघटन करने में लगा हुआ है। पर साथ ही वह अपने पूर्वी पड़ोसी की ओर से निश्चिन्त नहीं है। रूस चाहता है कि चीन में भी सोविएट शासन-प्रणाली स्थापित हो जाय और तब रूस से चीन तक हर जगह सोविएट-प्रणाली ही दिखाई दे। पर जापान चाहता है कि वह इन दोनों के बीच में पड़नेवाले मंगोलिया पर अधिकार कर ले और चीन में सोविएट शासन-प्रणाली न प्रचलित होने पावे। एक ओर तो रूस सारे एशिया पर अपना प्रभाव डालना चाहता है और दूसरी ओर जापान। लेकिन रूस को यह आशा है कि जब जापान अपने वित्त के बाहर कोई काम करना चाहेगा, तब सभी पूर्वी देश उसकी नीति के घोर विरोधी हो जायेंगे और तब हमारा काम आप-से-आप हो जायगा। लेकिन पाश्चात्य शक्तियों की बात कुछ और ही है। एशिया में चाहे रूस का प्रभुत्व स्थापित हो और चाहे जापान का, हर हालत में युरोप की शक्तियों के बल और प्रतिष्ठा का नाश होगा। जिस समय जापान ने मंचूरिया पर अधिकार किया था, उस समय राष्ट्र संघ की शक्तियाँ केवल इसी लिए चुप रह गई थीं कि वे मंचूरिया का रूस के हाथ में जाने की अपेक्षा जापान के हाथ में जाना कहीं

अच्छा समझती थी। जापान तो अपनी साम्राज्यवादी नीति के अनुसार एशिया के देशों पर अपना प्रभुत्व ही स्थापित करना चाहता है और उन्हें सदा अधीनता में ही रखना चाहता है; परन्तु रूस चाहता है कि एशिया के सब देश पराधीनता से छूट कर विलकुल स्वतन्त्र हो जायँ; और इसीलिए जापान के मनमानी करने पर युरोपीय शक्तियाँ चुप रहती हैं।

: ४ :

चीन की राजनीतिक प्रणाली

चीन की राजनीतिक प्रणाली का जिक्र करना एक तरह से इसलिए गलत है कि पाश्चात्य दृष्टि से चीन में किसी प्रकार की राजनीतिक प्रणाली है ही नहीं। वहाँ एक सरकार तो नानकिंग में न्यांग-काई-शेक के अधिकार में है। और वहाँ चीनी प्रजातन्त्र का एक संघटन-विधान भी है। इस प्रजातन्त्र में सरकार का एक राष्ट्रपति होता है, राज-मंत्रियों का एक मंत्री-मंडल होता है। लेजिस्लेटिव, एक्जिक्यूटिव तथा कुछ और प्रकार की काउन्सिलें होती हैं। करो के द्वारा राजस्व इकट्ठा होता है। सिविल सर्विस है और सेना है। परन्तु वास्तव में चीन के बहुत विस्तृत क्षेत्र का बहुत ही थोड़ा-सा अंश इस सरकार के हाथ में है और उसकी राजनीतिक तथा कानूनी प्रणाली का अधिकांश अभी तक सिर्फ कागजों पर ही लिखा पड़ा है, उसके सिवा और कहीं उसका कोई अस्तित्व नहीं है।

नानकिंग में जो प्रजातन्त्र की राष्ट्रीय सरकार है, उसके सिवा चीन में और भी कई सरकारें हैं। यदि सच पूछिए तो निश्चित रूप से कोई यह नहीं कह सकता कि वहाँ कितनी सरकारें हैं और उनका आपस में क्या सम्बन्ध है? सबसे पहले तो वहाँ

बहुत-सी प्रांतीय सरकारें हैं, जिनमें से कुछ तो किसी एक ही गवर्नर या सैनिक नेता के अधिकार में हैं और कुछ में राजनीतिज्ञों की काउन्सिलें सब काम करती हैं। इसी अन्तिम प्रकार की एक सरकार कैप्टन में है। और किसी हद तक यह भी कहा जा सकता है कि सभी प्रांतों में शासन-कार्यों के लिए किसी-न-किसी प्रकार की काउन्सिलें भी हैं। इनमें से कोई सरकार तो च्यांग-काई-शेक की सरकार का पूरा-पूरा अधिकार और नियंत्रण मानती है, कोई कम, और कोई अधिक मानती है, और कुछ ऐसी भी हैं जो उसका कुछ भी अधिकार नहीं मानतीं। हाँ, सभी सरकारें चीन की राष्ट्रीय एकता अवश्य मानती हैं; और सम्भव है कि आगे चलकर मिलकर एक हो जायँ और एक बड़ी राष्ट्रीय सरकार की सत्ता मानने लगें। लेकिन अभी तो यह राष्ट्रीय एकता भी सब जगह समान रूप से नहीं मानी जाती। यों कहने के लिए मंचूको भी चीनी राज्य की सीमा के अन्दर ही है, लेकिन जापान ने वहाँ जिस मंचूरियन साम्राज्य की स्थापना की है, वह चीन की किसी प्रकार की अधीनता नहीं मानता। भीतरी मंगोलिया और बाहरी मंगोलिया भी इसी प्रकार नाम मात्र के लिए चीनी सीमा के अन्दर हैं और चीनी राज्य के अन्तर्गत हैं। लेकिन बाहरी मंगोलिया में जो सोविएट प्रजातन्त्र है, उसका वास्तव में रूसी सोविएट प्रजातंत्र के साथ बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है और वह नानकिंग की कोई आज्ञा नहीं मानता। अब जेहोल भी मंचूको के साथ मिला लिया गया है। भीतरी मंगोलिया अभी तक भगड़े में ही पड़ा है। उसे चीन भी अपने अधिकार में रखना चाहता है, मंचूको, बल्कि यों कहना चाहिए कि जापान भी अपना अधिकार जमाना चाहता है और मंगोलिया का सोविएट प्रजातन्त्र भी उसे अपनी तरफ खींचना चाहता है। इसी तरह कानूनी दृष्टि से तिब्बत भी चीन का ही है। लेकिन

जापान की राजनीतिक प्रणाली

राजनीतिक दृष्टि से उस पर ब्रिटेन का कहीं अधिक प्रभाव है और चीन का राजनीतिक प्रभाव प्रायः नहीं के समान है। चीन के दूरस्थ प्रदेशों में जो कुछ होता है, उससे तिब्बती सरकार कुछ भी मतलब नहीं रखती। इसी प्रकार चीनी तुर्किस्तान भी है तो चीनी सीमा के ही अन्दर, लेकिन इधर बहुत दिनों से वह मध्य एशिया का रण-क्षेत्र हो रहा है। वहाँ चीनी गवर्नर भी रहते हैं, लेकिन वहाँ के स्थानिक मुसलमान शासक उनसे लड़-झगड़कर सब अधिकार छीनने का प्रयत्न करते हैं और कम्युनिस्ट उपद्रवियों तथा लुटेरों की सेनाएँ भी सदा कुछ-न-कुछ खुराफात करती रहती हैं। इस समय चीनी तुर्किस्तान में कोई ऐसी दृढ़ सत्ता नहीं है जिसका अधिकार सब लोग मानते हों।

इसके सिवा चीन के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिन पर कई विदेशी शक्तियों का अधिकार है। इनमें से कुछ हिस्से तो विदेशी शक्तियों ने जबरदस्ती अपने अधीन कर लिये हैं और कुछ हिस्सों का उन्होंने किसी न किसी तरह का पट्टा लिखाकर वहाँ अपने लिए बहुत से सुभीते और विशेष अधिकार प्राप्त कर रखे हैं। हाँगकाँग अँगरेजों के अधिकार में है जिसे उन्होंने सन् १८४१ में निश्चित रूप से अपने राज्य में मिला लिया था। फ्रान्सीसियों ने इंडो-चीन पर तो पूरा-पूरा अधिकार कर ही रखा है। इसके सिवा दक्षिण-पश्चिम में क्वांग चाऊ वान की जो खाड़ी है, उसका ६६ बरस का पट्टा उन्होंने सन् १८६८ में ही लिखा लिया था। अब शंघाई को लीजिए, जिसकी आबादी दस लाख से भी ज्यादा है और जिसमें मुश्किल से ३० हजार चीनी रहते हैं। वह एक सार्वराष्ट्रीय बस्ती हो गई है और उसमें सार्वराष्ट्रीय शासन तथा व्यवस्था होती है। चीन के साथ उसका किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। सारे चीन देश में बहुत से ऐसे बन्दरगाह हैं जो

सन्धिवाले बन्दरगाह (Treaty Ports) कहलाते हैं और जिन में सन्धियों के द्वारा विदेशियों को बहुत से अधिकार मिले हुए हैं। इसके सिवा देश के भीतरी भागों में भी नदियों के किनारे कुछ ऐसे बन्दरगाह हैं जिनमें विदेशियों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। इधर कुछ दिनों से ऐसे स्थानों की संख्या कुछ कम हो गई है, जिनमें विदेशियों को कुछ खास रिआयते मिली हुई थी। इसी प्रकार के स्थानों में वेई-हाई-वाई नाम का एक स्थान है जो ब्रिटिश सरकार ने सन् १९३० में चीन को लौटा दिया था; और तियेन्तसिन में इस प्रकार का जो अधिकार वेलजियनों को था, वह उन्होंने सन् १९३१ में चीन को लौटा दिया था। पहले हानकाऊ में भी अँगरेजों को कुछ अधिकार मिले हुए थे; लेकिन सन् १९२६ में चीन ने स्वयं ही वहाँ की सारी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली थी और तब से आज तक फिर कभी अँगरेजों ने उसे अपने हाथ में करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। लेकिन फिर भी इस समय चीनी भूमि पर विदेशी शक्तियों की जो बस्तियाँ बसी हुई हैं, उन सबके कारण चीनी सरकार का प्रभुत्व और अधिकार बहुत ही कम हो गया है; और इसका कारण यह है कि चीन का जितना विदेशी व्यापार है, उसका बहुत बड़ा अंश शंघाई और हांग-कांग के ही अधिकार में है। और इनमें भी शंघाई तो चीन के शिल्प और उद्योग-धन्धों का सबसे अधिक सहत्त्वपूर्ण केन्द्र है।

विदेशियों के अधिकार में और बाहरी क्षेत्रों में इसी प्रकार की व्यवस्था है; लेकिन फिर भी ये सब स्थान चीनी सरकार के प्रति थोड़ी बहुत निष्ठा और भक्ति अवश्य ही रखते हैं। लेकिन देश के भीतरी भागों की अवस्था तो इस से भी गई-बीती है। बहुत से प्रदेशों पर कम्युनिस्टों का या कम से कम सोवियट नियन्त्रण है। उधर उत्तर-पश्चिम में नानकिंग की

सरकार है और दक्षिण में कैन्टन की सरकार है। इन दोनों के बीच में कियॉंगसी में सोविएट सरकार है, और सोविएट क्षेत्रों में यही सबसे अधिक महत्व का क्षेत्र है। यह बिल्कुल प्रहाड़ी प्रदेश है और इधर कई बरसों से इसका बिल्कुल स्वतन्त्र अस्तित्व चला आ रहा है। च्यांग काई शेक ने यहाँ से सोविएट शासन हटाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं हुई। होनन और हुपेह नामक प्रदेश में भी सोविएट शासन है। परन्तु इन प्रदेशों की राजनीतिक अवस्था प्रायः बदलती रहती है और वहाँ की सरकारों का नियन्त्रण दृढ़ नहीं है। देश के मध्य भाग में भी और दक्षिणी भाग में इसी प्रकार के कुछ सोविएट क्षेत्र हैं। नानकिंग और कैन्टन के बीच में फूकियेन पड़ता है। अभी कुछ ही बरस पहले वहाँ च्यांग काई शेक के विरोध में एक वाम पार्श्व की स्वतन्त्र सरकार स्थापित करने का प्रयत्न किया गया था। लेकिन इसमें कैन्टन के नेताओं ने सहायता नहीं दी, जिससे वह प्रयत्न विफल हो गया और विद्रोहियों का पूरा-पूरा दमन हुआ। कैन्टन की सरकार कभी तो नानकिंग-वाली सरकार के साथ मिल जाती है और कभी उसके विरुद्ध हो जाती है। लेकिन फिर भी उसका सारा नियन्त्रण और शासन स्वतन्त्र ही रहता है। उत्तरी चीन का केन्द्र पेकिन में है, पर वहाँ कोई निश्चित राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। वहाँ का शासन प्रायः प्रान्तीय गवर्नरों या सैनिक नेताओं के हाथ में रहता है। ये लोग कहने के लिए तो नानकिंग के अधीन होते हैं, लेकिन जरा सी बात होते ही चट दूसरी तरफ भी जा मिलते हैं; और फिर अबसर मिलते ही अपने पुराने स्वामियों का भी प्रभुत्व मानने लगते हैं। इधर कई बरसों से इनमें से कुछ गवर्नर और सैनिक नेता जापान की तरफ मिल गये थे। और इधर तीन बरसों से जापान ने चीन में जो उपद्रव

मंचा रक्खा है, वह बहुत कुछ इन लोगों के षडयन्त्र का भी परिणाम है।

इस प्रकार बीस लाख वर्ग मील से भी अधिक, और यदि हम मंचूरिया, मंगोलिया और तिब्बत को भी इसमें शामिल कर लें तो चालीस लाख वर्ग मील से भी अधिक प्रदेश ऐसा है, जिस पर निश्चित रूप से किसी का राजनीतिक स्वामित्व नहीं है; और इसका अधिकांश ऐसा ही है जिसमें कोई निश्चित शासन-प्रणाली भी नहीं है। कोई यह भी नहीं जानता कि इन स्थानों में कितने आदमी रहते हैं। लेकिन फिर भी अनुमान किया जाता है कि इन सब प्रदेशों में ४५ से ५० करोड़ तक आदमी रहते हैं। सारे संसार में जितने आदमी बसते हैं, उनमें से करीब-करीब एक-चौथाई चीनी हैं।

आज-कल पढ़े-लिखे और समझदार लोगों की प्रायः यही धारणा रहती है कि किसी प्रकार का सभ्यतापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए एक दृढ़ और प्रबल राज्य की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। और इसी लिए पाश्चात्य देशों के निवासियों को यह देखकर बहुत अधिक आश्चर्य होता है कि जो चीनी निस्सन्देह रूप से बहुत अधिक सभ्य हैं, वे इस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियों में किस प्रकार जीवन-यापन करते हैं। हम प्रायः सुना करते हैं कि चीन में ऐसे गृह-युद्ध होते रहते हैं, जिनमें बहुत बड़े-बड़े और घने बसे हुए प्रदेश बिलकुल बरबाद हो जाते हैं, वहाँ सदा बहुत बड़ी बाढ़ें आती रहती हैं, अनेक प्रकार के भीषण मारक रोग फैलते रहते हैं, आये दिन बड़े-बड़े अकाल पड़ते हैं, लाखों आदमी अपना घर-बार छोड़कर भाग जाते हैं और लुटेरों और डाकुओं के बड़े-बड़े दल सारे देश में घूमते रहते हैं। उस समय हमें बहुत अधिक आश्चर्य होता है और हम सोचते हैं कि या तो इन चीनियों को अब तक नितान्त

बर्बर अवस्था में पहुँच जाना चाहिए था और या कमर कसकर इस बात का प्रयत्न करना चाहिए था कि यह सारी गड़बड़ी और अन्यवस्था दूर हो जाय और देश में एक ऐसी दृढ़ सरकार स्थापित हो जो सारी प्रजा को एक सूत्र में बाँधकर रख सके। पाश्चात्य देशों के राजनीतिज्ञ भी और व्यापारी भी बराबर चिल्लाते रहते हैं कि चीन में एक प्रबल केन्द्रित सरकार के स्थापित होने की बहुत आवश्यकता है; और जब कभी कोई नेता यह काम करने का वादा करता है, तब हर तरह से उसकी पूरी-पूरी सहायता भी करते हैं। कभी-कभी ऐसा अबसर भी आता है जब देखनेवालों को यह मालूम होने लगता है कि अब शीघ्र ही चीन में एकता स्थापित हो जायगी। लेकिन इसी बीच में फिर कोई ऐसी घटना हो जाती है जो सारे चीन को पहले की तरह झिन्न-भिन्न कर देती है। फिर कोई गृह-युद्ध छिड़ जाता है और फिर पुकार मचती है कि रोजगार चौपट हो रहा है। जो धन पुराने बड़े-बड़े ऋण चुकाने के लिए दिया जाना चाहिए था, वही फिर नये-नये अस्त्र-शस्त्र खरीदने में खतम हो जाता है—पुराने ऋणों का बहुत सा अंश भी अस्त्र-शस्त्र खरीदने में ही लगा है—और लोग चीनियों की इस आदत की शिकायत करने लगते हैं कि वे विदेशियों के साथ घृणा करते हैं। लेकिन सच बात यह है कि सभी विदेशी चीन में केवल इसलिए एक दृढ़ सरकार स्थापित करना चाहते हैं कि हम उससे खूब रुपये वसूल कर सकें। चीनियों की एक यह भी आदत है कि वे राष्ट्रीयता के भावों से प्रेरित होकर बहुत जल्दी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने लग जाते हैं। और इसका कारण यही है कि विदेशियों का मुकाबला करने के लिए और उनके प्रति अपनी घृणा और रोष प्रकट करने के लिए उनके यहाँ कोई संघटित राष्ट्रीय राज्य नहीं है। अब यदि बेचारे चीनियों का देश-प्रेम विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के रूप

मे न प्रकट हो, तो और किस रूप में प्रकट हो ? बस यही बहिष्कार उनका आखिरी सहारा रह जाता है ।

चीनी गांव—चाहे पाश्चात्य आलोचक और उनके साथ बहुत से शिक्षित चीनी भी भले ही लाख चिह्नाया करें, लेकिन फिर भी चीनियों का जीवन बिलकुल ठीक तरह से बीतता चलता है । उस पर इन सब अव्यवस्थाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ने

ता; बल्कि हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी हद तक वे इन सब अव्यवस्थाओं की कोई परवाह भी नहीं करते । इसके सिवा पाश्चात्य आलोचक चीन की राजनीतिक अवस्था देखकर जो यह समझ लेते हैं कि वहाँ किसी तरह का व्यवस्थित शासन नहीं है, यह भी उनकी भूल है । चीन बहुत पुराने जमाने से बीस-बाईस बड़े-बड़े प्रान्तों में बँटा हुआ है और वह एक बहुत बड़ा राष्ट्र समझा जाता है । लेकिन सामाजिक शासन के लिए वहाँ असल इकाई सारा चीनी राष्ट्र नहीं है, बल्कि उसके बहुत ही छोटे-छोटे टुकड़े हैं । सारे राष्ट्र अथवा प्रान्तों पर चाहे जो बीतती रहे, लेकिन गाँवों का जीवन तब तक बराबर ज्यों का त्यों चलता रहता है, जब तक स्वयं उन गाँवों में लड़नेवाली सेनाएँ न आ पहुँचें । और उस अवस्था में भी ज्यों-ही वे सेनाएँ गाँव से हट जाती हैं, त्यों-ही वहाँ के निवासी अपने घावों की मरहम-पट्टी करके फिर पहले की तरह जीवन व्यतीत करने लगते हैं । चाहे कितनी ही बड़ी बरबादी सामने क्यों न दिखाई देती हो और चाहे कितनी ही बड़ी बरबादी क्यों न हो चुकी हो, लेकिन चीन के देहाती अपनी जमीनें जोतने-बोने का काम कभी बन्द नहीं करते । हाँ, कुछ प्रदेश वहाँ अवश्य ऐसे हैं, जिन पर हर साल कुछ न कुछ आक्रमण होते रहते हैं, जैसे शान्टुंग के कुछ हिस्से । और ऐसे स्थानों के लोग वहाँ से हटकर ऐसी जगहों में चले गये हैं, जहाँ आबादी कम है । मंचूरिया और भीतरी मंगोलिया में

आज-कल बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे ही स्थानों से आकर बसे हैं। और इन प्रदेशों में हर साल मीलों बंजर जमीनें ये नवागन्तुक खेती-बारी के लिए तैयार करते हैं और उनमें फसलें पैदा करते हैं।

तात्पर्य यह कि गाँवों का जीवन प्रायः ज्यों का त्यों चलता रहता है; और इसका मुख्य कारण यही है कि चीन में परिवार की संस्था बहुत ही दृढ़ है। चीन में पूर्वजों की जो उपासना और पूजा होती है, वह पारिवारिक संस्था की दृढ़ता का सबसे अच्छा लक्षण है। राजनीति के विस्तृत क्षेत्र में चाहे जो हुआ करे, लेकिन आर्थिक और सामाजिक बातों में परिवार सदा एक सूत्र में बंधा रहता है और परिवारों के वर्ग गाँवों की अनुस्यूता नष्ट नहीं होने देते। चीन के अधिकांश स्थानों में आबादी बहुत घनी है और हर परिवार के पास प्रायः इतनी थोड़ी जमीन होती है कि उसकी पैदावार से बहुत ही मुश्किल से उसका गुजर होता है। वे लोग पश्चात्य वैज्ञानिक यंत्रों से तो किसी प्रकार की सहायता लेते ही नहीं; हाँ मेहनत भर-पूर करते हैं और जमीन से अधिक-से-अधिक जितनी पैदावार हो सकती है, उतनी कर लेते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सारे चीन में आबादी बहुत घनी है। दक्षिण की ओर के तो अधिकांश स्थान बहुत घने बसे हुए हैं, पर उत्तर में उतनी आबादी नहीं है और वहाँ से एशिया के मध्य भाग तक अभी बहुत-सी जमीन खाली पड़ी है। इस समय तो वह सारी जमीन प्रायः रेगिस्तान के ही रूप में है; हाँ, 'आबपाशी करके' वह खेती-बारी के काबिल बनाई जा सकती है। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। उधर यांग्जी की तराई और दक्षिणी प्रान्तों में आबादी इतनी ज्यादा है कि अब वहाँ और आदिमियों के बसने की बिल्कुल गंजाइश नहीं रह गई है। वहाँ के धीरे किसान चावल

और हरी तरकारियाँ पैदा करते हैं और रेशम के कीड़े पालते हैं और सोया बीन (एक प्रकार की फली) और मछली के साथ वही चावल और तरकारियाँ खाकर दिन बिताते हैं। यहाँ से उत्तर की ओर चावल की जगह लोग गेहूँ और ज्वार पैदा करते हैं। उत्तर में आबादी अपेक्षाकृत बहुत कम है। लेकिन सामाजिक जीवन वहाँ भी वैसा ही है, जैसा दक्षिण में है। वहाँ बाढ़ें भी खूब आती हैं और अकाल भी खूब पड़ते हैं और लड़ाके सरदार तथा डाकू भी बहुत होते हैं; और भविष्य की सभी बातें प्रायः अनिश्चित रहती हैं। यदि कोई बात निश्चित रहती है तो केवल यही कि कोई न कोई आफत जरूर आवेगी।

परिवार और गाँव का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है और दोनों मिलकर अपना काम चलाते रहते हैं। लेकिन ये गाँव अधिक आदिम युग के निवासियों के गाँवों की तरह न तो सारी दुनिया से न्यारे होकर ही रहते हैं और न इनका काम बिना दूसरे गाँवों और शहरों की सहायता के चलता है। चीन एक सभ्य देश है। वहाँ एक बहुत जबरदस्त सांस्कृतिक एकता है और किसी तरह का कठोर वर्ग-भेद भी नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर एक मामूली चीनी किसान चीनी अथवा पाश्चात्य दृष्टि के अनुसार शिक्षित होता है। फिर भी चीनी प्रजा के सबसे नीचेवाले स्तर को छोड़ कर और बाकी सभी स्तरों के लोग प्रायः अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। वहाँ बहुत दिनों से एक प्रकार की परीक्षा-प्रणाली चली आती है; और चाहे जितने गृह-युद्ध होते रहे, और चाहे जितने शासन-सम्बन्धी परिवर्तन होते रहे, परन्तु यह परीक्षा-प्रणाली बराबर चली चलती है; और इसके द्वारा एक मामूली किसान का लड़का भी बहुत बड़ा विद्वान् हो सकता है। चीन में विद्वानों का बहुत आदर होता है और उन्हें प्रायः जीविका-निर्वाह के लिए चिन्तित नहीं

होना पड़ता। चीन में जो बड़े सेनापति और गवर्नर होते हैं, उनका कोई अलग वर्ग नहीं है और न ये कार्य तथा पद वहाँ वंशानुक्रमिक रूप से ही चलते हैं। सभी तरह के लोग वहाँ सेनापति भी हो सकते हैं और गवर्नर भी। जापान में जिस तरह कुछ लोगों को वंशानुक्रमिक रूप से कुछ विशेष अधिकार होते हैं, उस तरह चीन में नहीं होते और न वहाँ भारत की तरह जाति-पाँति का ही कोई ऐसा बखेड़ा है, जो सारी प्रजा की एकता में बाधक हो। वहाँ का धार्मिक मत-भेद भी एकता में बाधक नहीं होता। अधिकांश चीनी बौद्ध है; लेकिन इसके सिवा वहाँ ताओ-धर्म और कनफूची का चलाया हुआ धर्म माननेवाले लोग भी बहुत हैं। लेकिन इन तीनों ही धर्मों के अनुयायी समान रूप से पूर्वजों की पूजा और उपासना करते हैं। और तीनों ही धर्मों के अनुयायी मजे में मिलकर रहते हैं। उनमें कभी किसी तरह का लड़ाई-झगड़ा नहीं होता। बल्कि कुछ लोग तो वहाँ ऐसे भी हैं जो तीनों ही धर्म समान रूप से मानते और तीनों ही धर्मों के कृत्य करते हैं। पाश्चात्य जगत् के धर्मों की अपेक्षा चीन का धर्म बहुत-सी बातों में भिन्न है। कनफूची का चलाया हुआ धर्म वस्तुतः आचारात्मक ही है और न तो उसमें किसी तरह का धार्मिक कृत्य ही होता है और न उसमें कोई ईश्वर-विद्या ही होती है। उसका मुख्य उद्देश्य तो लोगों को यही बतलाना है कि जीवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए और अपना आचरण किस प्रकार का रखना चाहिए। उसमें पर-लोक और स्वर्ग सरीखी वे सब बातें भी नहीं हैं जो साधारणतः और धर्मों में लोगों की भावुकता की तृप्ति के लिए हुआ करती हैं। इसके विरुद्ध बौद्ध-धर्म और ताओ-धर्म अधिकतर कर्म-कांड की बातों से सम्बन्ध रखते हैं। उनमें आचार सम्बन्धी बातें भी बहुत कम हैं और भावुकता के लिए भी बहुत थोड़ी जगह है। कनफूचीवाले

धर्म का अनुयायी बहुत सहज में बौद्ध भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में कोई बात ऐसी नहीं है जिससे दूसरे का विरोध होता हो। यदि कोई चीनी ये दोनों ही धर्म मानता हो तो भी पाश्चात्य जनता की दृष्टि से वह धार्मिक व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। और फिर सबसे बढ़कर बात यह है कि चीन की राजनीति पर चीनी धर्म का कुछ भी प्रभाव नहीं है। चीनियों का आचार-शास्त्र व्यक्तिगत है, राजनीतिक नहीं है; और धार्मिक मत-भेद के कारण चीनियों की राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति में कोई बाधा नहीं होती। चीन में बहुत-से मुसलमान भी रहते हैं और उनकी संख्या शायद दो करोड़ या इससे भी कुछ अधिक होगी। लेकिन वे भारत के मुसलमानों की तरह राष्ट्रीयता के मार्ग के कटक नहीं बनते और न बौद्ध तथा ताओ चीनियों के साथ लड़ना-भिड़ना ही पसन्द करते हैं। भारतीय मुसलमानों की तरह वे इस्लामी सभ्यता और संस्कृति के प्रचार के ठेकेदार भी नहीं बनते, उनकी दृष्टि भी शुद्ध राष्ट्रीय होती है और वे सबसे बढ़कर अपने देश का हित चाहते हैं। वे संसार के दूसरे इस्लामी देशों में आश्रित होकर रहना नहीं चाहते। और इन सब बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि वे भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रीयता और देश-प्रेम की बहुत अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। चीन में ईसाइयों की संख्या भी तीस-चालीस लाख के लगभग है। चीन में ईसाई धर्म-प्रचारकों का जाल तो बहुत बड़ा बिछा है, लेकिन उन्हें चीनियों को ईसाई धर्म में दीक्षित करने में बहुत ही कम सफलता होती है। धार्मिक क्षेत्र में तो नहीं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अवश्य ही ईसाई धर्म-प्रचारक बहुत अच्छा काम करते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ अधिकतर ईसाई धर्म-प्रचारक अमेरिका से ही आये हुए हैं; और उन लोगों की समझ में यह बात अच्छी तरह आ गई है कि यहाँ ईसाई धर्म

का सहज में प्रचार नहीं हो सकता। और इसी लिए वे व्यर्थ गिरजे न बनवाकर प्रायः अस्पताल, स्कूल और कालेज ही बनाते हैं और अधिकतर शिक्षा-प्रचार तथा स्वास्थ्य-रक्षा का ही काम करते हैं।

चीनी राष्ट्रीय दल के नेता प्रायः इस बात की शिकायत करते हैं कि चीन में दिन-पर-दिन मिशन स्कूलों और कालेजों की जो संख्या बढ़ती जाती है और विदेशी लोग पूँजी लगाकर यहाँ जो कल-कारखाने और कोठियाँ आदि खोल रहे हैं, इससे चीन की प्राचीन संस्कृति धीरे-धीरे नष्ट होती जा रही है। अमेरिकन लोग चीन में शिक्षा का जो प्रचार कर रहे हैं और अमेरिका के विश्व-विद्यालयों में चीनी विद्यार्थियों को जो शिक्षा मिल रही है, उससे भी प्राचीन संस्कृति के नाश में बहुत सहायता मिल रही है। इसमें सन्देह नहीं कि अमेरिका की यह नीति उसका व्यापार बढ़ाने में बहुत अधिक सहायक होती है। जो चीनी अमेरिकन कालेजों में शिल्प और उद्योग आदि की शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे अधिकतर अमेरिकन साज-सामान से ही परिचित होते हैं, उन्हीं की नाप-तौल और दूसरी खास-खास बातें जानते हैं और उन्हीं का काम करने का ढंग सीखते हैं। और इसीलिए उन्हें जिस चीज की जरूरत होती है, वह अमेरिका से ही खरीदते हैं। और इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि चीनी विद्यार्थियों की अमेरिकन साँचे में जो यह ढलाई होती है, उससे चीन की प्राचीन संस्कृति की बहुत-सी परम्परागत बातें नष्ट होती जा रही हैं। चीन के जिन प्रदेशों में पाश्चात्य शिल्प और उद्योग-धन्यो की जड़ जम गई है, उन प्रदेशों के देहातियों की रहन-सहन भी जल्दी-जल्दी बदलती जा रही है और उनकी बहुत-सी बातें पाश्चात्य ढंग से ही होने लगी है। चीन में जितने प्रकार के राष्ट्रीय आन्दोलन होते हैं, उन सबके नेता और प्रवर्तक भी वही लोग होते हैं जो

दूसरे देशों में शिक्षा प्राप्त करके आते हैं। चीन के अधिकांश विद्यार्थी पहले अमेरिका और पश्चिमी युरोप में शिक्षा प्राप्त करने जाते थे। फिर वे जापान जाने लगे और अब अधिकतर सोविएट रूस में जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। चीन की आधुनिक राष्ट्रीयता के जनक स्व० दा० सन-यात-सेन के अनुयायी प्रायः वही चीनी थे, जो या तो दूसरे देशों में जाकर बस गये थे और या अपने देश से किसी प्रकार निर्वासित कर दिये गये थे। दूसरा प्रसिद्ध चीनी नेता यूजेन-चेन पहले ट्रिनिडाड में रहा करता था। च्यांग-काई-शेक ने सैनिक शिक्षा मास्को में रहकर प्राप्त की थी। उसका सबसे बड़ा सहायक और आर्थिक विषयो का सबसे अच्छा ज्ञाता टी० बी० सूंग हारवर्ड विश्वविद्यालय का स्नातक है और च्यांग काई-शेक की स्त्री ने, जो सूंग की बहन है, वेलेस्ली कालेज में शिक्षा पाई थी। सूंग की एक और बहन थी जो सन-यात-सेन को व्याही थी और उसने भी जार्जिया के वेरिलियन कालेज में शिक्षा पाई थी। इस विदेशी और विशेषतः अमेरिकन प्रभाव ने चीन की पुरानी सांस्कृतिक परम्परागत बातों में बहुत कुछ परिवर्तन और सुधार तो अवश्य कर दिया है, लेकिन वह चीनी संस्कृति का नाश नहीं कर रहा है और न उसे केवल अनुकरणशील ही बना रहा है। वहाँ की प्राचीन सांस्कृतिक परम्परा इतनी प्रबल और दृढ़ है कि उसका जल्दी नाश हो ही नहीं सकता। चीन में यद्यपि बोलियाँ तो कई बोली जाती हैं, पर बहुत दिनों तक वहाँ साहित्य की भाषा केवल एक ही रही है और इसी लिए सारे देश में चीनी संस्कृति का प्रचार बहुत सहज में हो सका था। यद्यपि यह भाषा बहुत ही जटिल है और हर जगह इसका प्रचार करना बहुत ही परिश्रम-साध्य है, परन्तु फिर भी इसे साधारणतः सभी चीनियों ने मान्य कर लिया है; और इसी ने अब एक और भाषा के प्रचार के लिए बहुत अच्छा

रास्ता भी तैयार कर दिया है। अब चीन में जो नया साहित्य प्रस्तुत हो रहा है, वह सब उत्तरी मंडारिन बोली में है और उसी का अब सब जगह प्रचार होने लगा है।

चीनी प्रजातन्त्र—आज-कल चीन में जो प्रजातन्त्र स्थापित है, उसका आरम्भ सन् १९११ वाली सफल क्रांति के उपरान्त सन् १९१२ में हुआ था। सन-यात-सेन ने विदेश में रह कर एक क्रान्तिकारी संस्था का संघटन किया था और उस संस्था के नेतृत्व में सबसे पहले दक्षिणी चीन में क्रांति की थी। दक्षिणी चीन के निवासियों ने ही उत्तर में पहुँच कर मंचू राजवंश के उस अन्तिम राजा को सिंहासन से उतारा था, जिसे अब जापान ने मंचुको के सिंहासन पर बैठाया है और जो अब जापानियों के हाथ की कठ-पुतली बना हुआ है। चीन का राष्ट्रीय दल कोमिन्तांग कहलाता है। सन-यात-सेन ने पहले जो संघटन किया था, उसी के स्थान पर इस दल की सृष्टि १९११ वाली क्रांति के समय हुई थी। सन-यात-सेन ही चीनी प्रजातन्त्र का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। उस समय ऐसा जान पड़ता था कि चीन में भी पाश्चात्य पार्लमैण्टरी प्रतिनिधिसत्तात्मक शासन-प्रणाली के ढंग पर प्रतिनिधिसत्तात्मक प्रजातन्त्र स्थापित होना चाहता है। उस समय यद्यपि दक्षिणी चीन की सेनाएँ उत्तरी प्रदेश में घुस गई थी और वहाँ उन्होंने विजय भी प्राप्त कर ली थी और वहाँ के सेनापतियों को यांग्जी की तराई में भगा दिया था, तो भी उत्तरी प्रान्तों में प्रतिनिधिसत्तात्मक आन्दोलन ज्यादा जोर नहीं पकड़ सका था। वहाँ युआनशि-काई के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना तैयार थी जो दक्षिणी सेनाओं को आगे बढ़ने से बहुत सहज में रोक सकती थी। युआनशि-काई नये प्रजातन्त्र के साथ समझौता करने के लिए तो तैयार था, लेकिन वह यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि इस

प्रजातन्त्र का राष्ट्रपति सन-यात-सेन हो। युआन के साथ और भी ऐसे बहुत से शक्तिशाली लोग मिले हुए थे जो एक ऐसी हलकी क्रान्ति करना चाहते थे जिससे चीनी समाज की आर्थिक व्यवस्था में, जहाँ तक हो सके, बहुत ही कम विक्षेप हो। सन-यात-सेन यह नहीं चाहता था कि और अधिक भगड़ा बढ़े और वह प्रजातन्त्र के लिए अधिक-से-अधिक लोगों को एक में मिलाना चाहता था; इसलिए कुछ ही महीनों तक राष्ट्रपति के पद पर रह कर अन्त में उसने यह भगड़ा मिटाने के लिए उस पद का परित्याग कर दिया और उसकी जगह युआन-शि-काई राष्ट्रपति हो गया। इस प्रकार इस नवीन चीनी प्रजातन्त्र का आरम्भ उस चरमवादी सन-यात-सेन के नेतृत्व में नहीं हो सका था, जिसकी मृत्यु सन् १९२५ में हुई थी और जो तब से नये चीन का नेता और प्रवर्तक माना जाता है, बल्कि उस युआन-शि-काई के नेतृत्व में हुआ था जो सन-यात-सेन की चरम सीमावाली नीति का किसी तरह पालन नहीं करना चाहता था। सन-यात-सेन ने अपनी सारी नीति का आगे चलकर एक “टेस्टामेन्ट” या इच्छा-पत्र में उल्लेख किया था जो तब से अब तक कोमिन्टांग दल के लिए वेद-स्वरूप हो गया है। इस टेस्टामेन्ट में सन-यात-सेन के उन सभी विचारों का समावेश है, जिनका प्रचार करने के लिए वह जीवन भर प्रयत्न करता रहा। इसमें उसने यह घोषणा की थी कि हमारे प्रजातन्त्र के मुख्य आधार तीन सिद्धान्त हैं—राष्ट्रीयता, प्रतिनिधितन्त्र और साम्यवाद। वह एक ऐसा प्रजातन्त्र स्थापित करना चाहता था जो सारे चीनी राष्ट्र को मिलाकर एक ऐसी प्रबल शक्ति का रूप दे सके जो समस्त बाह्य हस्तक्षेपों और आक्रमणों को सहज में हटा कर दूर कर सके। पाश्चात्य देशों के प्रतिनिधिसत्तात्मक सिद्धान्तों के अनुसार वह अपने नये राष्ट्रीय राज्य का संघटन करना चाहता था और वह एक इस

तरह के साम्यवाद का प्रचार करना चाहता था जो चीनी समाज के आर्थिक संघटन के अनुरूप हो और जिसकी व्याख्या करते हुए वह कहा करता था—“प्रजा को इस बात का पूरा-पूरा अधिकार होना चाहिए कि जीवन-निर्वाह के साधन उसे ठीक तरह से प्राप्त हो।”

लेकिन युआन-शि काई इन सिद्धान्तों के अनुसार चीन का फिर से संघटन नहीं करना चाहता था। इसके विपरीत वह अपनी व्यक्तिगत सत्ता और प्रभुत्व दृढ़ करने के प्रयत्न में लग गया, जिससे क्रान्तिकारियों में बहुत ही विकट मत-भेद और विरोध उत्पन्न होने लगे। सन् १६१३ में दक्षिणवालों ने सन-यात-सेन के नेतृत्व में एक विद्रोह खड़ा किया जिसे युआन ने सफलतापूर्वक दबा दिया। सन-यात-सेन कैन्टन से भगा दिया गया और उसने चीन के बिलकुल भीतरी भाग में जाकर शरण ली और वही से उसने फिर से अपना राष्ट्रीय आन्दोलन खड़ा करने का प्रयत्न आरम्भ किया। इसके दूसरे ही साल यूरोप में महायुद्ध छिड़ गया जिससे जापान को अपना दुष्ट उद्देश्य सिद्ध करने का अच्छा अवसर मिल गया। उस समय जापान भी मित्र शक्तियों के साथ मिला हुआ था, इसलिए उत्तरी चीन में जरमनों के अधिकार में जितने स्थान थे, उन सब पर जापान ने कब्जा कर लिया और शान्दुङ्ग प्रदेश में भी उसने अपनी सेनाएँ भेज दीं। सन् १६१५ में जापान ने युआन-शि-काई के सामने अपनी वह प्रसिद्ध “इक्कीस माँगें” पेश की जो यदि पूरी तरह से मान ली जाती तो चीनी स्वतन्त्रता का पूर्ण रूप से नाश ही कर डालती। उस समय जापान ने सारे चीन देश पर एक प्रकार से अपना सरक्षण ही स्थापित कर रक्खा था। उस समय यूरोपीय शक्तियाँ महायुद्ध में लगी हुई थी और इस ओर बिलकुल ध्यान नहीं दे सकती थी। और युआन-शि-काई की

नीति यह थी कि जिस तरह से हो सके, जापान को कुछ दे-दिला कर राजी रखना चाहिए। लेकिन जापान के साथ समझौता करने के उसने जो प्रयत्न किये थे, उनसे देश में बहुत अधिक असन्तोष फैल गया; और जब दिसम्बर १६१५ में उसने अपने आप को सारे चीन का सम्राट् घोषित कर दिया, तब तुरन्त ही एक नया विद्रोह खड़ा हो गया। उस समय जो गृह-युद्ध आरम्भ हुआ था, उसी में युआन मारा गया था। लेकिन तभी से चीन बहुत से टुकड़ों में बँट गया। तब से अब तक वहाँ बराबर प्रतिद्वन्द्वी सेनापतियों में खूब लड़ाइयाँ भगाड़े होते आ रहे हैं। हर एक सेनापति के हाथ में एक या दो प्रान्त हैं और सभी अपने पड़ोसी प्रान्तों के सेनापतियों को परास्त करने के प्रयत्न में लगे रहते हैं—सभी एक दूसरे को खा जाना चाहते हैं। राजधानी पेकिन में एक बहुत कमजोर सरकार रहती है और वहाँ का सेनापति जिसे चाहता है, उसे उस सरकार का प्रधान बना देता है। यह प्रधान भी प्रायः नाम मात्र का ही शासक होता है और देश के शासन पर इसका कुछ भी अधिकार नहीं होता। सन् १६१७ में पेकिन सरकार ने यह सोचा था कि यदि हम भी महायुद्ध में सम्मिलित हो जायेंगे तो जापान के विरुद्ध हमें यूरोपीय शक्तियों की सहायता प्राप्त हो सकेगी; और इसी आशा से उसने युद्ध की घोषणा भी कर दी थी। जब युद्ध समाप्त हो गया, तब शान्ति महासभा में चीन की ओर से इस बात का प्रयत्न भी किया गया था कि शान्दुङ्ग पर से जापान का प्रभुत्व हट जाय। लेकिन जब उसका यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ, तब उसने वासईवाली सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। तो भी वह राष्ट्र-संघ में अवश्य सम्मिलित हो गया। लेकिन उस समय भी वहाँ एक ऐसी ही सरकार थी जिसके हाथ में कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी।

लेकिन इस बीच में भी चीनी बराबर यह सिद्ध करते रहे थे कि यद्यपि हमारे यहाँ कोई राष्ट्रीय राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब लोग मिलकर काम कर सकते हैं। सन् १९१६ में वहाँ जापानियों के विरुद्ध जो बहिष्कार आरम्भ हुआ था, वह एक राष्ट्रीय आन्दोलन था और सारे देश में उसने खासा जोर पकड़ा था। जापानी नीति पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ा था और इसी लिए सन् १९२१ में जो वाशिंगटन कान्फ्रेंस हुई थी, उसमें अमेरिका की तरफ से दबाव पड़ने पर जापान ने अपनी पुरानी नीति में कुछ परिवर्तन और सुधार भी किया था। उस समय वाशिंगटन में नौ महा शक्तियों की जो सन्धि हुई थी और जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिकन संयुक्त राज्य और जापान आदि सभी सम्मिलित थे, उसके अनुसार यह निश्चित हुआ था कि चीन के शासन और सीमा सम्बन्धी स्वतन्त्रता की रक्षा की जिम्मेदारी इन सभी शक्तियों पर रहेगी। इन सब शक्तियों ने मिलकर यह भी निश्चय किया था कि चीन के बाजारों में सभी राष्ट्रों के व्यापारियों के साथ समान व्यवहार होगा; और यह भी वादा किया था कि चीन में जो राजनीतिक झगड़े होंगे, उनसे हम लोग कोई अनुचित लाभ नहीं उठावेंगे और न अपने लिए कोई खास रियायत या सुभीता चाहेंगे। लेकिन इसके बाद ही पहले तो जापान ने मंचूरिया पर अधिकार कर लिया; और तब अप्रैल १९३४ में यह घोषणा कर दी कि चीन के सम्बन्ध में किसी यूरोपीय या विदेशी शक्ति को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। और १९३७ में एक बहाना निकालकर चीन पर आक्रमण भी कर दिया जिससे आज दिन तक वहाँ लड़ाई चल रही है। इन सब बातों के कारण वाशिंगटनवाली वह सन्धि रही के टोकरे में चली गई है। चीन १०

का सर्वनाश हो रहा है और अब तक उसके लगभग २० लाख आदमी मरे और घायल हुए हैं और सारे देश का नागरिक जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है। लेकिन बाकी आठ महाशक्तियों में से, जिन्होंने चीन की रक्षा का जिम्मा लिया था, कोई च तक नहीं कर रहा है। सभी चुपचाप यह लड़ाई देख रहे हैं। बीच-बीच में इन शक्तियों के अधिकृत स्थानों और उनके अधिकारों आदि पर भी और उनकी बस्तियों पर भी हमले होते रहते हैं। लेकिन अभी तक किसी को मौखिक विरोध करने के सिवा किसी प्रकार का क्रियात्मक विरोध करने का साहस नहीं हो रहा है।

सन् १९१६ में चीन में जापानियों के विरुद्ध जो आन्दोलन उठा था और शान्टुंग तथा दूसरे विदेशी प्रभाव-क्षेत्रों के सम्बन्ध में जो झगड़ा हुआ था, उसके कारण चीन के राष्ट्रीय आन्दोलन में फिर बहुत बल आ गया था और सारे देश में कोमिन्तांग का पक्ष बहुत प्रबल हो गया था। इस बार इस आन्दोलन का नेतृत्व विद्यार्थियों ने ग्रहण किया था। उस समय विद्यार्थी बहुत बड़ी संख्या में राष्ट्रीय मंडे के नीचे आये थे और जापानी माल का अधिकतर बहिष्कार उन्हीं के प्रयत्न से हुआ था। मिशनरियों के बहुत से स्कूल और कालेज हैं जिनसे विद्यार्थियों की संख्या बहुत बढ़ गई है; और चीनी जनता में विद्यार्थियों का वर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली हो गया है। उन विद्यार्थियों को शिक्षा भी अच्छी मिली है। इन सब बातों के कारण उन्होंने चीनी मजदूरों का भी अच्छा संघटन किया था और विशेषतः उन मजदूरों का और भी अच्छा संघटन किया था जो विदेशी पूँजीदारों के यहाँ काम करते थे। एक तो चीन में विद्या का यो ही बहुत आदर है और दूसरे वहाँ जाति-पाँति या वर्ग-विभेद भी नहीं है। इसलिए विद्यार्थियों का

आन्दोलन बहुत जोरदार हो गया था और उसका राजनीतिक प्रभाव भी बहुत बढ़ गया था। इधर कई वरसों से देश में राष्ट्रीय सरकार की जो बहुत जोरदार माँग हो रही है और विदेशियों के विरुद्ध जो उग्र राष्ट्रीय नीति काम में लाई जा रही है, वह सबसे अधिक विद्यार्थियों के वर्गों के कारण ही है। सन् १९१६ में देश के सभी विद्यार्थी सन-यात-सेन के बहुत बड़े भक्त और अनुयायी थे और आगे चलकर उनमें से बहुतों पर कम्युनिस्ट विचारों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। इसलिए कोमिन्टांग में विद्यार्थी ही सबसे ज्यादा और जोशीले काम करते थे। इसके सिवा उनमें संघटन और आन्दोलन करने की योग्यता भी बहुत अधिक है; और इसी लिए नानकिंग की सरकार सबसे अधिक इन विद्यार्थियों से ही डरती है।

महायुद्ध के उपरान्त उत्तरी चीन में तो केवल विद्यार्थी ही सन-यात-सेन के अनुयायी थे, लेकिन दक्षिणी चीन की सारी जनता उसकी पूरी भक्त हो गई थी। सन् १९१६ के बाद से ही प्रायः सारे देश में कोमिन्टांग का बहुत अच्छा संघटन होने लगा था। सन् १९१६ तक वाम पार्श्ववालों ने सन-यात-सेन के विचारों का कोई विशेष विरोध नहीं किया था। लेकिन उसके बाद जब एशियाई रूस में भी रूसी सोविएट प्रजातन्त्र स्थापित हो गया और खासकर जब सन् १९१६ में रूसियों के मुकाबले में जापानी सेना को साइबेरिया छोड़ कर पीछे हटना पड़ा, तब से चीनियों पर रूसियों का प्रभाव भी धीरे-धीरे बढ़ने लगा और वे सोविएट रूस के भक्त होने लगे। नवयुवक चीनी विद्यार्थी अच्छी संख्या में शिक्षा प्राप्त करने के लिए रूस पहुँचने लगे और रूसी घर भी चीन में कम्युनिस्ट सिद्धान्तों का प्रचार करने लगे। यहाँ तक कि सन् १९२० में चीन में कम्युनिस्ट दल की भी स्थापना हो गई।

कोमिन्टांग और कम्यूनिस्ट —कुछ दिनों तक तो कम्यूनिस्ट और कोमिन्टांग दोनों एक-दूसरे के विरुद्ध काम करते रहे। लेकिन सन् १९२३ में चीन में रहनेवाले रूसी प्रतिनिधि जोफे और सन-यात-सेन में समझौता हो गया और दोनों मिलकर काम करने लगे। यद्यपि कम्यूनिस्ट दल ज्यों का त्यों बना रहा, लेकिन फिर भी उस दल के बहुत से लोग कोमिन्टांग में सम्मिलित होने लगे। सन-यात-सेन ने यह घोषणा कर दी कि चीन अभी इस योग्य नहीं हुआ है कि यहाँ कम्यूनिस्ट सिद्धान्तों के अनुसार काम किया जाय और जोफे ने भी यह बात मंजूर कर ली। इसके सिवा उसने यह भी कह दिया कि सारे चीन में एक ही राष्ट्रीय और स्वतन्त्र सरकार की स्थापना में रूस पूरी-पूरी सहायता देगा। इसके बाद चीन में एक नया क्रान्तिकारी प्रजातन्त्र स्थापित करने में सहायता देने के लिए रूस से बोरोडिन नामक एक अधिकारी कैन्टन भेजा गया। और उसी के साथ चीन की नई क्रान्तिकारी सेना को सैनिक शिक्षा देने के लिए जनरल व्लुचर भी आया। व्हामपोआ नामक स्थान में एक सैनिक-विद्यालय भी स्थापित हो गया और उसका प्रधान वह च्यांग-काई-शेक बनाया गया, जिसे सन-यात-सेन ने अपना दूत बना कर रूस भेजा था। इस प्रकार एक ऐसी नई संस्था तैयार हो गई थी जिससे एक नई शक्ति के नेता तैयार हो सकते थे। बोरोडिन के कहने पर कम्यूनिस्ट दंग से कोमिन्टांग का राजनीतिक दृष्टि से फिर से संघटन हुआ। लेकिन जान-बूझ कर गरीब किसानों और मजदूरों पर उसका आधार नहीं रक्खा गया था, क्योंकि तब तक उनका कोई अच्छा संघटन ही नहीं हो सका था। पर साथ ही मजदूरों और किसानों के संघ स्थापित करने का भी प्रयत्न आरम्भ हो गया था। प्रायः सारे दक्षिणी चीन में सोविएटों के दंग पर मजदूरों और किसानों के संघ बनने

लग गये थे। दक्षिण मे दक्षिण पार्श्व के नेताओं ने चीन को रूसी सॉचे में ढालने का बहुत विरोध किया था और इसके लिए उन लोगो ने कुछ सिर भी उठाया था; लेकिन सन् १९२४ मे उन लोगों का पूरा-पूरा दमन कर दिया गया।

उस समय तक कोमिन्टांग और कम्युनिस्टो का जोर सिर्फ दक्षिणी चीन में ही था। उत्तरी चीन मे भी और यांग्जी की तराई मे भी अधिकतर ऐसे सैनिक नेताओं का ही प्रभुत्व था जो प्रायः आपस मे लड़ते-भगड़ते रहते थे। जनरल फेंग तथा दूसरे उत्तरी नेताओं के साथ समझौता करने के लिए जब सन-यात-सेन पेकिन गया, तब वही मार्च १९२५ मे उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरने के बाद कोई ऐसा नेता न रह गया जिसकी अधीनता सब लोग मान सकते और जिसके नेतृत्व मे क्रान्तिकारी आन्दोलन आगे बढ़ सकता। उस समय कुछ लोगों मे नेतृत्व और अधिकार के लिए आपस में भगड़ा होने लगा। एक ओर तो च्यांग-काई-शेक था जिसकी सहायता बोरोडिन करता था और दूसरी ओर सन-यात-सेन का प्रिय सहायक लायाओ-चुंग-काई था, जिसे पहले कम्युनिस्टो ने नेतृत्व के लिए खड़ा किया था और जिसने कम्युनिस्टो तथा कोमिन्टांग मे समझौता कराने में सबसे अधिक सहायता दी थी। लेकिन जब चुङ्ग-काई की हत्या कर डाली गई, तब च्यांग-काई-शेक इस नये आन्दोलन का नेता हो गया।

इस बीच में वाम पार्श्ववालो का आन्दोलन यांग्जी तराई में भी और दक्षिणी चीन में भी खूब जोरों से चल रहा था। जगह-जगह श्रमिकों के संघ स्थापित हो रहे थे और कई हड़तालें भी हुई थी, जिनमें से अधिकतर विदेशी पूँजीदारो के कारखानों में हुई थीं। अनेक स्थानो पर विदेशियों के विरुद्ध बड़े-बड़े प्रदर्शन भी होते थे। ३० मई १९२५ को अगरेज अफसरों की आज्ञा से

पुलिस ने हड़ताली प्रदर्शकों पर गोलियाँ भी चलाई थी, जिससे सारे देश में अंगरेजों के विरुद्ध एक जबरदस्त लहर उठ खड़ी हुई थी और ब्रिटिश माल का खूब जोरो से बहिष्कार होने लगा था। इस बहिष्कार के कारण चीन में ब्रिटिश व्यापार को जो गहरा धक्का लगा था, उससे वह आज तक संभलने नहीं पाया है। १९२६ में जब कि यह आन्दोलन खूब जोरों से चल रहा था, च्यांग-काई-शेक ने अपनी नवशिक्षित सेना को लेकर उत्तरी चीन पर चढ़ाई कर दी और वहाँ के स्थानिक सेनापतियों को मार भगाया और सब जगह कोमिन्तांग की नई क्रांति की घोषणा कर दी। सारे देश में ईसाई मात्र के विरुद्ध आन्दोलन होने लगा और बहुत से स्थानों से पादरी भी भगा दिये गये। मध्य यांग्जी में क्रान्तिकारियों ने चीनी कस्बों पर तो अधिकार कर ही लिया, पर साथ ही हांकाऊ के उन स्थानों पर भी अधिकार कर लिया, जिनमें विदेशियों को कुछ विशिष्ट अधिकार मिले हुए थे। ऐसे स्थानों में एक अधिक महत्व का वह स्थान भी था जिस पर अंगरेजों का विशेष अधिकार था। शंघाई में जो सार्वराष्ट्रीय बस्ती थी, उसमें इन क्रांतिकारियों के डर से बहुत-सी सार्वराष्ट्रीय सेनाएँ रक्खी गईं। इन सेनाओं की सबसे बड़ी टुकड़ी ग्रेट ब्रिटेन की भेजी हुई थी। मार्च १९२७ में राष्ट्रीय सेनाओं ने नानकिंग पर भी अधिकार कर लिया, जो पहले उत्तरवालों के हाथ में था। उस समय विदेशियों के मुहल्लों में खूब लूट-मार हुई थी और कुछ विदेशी मारे भी गये थे। बाकी सभी विदेशियों को नानकिंग छोड़कर भागना पड़ा था। यांग्जी नदी में जो अमेरिकन लड़ाई के जहाज थे, उन्हें चीन के राष्ट्रीय सैनिकों पर इसलिए गोलेबारी भी करनी पड़ी थी, जिसमें वे उन विदेशियों पर आक्रमण न कर सके जो शहर छोड़कर भाग रहे थे।

इस नानकिंगवाली घटना के कारण ही नई चानी क्रान्ति का

विकास रुक गया और उसका रुख ही बिलकुल बदल गया। कोमिन्तांग मे दक्षिण पक्ष के जो लोग थे, वे इस घटना के कारण रूसियों के घोर विरोधी हो गये। वे लोग कहते थे कि रूसियों ने यहाँ विदेशियों के विरुद्ध जो आन्दोलन खड़ा किया था, उसी के कारण यह सारा उपद्रव हुआ है। तभी से च्यांग-काई-शेक का भाव भी बदल गया और चीनी महाजनो तथा व्यापारियों की आर्थिक सहायता तथा विदेशी पूँजीदारों के प्रोत्साहन से च्यांग-काई-शेक ने अपनी एक ऐसी मजबूत सरकार बनाई जो कम्युनिस्टों की घोर विरोधी थी; और तब से वह रूसियों और उनके मददगारों को इस आन्दोलन से अलग करने लगा। शंघाई और दूसरे कई कस्बों में कम्युनिस्टों के बड़े-बड़े कत्ले-आम हुए। कुछ ही हफ्तों के अन्दर कोमिन्तांग का फिर से संघटन हुआ। इस संघटन का नेता च्यांग-काई-शेक था और यह संघटन रूसियों का पूरा-पूरा विरोधी हो गया था। इसी बीच में बोरोडिन के नाम मास्को से आये हुए कुछ ऐसे पत्र भी पकड़े गये, जिनमे गुप्त रूप से यह संकेत किया गया था कि कोमिन्तांग मे जितने बड़े और अधिकार के पद हैं, वे सब कम्युनिस्ट दल के सदस्य अपने हाथ मे ले ले; सन-यात-सेन के जो वाम पक्षवाले उत्तराधिकारी हैं, वे सब जगहों से हटा दिये जायँ; यांग्जी की तराई में कम्युनिस्टों के नियंत्रण में मजदूरों और किसानों की नई सेना तैयार की जाय, बिना सरकार से पूछे ही सब किसान अपनी जमीन पर पूरा-पूरा अधिकार कर ले; और ऐसा रास्ता तैयार किया जाय जिसमे कम्युनिस्ट दल आगे चलकर कोमिन्तांग को पूरी तरह से दबा सके। इन्हीं सब बातों के कारण उस समय सब चीनी रूसियों के घोर विरोधी और शत्रु हो गये थे। बोरोडिन ने ये सब बातें बिलकुल गुप्त रखी थी, क्योंकि वह जानता था कि यदि इन सूचनाओं के अनुसार सब काम करने का

प्रयत्न किया जायगा, तो भारी आफत खड़ी हो जायगी। लेकिन जब ये सब बातें खुल गईं, तब कोमिन्टान्ग के वाम पार्श्ववाले नेता रूसियों के विरोधी हो गये और च्यांग-काई-शेक ने बिना किसी विशेष विरोध के अपना पूरा-पूरा प्रभुत्व स्थापित कर लिया।

अब चीन के दक्षिण पार्श्ववाले भी च्यांग-काई-शेक के मददगार हो गये और वे विदेशी सरकारें भी उसकी सहायता करने लग गईं, जो यह समझती थीं कि चीन को कम्युनिस्टों के चुंगुल से इसीने बचाया है। इसी लिए सन् १९२७ के बाद से च्यांग-काई मजे में नानकिंग में शासन करने लगा। उसे प्रसन्न करने के लिए ग्रेट ब्रिटेन ने अपने वे विशेष अधिकार भी छोड़ दिये जो उसे हांकाऊ में मिले थे। अमेरिकन संयुक्त राज्यों ने भी आयात और निर्यात पर कर लगाने की उसे पूरी स्वतन्त्रता दे दी; वे सब सन्धियाँ भी फिर से दोहराकर ठीक कर दी जो चीन के साथ समानता का व्यवहार करने में बाधक होती थी; और उसे यह भी विश्वास दिला दिया कि कुछ स्थानों में हम लोगों को जो विशेष अधिकार प्राप्त हैं, उनका भी हम परित्याग कर देंगे। रूस तथा कुछ दूसरे देशों ने यह घोषणा भी कर दी है कि अमुक-अमुक स्थानों पर से हम अपना विशेष अधिकार हटा लेते हैं। इससे दूसरे देशों को भी विवश होकर चीन के साथ नरमी का बरताव करना पड़ा। परन्तु विशिष्ट क्षेत्रों के विशिष्ट अधिकार का यह प्रश्न अब भी बहुत से अंशों में पहले की ही तरह बना हुआ है। सन् १९३० में नानकिंग की सरकार ने यह घोषणा तो कर दी थी कि अब हमारे किसी क्षेत्र में किसी विदेशी सरकार को कोई विशेष अधिकार न रहेगा। लेकिन जब बड़ी-बड़ी शक्तियों का उस पर दबाव पड़ा, तब उसने विवश होकर इस निश्चय के अनुसार काम करना रोक दिया। जबसे नानकिंग की सरकार ने रूसियों को दूर हटा दिया, तब

से विदेशी सरकारें च्यांग-काई-शेक को एक दृढ़ सरकार स्थापित करने के लिए ऋण देने लगीं और सुधारों के बड़े-बड़े वादे किये जाने लगे। सन् १९२७ से १९३० तक नानकिंग की सरकार ने प्रायः पाश्चात्य ढंग के बहुत से नये-नये कानून बनाये और इस बात का प्रयत्न आरम्भ किया कि सारे देश में न्याय की व्यवस्था एक सी हो और विदेशी शक्तियों की प्रजा को अपने लिए विशेष अधिकार माँगने का अवसर न रह जाय। अब फिर से चीन में और विशेषतः शंघाई में विदेशी पूँजी से नये-नये कल-कारखाने खुलने लगे और आयात तथा निर्यात पर कर लगाने की स्वतन्त्रता मिल जाने के कारण नानकिंग सरकार के लिए आय का एक और द्वार खुल गया। पहले विदेशी शक्तियों के साथ चीन की जो सन्धियाँ हुई थीं, उनके अनुसार विदेशों से वहाँ जानेवाले माल पर पाँच रुपये सैकड़े से अधिक चुंगी नहीं लग सकती थी; पर अब नानकिंग की सरकार यह चुंगी बढ़ा सकती थी। लेकिन जितना धन सरकार के हाथ में आता था, उसका बहुत बड़ा अंश सेना-विभाग के लिए ही व्यय होता था। इसका कारण यही था कि देश के बहुत बड़े भाग पर च्यांग-काई-शेक की सरकार का कोई विशेष नियन्त्रण नहीं था; और बिना सैनिक बल की सहायता के नानकिंग की सरकार का काम एक दिन भी नहीं चल सकता था। इसके सिवा कियांगसी और यांग्जी प्रान्तों में जो सोविएटें स्थापित हो चुकी थीं, उन पर आक्रमण करने के लिए भी च्यांग को और अधिक सेना की आवश्यकता थी। उसके पास इतने सिपाही ही नहीं थे जो जापान के साथ लड़ सकते। उत्तरी चीन के सेनापतियों ने मंचूरिया पर जो चढ़ाई की थी, उसकी सहायता के लिए भेजने को भी उसके पास सेना नहीं थी। सन् १९३२ में शंघाई में चीनियों ने जापानियों का जो डटकर और वीरता-

पूर्ण विरोध किया था, उनमें दक्षिण की ऐसी ही सेनाएँ थीं जो च्यांग-काई-शेक अथवा उसकी सरकार की मित्र नहीं थी। यद्यपि आरम्भ में उसने कैन्टनवालों की सहायता से ही और उन्हीं के बल पर सारे चीन में कोमिन्टांग का आन्दोलन चलाना चाहा था, लेकिन फिर भी जब वह वाम पार्श्व से हटकर दक्षिण पार्श्व में चला गया, तब दक्षिणी चीन के निवासियों ने उसे सहायता देना बन्द कर दिया। कैन्टन भी यद्यपि नाम मात्र के लिए नानकिंग की अधीनता मानता था, पर फिर भी इधर बहुत दिनों से वह प्रायः स्वतन्त्र ही चला आ रहा है।

चीन का संघटन—यही कारण है कि नानकिंग की सरकार के संघटन-विधान में तो कुछ और ही प्रकार की बातें लिखी हुई हैं और वह प्रणाली उससे बिल्कुल भिन्न है जिसके अनुसार चीन का शासन होता है। वास्तव में नानकिंग की सरकार का स्वरूप कुछ ऐसा ही रक्खा गया था कि वह सारे देश का शासन कर सके। सारे देश में कोमिन्टांग ने ही राष्ट्रीय क्रान्ति की थी और इस नई सरकार में इसी लिए सब अधिकार भी उसी दल के हाथ में रक्खे गये थे। सन् १९२७ के बाद कुछ दिनों के लिए कोमिन्टांग पर दक्षिण पार्श्ववालों का ही पूरा-पूरा अधिकार हो गया था। सन् १९२८ में वहाँ का जो संघटन-विधान बना था, वह इसी दल की राष्ट्रीय महासभा में स्वीकृत हुआ था। यह विधान उन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर बना था, जो सन-यात-सेन ने अपने टेस्टामेन्ट में स्थिर किये थे। चीनी राष्ट्रीय दलवालों के लिए यह टेस्टामेन्ट एक पूज्य धर्म-पुस्तक के रूप में हो गया था। दल की सभाओं में जोर-जोर से इसका पाठ किया जाता था और इसकी व्याख्याएँ की जाती थीं; लेकिन इसके सिद्धान्तों के सम्बन्ध में कभी कोई वाद-विवाद नहीं होता था। इस संघटन-विधान के अनुसार यह निश्चय हुआ था कि

शासन के सब काम करने के लिए पाँच काउन्सिले रहे । यथा—पहली एक्जिक्यूटिव या कार्यकारिणी, दूसरी लेजिस्लेटिव या कानून बनानेवाली, तीसरी जुडीशल या न्याय की व्यवस्था करनेवाली, चौथी एक्जामिनिंग या परीक्षाओं की व्यवस्था करनेवाली और पाँचवीं कन्ट्रोलिंग या नियन्त्रण रखनेवाली । ये काउन्सिले मन्त्री-मंडल से बिलकुल अलग हैं और मन्त्री-मंडल के सदस्य ही भिन्न-भिन्न काउन्सिलों के सभापति और उप-सभापति होते हैं और वही राज्य के भिन्न-भिन्न महकमों के प्रधान भी होते हैं । शासन-सम्बन्धी सब कार्यों के लिए एक्जिक्यूटिव काउन्सिल की ही आज्ञा मानी जाती है । यही मन्त्री-मंडल भी स्थापित करती है, उनके कर्तव्य भी निश्चित करती है और उनके कामों की देख-रेख भी करती हैं । कानून बनाने का सब काम लेजिस्लेटिव काउन्सिल के हाथ में है । एक्जिक्यूटिव काउन्सिल सब तरह के कानूनों के मसौदे, सन्धियाँ और आय-व्यय का सालाना लेखा तैयार करके लेजिस्लेटिव काउन्सिल में भेजती है और लेजिस्लेटिव काउन्सिल उन्हें मंजूर कर सकती है, उनमें सुधार या परिवर्तन कर सकती है और आवश्यकता समझने पर उन्हें ना-मंजूर भी कर सकती है । तात्पर्य यह कि यही काउन्सिल एक प्रकार से पार्लैमेंट के सब काम करती है । लेकिन अन्यान्य सभी काउन्सिलों की तरह इस काउन्सिल के सदस्य भी कोमिन्टांग के द्वारा ही नामांकित होते हैं और इनका कोई सार्वजनिक निर्वाचन नहीं होता । अदालतों पर पूरा-पूरा नियन्त्रण जुडीशल काउन्सिल का रहता है । इधर कुछ बरसों में वहाँ जो बड़े कानून बने हैं, कम-से-कम कहने के लिए वे सब इसी काउन्सिल के बनाये हुए हैं । चीन में बहुत पुराने जमाने से सरकारी पदों के लिए कई तरह की बड़ी-बड़ी परीक्षाएँ चली आ

रही हैं; और यह आशा की जाती है कि आगे चलकर देश में चाहे जिस प्रकार की शासन-प्रणाली स्थापित हो, परन्तु मरकरारी पदों के लिए ये परीक्षाएँ बराबर बनी ही रहेंगी। इन्हीं सब परीक्षाओं की व्यवस्था करने के लिए वहाँ एक्जामिनिंग काउन्सिल बनी है। जबतक कोई व्यक्ति इस काउन्सिल के द्वारा नियत की हुई परीक्षा में उत्तीर्ण न हो, तब तक वह किसी मरकरारी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग प्रकार की परीक्षाएँ हैं। कंट्रोलिंग काउन्सिल समस्त सरकारी नौकरियों की व्यवस्था करती है और सब मार्गजनिक लेखे भी वही जाँचती है। वस यही वह पँचदरी प्रणाली है, जिस पर कम-से-कम सिद्धान्ततः आज-कल चीन का सारा शासन और संघटन-विधान आश्रित है।

परन्तु यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन सब काउन्सिलों के सदस्य निर्वाचित नहीं होते, बल्कि नामांकित होते हैं। इनके सदस्य तभी तक अपने पद पर रह सकते हैं, जबतक कोमिन्टांग उन्हें रखना चाहे या रहने दे। आज-कल जिस चीन का नानकिंग से शासन होता है, वह सिद्धान्ततः उसी प्रकार का एक-दलीय राज्य है, जिस प्रकार का इटली, जर्मनी या सोविएट रूस में है। परन्तु कार्य रूप में इस प्रणाली में उक्त देशों की प्रणालियों से बहुत अन्तर पड़ जाता है। यद्यपि कोमिन्टांग दल के सभी लोग यह मानते हैं कि हम सन-थात-सेन के स्थिर किये हुए सिद्धान्तों पर ही चलते हैं, परन्तु मूल सिद्धान्त के सम्बन्ध में वे लोग उस प्रकार एक-मत नहीं हैं, जिस प्रकार फ़ैसिस्ट, नाज़ी या कम्यूनिस्ट दल के सब सदस्य एक-मत होते हैं। कम्यूनिस्टों के निकाल दिये जाने पर भी कोमिन्टांग में कई ऐसे दल मौजूद हैं जो अक्सर आपस में लड़ते-झगड़ते रहते हैं।

उस से बहुत से ऐसे व्यापारी और महाजन भी हैं जो साम्यवाद के/कट्टर दुश्मन हैं; और पाश्चात्य देशों में शिक्षा पाये हुए ऐसे लोग भी हैं जो सभी प्रकार के उदार विचार रखते हैं और साम्यवादी सिद्धान्तों के भी भक्त हैं। उसमें ऐसे किसान और मजदूर भी हैं जो अपनी सभी प्रकार की आर्थिक कठिनाइयाँ तुरन्त ही दूर करना चाहते हैं; और ऐसे सैनिक नेता भी हैं जो केवल नानकिंग के साथ सम्बन्ध बनाये रखने के कारण ही अपने प्रान्तों को ठीक तरह से अपने नियन्त्रण में रख सकते हैं। मतलब यह कि एक कम्युनिस्टों को छोड़कर चीन में राष्ट्रीयता के जितने प्रकार के पक्षपाती हैं, वे सभी कोमिन्टांग में मौजूद हैं। कोमिन्टांग की जितनी बड़ी-बड़ी सभाएँ और जलसे होते हैं, उनमें प्रायः सभी वर्गों और दलों के प्रतिनिधि रहते हैं और उन सब को आपस में लड़ा-भिड़ाकर ही च्यांग-काई-शेक को अपने सब काम निकालने पड़ते हैं। च्यांग-काई-शेक के हाथ में सब अधिकार इसलिए है कि देश का सबसे बड़ा सैनिक बल उसके अधिकार में है। वाम पक्षवाले च्यांग-काई-शेक के विरोधी हैं और उन्हें अधिकांश सहायता दक्षिणी चीन से मिलती है। भिन्न-भिन्न दलों में वहाँ केवल साधारण विरोधी ही नहीं होता, बल्कि सदा उनमें गृह-युद्ध छिड़ने की भी सम्भावना बनी रहती है। और तमाशा यह है कि सभी दल यह भी कहते हैं कि हम सन-यात-सेन के सिद्धान्तों को पूरी तरह से मानते हैं। हमेशा इस बात का डर बना रहता है कि कोमिन्टांग कहीं छिन्न-भिन्न न हो जाय। सन् १९३३ के अन्त में यूजेन-चेन के नेतृत्व में कई फूकियन नेता इस दल से बिलकुल अलग हो गये थे और वह उन्नीसवीं सेना उनकी मदद पर थी, जिसका काम शंघाई की रक्षा करना था। उस समय वे लोग यही देखना चाहते थे कि च्यांग-काई-शेक का विरोध करने के लिए कैन्टन के नेता

हमारा साथ देते हैं या नहीं। लेकिन कैन्टनवालो ने उनका साथ नहीं दिया और फूकियन विद्रोह का चुपचाप दमन हो जाने दिया। लेकिन फिर भी निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता था कि कैन्टनवाले किसी अवसर पर नानकिंग की सरकार के साथ लड़ नहीं जायेंगे।

चीन का भविष्य—एक तो कोमिन्टांग में सदा दलों के झगड़े-बखेड़े होते रहते हैं, दूसरे उसका वास्तविक और पूरा अधिकार भी केवल कुछ ही प्रान्तों पर है। तिस पर मध्य चीन में उसे बराबर कम्युनिस्टों के साथ लड़ना पड़ता है; उसकी सारी आय सैनिक कार्यों में लगती रहती है; और स्वतन्त्र प्रान्तों के गवर्नर अपने यहाँ का एक पैसा भी जल्दी नानकिंग सरकार के खजाने में नहीं जाने देते। इन सब बातों को देखते हुए यदि नानकिंग की सरकार चीन की सामाजिक और आर्थिक दशा में कुछ भी सुधार न कर सकी हो तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। फिर इधर कई बरसों से उसे मंचुको के लिए जापान के साथ बराबर कुछ-न-कुछ लड़ाई भी लड़नी ही पड़ती है। जापानी सेना चीन की बड़ी दीवार पहले ही पार कर चुकी थी और पेकिन के दरवाजों तक पहुँच चुकी थी; और इसलिए कोई नहीं जानता था कि वह कब भीतरी मंगोलिया या उत्तरी चीन पर आक्रमण कर बैठेगी। और इधर तीन बरसों से तो जापान ने चीन के साथ पूरा-पूरा युद्ध ही छेड़ रक्खा है। इस बीच में चीन का प्रायः दो तृतीयांश जापानी सेना द्वारा पद-दलित हो चुका है और कई प्रान्तों में जापान ने अस्थायी सरकारें भी स्थापित कर रक्खी हैं। वहाँ के अधिकांश स्थानों पर जापानी हवाई जहाजों ने खूब गोले बरसाये हैं; और जहाँ तक हो सका है, देश को खूब तहस-नहस किया है। च्यांग-काई-शेक की सरकार जैसे-तैसे उसका मुकाबला किये चलती है। पहले आशा तो यही थी कि

चीन पर बहुत जल्दी जापान का अधिकार हो जायगा। लेकिन फिर भी चीनी प्रजा जापानियों का अच्छा सामना कर रही है। जिन स्थानों पर जापानी सेनाएँ अधिकार कर चुकी हैं, उन स्थानों की चीनी प्रजा भी जापानियों को तंग करती रहती है। कभी जापानी सेनाएँ हल्ला करके बहुत आगे तक जा पहुँचती हैं और कभी अनुकूल अवसर पाकर चीनी सेनाएँ उन्हें दूर तक खदेड़ आती हैं। यही अवस्था आज-कल चल रही है। कोई यह नहीं कह सकता कि इसका कब और कैसे अन्त होगा। परन्तु जापान सारे चीन पर अधिकार कर लेना जितना सहज समझता था, उसकी अपेक्षा वह उसे अब कहीं अधिक कठिन प्रतीत हो रहा है। जिन महाशक्तियों ने चीन की रक्षा की जिम्मेदारी ली थी, वे भी चुपचाप बैठी तमाशा देख रही हैं। चीन ने अब तक कई बार राष्ट्र-संघ में जापान की शिकायत की और कई बार उससे सहायता की प्रार्थना की, लेकिन कुछ भी परिणाम नहीं हुआ।

च्यांग-काई-शेक के पास बहुत बड़ी सेना है, जिसमें लाखों सिपाही हैं। उसे स्वयं भी अच्छी सैनिक शिक्षा मिली है। अपने यहाँ से रूसियों को निकालने के बाद उसने बहुत से जर्मनों को ऊँचे ओहदों पर रक्खा था, जिनसे वह प्रायः परामर्श लिया करता था। लेकिन यह भी कहा जाता है कि चीनी सेनाएँ लड़ाई के काम के लिए ठीक नहीं होतीं। चीनी सैनिक बहुत जल्दी युद्ध-क्षेत्र से भाग जाते हैं। यहाँ तक कि जिस समय लड़ाई होती रहती है, उस समय भी प्रायः बड़े-बड़े सेनापति अपने समस्त सैनिकों के साथ एक पक्ष को छोड़कर दूसरे पक्ष में जा मिलते हैं। चीन में लोग प्रायः अपना पेट भरने के लिए ही फौज में भरती होते हैं, क्योंकि वहाँ भोजन मिलना प्रायः बहुत ही कठिन होता है। वे न तो लड़ने के लिए ही फौज में भरती

होते हैं और न देरा-प्रेम की प्रेरणा से सैनिक बनते हैं। उन्हें तो पेट भरने के लिए भोजन चाहिए। प्रायः ऐसा भी होता है कि जब कुछ दिनों तक सैनिकों की तनख्वाह रुक जाती है, तब वे आस-पास के देशों में लूट-पाट भी शुरू कर देते हैं। वहाँ की सेना में कुछ अच्छे सैनिक भी हैं, लेकिन अधिकतर सैनिक ऐसे ही हैं जिन पर या तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता और या जिनके पास लड़ाई का पूरा सामान ही नहीं होता। प्रान्तीय सेनाओं के पास प्रायः पूरी बन्दूकें और गोले आदि भी नहीं होते। विशेषतः कम्युनिस्ट सेनाओं के पास तो लड़ाई के सामान की और भी कमी रहा करती थी। उनका काम उसी सामान से चलता था जो वे अपने शत्रुओं से छीना करती थीं। इधर कुछ दिनों से च्यांग-काई-शेक को विदेशों से कुछ ऋण भी मिल रहा है और लड़ाई के सामान की भी मदद मिल रही है। तो भी सारे देश की भौति उसकी सेनाएँ भी न तो अधिक व्यवस्थित ही हैं और न अधिक संघटित ही। इतना होने पर भी वह जो बराबर जापान का मुकाबला करता चलता है, यह आश्चर्य है।

बहुत से लोगो का बहुत दिनों से बराबर यही विश्वास चला आता था कि चीनी सैनिक लड़ाई के काम के नहीं होते। लेकिन जब जापानियों ने शंघाई पर आक्रमण किया था, तब दक्षिणी चीन की सेनाओं ने जिस तरह जमकर उनका मुकाबला किया था, उसे देखकर सारा संसार चकित हो गया था। स्वयं जापानी भी उनकी वीरता देखकर दंग हो गये थे। अगर उन्हें पहले से मालूम होता कि यहाँ चीनी सैनिक इस तरह बहादुरी से हमारा मुकाबला करेंगे, तो वे शायद उन पर चढ़ाई ही न करते। और सबसे बढ़कर तो इस बात से स्वयं चीनियों को ही आश्चर्य हुआ था। लेकिन दक्षिण की ये सेनाएँ अपवाद-स्वरूप थी। जिस समय जापानी सेना ने मंचुको पर चढ़ाई की थी, उस

समय उत्तरी चीन की सेनाएँ उसके सामने बिल्कुल ठहर नहीं सकी थी। लेकिन शंघाई में चीनियों ने अवश्य ही यह सिद्ध कर दखलाया था कि अच्छी सैनिक शिक्षा मिलने पर और लड़ाई का काफी सामान पास होने पर वे क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी पूरी तरह से सैनिक कार्यों के लिए चीनी उपयुक्त नहीं हो सके हैं। अभी उनमें उन गुणों का बहुत कुछ अभाव है जो योद्धाओं में और विशेषतः आज-कल के योद्धाओं में होने चाहिए। लेकिन हाँ, शंघाईवाले झगड़े में भी और इस युद्ध ने भी, जो इधर दो बरसों से चीन और जापान में हो रहा है, यह बात अच्छी तरह सिद्ध कर दी है कि जिस काम के लिए चीनी लड़ना चाहते हैं, वह काम अगर उनके मन के मुताबिक हो, तो फिर वे जरूर ही खूब अच्छी तरह लड़ सकते हैं।

इस समय तो चीन में हर जगह राजनीतिक और सामरिक गड़बड़ी ही मची हुई है। इधर सौ बरसों से कई पाश्चात्य साम्राज्यवादी शक्तियाँ उसे खूब लूट और नोच-खसोट रही हैं। जब जिसे जहाँ मौका मिलता है, तब वह वहाँ का कुछ-न-कुछ हिस्सा किसी-न-किसी तरह अपने कब्जे में कर लेता है। बहुत से पाश्चात्य देशों ने वहाँ अपने-अपने अलग प्रभाव-क्षेत्र बना रखे हैं और उसके बहुत से हिस्से अपने राज्य में मिला भी लिये हैं। बहुत से स्थानों में विदेशियों ने अपने लिये विशेष अधिकार भी प्राप्त कर लिये हैं और वहाँ अपनी बस्तियाँ भी बसा ली है। यूरोपवालों ने वहाँ पहुँचकर ये सब बातें ठीक उसी तरह की हैं, जिस तरह किसी बर्बर और असभ्य देश में पहुँचकर की जाती हैं। जारशाही के जमाने में रूस ने मंचूरिया पर अधिकार कर रक्खा था, मंगोलिया में भी वह कुछ दूर तक पहुँच गया था; और लक्ष्मणों से ऐसा मालूम होता था कि सारे

उत्तरी चीन पर उसका अधिकार हो जायगा। लेकिन जापान ने उक्त स्थानों से रूसियों को मार भगाया और स्वयं वहाँ अधिकार कर लिया। अँगरेजों ने हांगकांग अपने राज्य में मिला लिया और यह कहना शुरू किया कि यांग्जी हमारे प्रभाव-क्षेत्र में है। फ्रांसीसियों ने पहले तो दक्षिण-पश्चिम में इंडो-चीन पर अधिकार कर लिया और तब वहाँ से चीन के मध्य भाग में प्रवेश करना चाहा था। जापान ने पहले तो फारमोसा और कोरिया ले लिया और तब शान्टुङ्ग पर से जर्मनों का अधिकार हटाकर वहाँ अपना अधिकार कर लिया और फिर मंचूरिया और जेहोल भी अपने हाथ में ले लिया। एक अमेरिकन ही ऐसे थे जिन्होंने चीन के किसी प्रदेश पर अधिकार नहीं किया था और जो बिना अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किये वहाँ केवल अपना व्यापार ही बढ़ाते थे। अमेरिकन यह चाहते थे कि सारे चीन में मुक्त-द्वारवाली नीति का पालन हो और सब जगह सभी देशों को व्यापार करने का समान रूप से अधिकार हो, किसी विशिष्ट क्षेत्र में किसी महा-शक्ति को कोई विशेष अधिकार न मिले। यूरोपीय महा-युद्ध के समय कुछ दिनों के लिए परिस्थिति कुछ बदल गई थी, क्योंकि चीन पर से विदेशी शक्तियों का दबाव हट गया था। लेकिन जैसा कि जापान की सन् १९१५ वाली इक्कीस माँगों से स्पष्ट सिद्ध होता है, यूरोपीय शक्तियों का दबाव हटते ही वह चीन के सिर पर आ सवार हुआ। युद्ध के बाद कुछ दिनों तक तो जापान को इसलिए आगे बढ़ने का साहस नहीं होता था कि यूरोप की सभी शक्तियाँ अमेरिकन संयुक्त राज्यों के साथ मिलकर हमारा विरोध करेंगी; और चीन के बाजारों में फिर से अपना सिक्का जमाने के लिए ग्रेट-ब्रिटेन को बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ा था। लेकिन जब सारे संसार में व्यापार की मन्दी आई और उसके बाद ही यूरोप में

इटली और जर्मनी प्रबल होने लगे और सब को एक नये महायुद्ध की आशंका होने लगी, तब यूरोपियन शक्तियाँ भी और संयुक्त राज्य भी स्वयं अपने ही यहाँ की व्यवस्था में इतने व्यस्त हो गये कि किसी को सुदूर पूर्व की ओर देखने का अवसर ही नहीं मिलता था। इस प्रकार जापान को अपनी उच्चाकांक्षाएँ पूरी करने का बहुत अच्छा अवसर मिल गया। पहले तो उसने मंचूरिया पर अधिकार कर लिया। राष्ट्र संघ के सामने चीन परियाद ही करता रह गया और अमेरिकन संयुक्त राज्य उसकी परियादों का समर्थन भी करते रहे, लेकिन उन परियादों की जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई और जापान ने अच्छी तरह देख लिया कि अब कोई पाश्चात्य शक्ति चीन के मामले में दखल नहीं देगी, तब उसने चीन के साथ वह युद्ध छेड़ दिया जो इधर तीन चरसो से बहुत कुछ भीषण रूप से चल रहा है और जिसके कारण चीन की दो-तिहाई जमीन जापानी सैनिकों के पैरों तले रौंदी जा रही है।

इन सब बातों से पता चलता है कि पहले तो कई यूरोपीय महाशक्तियाँ चीन की शत्रु थीं, लेकिन इधर कुछ दिनों से केवल जापान ही उसका सबसे बड़ा शत्रु हो रहा है। इधर जापानवालों का यह विचार दिन-पर-दिन बढ़ता जाता है कि एशिया के सब देशों को मिलकर एक हो जाना चाहिए; और जापान का कर्तव्य है कि वह सुदूर पूर्व को पाश्चात्य शक्तियों के प्रभुत्व से निकाल कर स्वतन्त्र करे। चीन के कुछ लोगों को भी यह विचार अच्छा लगता है। वे सोचते हैं या तो हमें जापान के साथ समझौता करना पड़ेगा और उस की मुख्य-मुख्य बातें माननी पड़ेंगी और या सोविएट रूस के हाथ में फँसना पड़ेगा; और इन दोनों में वे जापान को इसलिए अच्छा समझते हैं कि कम्युनिस्टों से उन्हें बहुत डर लगता है। लेकिन एक पक्ष वहाँ

ऐसा भी है जो न तो जापान की अधीनता ही स्वीकृत करना चाहता है और न सोविएट रूस के अधिकार में ही जाना चाहता है। वह स्वतन्त्र रूप से अपना विकास करना चाहता है। अमेरिका के संयुक्त राज्य यदि प्रशान्त महासागर पार करके सुदूर पूर्व में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहें तो बिना यूरोपीय महाशक्तियों की सहायता के ऐसा नहीं कर सकते। और यूरोपवालों के सिर खुद ही इतने बड़े-बड़े भगड़े आ पड़े हैं कि वे चीन के लिए जापान के साथ लड़ नहीं सकते। बहुत दिनों से लोग यह समझते आ रहे थे कि चीन को या तो जापान के हाथ पड़ना पड़ेगा और या सोविएट रूस के हाथ। सोविएट रूस एक बार चीन में धोखा खा चुका है और अपनी षड़यन्त्रवाली प्रवृत्ति के कारण बहुत से चीनियों को अपना शत्रु बना चुका है। यह ठीक है कि आज-कल सोविएट रूस की वह नीति नहीं है जो सन् १९२७ में थी और जिसके अनुसार बोरोडिन के पास मास्को से गुप्त आज्ञाएँ आई थीं। लेकिन फिर भी उसके उस कार्य ने चीनियों के मन में भय और आशंका तो उत्पन्न कर ही दी है। अब तो सोविएट रूस की नीति प्रायः यही रहती है कि जहाँ तक हो सके, दूसरों की बातों में दखल न दिया जाय। लेकिन जापान के सम्बन्ध में यह बात नहीं है। एक तो उसे अपनी प्रजा को बसाने के लिए स्थान चाहिए; दूसरे अपनी आर्थिक अवस्था सुधारने के कुछ साधन चाहिए। और तीसरे एशिया और विशेषतः पूर्वी एशिया में वह अपना पूरा-पूरा प्रभुत्व भी स्थापित करना चाहता है। और इन्हीं सब कारणों से उसने जर्मनी और इटली के साथ समझौता करके यूरोपीय शक्तियों को तो उधर यूरोप की समस्याओं में फँसा दिया है और स्वयं इधर चीन पर चढ़ाई कर दी है। लेकिन अभी यह भी नहीं कहा जा सकता कि चीन का इस प्रकार जापान के

हाथ में चला जाना सोविएट रूस चुपचाप देखता रहेगा और इस के प्रतिकार का कोई उपाय न करेगा। बहुत सम्भव है कि कोई उपयुक्त अवसर देखकर वह जापान के हाथ से चीन को छुड़ाने का भी कोई प्रयत्न करे। वस्तुतः चीन के भविष्य पर संसार के अनेक देशों का भविष्य निर्भर है। यदि चान पर जापान का प्रभुत्व पूरी तरह से स्थापित हो गया, तो सम्भवतः समस्त पूर्वीय एशिया और कदाचित् भारत में भी सैनिक साम्राज्यवाद की तूती बोलने लगेगी और फिर यह आशा नहीं रह जायगी कि संसार के सब देश एक साथ मिलकर शान्तिपूर्वक रह सकेंगे। उस अवस्था में कोई नई शान्तिमयी राजनीतिक व्यवस्था बहुत दूर जा पड़ेगी। इसके विपरीत यदि सोविएट रूस को चीन में भी सोविएट शासन-प्रणाली स्थापित करने में सफलता हुई तो फिर युरोप के बहुत बड़े भाग में भी और भारतवर्ष में भी कम्युनिस्ट सिद्धान्तों की विजय होगी।

इधर वर्तमान युरोपीय युद्ध के समय जब जापान ने देखा कि इंग्लैण्ड आत्म-रक्षा की चिन्ता में बुरी तरह ग्रस्त है, तब उसने इंग्लैण्ड पर दबाव डालकर बरमा के रास्ते चीन तक युद्ध-सामग्री का भेजा जाना बन्द करा दिया। और जब फ्रान्स ने जर्मनी के आगे हथियार डाल दिये, तब वह इस बात के प्रयत्न में लगा है कि इंडो-चीन हमारे हाथ में आ जाय और हम वहाँ पहुँचकर दक्षिण-पश्चिम के रास्ते भी चीन पर आक्रमण कर सकें और वहाँ अपने सैनिक अड्डे भी कायम कर सकें। जर्मनी भी फ्रान्स पर इस बात के लिए दबाव डाल रहा है कि वह इंडो-चीन के सम्बन्ध में जापान की मर्गे पूरी करे। पर फ्रान्स जानता है कि जब एक बार इंडो-चीन में जापान की सेना पहुँच जायगी, तब वह देश सदा के लिए हमारे हाथ से निकल जायगा। इसी लिए वह राजी नहीं हो रहा है। अभी

बात-चीत चल रही है। पर लक्ष्मणों से जान पड़ता है कि इस मामले में फ्रान्स को दबना पड़ेगा; और उस अवस्था में चीन पर और एक तरफ से आक्रमण होने लगेगा।

: ५ :

ब्रिटिश भारत की राजनीतिक प्रणाली

इस पुस्तक में अब तक जितने देशों की राजनीतिक प्रणालियों का वर्णन किया गया है, वे सब स्वतंत्र देश हैं। उनका सारा शासन स्वयं उन्हीं देशों के निवासियों के हाथ में है। लेकिन अब हम भारतवर्ष के सम्बन्ध की भी कुछ बातें बतलाना चाहते हैं, जो परतन्त्र होने पर भी कई दृष्टियों से बहुत महत्व रखता है। पहली बात तो यह है कि एक चीन को छोड़कर संसार में और कोई ऐसा देश नहीं है जो आबादी में भारत की बराबरी कर सके। और दूसरी बात यह है कि इस देश में एक साम्राज्यवादी शक्ति की स्थापित की हुई एक ऐसी सरकार है जो इस देश के निवासियों के सामने उत्तरदायी नहीं है। भारतवर्ष कम-से-कम इस बात का अवश्य ही एक अच्छा उदाहरण उपस्थित करता है कि दूर देश की कोई सरकार एक बहुत बड़े देश को किस प्रकार अपने नियन्त्रण में रखती है। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि भारत में औपनिवेशिक शासन अपने आदर्श रूप में दिखाई देता है। वास्तव में इस प्रकार के शासन का कोई आदर्श या निश्चित रूप ही नहीं सकता। कई महाशक्तियों के बड़े-बड़े औपनिवेशिक साम्राज्य हैं और उन उपनिवेशों में भिन्न-भिन्न संस्कृतियों तथा सभ्यताओं के लोग रहते हैं। फिर सब उपनिवेशों और देशों की अवस्थाएँ भी एक-सी नहीं होती। इसलिए किसी देश का शासन नमूने का

काम नहीं दे सकता। परन्तु सस्कृति, सभ्यता और जन-संख्या आदि के विचार से भारत का एक विशेष महत्व है और उसके भविष्य का भी संसार के भविष्य पर बहुत कुछ प्रभाव पड़ सकता है। और इसी लिए ब्रिटिश भारत की राजनीतिक व्यवस्था के सम्बन्ध की कुछ मुख्य-मुख्य बातें यहाँ बतलाई जाती हैं।

भारतवर्ष दो भागों में विभक्त माना जा सकता है। उसका एक भाग तो वह है जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन है और दूसरा भाग वह है जिस में देशी राजाओं के राज्य हैं। देशी रियासतों में सात-आठ करोड़ आदमी बसते हैं। लेकिन हम इस प्रकरण में केवल ब्रिटिश भारत की राजनीतिक अवस्था का वर्णन करना चाहते हैं। ब्रिटिश भारत में अनेक प्रकार की समस्याएँ हैं। पहली बात तो यह है कि सारे भारत में एक ही तरह के लोग नहीं बसते। भिन्न-भिन्न प्रान्तों के निवासियों की भाषा और रहन सहन आदि में बहुत भेद है। यहाँ जाति-पाँति के भी बहुत से झगड़े हैं और अनेक प्रकार के धार्मिक तथा सामाजिक भेद भी हैं। इन सब बातों के कारण कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भारत कोई राष्ट्र नहीं है, बल्कि एक छोटा सा महादेश है जिसमें तरह-तरह के लोग बसते हैं। परन्तु यह बात बहुत से अंशों में ठीक नहीं है। सारे भारत में भौगोलिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आदि अनेक प्रकार की ऐसी एकताएँ हैं जो हजारों बरसों से चली आ रही हैं। बहुत विस्तृत देश होने के कारण स्वभावतः उसमें अनेक प्रकार के विभेद देखने में आते हैं; परन्तु उन सब भेदों के मूल में एक ऐसी एकता है जिसका अनुभव सभी प्रान्तों के लोग समान रूप से करते हैं। तिस पर अब तो पाश्चात्य जातियों के संसर्ग के कारण देश में राष्ट्रीयता की जो नई लहर उठी है, हुए कहा जा सकता है कि यदि पाश्चा

दृष्टि में इस समय भारत में कोई एक राष्ट्र न भी हो, तो भी बहुत जल्दी यहाँ एक राष्ट्र की स्थापना अवश्य हो ही जायगी; और राष्ट्र की इस स्थापना का कार्य बहुत दिनों से चल भी रहा है। जो लोग भारत और भारतवासियों के शत्रु हैं, वही अपने लाभ के लिए यह कहते हैं कि भारत कोई राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र के लिए आवश्यकता इसी बात की होती है कि उसकी कोई राष्ट्रीय परम्परा चली आ रही हो और सब लोगो को अपनी उस राष्ट्रीयता और परम्परा का ज्ञान हो। सब लोग यह समझते हो कि हम लोग एक ही जाति के हैं, एक ही पूर्वजों के वंशज हैं, एक ही धर्म के माननेवाले हैं और एक ही देश में रहते हैं। और ये सभी बातें भारत के बहु-संख्यक निवासियों में वर्तमान हैं। यह समझना भूल है कि केवल समान भाषा, समान रहन-सहन और समान आर्थिक अवस्थाओं से ही राष्ट्र बनता है। एक तो अंग्रेजों के आने के पहले से ही सारे देश में राष्ट्रीयता का भाव वर्तमान था। तिस पर इतने दिनों तक ब्रिटिश शासन में रहने के कारण तो राष्ट्रीयता के भावों में और भी बल आ गया है; और इस नवीन राष्ट्रीय आन्दोलन के कारण सारे भारत की एक ही समस्या हो गई है।

प्रायः यह भी कहा जाता है कि सारे भारत की कोई एक भाषा नहीं है, और इसी लिए भारत की जितनी राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं, उन सब को विवश होकर अपने सब काम अँग्रेजी भाषा में करने पड़ते हैं। अँग्रेजी भाषा की इस प्रकार प्रधानता दिखला कर कुछ लोग यह सिद्ध करना चाहते हैं कि भारतवर्ष में राष्ट्रीयता की सृष्टि अँग्रेजों की ही कृपा से हुई है। यह ठीक है कि भारत में सैकड़ों स्थानिक बोलियों के सिवा बाईस ऐसी भाषाएँ भी प्रचलित हैं जिनमें से हर एक के बोलने वालों की संख्या दस लाख से अधिक है। इनमें से सबसे अधिक बोली जानेवाली

भाषा पश्चिमी हिन्दी है जिसके बोलनेवालों की संख्या दस करोड़ से भी अधिक है। आज-कल तो राष्ट्रीय संस्थाओं की ओर से मदरास, उड़ीसा और आसाम तक में इस भाषा के प्रचार का पूरा-पूरा प्रयत्न हो ही रहा है, लेकिन आवश्यकता होने पर यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि अंग्रेजों के इस देश में आने से सैकड़ों वर्ष पहले भी इस भाषा का सारे देश में कुछ-न-कुछ प्रचार था; और यदि किसी मदरासी को किसी पंजाबी के साथ या किसी कच्छी को किसी बंगाली के साथ विचार-विनिमय करने की आवश्यकता होती थी, तो उन दिनों भी उसे इसी भाषा की शरण लेनी पड़ती थी। और इस बात के भी अनेक प्रमाण हैं कि जिस समय मुसलमान इस देश में आये थे, उस समय भी एक प्रान्त के लोग दूसरे प्रांतवालों से इसी भाषा में बात-चीत करते थे।

प्रायः कहा जाता है कि ग्रेट ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कम्पनी के द्वारा अनजान में ही भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी। यह ठीक है कि अंग्रेजों ने जान-बूझकर या पहले से निश्चित की हुई किसी योजना के अनुसार भारत पर विजय प्राप्त नहीं की थी। देशी रियासतों के मुकाबले में ब्रिटिश भारत का विस्तार जो इतना अधिक है, उसका कारण प्रायः कुछ बड़ी-बड़ी घटनाएँ ही हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत में अंग्रेज केवल आर्थिक लाभ के विचार से आये थे। वे यहाँ केवल व्यापार करना चाहते थे; अथवा अधिक-से-अधिक यह कहा जा सकता है कि व्यापार के नाम पर वे यहाँ का धन लूटने के लिये आये थे। आरम्भ में उन्होंने यहाँ जो आसन जमाया था और यहाँ के कुछ स्थानों पर अधिकार किया था, वह केवल इसी लिये कि उन्हें जम कर व्यापार करने और खूब धन कमाने का अवसर मिले। लेकिन आगे चल कर जब संयोग से उनके

हाथ में एक बहुत बड़ा साम्राज्य आ गया, तब उन्हें लाचार होकर यहाँ अमन और कानून की हिफाजत के लिए भी कुछ इन्तजाम करना ही पड़ा। मतलब यह कि भारत में जो ब्रिटिश राज्य स्थापित हुआ था, वह ब्रिटिश हितों के लिये था, भारतीय हितों के लिए नहीं। और इस समय भी अंग्रेज यहाँ जो कुछ करते हैं, उसका मूल उद्देश्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने के सिवा और कुछ नहीं होता। यदि भारत के साथ अंग्रेजों का व्यापार न रह जाय तो उनके बहुत से शिल्प और उद्योग-धन्धे बिलकुल नष्ट ही हो जायँ। इधर कुछ दिनों से भारत में जो स्वदेशी-आन्दोलन चला है और भारत में बहुत से पुतलीघर खुल गये हैं, उनसे मैन्चेस्टर आदि स्थानों का काम बहुत ही मन्दा पड़ गया है। अंग्रेज पूँजीदारों ने अपनी बहुत अधिक पूँजी ऐसे ही कामों में लगा रक्खी है जो बिना भारत के किसी तरह चल ही नहीं सकते। और इस सम्बन्ध में सबसे अधिक बिलक्षण बात यह है कि वह सारी पूँजी भी उन लोगों के हाथ में भारतीय व्यापार आदि की ही कृपा से पहुँची है। आज अगर इंग्लैण्ड के हाथ से भारत निकल जाय तो एक ओर तो उसकी बहुत अधिक आर्थिक हानि होगी और दूसरी ओर ब्रिटिश साम्राज्य के सम्मान को भी बहुत बड़ा धक्का लगेगा। तात्पर्य यह कि आर्थिक कारणों से भी और राजनीतिक कारणों से भी ग्रेट ब्रिटेन के शासकों के लिये भारत पर अपना राज्य बनाये रखना नितान्त आवश्यक है।

आज-कल बहुत से अंग्रेज यह कहा करते हैं कि पहले चाहे जो कुछ हुआ हो, लेकिन इस समय भारत पर अंग्रेजों का जो शासन है, वह भारत के ही हित के लिए है। यह भी कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन भारतवासियों को धीरे-धीरे सभ्य बना रहा है और उसकी आर्थिक अवस्था में सुधार कर रहा है। पहले

भारत में बहुत जल्दी-जल्दी और बड़े-बड़े अकाल पड़ा करते थे; लेकिन अब ब्रिटिश शासन ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि न तो उतनी जल्दी और न उतने बड़े अकाल पड़ते हैं। जन-साधारण के स्वास्थ्य और शिक्षा की उन्नति का भी ब्रिटिश शासन ने बहुत कुछ काम किया है। यह भी कहा जाता है कि आज-कल भारत जो एक राष्ट्र का रूप धारण कर रहा है और स्वराज्य की योग्यता प्राप्त कर रहा है, वह भी ब्रिटिश शासन की ही बदौलत कर रहा है। आगे भी अंग्रेजों के ही प्रभाव में रह कर वह राष्ट्र बन सकेगा और अपना शासन आप करने में उसे सबसे अधिक सहायता ब्रिटेन से ही मिल सकती है। ऐसे लोगों का यह भी कहना है कि आज अगर भारत पर से ब्रिटिश शासन उठ जाय और अंग्रेजी सेनाएँ यहाँ से हटा ली जायँ, तो फिर भारत छिन्न-भिन्न हो जायगा और यहाँ अराजकता फैल जायगी, भीषण गृह-युद्ध छिड़ जायगा और सम्भवतः बहुत जल्दी उस पर फिर किसी दूसरी विदेशी शक्ति का राज्य हो जायगा। कुछ अंग्रेजों का यह भी कहना है कि उत्तर की ओर से रूसी यहाँ आ पहुँचेगे और बोलशेविक सिद्धान्तों का प्रचार करके सारा देश उजाड़ डालेंगे। कुछ लोग यह कहते हैं कि भारत पर जापान का अधिकार हो जायगा और वह यहाँ का धन अपहरण करने लगेगा और एशिया के सब देशों को एक में मिलाकर यूरोप के लिए एक नया आतंक खड़ा कर देगा।

ये सब बातें कुछ अंशों में ठीक भी हो सकती हैं। आज-कल राजनीतिक दृष्टि से जिसे राष्ट्रीयता कहते हैं, उसकी उत्पत्ति तो भारत में अंग्रेजी शासन की कृपा से अवश्य हुई है, परन्तु वह इसलिए हुई है कि भारतवासियों को अंग्रेजी शासन का विरोध करना पड़ता है। और नहीं तो जब हम यह देखते हैं कि भारत में सांस्कृतिक एकता हजारों बरसों से चली आ रही है,

तब उसके सामने हमें अँग्रेजों का शासन-काल युग के सामने क्षण के ही समान जान पड़ता है। यह ठीक है कि ब्रिटिश शासन के कारण ही भारत का संसार के दूसरे देशों के साथ व्यापार होने लगा है; पर साथ-ही-साथ यह भी ठीक है कि अँग्रेजों ने यहाँ का पुराना शिल्प और व्यापार केवल अपना शिल्प और व्यापार बढ़ाने के लिए बिल्कुल नष्ट कर डाला है। और फिर विदेशी व्यापार भी भारत के लिए कोई नई चीज नहीं है। हजारों बरस पहले से चीन, तिब्बत, फारस, अरब और यूनान आदि देशों के साथ भारत का व्यापार होता था। अँग्रेजों ने इस देश में रेलें चलाई हैं, नहरें निकाली हैं, लोगों को भूखों मरने से बचाने के लिए कुछ उपाय किये हैं और पाश्चात्य ढंग की शिक्षा का भी थोड़ा बहुत विस्तार किया है। लेकिन यह सब बातें तो इस युग का धर्म ही हैं; और यदि यहाँ अँग्रेजों का राज्य न होता तो भी शायद किसी-न-किसी रूप में ये सब बातें यहाँ होती हीं। फिर यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यदि आज यहाँ से एकाएक अँग्रेजों का शासन हट जाय तो क्या होगा। सम्भव है कि देश कई भागों में विभक्त हो जाय अथवा यहाँ रूसियों या जापानियों का राज्य स्थापित हो जाय और भारतवासी अपने देश की विदेशियों से रक्षा न कर सकें। लेकिन इसका उत्तरदायित्व तो स्वयं भारतवासियों की अपेक्षा उन अँग्रेजों पर ही अधिक है जिन्होंने डेढ़ सौ बरसों के शासन से भारतवासियों को सब प्रकार से अयोग्य और अकर्मण्य बना रक्खा है और उनकी वह शक्ति ही नष्ट कर दी है, जिससे वे अपने देश की रक्षा कर सकते। जो लोग इस बात का विचार करते हैं कि आज अगर भारत पर से अँग्रेजों का शासन हट जाय, तो क्या होगा, वे यदि साथ-ही-साथ इस बात का भी थोड़ा विचार करने का कष्ट करें कि यदि अँग्रेज

इस देश में न आते तो यहाँ का कितना धन व्यर्थ ही विदेश जाने से बचता; या इस बात का ध्यान करें कि यदि अंग्रेजों ने भारतवासियों के हथियार न छीन लिये होते और उन्हें सेना तथा शासन विभाग में सम्मिलित होने का अच्छा और पूरा अवसर दिया होता, तो भारत की क्या अवस्था होती, तो शायद बहुत अच्छा होता ।

भारतीय सामाजिक अवस्थाएँ—भारतवर्ष के एक बहुत बड़े भाग पर अठारहवीं शताब्दी से ही अंग्रेजों का शासन चला आ रहा है । इस बीच में भारतीय जनता की जो आर्थिक उन्नति हुई है, वह अत्यन्त मन्द गति से हुई है, और बहुत बड़े अर्थापहरण के बाद हुई है । यहाँ बहुत सी रेलें जरूर बनी हैं और इधर कुछ दिनों से शिल्प आदि की उन्नति के लिए कुछ कल-कारखाने भी बनने लगे हैं । लेकिन फिर भी भारतीय जनता के उस बहुत बड़े अंश की आर्थिक अवस्था बहुत ही शोचनीय है, जो यहाँ के देहातो में रहता है । देश की सारी खेती-बारी अब भी बिल्कुल उसी तरह से होती है, जिस तरह आज से हजारों बरस पहले होती थी; और यहाँ के खेतों में उतनी पैदावार भी नहीं होती, जितनी होनी चाहिए, अथवा जितनी और देशों के किसान करते हैं । यहाँ के देहातों में स्वास्थ्य-सुधार का अब तक कोई काम ही नहीं हुआ है । यहाँ आये दिन जो हैजा और प्लेग आदि महामारियाँ फैलती रहती हैं, उन्हें रोकने का भी बहुत ही कम उपाय किया गया है । विद्यालयों की संख्या अब भी बहुत कम है और सौ में केवल १४ पुरुष ऐसे हैं जो कुछ पढ़ना-लिखना जानते हैं; और इनमें भी अधिकांश ऐसे ही हैं जो नाम मात्र के लिए कुछ पढ़-लिख लेते हैं । स्त्रियों में तो शायद सौ में २ ही पढ़ी-लिखी होंगी । पाश्चात्य सभ्यता के साथ जापान का अपेक्षाकृत बहुत हाल में ही सम्बन्ध हुआ है । लेकिन

इस थोड़े से समय में ही वहाँ की समस्त जनता में शिक्षा का पूरा-पूरा प्रचार हो गया है। विदेशों से मशीनों का बना हुआ जो सामान यहाँ आता है, उसने यहाँ के सभी पुराने शिल्पों और उद्योग-धन्धों को बिल्कुल नष्ट कर दिया है और अब भारत सूई और सलाई तक के लिए दूसरे देशों का मोहताज हो गया है। पहले यहाँ के किसान कई छोटे-मोटे शिल्प के काम भी किया करते थे, जिनसे उनकी जीविका अच्छी तरह चलती थी। पर अब उन शिल्पों का कहीं नाम भी नहीं रह गया है। अब तो यहाँ के किसानों का बहुत सा समय व्यर्थ ही इधर-उधर की बातों में नष्ट होता है। इधर हाल में महात्मा गान्धी की कृपा से सारे देश में खहर का जो आन्दोलन चला है, वह देश को उस पुरानी अवस्था तक पहुँचाने के लिए निरा पागलपन नहीं है, बल्कि भारतीय देहातियों की अवस्था सुधारने और उनकी दरिद्रता दूर करने का बहुत ही उपयोगी और सच्चा प्रयत्न है।

इसके सिवा यह भी कहा जाता है कि भारतवासियों में बहुत से सामाजिक दोष हैं। वे छोटे-छोटे बच्चों का व्याह्र करते हैं और आपस में ही छुआ-छूत का भाव रखते हैं, आदि आदि। और अगर अँग्रेजों का यहां शासन न रहेगा तो ये दोष और भी बढ़ते जायँगे। लेकिन ये सब बातें भारत के उन विदेशी शासकों के मुँह से शोभा नहीं देतीं जो अपने ही साम्राज्य के अन्य भागों में भारतवासियों के साथ अछूतों का सा व्यवहार करते हैं। अब भारतवासियों में राष्ट्रीयता का भाव जाग्रत हो चुका है। अब वे अपने दोषों के सुधार का भी प्रयत्न करने लगे हैं और अपने देश को विदेशियों के शासन से मुक्त करने का भी। अब वे बिना पूर्ण स्वराज्य लिये कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। पहले अँग्रेजों को यह डर रहता था कि कहीं देश की साधारण अशिक्षित जनता उन पढ़े-लिखे लोगों के पक्ष में न हो जाय जो

देश को स्वतन्त्र करना चाहते हैं। लेकिन जबसे महात्मा गान्धी ने असहयोग का आन्दोलन शुरू किया, तबसे देश के कोने-कोने में जाग्रति हो गई है। अब सब लोगो को देश की वास्तविक अवस्था का ज्ञान हो गया है और वे समझ गये हैं कि हमारी सारी दरिद्रता और अधिकांश कष्टों तथा अपमानों का कारण यही विदेशी शासन है। अंग्रेज तो प्रायः इसी लिए भारतवासियों के सामाजिक दोषों की चर्चा करते थे कि इस देश के बहुत से लोगो के मन में यह भाव उत्पन्न हो कि हमारे देश-भाई हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते और अंग्रेज हमारे पक्षपाती हैं। लेकिन अब उनका वह उद्देश्य विफल हो रहा है। अब लोग यह समझने लगे हैं कि हमारे भाइयों का हम पर उतना अधिक अत्याचार नहीं होता, जितना सारे देश पर विदेशी शासन का होता है। शिक्षित भारतवासी तो बहुत दिनों से अपने सामाजिक दोष दूर करने का प्रयत्न करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार से जो उन्हें इस तरह के कामों में कोई सहायता नहीं मिलती, उसका कारण यही है कि सरकार यही चाहती रही है कि देश के सब वर्ग मिलकर एक न होने पावे। उसका प्रयत्न बराबर यही रहा है कि देश में जितने अधिक विभेद और विषेय हैं, वे सब बराबर बने रहें, बल्कि बढ़ते ही रहें; क्योंकि यही सब बातें देश को परतन्त्र रखने में सहायक हो सकती हैं—इन्हीं से विदेशी शासकों का उद्देश्य सिद्ध हो सकता है। सरकार ने आज तक भारत के सामाजिक दोष दूर करने में तो कोई विशेष सहायता दी नहीं; और इसके लिए बहाना यह निकाला कि हम इस देश के रीति-रवाज में कोई दखल नहीं देना चाहते। लेकिन वास्तव में उसके दखल न देने का उद्देश्य कुछ दूसरा ही था। इसमें सन्देह नहीं कि यह सिद्धान्त बहुत कुछ ठीक है कि विदेशी शासकों को किसी देश के रीति-रवाज में

दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन जो लोग सामाजिक दोष दूर करना चाहते हो, उन्हें किसी तरह की सहायता न देना, बल्कि अवसर पड़ने पर उनके मार्ग में बाधक होना उससे कहीं ज्यादा बुरा है। लेकिन फिर भी भारत सरकार बहुत दिनों से ऐसा ही करती आ रही है।

प्रायः यह भी कहा जाता है कि भारत में उत्पादन के जितने उद्गम हैं, वे कुछ इस तरह के हैं कि उनकी उन्नति अधिक तीव्र गति से हो ही नहीं सकती; और इसी लिए भारतीय गाँवों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति बहुत मन्द गति से होती है। यह बात बिलकुल ठीक है कि भारतीय किसानों पर लगान और करों आदि का बोझ बहुत अधिक है—इतना अधिक है कि वे उस बोझ से दबकर मरे जा रहे हैं। बहुत से स्थानों में सरकार उन किसानों से प्रत्यक्ष रूप से कर आदि नहीं वसूल करती, बल्कि जमींदारों आदि के द्वारा वसूल करती है, जिससे उन लोगों की कठिनाइयाँ बहुत बढ़ जाती हैं और उन पर अनेक प्रकार के अत्याचार होते हैं। किसानों को जो रकम देनी पड़ती है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जमींदारों के ही पास रह जाता है और सरकारी खजाने तक नहीं पहुँचता। इसके सिवा भारत का सैनिक व्यय बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। देशी सेनाओं के अतिरिक्त सरकार यहाँ बहुत सी अंग्रेजी सेना भी रखती है, जिसका व्यय अपेक्षाकृत बहुत अधिक होता है। सिविल सर्विस और पुलिस विभाग का खर्च भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। भारत सरकार ने समय-समय पर जो बहुत से बड़े बड़े ऋण लिये हैं, उनका सूद चुकाने के लिए भी एक बड़ी रकम की जरूरत होती है। अंग्रेज पूँजीदारों को भी और अंग्रेजों के संरक्षण में काम करने-वाले भारतीय पूँजीदारों को भी कई तरह से बहुत सा धन मिलता है; और इसी लिये उनमें से अधिकांश यही चाहते हैं कि

भारत में अंग्रेजों का शासन बराबर बना रहे ।

यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि अगर भारत को अपनी मर्जी के मुताबिक काम करने के लिए छोड़ दिया जाय तो यहाँ समाज और शिक्षा सम्बन्धी सुधार कदाचित् और भी मंद गति से होंगे और जनता की अवस्था सुधरने में और भी विलम्ब होगा । लेकिन इस तरह की बातें ठीक नहीं हैं । जब कोई देश परतन्त्र होता है और उस पर विदेशियों का राज्य होता है, तब उस देश के निवासी अपना सारा उत्तरदायित्व भूल जाते हैं । वे हर तरह से विदेशी सरकार पर ही निर्भर रहने लगते हैं । उन्हें अपना सुधार और उन्नति करने की उतनी विशेष आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । किसी राष्ट्र को दरिद्रता और दुर्दशा के गड्ढे से निकालने के लिए जिस उत्साह की आवश्यकता होती है वह विदेशी शासन के अधीन रहने की अवस्था में लोगों में उत्पन्न ही नहीं होता । डेन्मार्क में प्रायः सभी काम सहयोग समितियों के द्वारा होते हैं और उसकी सारी उन्नति का मूल यही सहयोग समितियोंवाला आन्दोलन है । लेकिन अगर वह देश स्वतन्त्र न होता और उस पर किसी विदेशी जाति का राज्य होता तो क्या यह कभी सम्भव था कि वह इतनी उन्नति करता ? यदि जापान पर किसी विदेशी शक्ति का अधिकार होता तो क्या आज वह इतनी उन्नत अवस्था में दिखाई पड़ सकता था ? इधर थोड़े ही दिनों में रूस ने जो आश्चर्यजनक उन्नति की है, वह इसी लिए कि वहाँ के निवासी समझते हैं कि सारा अधिकार हमारे ही हाथ में है और अपने देश की उन्नति तथा सुधार का सारा उत्तरदायित्व स्वयं हमही पर है । इस समय भारत नितान्त दरिद्र भी है और परम अशिक्षित भी । और इसी लिए कुछ लोगों का यह कहना है,

और बहुत से अंशों में बिल्कुल ठीक कहना है कि बिना सामाजिक क्रान्ति हुए भारतवासियों की आँखें नहीं खुल सकती। वे लोग यह भी कहते हैं कि जब तक भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व रहेगा, तब तक देश के ये दोष और ये दुर्बलियाँ किसी तरह दूर नहीं हो सकती। कम-से-कम इतना अधिकार तो भारतवासियों को अवश्य ही मिलना चाहिए कि वे समझने लगे कि देश का सारा भार और सारा उत्तरदायित्व हमही लोगों पर है। हमारी विदेशी सरकार पर इसका भार और उत्तरदायित्व नहीं है। भारतवासियों को अपने राष्ट्रीय उद्धार का काम अपने ढंग पर करने का पूरा-पूरा अवसर मिलना चाहिए।

भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन—भारतीय क्रान्ति के पक्ष में यही सब समझदारी की दलीलें हैं। यदि ग्रेट ब्रिटेन के शासक भारतवर्ष को स्वराज्य के वास्तविक अधिकार नहीं देंगे तो एक-न-एक दिन किसी-न-किसी तरह से यह क्रान्ति अवश्य होगी। देश को जो अधूरे अधिकार^१ दिये जायेंगे, उनका कोई फल नहीं होगा। अधूरे सुधारों का परिणाम यही होगा कि भारतवासियों में वास्तविक उत्तरदायित्व का भाव तो उत्पन्न होने पावेगा ही नहीं, हाँ उससे ब्रिटिश शासन की जड़ जरूर कमजोर हो जायगी। लेकिन कठिनता तो यह है कि ग्रेट ब्रिटेन भारत को अपनी

१. इधर हाल में भारत को प्रान्तीय शासन के जो थोड़े-बहुत अधिकार मिले हैं, वे इसी प्रकार के अधूरे अधिकार हैं जिनकी मूल लेखक ने निन्दा की है। इन नये अधिकारों से लोगों को भाषण और लेखन की कुछ स्वतन्त्रता तो मिली थी और नेताओं का जेल जाना भी बन्द हो गया था, लेकिन वास्तविक अधिकार नहीं मिले थे। इधर दूसरा युरोपीय महायुद्ध छिड़ने पर तो अवस्था पहले से भी कहीं बुरी हो गई है। सुधारों के सम्बन्ध की कुछ बातें आगे आवेंगी। —रामचन्द्र वर्मा।

सामरिक शक्ति का आधार भी बनाये रखना चाहता है, भारतवासियों की इच्छा के विरुद्ध उनके हाथ अपना माल भी बेचना चाहता है, संसार में अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए उसे अपने साम्राज्य के अन्तर्गत भी रखना चाहता है और भारत को ही रूस तथा जापान के प्रसार के मार्ग में बाधा के रूप में भी रखना चाहता है। और जब तक वह ये सब बातें चाहता है, तब तक वह उसे स्वराज्य के वास्तविक अधिकार किसी तरह नहीं दे सकता। देश में वास्तविक स्वराज्य तो अभी स्थापित हो सकता है, जब सेना, सिविल सर्विस और पुलिस सभी पर स्वयं भारतवासियों का अधिकार हो और वे अपनी इच्छा के अनुसार आय-व्यय कर सकें। इसके सिवाय स्वराज्य के लिए यह भी आवश्यक है कि भारतवासियों की ही मर्जी पर यह बात छोड़ दी जाय कि वे ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत रहेंगे या उसके बाहर और उससे अलग होकर रहेंगे। यदि ग्रेट ब्रिटेन भारत को इतने विस्तृत अधिकार न देगा तो वह भले ही और कुछ दिनों तक अपनी सेना और पुलिस के बल पर उस पर अपना अधिकार बनाये रखे, आर्द्धिनेन्सो के द्वारा यहाँ के लोगों के मुँह बन्द रखे और आन्दोलन करनेवाले नेताओं को जेलों में बन्द रखे, लेकिन यह बात निश्चित है कि अधूरे सुधारों और अधिकारों से कभी काम नहीं चलेगा। जब तक पूरे अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक वे लोग बराबर सरकार के विरुद्ध आन्दोलन करते ही रहेंगे, जिन्हे देश की उन्नति का भार अपने ऊपर लेना चाहिए।

इधर ब्रिटिश सरकार ने दो-तीन बार में भारतवासियों को थोड़े-थोड़े अधिकार दिये हैं, पर उन सभी अधिकारों और सभी सुधारों में सबसे बड़ा दोष यही है कि वे अधूरे हैं। न तो उनसे भारतवासियों को सन्तोष ही हो सकता है और न देश की

उन्नति ही। यही कारण है कि देश ने इन सुधारों को अनुपयुक्त समझ कर इनका त्याग और तिरस्कार ही किया है। अभी हाल में सरकार ने अपनी तरफ से जो सुधार किये हैं और जिन्हे वह बहुत बड़े सुधार कहती है, वे भी राष्ट्रीय भारतवासियों को तुच्छ जँचते हैं। उन सुधारों के अनुसार आठ प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्री-मण्डलों ने शासन का काम अपने हाथों में भले ही ले लिया हो, लेकिन फिर भी वे लोग साफ तौर पर यही कहते थे कि हम इन अधिकारों का उपयोग केवल अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कर रहे हैं; और नहीं तो वस्तुतः हम इन अधूरे सुधारों का अन्त और नाश ही करना चाहते हैं। कांग्रेस का संघटन ही देश में सबसे बड़ा है और वही देश के सब प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता और करता है। इधर बहुत दिनों से कांग्रेस के आन्दोलन का दमन ही होता रहा है और अब भी लोगों को सदा यह आशंका बनी ही रहती है कि न जाने, कब वह दमन-चक्र फिर से चलने लगे। देश के अधिकांश नेता और राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता एक नहीं अनेक बार जेल हो आये हैं। इधर बहुत दिनों से भारत का शासन केवल दमन से होता आ रहा है। जब से इंग्लैण्ड में राष्ट्रीय सरकार बनी है, तब से फिर बराबर इस बात के प्रयत्न होते रहते हैं कि भारतवासियों को नाम मात्र के लिए जो थोड़े-बहुत अधिकार दिये गये हैं, वे भी जहाँ तक हो सके, कम किये जायें।

यह ठीक है कि इधर कुछ दिनों से सरकार ने कांग्रेस का दमन करने का विचार छोड़ दिया था और आठ प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्री-मण्डलों को एक संकुचित क्षेत्र में शासन करने की बहुत कुछ स्वतन्त्रता दे रखी थी। लेकिन कांग्रेस भी साफ तौर पर कहती थी कि हम आगे आनेवाली लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं; और सरकार भी अन्दर-ही-अन्दर ऐसे उपाय कर रही थी

जिनसे आवश्यकता पड़ने पर वह पूरी तरह कांग्रेस-आन्दोलन का दमन कर सके। इस बात का कहीं कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया कि सरकार ने अपना पुराना रुख बदल दिया है और वह देश को पूरे अधिकार देकर स्वतन्त्र करना चाहती है। ये सुधार तो केवल लोगों को दिखलाने और शासन सम्बन्धी छोटे-मोटे कामों में फँसाये रखने के लिए ही थे। यह बात एक प्रकार से निश्चित सी है कि अभी एक बार कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार से फिर जबरदस्त मोर्चा लेना पड़ेगा; और यदि उस मोर्चे में वह विजयी हुई, तो देश को बहुत से अंशों में वास्तविक स्वतन्त्रता मिल सकेगी।

प्रायः यह कहा जाता है कि दमनवाली नीति इसलिए ठीक है कि कांग्रेस सारे देश की सम्मति और विचार नहीं प्रकट करती, बल्कि उसमें बहुत थोड़े से ऐसे अर्द्ध-शिक्षित हैं, जो अंग्रेजों को हटाकर देश का शासन अपने हाथ में लेना चाहते हैं और देश की साधारण जनता यह नहीं चाहती कि यहाँ अंग्रेजों का राज्य न रहे। लेकिन सन् १९२१ व १९३०-३१ के देश-व्यापी आन्दोलनों ने और उनके बाद प्रान्तों की एसेम्बलियों के हाल के निर्वाचनों ने यह बात बहुत अच्छी तरह सिद्ध कर दी है कि भारतीय जनता का बहुत बड़ा अंश कांग्रेस के साथ है। और फिर एक यह बात भी ध्यान रखने की है कि संसार के सभी देशों में जितने राष्ट्रीय आन्दोलन होते हैं, वे सब मुख्यतः थोड़े से शिक्षितों और अर्द्ध-शिक्षितों के ही आन्दोलन होते हैं। देश के किसान और जन-साधारण तो केवल क्रान्ति के समय ही सामने आते हैं। आधुनिक जर्मनी और जापान का काया-पलट भी तो वहाँ के थोड़े से शिक्षितों और अर्द्ध-शिक्षितों ने ही किया था। सन् १९१७ में रूस में जो क्रान्ति हुई थी, उसमें भी सारी रूसी जनता सम्मिलित नहीं हुई थी। अतः इस प्रकार

के आक्षेप निरर्थक हैं।

एक बात और है। जिन परिस्थितियों में इधर कुछ दिनों से देश का विकास हो रहा है, उन परिस्थितियों में देश के थोड़े से शिक्षितों और अर्द्ध-शिक्षितों के सिवा और लोग सम्मिलित हो ही नहीं सकते। राष्ट्रीय आन्दोलन में भारत की प्रमुख राष्ट्रीय संस्था यहाँ की महा-सभा या नेशनल कांग्रेस ही है। और इस कांग्रेस में प्रमुख व्यक्ति महात्मा गान्धी है। कांग्रेस का आरम्भ सन् १८८५ में हुआ था। पहले वह सिर्फ नरम दिलवालों की संस्था थी और देश में केवल थोड़े से शासन सम्बन्धी सुधार ही कराना चाहती थी। सन् १९०६ से उसका प्रभाव राष्ट्र-व्यापी होने लगा और उसी समय उसने सब से पहले यह घोषणा की कि हम ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत स्वराज्य चाहते हैं। लेकिन 'स्वराज्य' एक ऐसा शब्द है जिसकी कई प्रकार की व्याख्याएँ हो सकती थीं, और इसी लिए कांग्रेस में ऐसे लोग भी सम्मिलित थे जो उसकी बहुत विशद और व्यापक व्याख्या करते थे और ऐसे लोग भी थे जो उसे बहुत संकीर्ण अर्थ में लेते थे। पहले युरोपीय महायुद्ध के बाद इस शब्द का प्रयोग दिन पर-दिन अधिक व्यापक अर्थ में होने लगा। उस महायुद्ध के समय ही एनी बेसेन्ट ने अपना होम-रूलवाला आन्दोलन चलाया था। लेकिन जब यह माँग भी ना-मंजूर कर दी गई, तब भारतवासी कहने लगे कि हमें भी यह निश्चय करने का अधिकार मिलना चाहिए कि देश में किस प्रकार शासन हो। उसी समय मान्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधारों का आरम्भ होनेवाला था, लेकिन उससे पहले ही सन् १९१६ में अमृतसर में जो जल्यौवाले बाग का हत्याकांड हुआ था और देश में जो दमनकारी रालेट एक्ट प्रचलित हुआ था, उससे सारा देश बहुत लुब्ध हो गया था। और इसी लिए महात्मा गान्धी के नेतृत्व में सन् १९२१ में देश-व्यापी असहयोग आन्दोलन हुआ था जो चौरीचौरावाले कांड

के कारण बाद में रोक दिया गया था। उस समय सरकार ने दमन भी खूब जोरों से किया था। तब से अब तक किसी-न-किसी रूप में बराबर सरकार के साथ कांग्रेस का संघर्ष होता आ रहा है। बीच-बीच में कभी कुछ कारणों से यह संघर्ष कुछ कम हो जाता है, लेकिन कांग्रेस अपने पूर्ण स्वराज्य-वाले ध्येय पर अड़ी हुई है और अब तो उसकी माँग पूर्ण स्वतन्त्रता हो गई है। कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि भारत सिर्फ इसी शर्त पर ब्रिटिश साम्राज्य में रह सकता है कि उसका बराबरी का दावा मान लिया जाय; और यह भी मान लिया जाय कि उसे इस बात का अधिकार है कि वह जब चाहे, तब ब्रिटिश साम्राज्य से अलग भी हो सके।

कांग्रेस के प्रयत्न से देश में समाज-सुधार और आर्थिक उन्नति के भी बहुत से काम हो रहे हैं। विशेषतः जब से (जुलाई १९३७) प्रान्तों का शासन कांग्रेसी सरकारों के हाथ में आया था, तब से इस प्रकार के बहुत से काम होने लगे थे। जेलों के जीवन में सुधार हुआ था, अनेक स्थानों में मद्य तथा मादक द्रव्यों का प्रचार कम किया गया था और कुछ स्थानों में बन्द भी कर दिया गया था। जन-साधारण को शिक्षित बनाने के प्रयत्न हो रहे थे और उनके लिए देहातो तक में पुस्तकालय आदि खुल रहे थे। ग्रामों की अवस्था सुधारने का प्रयत्न हो रहा था और किसानों की बिगड़ी हुई आर्थिक अवस्था सुधारने का उद्योग होता था। गाँवों और देहातों के लिए नये-नये शिल्पों की व्यवस्था हो रही थी और कुछ स्थानों में मोटरे, बाइसिकिलें और बहुत सी ऐसी दूसरी चीजें तैयार करने के लिए बड़े-बड़े कारखाने खोलने का भी आयोजन हो रहा था, जिन चीजों के खरीदने में देश के करोड़ों रुपये हर साल विदेशों में चले जाते हैं। देश के बहुत से किसान ऋण के बोझ से बुरी तरह दबे

हुए हैं। इसके सिवा वे जमींदारों के बोझ से भी परेशान हो रहे हैं। इसलिए ऐसा उद्योग हो रहा था कि उन पर के ये सब बोझ कुछ कम हों और उन्हें साँस लेने की फुरसत मिले। जहाँ तक हो सकता था, स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार को प्रोत्साहन दिया जाता था। शिक्षा का स्वरूप भी अब बहुत कुछ राष्ट्रीय करने की व्यवस्था हो रही थी। तात्पर्य यह कि प्रायः दो ही बरसों में सभी प्रान्तों की कांग्रेसी सरकारों ने देश की उन्नति के बहुत से नये काम एक साथ ही छोड़ दिये थे और उनमें से कुछ में उन्हें अच्छी सफलता भी हुई थी। कांग्रेसी प्रान्तों की देखा-देखी इसी तरह के कुछ काम उन प्रान्तों में भी होने लगे थे, जिनमें कांग्रेसी सरकार नहीं थी। लेकिन जब दूसरा महायुद्ध छिड़ने पर सैद्धान्तिक कारणों से कांग्रेसी मंत्री-मंडल अधिकार छोड़कर अलग हो गये, तब सारे देश में बहुत कुछ वही पहलेवाली अवस्था हो गई। कांग्रेसी मंत्री-मण्डलों के किये हुए प्रयत्नों पर पानी फिरने लगा; और भारत-रक्षा कानून के नाम पर दमन-चक्र भी जोरों पर चलने लगा।

अस्पृश्यता—इधर कुछ दिनों से महात्मा गांधी राजनीतिक क्षेत्र से कुछ अलग से हो गये थे और अपना अधिकांश समय अस्पृश्यता का निवारण और अछूतों का उद्धार करने में लगाते थे। अस्पृश्यता का प्रश्न सामाजिक तो है ही, पर साथ ही अग्रत्यक्त रूप से राजनीतिक भी है और गोल मेज कान्फ्रेंसों के समय इस प्रश्न ने बहुत ही उग्र रूप धारण किया था। कुछ लोग यह चाहते थे कि अस्पृश्यों को हिन्दुओं से बिल्कुल अलग कर दिया जाय, जिससे हिन्दुओं की संख्या और बल कम हो जाय। जब इस प्रश्न के सम्बन्ध में गोल मेज कान्फ्रेंस में कोई समझौता न हो सका, तब तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान मंत्री स्व० मि० 'रैम्से मैकडानल्ड' ने यह फैसला कर दिया कि अछूतों की गिनती

हिन्दुओं से अलग हो और काउन्सिलो आदि के लिए उनके निर्वाचन और प्रतिनिधि भी हिन्दुओं से अलग हो। उस समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे। वे पहले ही एक अवसर पर कह चुके थे कि मैं अपने प्राणों की बलि देकर भी अछूतों को हिन्दुओं से अलग होने से बचाऊंगा। जब ब्रिटिश सरकार के इस निणय की सूचना उन्हें मिली, तब उन्होंने यह घोषणा कर दी कि मैं तब तक अन्न ग्रहण न करूंगा, जब तक इस प्रश्न का सन्तोषजनक निणय नहीं हो जायगा। इससे हिन्दुओं और अछूतों में जल्दी ही समझौता हो गया और हिन्दू समाज का एक बड़ा अंश उससे कट कर अलग होने से बच गया।

लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि समस्त भारत के हिन्दुओं में से अस्पृश्यता का भाव निकल गया है और उन्होंने सब अछूतों को अपना लिया है। सारे भारत में प्रायः साढ़े चार करोड़ अछूत हैं, जिनमें से पौने तीन करोड़ के लगभग बङ्गाल, बिहार और संयुक्त प्रान्त में ही हैं। लेकिन इन प्रदेशों में अछूतों की अवस्था उतनी शोचनीय नहीं है, जितनी मद्रास में है। तो भी सारे भारत में अस्पृश्यता-निवारण का आन्दोलन अच्छी गति से चल रहा है। अनेक स्थानों पर उनके लिए मन्दिरों में दर्शन कराने का और कूओं पर पानी भरने का निषेध नहीं रह गया है, बहुत से स्थानों पर उनके बालकों को पढ़ाने के लिए विद्यालय आदि खुल रहे हैं और उनके रहने के महल्लों की सफाई हो रही है। इस बात का निरन्तर उद्योग हो रहा है कि उनका नैतिक, आर्थिक और शागीरिक सुधार तथा उन्नति हो।

कम्यूनिज्म और मजदूरों के संघटन—भारत सरकार की आज्ञा से सारे भारत में कम्यूनिस्ट सिद्धान्तों के प्रचार की मनाही है और कम्यूनिस्ट विचारोंवाले भारतीय नेताओं को प्रायः अपने देश से निर्वासित होकर और दूसरे देशों में रह कर अपना जीवन

बिताना पड़ता है। मजदूरो के जो संघ हैं, उनके सम्बन्ध में भी भारत सरकार को यह सन्देह बना रहता है कि ये लोग छिपे तौर पर उनमें कम्युनिस्ट सिद्धान्तों का प्रचार करते हैं। भारत में मजदूरो के संघ अभी बहुत ही दुर्बल हैं और उनका ठीक तरह से संघटन भी नहीं हुआ है। रेलों में काम करनेवालों का संघटन कुछ अच्छा है और इसके सदस्यों की संख्या डेढ़ लाख से ऊपर है। अहमदाबाद और बम्बई के कपड़ों के कारखानों में काम करनेवालों का भी अच्छा संघटन है। मजदूरो की अखिल भारतीय संस्थाएँ दो हैं। इनमें से एक का नाम है आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और दूसरी का नाम है नेशनल फ़ैडरेशन आफ़ ट्रेड यूनियन्स। ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेता मुख्यतः राष्ट्रीय दल के और कांग्रेसी नेता हैं और फ़ैडरेशन अपेक्षाकृत कुछ नरम दलवालों के हाथ में है। इनके सिवा मजदूरो के और भी अनेक छोटे-मोटे संघ हैं जो इन दोनों से अलग रहते हैं। लेकिन अधिकतर संघों की प्रवृत्ति राष्ट्रीयता और साम्यवाद की ओर ही है।

राजनीतिक दल—सन् १९३१ की सर्वेक्ष-शुमारी के अनुसार सारे भारत में २४ करोड़ से कुछ कम हिन्दू हैं और १२॥ करोड़ से अधिक बौद्ध हैं, जिनमें से अधिकांश बरमा में रहते हैं; और राजनीतिक कार्यों के लिए बरमा अब भारत से अलग कर दिया गया है। ४३॥ लाख के लगभग सिक्ख, १२॥ लाख के करीब जैन, ६३ लाख के करीब ईसाई और ७॥ करोड़ के करीब मुसलमान हैं। ८० लाख से ऊपर ऐसे लोग हैं जो अनेक प्रकार के जंगली धर्म मानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासभा में हिन्दुओं की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन उसमें बहुत से सिक्ख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी और मुसलमान भी हैं। आज से अठारह-बीस वर्ष पहले कांग्रेस में मुसलमानों की संख्या भी बहुत

अधिक हो गई थी और तभी से कांग्रेस का स्वरूप नितान्त राष्ट्रीय माना जाता है। सन् १९२१ वाले असहयोग आन्दोलन के समय हिन्दुओं और मुसलमानों में पूरी एकता हो गई थी, जिसे देखकर ब्रिटिश सरकार बहुत ही सशंकित हुई थी। तभी से अन्दर-ही-अन्दर हिन्दुओं से मुसलमानों को अलग करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न और षड़यन्त्र होने लगे, जिनमें आगे चलकर बहुत कुछ सफलता भी हुई। इन्हीं प्रयत्नों का यह फल है कि इधर पन्द्रह-सोलह बरसों से जगह-जगह हिन्दू-मुस्लिम दंगे भी होते रहते हैं और मुसलमानों की संस्था मुस्लिम लीग हर बात में हिन्दुओं और कांग्रेस का विरोध करती रहती है और नित्य अपनी नई और अनोखी माँगें भी पेश करती रहती है। हिन्दुओं और कांग्रेस का विरोध करने के लिए मुस्लिम लीगवाले प्रायः बहुत सी बातों में ब्रिटिश सरकार का भी साथ देते हैं। अब तो मुस्लिम लीग की माँग इस हद तक आ पहुँची है कि पंजाब, सिन्ध, सीमा-प्रान्त, बंगाल और काश्मीर आदि जिन प्रदेशों में मुसलमानों की आबादी अधिक है, वे सब पूरी तरह से मुसलमानों के अधीन कर दिये जायें, और उनके साथ हैदराबाद, भोपाल और रामपुर आदि ऐसी रियासतें भी मिला दी जायें, जिनके निवासियों में बहुत अधिक संख्या है तो हिन्दुओं की ही, पर फिर भी जो मुसलमान शासकों की रियासतें हैं। यह पाकिस्तानी योजना कहलाती है; और इसके अनुसार प्रायः सभी बातों में मुस्लिम लीग अपने लिए आधा हिस्सा माँगती है। महात्मा गांधी और कांग्रेस दोनों ही बराबर इस बात का प्रयत्न करते रहते हैं कि किसी प्रकार हिन्दुओं और मुसलमानों में मेल हो जाय और इसके लिए कोई डेढ़ बरस पहले महात्मा गांधी स्वयं चलकर मुस्लिम लीग के नेता मि० मुहम्मद अली जिन्ना के पास गये थे। लेकिन

फिर भी दोनों में इसलिए कोई समझौता न हो सका कि मुस्लिम लीग की माँगे इतनी बड़ी और जबरदस्त थीं जो कभी न्याय-संगत नहीं कही जा सकती थी। इसलिए कम-से-कम इस समय के लिए कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता करने का विचार छोड़ दिया है और वह मुसलमान जनता में कांग्रेसी सिद्धान्तों का प्रचार करने और उन्हें कांग्रेस का सदस्य बनाने का प्रयत्न कर रही है। लेकिन मुसलमान एक तो उसके इस प्रयत्न से भी नाराज होते हैं और दूसरे वे भिन्न-भिन्न प्रान्तों की कांग्रेसी सरकारों को भी तरह-तरह से बदनाम करने की कोशिश करते रहे हैं। इसमें सन्देह नहीं कि मुसलमानों की इस अदूरदर्शितापूर्ण वृत्ति का देश पर बहुत ही बुरा प्रभाव हो रहा है और उसकी स्वतन्त्रता के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी हो रही है। भारत के मुसलमान अपने उन हिन्दू भाइयों के तो शत्रु हो रहे हैं, जिनके साथ उन्हें सदा इस देश में बसना है; और उन इस्लामी देशों के साथ नाता जोड़ना चाहते हैं जो उनकी कोई खास परवाह ही नहीं करते। परन्तु इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि इस फूट का बीज विदेशी सरकार के चरो का ही बोया हुआ है और अधिकांश नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए ही हिन्दू-मुस्लिम एकता के मार्ग में बाधक हो रहे हैं। यह तो निश्चित ही है कि आगे चलकर कभी-न-कभी हिन्दू-मुस्लिम एकता होगी ही और मुसलमानों में कभी-न-कभी देश-प्रेम जाग्रत होगा ही। लेकिन इससे पहले देश की बहुत बड़ी हानि हो लेगी। यदि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों मुसलमान यह समझने के लिए बाध्य होंगे ही कि हिन्दुओं के साथ व्यर्थ की लड़ाइयाँ लड़ने और अ-कारण ही दंगा-फसाद करने से हमारा कोई वास्तविक लाभ नहीं हो सकता; उलटे हम बराबर घाटे में ही रहते हैं। परन्तु

अभी तो दस-बीस बरस मुसलमानों को ऐसी सुबुद्धि आती हुई दिखाई नहीं देता। इस अवसर पर हमें स्व० स्वामी श्रद्धानन्द जी का वह कथन स्मरण हो आता है कि हिन्दुओं और मुसलमानों में एका होने से देश स्वतन्त्र नहीं होगा, बल्कि जब देश स्वतन्त्र हो जायगा, तब हिन्दुओं और मुसलमानों में एका होगा। इसी लिए इस समय जो थोड़े से समझदार मुसलमान कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, या जो मुसलमान नेता मुस्लिम जनता में राष्ट्रीय भावों का प्रचार करने के लिए अपना संघटन कर रहे हैं, उन्हीं की सहायता से कांग्रेस देश को स्वतन्त्र करने के प्रयत्न में लगी हुई है।

इस प्रकार भारत में एक ओर तो राष्ट्रीय महासभा है जो देश को पूर्ण रूप से स्वतन्त्र करना चाहती है और दूसरी ओर वह मुस्लिम लीग है जो कहती है कि या तो सारा देश सदा के लिए परतन्त्र रहे और या हमारी उचित तथा अनुचित सभी माँगें पूरी की जायँ और सारे भारत में हमें इस्लाम धर्म और इस्लामी सभ्यता तथा सस्कृति का पूरा-पूरा प्रचार करने की अबाध्य स्वतंत्रता मिले। इसके सिवा देश में थोड़े से नरम दलवाले नेता भी हैं जिनके अनुयायियों की संख्या बहुत ही कम है। कांग्रेस से मुख्यतः दो बातों में इन लोगों का मत-भेद है। कांग्रेस तो कहती है कि हमें पूर्ण स्वराज्य मिले और इस बात का अधिकार हो कि हम यदि चाहे तो ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत रहे और चाहे तो उससे अलग हो सकें। लेकिन नरम दलवाले या लिबरल ब्रिटिश साम्राज्य से किसी तरह अलग नहीं होना चाहते और कहते हैं कि हमें ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत ही स्वराज्य के अधिकार मिलने चाहिए। इसके सिवा कांग्रेस समय-समय पर असहयोग और सविनय अवज्ञा आदि साधनों से भी काम लेती है; और नरम दलवाले कहते हैं कि हमें सिर्फ पुराने

ढंग से अपने प्रस्ताव सरकार के सामने रख देने चाहिए। और जो अधिकार वह दया करके हमें दे दे, उसी से हमें सन्तुष्ट हो जाना चाहिए और आगे के लिए फिर अपनी माँगें उसके सामने रखते चलना चाहिए। कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत बहुत दिनों से इस रास्ते पर चलकर बिलकुल निराश हो चुका है और उसे अब भिखमंगोंवाली नीति बिलकुल नापसन्द है। वह अब अपने बल पर सब अधिकार प्राप्त करना चाहता है; और इसी लिए नरम दल में थोड़े से नेता ही नेता है—अनुयायी कोई नहीं है।

जिस प्रकार सारे भारत में अल्प-संख्यक मुसलमानों की एक बड़ी समस्या है, उसी प्रकार पंजाब में अल्प-संख्यक सिक्खों की भी एक समस्या है। पहले अधिकांश सिक्ख अँग्रेजों और अँग्रेजी शासन के पूरे भक्त होते थे। लेकिन अब उनमें भी राष्ट्रीयता का भाव पूर्ण मात्रा में आ गया है और वे भी प्रायः राष्ट्रीय महासभा के साथ मिलकर काम करते हैं। देश में एक और अल्प-संख्यक दल पारसियों का है। लेकिन पारसी सदा से बहुत अधिक शिक्षित और समझदार होते आये हैं और सदा कांग्रेस का साथ देते रहे हैं। इस समय भी वे कांग्रेस से अलग या उसके विरोधी नहीं हैं। एक और अल्प-संख्यक समाज ईसाइयों का है जो अब तक कांग्रेस से अलग रहता था। लेकिन यह समाज भी शिक्षित, समझदार और अग्रसर होने के कारण अब कांग्रेस की ओर प्रवृत्त होने लगा है।

भारत सरकार—यद्यपि सन् १९३५ में सारे भारत के लिए एक नया संघटन विधान बन गया है, परन्तु अभी तक भारत सरकार का काम सन् १९१६ वाले उसी संघटन विधान के अनुसार चल रहा है जो मान्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से प्रसिद्ध है। इसका कारण यह है कि सन् १९३५ में जो नया विधान

बना है, उसके दो विभाग हैं। एक विभाग तो प्रान्तीय शासन से सम्बन्ध रखता है और दूसरा विभाग उस भावी भारत सरकार से सम्बन्ध रखता है जो संघ सरकार कहलावेगी। यह पहला विभाग तो सन् १९३७ से ही प्रचलित हो गया है और इसके अनुसार सभी प्रान्तों का शासन हो रहा है। लेकिन संघ सरकार-वाली योजना अभी तक काम में नहीं लाई गई है। अभी सिर्फ उसकी तैयारियाँ हो रही थी और आशा की जाती थी कि साल दो साल में उस योजना के अनुसार भी सरकार काम करने का प्रयत्न करेगी। लेकिन वर्तमान युरोपीय युद्ध के कारण जो नई परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, उन से ज्ञान पड़ता है कि युद्ध की समाप्ति पर फिर नये सिरे से कोई साँचा खड़ा करने का प्रयत्न किया जायगा। यह तो निश्चित ही है कि अभी तक भारत औपनिवेशिक स्वराज्य से भी बहुत दूर है; फिर पूर्ण स्वराज्य का तो पूछना ही क्या है। अभी तक भारत का सारा अधिकार ब्रिटिश पार्लामेंट के ही हाथ में है जो भारत का शासन भारत मंत्री के द्वारा करती है। और अब महायुद्ध के कारण बहुत कुछ अधिकार वाइसराय को सौंप दिये गये हैं। पर अभी तक उसी पुराने ढंग से सब काम होते आ रहे हैं।

भारत में भारत सरकार का प्रधान वाइसराय है जो अपनी काउन्सिल की सहायता से सब काम करता है। कानून बनाने के लिए दो चेम्बर हैं। बड़ी चेम्बर काउन्सिल आफ स्टेट कहलाती है जिसमें ३३ चुने हुए सदस्य हैं और २७ सरकार के नामांकित सदस्य होते हैं। ये सदस्य प्रायः बहुत बड़े आदमी ही होते हैं और युरोपियनो के प्रतिनिधि भी इन्हीं चुने हुए सदस्यों में से होते हैं। छोटा हाउस लेजिस्लेटिव एसेम्बली कहलाता है। और उसमें १०४ जनता के चुने हुए और ४१ सरकार द्वारा नामांकित सदस्य होते हैं। परन्तु इस भारतीय पार्लामेंट के

अधिकार बहुत ही संकुचित हैं। वाइसराय जिस बिल को चाहे, ना-मंजूर कर सकता है। इसके सिवाय अगर कोई बिल किसी एक ही हाउस में स्वीकृत हो और दूसरे में अस्वीकृत हो, तो उसे भी वह अपनी इच्छा से स्वीकृत कर सकता है। जो बिल दोनों चेम्बरो में अस्वीकृत हुआ हो, उसे भी वह यदि आवश्यक समझे तो ब्रिटिश पार्लमेण्ट की स्वीकृति से मंजूर करके जारी कर सकता है। और कोई बहुत जल्दी का काम हो तो बिना पार्लमेण्ट की स्वीकृति के खुद भी मंजूर और जारी कर सकता है। साधारणतः बजट लेजिस्लेटिव एसेम्बली के सामने जरूर पेश होता है। लेकिन अगर वह एसेम्बली कोई खर्च ना-मंजूर कर दे तो वाइसराय को अधिकार है कि अपनी इच्छा से भी वह खर्च कर सके। इसके सिवा खर्च की कई बहुत बड़ी-बड़ी मदे ऐसी भी हैं जिन पर एसेम्बली का किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं है। जैसे सेना विभाग का खर्च, राजनीतिक और धार्मिक विभाग के खर्च, कुछ खास नौकरों की तनखावे और पेन्शने और लिये हुए ऋणों का सूद या इसी प्रकार के कुछ और खर्च। मतलब यह कि देश के आय-व्यय पर एसेम्बली का वस्तुतः कुछ भी अधिकार नहीं है। जो थोड़े-बहुत अधिकार नाम के लिए भारतीय पार्लमेण्ट को मिले भी हैं, उन सब पर वाइसराय का पूरा-पूरा नियन्त्रण है। और जहाँ तक केन्द्रीय सरकार का प्रश्न है, वहाँ तक देश में कोई उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन नहीं है। वाइसराय की सहायता के लिए जो एक्जिक्यूटिव काउन्सिल है, उसके छः सरकारी सदस्य हैं, जिनमें से प्रत्येक किसी केन्द्रीय विभाग का प्रधान है। इन छः में से चार अंग्रेज और दो हिन्दुस्तानी होते हैं। लेकिन वे दोनों भी सरकारी अफसर ही होते हैं, प्रजा के प्रतिनिधि नहीं होते। मतलब यह है कि यहाँ भी किसी प्रकार की उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवस्था नहीं है। इधर अधिकारों की माँग

बढ़ने के कारण सरकार इस काउन्सिल में कुछ और लोगों को भी लेने की घोषणा तो कर चुकी है। पर उन थोड़ी सी जगहों पर अधिकार चाहनेवालों की संख्या इतनी बढ़ रही है कि उसने एक विकट समस्या का रूप धारण कर लिया है।

प्रान्तीय शासन—जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, प्रान्तीय शासन की व्यवस्था इधर तीन बरसों से सन् १९३५ वाले नये विधान के अनुसार हो रही है। इस नये विधान के अनुसार सब प्रान्त दो भागों में विभक्त हैं। पहले विभाग में मद्रास, बम्बई, बंगाल, संयुक्त प्रान्त, पंजाब, बिहार, मध्यप्रान्त और बरार, आसाम, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, उड़ीसा और सिन्ध ये ११ प्रान्त हैं जो गवर्नरों के प्रान्त हैं; और ब्रिटिश बिलोचिस्तान, दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा, कुर्ग, अंडमन, निकोबार और पन्थ-पिपलोदी नाम के क्षेत्र चीफ कमिश्नरों के प्रान्त कहलाते हैं। पहले विभाग के ११ प्रान्तों में सम्राट् द्वारा नियुक्त गवर्नर ही मुख्य शासक होते हैं। सब प्रकार के प्रान्तीय शासन, शान्ति और सुव्यवस्था आदि के लिए वस्तुतः वे ही उत्तरदायी हैं। मद्रास, बम्बई, बंगाल, संयुक्त प्रान्त, बिहार और आसाम में दो-दो हाउस होते हैं और पंजाब, मध्य प्रान्त तथा बरार, पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त, उड़ीसा और सिन्ध में केवल एक-एक ही हाउस होता है। प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल ५४ विशिष्ट विषयों से सम्बन्ध रखने-वाले कानून बना सकता है, जिनमें सार्वजनिक शान्ति, प्रान्तीय अदालतें, पुलिस, जेल, आबकारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मालगुजारी और लगान आदि विषय मुख्य हैं। प्रान्तीय विषयों की व्यवस्था में गवर्नर को सहायता देने के लिए एक मन्त्री-मंडल होता है। भिन्न-भिन्न प्रान्तों में मन्त्री-मंडल के सदस्यों की संख्या अलग-अलग होती है। कुछ विषयों की व्यवस्था में गवर्नर का

विशेष उत्तरदायित्व होता है। यथा—प्रान्त की शान्ति-रक्षा, अल्प-संख्यकों के उचित हितों की रक्षा, सिविल सरविस के उचित हितों की रक्षा, व्यापार और उद्योग आदि के क्षेत्रों में विदेशियों को मिले हुए विशेष अधिकारों की रक्षा, प्रान्त के अन्तर्गत देशी राज्यों और उनके नरेशों के हितों तथा मान-मर्यादा की रक्षा और स्वयं अपनी प्रचलित की हुई आज्ञाओं की व्यवस्था आदि। गवर्नर अपने मन्त्रियों को जैसी चाहे, वैसी आज्ञाएँ दे सकता है; और यदि वे उन आज्ञाओं के अनुसार कार्य न करें तो वह व्यवस्थापक सभा को भंग करके अथवा बिना किये ही मन्त्रियों को त्याग-पत्र देने के लिये बाध्य कर सकता है। वह नये मन्त्री भी नियुक्त कर सकता है और बिना मन्त्रियों की सहायता के स्वयं अपने अधिकार से भी शासन के सब कार्य कर सकता है।

यदि गवर्नर को ऐसा जान पड़े कि प्रान्त की शान्ति हिंसात्मक कार्यों से भंग होना चाहती है, तो वह उसे रोकने के लिए कोई विशेष आदेश दे सकता है और कोई काम या विभाग अपने हाथ में ले सकता है। यदि वह चाहे तो ऐसी आज्ञा भी दे सकता है कि पुलिस के कागजात किसी को (अर्थात् मन्त्रियों तक को) न दिखलाये जायें। प्रान्त में शासन सम्बन्धी जितने काम होते हैं, वे सब गवर्नर के नाम पर होते हैं; और जो काम वह स्वयं नहीं करना चाहता, उनके लिए वह नियम बना देता है और मन्त्रियों को उन्हीं नियमों के अनुसार सब काम करने पड़ते हैं।

ऊपर चीफ कमिश्नरों के जो छः प्रान्त बतलाये गये हैं, उनका शासन स्वयं गवर्नर जनरल एक चीफ कमिश्नर के द्वारा करता है। इन प्रान्तों के लिए कानून भारतीय व्यवस्थापक मण्डल बनाता है। इन प्रान्तों में से एक कुर्ग को छोड़कर और किसी प्रान्त में व्यवस्थापक परिषद् नहीं है। चीफ कमिश्नर को

अपने प्रान्त के शासन के लिए प्रत्यक्ष रूप से वे सभी अधिकार होते हैं जो बड़े प्रान्तों के गवर्नरों और उनके मन्त्रियों को होते हैं।

प्रान्तीय व्यवस्था—हम पहले बतला चुके हैं कि मद्रास, बम्बई, बङ्गाल, संयुक्तप्रान्त, बिहार और आसाम में दो-दो हाउस या सभाएँ हैं। इनमें से बड़ा हाउस लेजिस्लेटिव काउन्सिल कहलाता है और छोटा लेजिस्लेटिव एसेम्बली। शेष पाँचों प्रान्तों में केवल एक ही हाउस या सभा है जो लेजिस्लेटिव एसेम्बली कहलाती है। प्रत्येक लेजिस्लेटिव एसेम्बली का कार्य-काल साधारणतः पाँच वर्ष होता है। यह बीच में जब चाहे तब गवर्नर की आज्ञा से भंग भी की जा सकती है। हाँ, लेजिस्लेटिव काउन्सिल स्थायी संस्था होती है जो कभी भंग नहीं हो सकती। परन्तु हर तीसरे वर्ष इसके एक-तिहाई सदस्य कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार बदलते रहते हैं। सिक्ख, मुसलमान, युरोपियन, एंग्लो-इंडियन और देशी ईसाई केवल अपने ही वर्ग के प्रतिनिधि चुन सकते हैं। यदि कोई सिक्ख किसी हिन्दू को चुनना चाहे या कोई ईसाई किसी मुसलमान को चुनना चाहे तो वह नहीं चुन सकता। इस सम्बन्ध में भी कुछ विशेष नियम हैं कि कैसे लोग निर्वाचित हो सकते हैं और कैसे लोग निर्वाचक हो सकते हैं। प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं या लेजिस्लेटिव एसेम्बलियों के कुल सदस्यों की संख्या इस प्रकार है:—

मद्रास	२१५
बम्बई	१७५
बङ्गाल	२५०
संयुक्तप्रान्त	२२८
पंजाब	१७५
बिहार	१५२

मध्यप्रान्त-बरार	११२
आसाम	१०८
सीमा प्रान्त	५०
उड़ीसा	६०
सिन्ध	६०

इनमें से प्रायः सभी प्रान्तों में मुसलमानों, एंग्लो-इण्डियनों, युरोपियनों, भारतीय ईसाइयों, व्यापारों, उद्योग-धन्धों और खानों आदि के प्रतिनिधियों और जमींदारों आदि को उनकी आबादी के हिसाब से कहीं अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। बाकी और सब जातियाँ तथा वर्ग एक में हैं, जिन्हें स्वभावतः अपनी जन-संख्या के अनुपात से बहुत ही कम प्रतिनिधित्व मिला है। इसके सिवा भिन्न-भिन्न जातियों और वर्गों की स्त्रियों के लिए भी स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व है। अस्पृश्य जातियों के लिए भी कुछ विशेष स्थान नियत हैं। हर जगह सब जातियों और वर्गों का पृथक् निर्वाचन होता है, जिससे सारे देश में १५ भिन्न-भिन्न निर्वाचक संघ हो गये हैं जो इस प्रकार हैं—

१. साधारण । २. सिक्ख । ३. मुसलमान ।
४. एंग्लो-इण्डियन । ५. युरोपियन । ६. भारतीय ईसाई ।
७. व्यापार और उद्योग । ८. जमींदार । ९. विश्व-विद्यालय ।
१०. श्रम । ११. स्त्रियाँ—साधारण । १२. स्त्रियाँ—सिक्ख ।
१३. स्त्रियाँ—मुसलमान । १४. स्त्रियाँ—एंग्लो-इण्डियन । और
१५. स्त्रियाँ—भारतीय ईसाई ।

इसके सिवा अभी हरिजनों का एक और पृथक् निर्वाचक संघ होने को था, लेकिन महात्मा-गान्धी के अनशन करने और अधिक प्रयत्न करने पर बहुत कठिनाता से उन्हें साधारण निर्वाचक संघ में सम्मिलित किया गया था। कदाचित् पाठकों को यहाँ यह बतलाने की आवश्यकता न होगी कि ब्रिटिश सरकार ने इस

प्रकार की निर्वाचन प्रथा से सारे देश को बहुत से भिन्न-भिन्न टुकड़ों में बाँट दिया है और उनमें से अधिकांश टुकड़ों को उनकी जन-संख्या के अनुपात से इतना अधिक प्रतिनिधित्व दे रक्खा है कि वे कभी सहज में पृथक् निर्वाचन की प्रथा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। इनमें से जो वर्ग पृथक् निर्वाचन के विरोधी थे, उन्हें भी जबर्दस्ती पृथक् निर्वाचन संघ दिये गये हैं। उदाहरणार्थ, स्त्रियाँ यह नहीं चाहती थीं कि उनका पृथक् निर्वाचन हो; और कई बार उनकी महासभाओं में सम्मिलित निर्वाचन के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे। लेकिन सरकार ने उनके लिए भी जबर्दस्ती पृथक् निर्वाचन ही रक्खा है। शीया मुसलमान भी सम्मिलित निर्वाचन चाहते थे, लेकिन वे भी सुन्नी मुसलमानों के साथ रखे गये। अब देशी ईसाई भी सम्मिलित निर्वाचन के पक्ष में हो गये हैं; लेकिन उनकी माँग पूरी होने के भी अभी कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। यह पृथक् निर्वाचन का विषय सारे देश को इसी लिए जबर्दस्ती पिलाया गया है कि देश कभी मिलकर एक न हो सके—वह कभी विदेशी शासन से मुक्त होने का कोई सम्मिलित उद्योग न कर सके।

लेजिस्लेटिव काउन्सिल—जिन छः प्रान्तों में जिस्लेटिव एसेम्बली के अतिरिक्त लेजिस्लेटिव काउन्सिल भी है, उनके नाम और उनके सदस्यों की संख्या इस प्रकार है—

मद्रास	५४ से ५६ तक
बम्बई	२६ से ३० तक
बंगाल	६३ से ६५ तक
संयुक्तप्रान्त	५८ से ६० तक
बिहार	२६ से ३० तक
आसाम	२१ से २२ तक

इनमें से मद्रास में ८ से १० तक, बम्बई में ३ से ४ तक,

बंगाल में ६ से ८ तक, संयुक्त प्रान्त में ६ से ८ तक, बिहार में ३ से ४ तक और आसाम में भी ३ से ४ तक ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें उन प्रान्तों के गवर्नर अपनी तरफ से नामजद करते हैं। बाकी सदस्य चुने हुए होते हैं और प्रायः बड़े आदमी और उनके प्रतिनिधि होते हैं। हम ऊपर बतला चुके हैं कि ये काउन्सिलें स्थायी होती हैं और भंग नहीं की जा सकती; और इनके एक तिहाई सदस्य हर तीसरे वर्ष बदले जाते हैं। इसका मतलब यही होता है कि हर सदस्य का कार्य-काल साधारणतः नौ वर्ष होता है। तथापि इन काउन्सिलों का जिस समय पहले-पहल संघटन हुआ था, उस समय गवर्नरों ने कुछ सदस्यों का कार्य-काल घटाकर ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि प्रत्येक प्रकार के सदस्यों में लगभग एक-तिहाई हर तीसरे वर्ष अपना स्थान खाली करते जायँ और उनकी जगह नये सदस्य आते जायँ। इन काउन्सिलों में भी मुसलमानों और ईसाइयों को उनकी जन-संख्या के अनुपात से कहीं अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। और ये लोग अपने ही वर्ग के लोगों को चुन भी सकते हैं—दूसरे वर्गों के लोगों को इच्छा होने पर भी इन्हें चुनने का कोई अधिकार नहीं है। इन काउन्सिलों में प्रायः जमींदार, ताल्लुकेदार और पूँजीदार ही अधिक संख्या में होते हैं, जिनका स्वार्थ साधारण जनता के स्वार्थ से भिन्न होता है और जो देश की प्रगति के मार्ग में प्रायः बाधक ही होते हैं। इसके अतिरिक्त इनके संघटन की व्यवस्था कुछ ऐसी पेचीदी रक्खी गई है कि इनमें अधिकतर वही लोग पहुँचते हैं जो देश को स्वाधीनता प्राप्त करने में सहायता मिलना तो दूर रहा, उल्टे उसके मार्ग में अड़चने ही पैदा करती हैं। और वास्तव में इन काउन्सिलों की सृष्टि भी इसी उद्देश्य से की गई है।

जिन प्रान्तों में एसेम्बली और काउन्सिल दोनों होती हैं,

उनमें कोई नया कानून तभी बनता है, जब दोनों हाउस उसे स्वीकृत कर लें और गवर्नर भी उस पर अपनी स्वीकृति दे दे। जिन प्रान्तों में केवल एसेम्बली होती है, वहाँ एसेम्बली का पास किया हुआ कानून जब गवर्नर स्वीकृत कर लेता है, तब काम में लाया जाता है।

इस नवीन विधान में इस बात की पूरी व्यवस्था की गई है कि यदि इंग्लैंड में बसनेवाली कोई ब्रिटिश प्रजा भारत में आकर बसना, नौकरी करना या व्यापार आदि करना चाहे तो उसमें किसी प्रकार की बाधा न हो सके और उसे भी वे सब पूरे-पूरे अधिकार प्राप्त हों, जो भारतीय प्रजा को हैं। भारत में इंग्लैंड से जो माल आता है, उसके सम्बन्ध में भी कोई भेद-भाव-मूलक कानून यहाँ नहीं बन सकता। अंग्रेजी कम्पनियों आदि के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। और ये सब व्यवस्थाएँ इसी लिए रखी गई हैं कि अंग्रेजों के मुक्ताबले में भारतीय अपने लिए कोई खास सुभीता न करने पावे और उन्हें पहले से जो अधिकार मिले हुए हैं, उन पर कोई आघात न हो।

गवर्नरों को अपनी ओर से आर्डिनेन्स जारी करने या नया कानून बनाने या कोई विशेष आज्ञा देने का भी पूरा अधिकार है। जिस समय व्यवस्थापक-मंडल काम न करता हो, उस समय तो उसे यह अधिकार होता ही है; पर जिस समय व्यवस्थापक मंडल काम करता हो, उस समय भी उसे यह अधिकार होता है। अर्थात् प्रान्तीय व्यवस्थापक-मंडल को कानून बनाने का जितना अधिकार है, उतना सब अधिकार और उसके अतिरिक्त कुछ और अधिकार भी गवर्नर को कानून बनाने के सम्बन्ध में प्राप्त हैं। यह अधिकार उन्हें पहले प्राप्त नहीं था, पर इस नये विधान के अनुसार प्राप्त हो गया है। अर्थात् प्रान्तीय शासन की सारी व्यवस्था कुछ ऐसे ढंग की रखी गई

है कि वह देखने में तो पूरी तरह से प्रतिनिधिसत्तात्मक जान पड़ती है, लेकिन वह उसी सीमा तक प्रतिनिधि-सत्तात्मक रह सकती है, जिस सीमा तक गवर्नर की इच्छा से उसका विरोध न हो। एक तो व्यवस्थापक-मंडल और मन्त्री-मंडल के अधिकार यों ही बहुत संकुचित हैं। तिस पर गवर्नर को इतने विस्तृत अधिकार दे दिये गये हैं कि वह जब जो काम चाहे, बिना किसी प्रकार की बाधा या विरोध के कर सकता है। और इस अंश में यह नवीन शासन बहुत कुछ स्वेच्छा-मूलक भी हो सकता है। शासन और आय-व्यय सम्बन्धी जितने महत्वपूर्ण अधिकार हैं, उन सबसे व्यवस्थापक-मंडल और मन्त्री-मंडल वंचित रखे गये हैं।

न्याय-विभाग—भारत के न्याय-विभाग की और मारी व्यवस्था तो पहले की तरह ज्यों-की-त्यों रखी गई है, पर इसमें संघ-न्यायालय नाम का एक सर्वोच्च न्यायालय और बढ़ा दिया गया है। इसमें छः तक जज रह सकते हैं, पर इस समय तीन ही जज हैं। यदि संघ के प्रान्तों या देशी राज्यों का कोई कानूनी झगड़ा खड़ा होगा तो उसका निर्णय इसी न्यायालय में होगा। यही न्यायालय यह निश्चित करेगा कि नये विधान के अनुसार संघ, प्रान्तीय सरकार और देशी राज्यों के क्या अधिकार हैं और इसका निर्णय सर्व-मान्य होगा। इस न्यायालय में हाईकोर्टों के ऐसे फैसलों की अपील भी हो सकेगी जिनके सम्बन्ध में हाईकोर्ट यह निश्चय कर दे कि इसमें शासन-विधान से सम्बन्ध रखनेवाला कोई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न विचारणीय है।

संघ-शासन—नये विधान में मारे भारत के लिए एक ऐसे संघ-शासन की योजना है जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों का एक संघ होगा। लेकिन इसमें खास शर्त यह रखी गई है कि आगे चलकर नई राज्य परिपद्ध या काउन्सिल आफ स्टेट तब

बनेगी, जब उससे उतने देशी राज्य सम्मिलित होना स्वीकृत कर लेंगे, जितनों को उसके लिये कम-से-कम ५२ सदस्य चुनने का अधिकार होगा और जिनकी आवादी सारे देशी राज्यों की आवादी की कम-से-कम आधी होगी। उस अवस्था में ब्रिटिश पार्लियामेंट इस आशय का एक प्रस्ताव सम्राट् की सेवा में उपस्थित करेगी और तब सम्राट् द्वारा इस संघ-शासन की स्थापना की घोषणा होगी। देशी राज्यों में लगभग ८ करोड़ प्रजा बसती है; और जब ४ करोड़ की आवादी के देशी राज्य संघ-शासन में सम्मिलित होना स्वीकृत कर लेंगे, तब यह नया शासन आरम्भ होगा। ब्रिटिश सरकार भारत में बहुत जल्दी संघ सरकार स्थापित करना चाहती थी और इसी लिए वह देशी राज्यों को इसके लाभ बतलाने और उन्हें इसके लिए राजी करने के प्रयत्न में लगी हुई थी। यदि केवल बहुत बड़ी-बड़ी आवादीवाले पाँच-सात देशी राज्य मिलकर संघ-शासन में सम्मिलित होना चाहेंगे, तो भी संघ-शासन की इसलिए स्थापना नहीं हो सकेगी कि दूसरी शर्त के मुताबिक इसके लिए इतने राज्य तैयार होने चाहिएँ जो कुल मिलाकर ५२ सदस्य काउन्सिल आफ स्टेट में भेज सकें। ऐसे राज्यों को एक खास सरकारी शर्तनामा मंजूर करना पड़ेगा और यह घोषणा करनी पड़ेगी कि हम स्वयं भी और अपने उत्तराधिकारियों की ओर से भी संघ में सम्मिलित होना चाहते हैं और अपने राज्य में इस शर्तनामे की सब बातों की पाबन्दी करना मंजूर करते हैं; और अपने यहाँ की कुछ विशिष्ट बातों की व्यवस्था सम्राट्, गवर्नर-जनरल, संघीय व्यवस्थापक-मंडल, संघ-न्यायालय और संघीय रेल्वे विभाग के अधीन करते हैं। आरम्भ में जो देशी राज्य संघ में सम्मिलित हो जायेंगे, वे तो दो ही जायेंगे। लेकिन बाद में जो राज्य उसमें सम्मिलित होना चाहेंगे, वे संघ का निर्माण होने से बीस बरस

के अन्दर नहीं हो सकेंगे। उस अवस्था में उनके लिए पहले संधीय व्यवस्थापक-मंडल की स्वीकृति की भी आवश्यकता होगी।

संधीयशासन-व्यवस्था प्रचलित होने पर भारत-मन्त्री की इण्डिया काउन्सिल तोड़ दी जायगी, पर उसके कुछ परामर्शदाता अवश्य रहा करेंगे। इसके सिवा भारत-मन्त्री का वेतन और उसके विभाग का व्यय भी भारत सरकार न देगी, बल्कि वह ब्रिटिश सरकार के कोष से दिया जायगा। अपने परामर्शदाताओं की नियुक्ति भारत-मन्त्री स्वयं करेगा। उनमें से आधे ऐसे होंगे जो कम-से-कम दस वर्ष तक भारत सरकार की नौकरी कर चुके होंगे। भारत के शासन सम्बन्धी सब काम करने के लिए यहाँ गवर्नर-जनरल रहेगा, जिसकी नियुक्ति स्वयं सम्राट् करेंगे। देशी राज्यों से सम्बन्ध रखनेवाली बातों की व्यवस्था के लिए एक वाइसराय भी रहा करेगा। परन्तु यदि सम्राट् चाहे तो इन दोनों पदों पर एक ही व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकते हैं।

यह भी निश्चय हुआ था कि संधीय-शासन स्थापित होजाने के बाद गवर्नर-जनरल की काउन्सिल नहीं रह जायगी, बल्कि उसके स्थान पर उसका एक मन्त्री-मंडल होगा, जिसका नाम काउन्सिल आफ मिनिस्टर्स होगा। जिन विषयों में गवर्नर-जनरल को विशेष अधिकार प्राप्त हैं, उन्हें छोड़कर बाकी विषयों में मन्त्री-मंडल उसे सहायता या परामर्श देगा। इसमें अधिक-से-अधिक दस मन्त्री हो सकेंगे। गवर्नर-जनरल को इस बात का पूरा अधिकार होगा कि वह जो काम चाहे, वह बिना मन्त्रियों से परामर्श लिये केवल अपनी इच्छा से ही कर सके। अपने मन्त्री भी वही चुनेगा और जब तक चाहेगा, उन्हें उनके पद पर रहने देगा। सेना, धर्म, पर-राष्ट्र और जंगली जातियों के सम्बन्ध में सब काम गवर्नर-जनरल अपनी इच्छा के अनुसार

करेगा। इस सम्बन्ध में यदि वह उचित समझेगा तो अपने लिए तीन परामर्शदाता भी रख सकेगा। देश में शान्ति की रक्षा, संघ सरकार की आर्थिक दृढ़ता और साख की रक्षा, सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों और उचित हितों की रक्षा, देशी नरेशों के अधिकारों और मान-मर्यादा की रक्षा तथा इसी प्रकार की कुछ और बातों के लिए वस्तुतः वही उत्तरदायी समझा जायगा और ऐसे मामलों में जब चाहे, तब दखल दे सकेगा।

संघीय व्यवस्थापक मण्डल—संघीय व्यवस्थापक मंडल में दो हाउस या सभाएँ होगी। उनमें से बड़ी सभा राज्य परिषद् या काउन्सिल आफ स्टेट कहलावेगी और छोटी सभा का नाम संघीय व्यवस्थापक सभा या फेडरल एसेम्बली होगा। राज्य परिषद् में अधिक-से-अधिक २६० सदस्य होंगे, जिनमें से १५६ ब्रिटिश भारत के और १०४ देशी राज्यों के सदस्य होंगे। प्रान्तीय काउन्सिलों की तरह यह भी स्थायी संस्था होगी और इसके एक-तिहाई सदस्य हर तीसरे वर्ष चुने जायेंगे। ब्रिटिश भारत के १५६ सदस्यों में से १५० जनता द्वारा निर्वाचित होंगे और ६ सदस्य नामांकित होंगे। भिन्न-भिन्न प्रान्तों से उनकी जन-संख्या के अनुसार उनकी काउन्सिलों और एसेम्बलियों से इसके प्रतिनिधि चुने जायेंगे।

फेडरल एसेम्बली में अधिक से अधिक ३७५ सदस्य होंगे, जिनमें से २५० ब्रिटिश भारत के और १२५ देशी राज्यों के सदस्य होंगे। ब्रिटिश भारत के सदस्यों का चुनाव हर पाँचवें वर्ष प्रान्तों की एसेम्बलियों के द्वारा हुआ करेगा। इस एसेम्बली के स्वरूप आदि के सम्बन्ध में भी बहुत सी वही बातें हैं जो प्रान्तीय एसेम्बलियों के सम्बन्ध में पहले दी जा चुकी हैं। अर्थात् इसमें भी मुसलमानों, युरोपियनों, ईसाइयों और व्यापार तथा उद्योग-धन्धोवालों को उनकी जन-संख्या के अनुपात

से कहीं अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा।

देशी राज्यों को ओर से जो सदस्य आवेंगे, उनकी नियुक्ति वहाँ के नरेशों के द्वारा होगी। इसके लिए अलग-अलग राज्यों की, उनकी हैसियत के अनुसार, १७ श्रेणियाँ बनाई गई हैं। किसी राज्य को १, किसी को २, और किसी को ५ सदस्य तक भेजने का अधिकार होगा; और छोटे-छोटे कई राज्यों को मिलकर केवल एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जब उतने राज्य संघ में सम्मिलित होना स्वीकृत कर लेंगे, जितनों को सब मिलाकर ५२ सदस्य राज्य परिषद् में भेजने का अधिकार होगा, तब संघीय-शासन प्रचलित किया जायगा।

संघ का निर्माण हो जाने पर उस संघीय व्यवस्थापक-मंडल का कार्य आरम्भ होगा, जिसके दो हाउसों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। यह मंडल सारे भारत के लिए संघीय व्यवस्थापक मंडल, सेना, टकसाल, तार, सरकारी नौकरियों, काशी और अलीगढ़ के विश्वविद्यालयों, आयात-निर्यात, हवाई जहाजों, नमक, आय-कर, उत्तराधिकार-कर और संघीय आय के साधनों आदि के सम्बन्ध में कानून बना सकेगा। प्रान्तों के व्यवस्थापक मंडल जिन विषयों के कानून बना सकते हैं, वे “प्रान्तीय विषय” कहलाते हैं और संघीय व्यवस्थापक मंडल जिन विषयों के कानून बना सकेगा, वे “संघीय विषय” कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे विषय भी हैं जिनके सम्बन्ध में यदि संघीय व्यवस्थापक मंडल कानून न बनावे तो प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडलों को अधिकार होगा कि वे उस विषय के कानून बना सकें। ऐसे विषय “संयुक्त विषय” कहलाते हैं। इनमें से मुख्य विषय ये हैं—फौजदारी कानून, विवाह और वैवाहिक सम्बन्ध-विच्छेद, ठेका, दिवाला, चिकित्सा, छापेखाने,

मोटर, कारखाने, मजदूर-संघ, बिजली, बेकारी और बीमा आदि। इस प्रकार के कानूनों को अमल में लाने के बारे में संघीय सरकार प्रान्तीय सरकारों को कुछ हिंदायते भी कर सकेगी। प्रान्तीय विषयों से सम्बन्ध रखनेवाले कानून संघीय व्यवस्थापक मंडल प्रायः उसी अवस्था में बनावेगा, जब कि उसका सम्बन्ध एक से अधिक प्रान्तों के साथ हो। परन्तु युद्ध या अशान्ति आदि के दिनों में गवर्नर-जनरल की आज्ञा से संघीय मंडल को किसी एक प्रान्त या उसके किसी विशिष्ट विभाग के सम्बन्ध में भी कानून बनाने का अधिकार होगा। यदि प्रान्तीय मंडल के किसी कानून से संघीय मंडल के किसी कानून का विरोध हो, तो संघीय मंडल का कानून ही अमल में आवेगा। संघीय मंडल में कोई ऐसा कानून नहीं पेश हो सकेगा जो ब्रिटिश भारत के लिए पार्लियामेंट के बनाये हुए किसी कानून को या पुलिस सम्बन्धी किसी कानून को रद्द करता हो या गवर्नर-जनरल के अधिकारों को कम करता हो या जिससे ब्रिटिश भारत के बाहर के आदमियों और कम्पनियों पर कोई अतिरिक्त कर लगता हो, आदि। परन्तु यदि इस तरह का कोई कानून गवर्नर-जनरल या सम्राट् स्वीकृत कर ले तो वह अमल में आ सकेगा। कई विशेष अवस्थाओं में स्वयं गवर्नर-जनरल अपनी इच्छा से भी कोई कानून बना सकता है या किसी प्रकार की आज्ञा प्रचलित कर सकता है। और यदि किसी समय उसे यह विश्वास हो जाय कि इस नवीन विधान के अनुसार संघ सरकार का काम नहीं चल सकता, तो वह सारे देश का शासन अपने हाथ में भी ले सकता है।

संघ, प्रान्त और देशी राज्य—प्रत्येक प्रान्त और देशी राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि संघ के शासन-कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न हो। साथ ही सारे भारत के लिए

संघ जो कानून बनावेगा, उसका पालन करना सबके लिए आवश्यक होगा। गवर्नर को यह अधिकार होगा कि प्रान्तों और राज्यों के शासन के सम्बन्ध में कुछ विशेष अवस्थाओं में गवर्नरों और राजाओं को कुछ हिदायतें कर सके। आवश्यकता पड़ने पर गवर्नर-जनरल एक ऐसी काउन्सिल भी बना सकेगा जो भिन्न-भिन्न प्रान्तों की पारस्परिक विरोध सम्बन्धी बातों की जाँच करके उन्हें दूर करने के उपाय बतलावे। आयात और निर्यात-कर, अफीम, तम्बाकू, नमक, आय-कर, डाक, तार आदि की सारी आय संघ सरकार लेगी। अदालतों के रसूम, जंगल, आब-पाशी, मादक द्रव्यो और मालगुजारी आदि की आय प्रान्तीय सरकारों की होगी। प्रान्तीय मदों पर संघ सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कर भी लगा सकेगी। जिन प्रान्तों का व्यय उनकी आय से कम होगा, उन्हें संघ सरकार कुछ आर्थिक सहायता भी देगी। अब भारत-मन्त्री को समस्त भारत की आय की जमानत पर ऋण लेने का अधिकार न रहेगा। हाँ, संघ सरकार और प्रान्तीय सरकारें अपनी-अपनी आय की जमानत पर ऋण ले सकेंगी। प्रान्तों और राज्यों को संघ सरकार स्वयं भी ऋण दे सकेंगी और अपनी जमानत पर औरों से भी दिलवा सकेंगी। अब तक भारत-मन्त्री के नाम पर जितने ऋण लिये गये हैं, वे सब भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारों के नाम पर हो जायेंगे। किसी देशी राज्य को कितना सैनिक व्यय संघ सरकार के कोष में भेजना पड़ेगा या किसी देशी राज्य से ब्रिटिश भारत में आनेवाले माल पर कितना आयात-कर लगेगा, इसका निर्णय उस शर्तनामे में होगा, जो किसी देशी राज्य के संघ सरकार में सम्मिलित होने के समय दोनों पक्षों से स्वीकृत होगा। संघीय व्यवस्थापक मण्डल में या तो स्वयं देशी राजा और या उनके नामजद किये हुए प्रतिनिधि रहेंगे।

समीक्षा—ऊपर बतलाया जा चुका है कि इस नये विधान क प्रान्तीय शासन और व्यवस्थावाला अंश सन् १९३७ से प्रचलित हो गया है। उसके अनुसार कुछ समय तक ११ प्रान्तों में से उड़ीसा, आसाम, बिहार, संयुक्त प्रान्त, सीमा प्रान्त, मध्य प्रदेश, चम्बई और मद्रास में तो कांग्रेसी मंत्री-मंडल काम कर रहे थे और बाक़ी बंगाल, पंजाब, और सिंध में ऐसे संयुक्त मंत्री-मंडल काम कर रहे हैं, जिनमें अधिकतर मंत्री या तो मुस्लिम लीग के अनुयायी और या मुसलमान हैं। कांग्रेसी मंत्री-मण्डलों में भी मुसलमान थे, लेकिन वही मुसलमान थे, जो कांग्रेस के सिद्धांतों को पूरी तरह से मानते थे। कांग्रेसी मंत्री-मंडलों ने प्रजा के हित के जो काम किए थे, उनका संक्षिप्त उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इनकी देखा-देखी अन्य प्रान्त भी उसी प्रकार के कुछ कार्य करने लगे थे। प्रायः दो वर्षों तक प्रान्तीय शासन का जो अनुभव हुआ, उससे उस अनुमान की बहुत कुछ पुष्टि हुई जो इस विधान के बनने के समय किया गया था। यह तो निश्चित है कि भारतवासियों को पहले से कुछ अधिक अधिकार अवश्य मिले हैं, और यदि इन अधिकारों का ठीक तरह से उपयोग किया जाय तो भारतीय जनता का बहुत कुछ कल्याण हो सकता है। लेकिन इस सम्बन्ध में सबसे अधिक आपत्तिजनक बात यही है कि गवर्नरों और गवर्नर-जनरल को पहले की अपेक्षा बहुत अधिक अधिकार मिल गये हैं; और पहले भारत पर जो बन्धन थे, केवल वही हट नहीं किये गये हैं, बल्कि उनकी संख्या में भी कुछ वृद्धि हुई है। एक ओर देश की आन्तरिक व्यवस्था में लोगों की थोड़ी बहुत स्वतन्त्रता मिली और दूसरी ओर समस्त देश की परतन्त्रता कुछ और बढ़ी। यदि यही संघ शासन प्रचलित होगा, तो यह परतन्त्रता और भी बढ़ जायगी; और इसी भय से

कांग्रेस आरम्भ से ही उस संघ शासन का घोर विरोध कर रही थी जो इस नवीन विधान के अनुसार साल दो साल में प्रचलित होनेवाला था। केवल कांग्रेस ही नहीं, बल्कि लिबरल भी इस नई व्यवस्था के घोर विरोधी थे। विरोध तो मुसलमानों और मुस्लिम लीग का भी था और है, परन्तु वह बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण से था। देशी राजे-महाराजे भी जल्दी इस संघ-शासन में सम्मिलित होने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे; और इसका कारण यह था कि वे समझते थे कि इससे हमारी वर्तमान अवाध्य स्वतन्त्रता में बाधा होगी। इस समय ब्रिटिश भारत में एक प्रकार की परिमित प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन-प्रणाली प्रचलित है और देशी राज्यों में स्वेच्छापूर्ण एकतन्त्र प्रचलित है। ये दोनों एक गाड़ी के दो ऐसे पहिये हैं जो एक दूसरे से भिन्न दिशा को जा रहे हैं। अतः इन दोनों का संयोग बहुत विलक्षण होगा। नवीन विधान के अनुसार देशी राजाओं को अधिकार होगा कि वे संघीय व्यवस्थापक मंडल में अपने नामजद किये हुए प्रतिनिधि भेजे। ऐसे नामजद अवश्य ही प्रगति-विरोधी होंगे। फिर जब तक मुसलमानों के साथ कांग्रेस का समझौता नहीं हो जायगा, तब तक वे भी हर बात में सदा अड़ंगा ही लगाते रहेंगे और कोई काम ठीक तरह से न होने देंगे। कांग्रेस यह चाहती है कि देशी राज्यों की प्रजा को भी उसी प्रकार के अधिकार मिले, जिस प्रकार के अधिकार ब्रिटिश भारत की प्रजा को हैं और वहाँ भी उत्तरदायित्वपूर्ण प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन-प्रणाली प्रचलित हो। उस अवस्था में संघीय व्यवस्थापक मंडल में देशी राज्यों से प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधि आ सकेंगे—नरेशों के नामजद किये हुए प्रतिनिधि नहीं आवेंगे। यद्यपि पहले भी कुछ कारणों से मुस्लिम लीग संघ शासन का विरोध करती थी, पर अब उसका विरोध इसलिए और भी बढ़ गया है कि उसे भय है कि देशी राज्यों

में प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन-प्रणाली प्रचलित हो जाने पर संघीय व्यवस्थापक-मंडल में कांग्रेस का बहुमत हो जायगा, जिसे वे स्वार्थवश विशुद्ध हिन्दुओं का बहुमत बतलाते हैं। कांग्रेस तो अपने कार्यों में कभी साम्प्रदायिकता का कोई विचार आने नहीं देती और न वह राजनीतिक क्षेत्र में साम्प्रदायिकता का भाव रहना ही अच्छा समझती है। पिछले वर्षों जिन प्रान्तों में कांग्रेसी शासन प्रचलित था, उनमें एक भी काम ऐसा नहीं हुआ, जिसमें किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता की गन्ध हो। लेकिन मुस्लिम लीग फिर भी ऐसे प्रान्तों के मन्त्री-मण्डलों पर चराचर ऐसे मिथ्या अभियोग लगाती रही है, जिनका कोई सिर-पैर नहीं होता था। इसके सिवा अधिकांश कांग्रेसी प्रान्तों में साम्प्रदायिकता के नाम पर आये दिन जो दंगे होते रहते थे, वे भी वस्तुतः किसी साम्प्रदायिक कारण से नहीं होते थे, बल्कि उनका मूल भी राजनीतिक होता था। बात सिर्फ यह है कि पुरानी सरकारों ने इधर पन्द्रह-बीस बरसों से साम्प्रदायिकता का जो बीज बो रक्खा था, उसीके कुफल अब फल रहे हैं। विशेषतः इस नये विधान में भारत के अधिक-से-अधिक खरब करने का जो प्रयत्न किया गया है और हर जगह, यहाँ तक कि बंगाल, पंजाब और सिंध में भी, जहाँ मुसलमानों की आबादी अधिक है, मुसलमानों को उचित से जो बहुत अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है, उससे कुछ स्वार्थी मुस्लिम नेता अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। कांग्रेस तो सभी को उचित अधिकार देना चाहती है, परन्तु मुस्लिम लीग आधे से भी अधिक अधिकार और नौकरियाँ आदि सिर्फ इसलिए मुसलमानों को दिलाना चाहती है कि जिस से आगे चलकर उन्हें सारे भारत में इस्लाम का प्रचार करने का अवसर मिले। वे यह समझते हैं कि भारत में पहले मुसलमानों

का राज्य था और उस समय इस्लाम धर्म का यहाँ जोरो से प्रचार होता था। अब यदि अंग्रेजों के हाथ से अधिकार निकले तो वह फिर मुसलमानों के ही हाथ में आना चाहिए—हिन्दुओं के हाथ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे उसके अधिकारी और पात्र नहीं हैं। यह बात चाहे वे लोग खुलकर न कहते हों, लेकिन फिर भी इतना तो वे अवश्य ही स्पष्ट रूप से कहने लग गये हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं, बल्कि एक संस्कृति है और हम सारे भारत में उस संस्कृति का प्रचार करेंगे। इन सब बातों का मुख्य कारण यही है कि मुसलमानों में शिक्षितों और समझदारों की संख्या बहुत ही कम है और उनमें जो लोग अपना नेतृत्व बनाये रखना चाहते हैं, वे अनेक प्रकार की मिथ्या और आवेशपूर्ण बातें कहकर अपने अनुयायियों को उत्तेजित करते रहते हैं और देश में शांति नहीं स्थापित होने देते। अवश्य ही यह अवस्था बहुत दिनों तक नहीं रह सकती। जब मुसलमानों में शिक्षा का यथेष्ट प्रचार होगा और उन्हें आधुनिक जगत् की परिस्थितियों का ज्ञान होगा, तब वे अवश्य ही समझने लगेंगे कि इस बीसवीं शताब्दी में धर्म और संस्कृति के प्रचार का प्रयास वस्तुतः ढोंग और दम्भ ही है; और इस तरह की बातों को देश की राजनीतिक प्रगति के मार्ग में कभी बाधक नहीं होना चाहिए।

संघ-शासन के दूसरे विरोधी हमारे यहाँ के अधिकांश देशी नरेश थे। उनके विरोध का कारण भी मुस्लिम नेताओं की तरह व्यक्तिगत स्वार्थ ही था। वे बहुत दिनों से नितान्त स्वच्छापूर्ण शासन करते आये हैं, प्रजा पर अनेक प्रकार के अत्याचार करते आये हैं और प्रजा से एकत्र किये हुए धन का अपने भोग-विलास में मनमाना उपयोग करते आये हैं। यह ठीक है कि कुछ देशी नरेश इसके अपवाद हैं और वे अपने राज्य का बहुत

ही अच्छी तरह शासन करते हैं; परन्तु अधिकांश नरेश ऐसे ही हैं, जिन्हें प्रजा के हितों की अपेक्षा अपने सुख और अधिकार का ही अधिक ध्यान रहता है। वे यह नहीं चाहते कि हमारे अनियन्त्रित अधिकार किसी प्रकार नियन्त्रित हों। यद्यपि ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा समय-समय पर उन्हें संघ-शासन में सम्मिलित होने के लाभ बतलाये जाते थे और उन्हें उसमें सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता था, लेकिन वे बराबर आगा-पीछा ही कर रहे थे। वे नये संघ-शासन के विधान की एक-एक बात बहुत बारीकी से जाँच रहे थे और देख रहे थे कि हम पर ब्रिटिश सरकार या मंघीय व्यवस्थापक-मंडल का नियन्त्रण तो नहीं हो जायगा। वे अपने हाथ के अधिकार न तो अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों के हाथ में ही देना चाहते थे और न मंघीय व्यवस्थापक-मंडल के हाथ में ही।

तात्पर्य यह कि नया विधान और विशेषतः इसका संघ-शासनवाला अंश बिल्कुल भानमती का पिटारा था, जिसमें बहुत से परस्पर-विरोधी तत्व एक में भरने का प्रयत्न किया गया है और जिसकी सहायता से ब्रिटिश सरकार बड़ी बड़ी करामाते दिखलाने का वादा करती थी। ब्रिटिश सरकार चाहती है कि भारत हमारे चंगुल से न निकलने पावे। कांग्रेस चाहती है कि देश के सब अधिकार पूरी तरह से प्रजा के प्रतिनिधियों के हाथ में आ जायें। देशी नरेश चाहते हैं कि हमारे अधिकार अनियन्त्रित और अमर्यादित बने रहें और हमारे ऐश-आराम में कमी न होने पावे। मुस्लिम लीग चाहती है कि सारे भारत पर फिर से मुसलमानों का राज्य हो। मजदूर और किसान चाहते हैं कि हमें अपने पूरे अधिकार मिलें। ब्रिटिश व्यापारी चाहते हैं कि भारत में हमारा माल उसी तरह बिकता रहे, जिस तरह पहले बिकता था। अंग्रेज अधिकारी चाहते हैं कि हमारा प्रभुत्व

ज्यो-कान्त्यो बना रहे। इसी प्रकार के और भी अनेक ऐसे भिन्न-भिन्न तथा परस्पर-विरोधी तत्व हैं जिनका समन्वय करने का विधान म कुत्र ऐसा प्रयत्न किया गया था, जो सफल होता हुआ दिखाई नहीं देता था।

इस समय भारत पर ग्रेट ब्रिटेन ने बलपूर्वक अधिकार कर रक्खा है; और सभी भारतीय उस अधिकार के विरोधी हैं। भारत में राजभक्तों का भी एक वर्ग अवश्य है, जिसमें अधिकतर राजे-महाराजे, जमींदार और दालनमन्द आदमी हैं। ऐसे लोगों को यह डर है कि यदि देश में राष्ट्रीय भावों का प्रचार होगा, तो हमारे बहुत से अधिकार खिन जायेंगे और हमें अपने वैभव से हाथ धोना पड़ेगा। प्रजा का बहुत बड़ा अंश कांग्रेस के साथ में है, जिसमें अनेक मुस्लिम राष्ट्रीय संस्थाएँ भी हैं। लिबरलो की संख्या बहुत ही कम है और उनमें अधिकतर बड़े आदमी और नेता ही हैं। यद्यपि कुछ नवयुवक राष्ट्रीय नेता कम्युनिस्ट सिद्धान्तों के ही प्रचार के पक्षपाती हैं, तथापि कम्युनिस्टवाद का कोई संघटन यहाँ नहीं है और न ब्रिटिश सत्ता के रहते हुए हो ही सकता है। स्वयं कांग्रेस में भी कई ऐसे वर्ग हैं जो सामाजिक और आर्थिक विषयों में एक दूसरे से बहुत ही भिन्न प्रकार के विचार रखते हैं। समाजवाद और साम्यवादी सिद्धान्तों का भी लोगों में कुछ प्रचार होने लगा है। तो भी अभी तक अधिकतर लोग महात्मा गान्धी के शान्तिमय और अहिंसात्मक असहयोग तथा मविनय अवज्ञा के सिद्धान्तों के ही पक्षपाती हैं। स्वयं कांग्रेस के सदस्यों में भी अनेक दोष आ गये हैं और उनके निर्वाचनों में अनेक ऐसे उपायों का अवलम्बन होने लगा है जो कभी प्रशंसनीय नहीं कहे जा सकते। कांग्रेस का ध्यान इस ओर महात्मा गांधी ने जोरदार शब्दों में दिलाया है और इसके सुधार के कुछ उपाय सोचे भी गये हैं। प्रान्तों की कांग्रेसी सरकारें जनता

को आर्थिक और सामाजिक अवस्था सुधारने के कई अच्छे आयोजन कर गई हैं। तात्पर्य यह है कि इस समय सारा देश एक नये सॉचे में ढल रहा है और अभी देश के भविष्य के सम्बन्ध में इसके सिवा और कोई बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती कि बहुत से लोग उगे उज्ज्वल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन इस प्रयत्न की सफलता केवल उन्हीं लोगों के हाथ में नहीं है, बल्कि वह और भी अनेक ऐसी बातों पर निर्भर करती है जो उनके नियन्त्रण से बाहर हैं।

एक बात और है। बहुत से अंग्रेज भी यही चाहते हैं और शिक्षित भारतवासी भी यह चाहते हैं कि भारत में पाश्चात्य देशों की तरह प्रतिनिधि-सत्तात्मक पार्लमेण्टरी शासन-प्रणाली प्रचलित हो। परन्तु प्रश्न तो यह है कि क्या यही प्रणाली भारतीय स्वराज्य के लिए सबसे अधिक आदर्श और अनुकरणीय है? अनेक पाश्चात्य विचारशीलों का मत है कि यह पार्लमेण्टरी शासन-प्रणाली भी नितान्त निर्दोष नहीं है। इसमें भी अनेक दोष हैं। इसके सिवा कुछ लोगों का यह भी मत है कि पाश्चात्य देशों में यह प्रणाली अनेक अशो में विफल सिद्ध हो रही है। अतः ऐसी प्रणाली का अनुकरण कहाँ तक वांछनीय और कल्याणकारी हो सकता है? फिर इस प्रणाली के लिए सबसे अधिक आवश्यक यह है कि प्रजा पूरी तरह से शिक्षित हो, उसे भिन्न-भिन्न राजनीतिक प्रणालियों का अच्छा ज्ञान हो और वह यह समझ सकती हो कि हमारा कल्याण किन बातों में है और उसका साधन किन लोगों के हाथों से हो सकता है। भारत की अधिकांश जनता अभी नितान्त अशिक्षित है; और यदि हम क्षमा किये जायँ तो कह सकते हैं कि वह अभी मताधिकार का ठीक-ठीक उपयोग करने में समर्थ नहीं है। कांग्रेस कहती है कि देश के सभी वयस्क पुरुषों को निर्वाचन में मत देने का

अधिकार मिले। अंग्रेज कहते हैं कि इस मताधिकार का उपयोग केवल शिक्षित मतदाता ही कर सकते हैं। गोलमेज कान्फ्रेंस में महात्मा गान्धी ने यह अड़चन दूर करने के लिए प्रायः वही प्रणाली बतलाई थी, जो सोविएट रूस में प्रचलित है। उन्होंने कहा था कि सब देहातियों को मिलकर पहले अपने-अपने गाँव के प्रतिनिधि चुन लेने चाहिए और तब आगे का निर्वाचन उन प्रतिनिधियों के मत से होना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने इसीलिए इस सूचना का विरोध किया था कि इसमें सोविएटी तत्व वर्तमान था। लेकिन फिर भी इसमें कोई सन्देह नहीं कि देहातियों का मत जानने का इससे अच्छा उपाय, कम-से-कम वर्तमान परिस्थिति में, दूसरा नहीं हो सकता। हम तो यही समझते हैं कि इस समय ब्रिटिश सरकार चाहे जो प्रणाली भारत पर लादे और उसके नेता चाहे जो प्रणाली स्वीकृत कर ले, परन्तु आगे चलकर जब भारतीय जनता शिक्षित और जाग्रत होगी, तब वह अपनी सरकार का स्वरूप आप ही निश्चित करेगी। तब तक शायद पार्लमेण्टरी शासन-प्रणाली की भी, अधिनायक-तन्त्र की भी और सोविएट प्रणाली की भी कुछ और परख हो जायगी और उनके गुण-दोष भी अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट हो जायँगे। इस समय की परिस्थिति को देखते हुए अधिक-से-अधिक यही कहा जा सकता है कि शायद पार्लमेण्टरी शासन-प्रणाली का अपेक्षा भारत सोविएट शासन-प्रणाली ही अधिक पसन्द करेगा। सिर्फ भारत ही नहीं, सम्भव है कि संसार के अन्यान्य देश भी वही प्रणाली अच्छी समझे।

अतिरिक्त बातें—जब यूरोप में दूसरा महायुद्ध हुआ, तब भारत सरकार भी और प्रान्तीय सरकारें भी देश से युद्ध के लिए मनमाने ढंग से सहायता लेने लगी और ब्रिटिश सरकार ने भी भारत को बिना उसके प्रतिनिधि मण्डलों का मत जाने ही युद्ध

में सम्मिलित कर लिया। कांग्रेस को यह बात पसन्द नहीं आई। जिन प्रान्तों में कांग्रेसी शासन था, वहाँ के मन्त्री-मण्डलों के लिए विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई। वे युद्ध के कार्यों में बाधा भी नहीं दे सकते थे और सिद्धान्ततः उसमें सहायक भी नहीं हो सकते थे। इसलिए कांग्रेस ने निश्चय किया कि प्रान्तों से सब मन्त्री इस्तीफा देकर अलग हो जायें। हाँ, एसेम्बलियों और काउन्सिलों के लिए जो लोग प्रजा के प्रतिनिधि-रूप में निर्वाचित हुए हैं, वे अवश्य अपने-अपने पदों पर बने रहें। इसके अनुसार सभी कांग्रेसी प्रान्तों से कांग्रेसी मंत्री-मण्डल हट गये। उस समय उन प्रान्तों में गवर्नरों ने अपने विशेषाधिकार से उन मन्त्रियों के स्थान पर अपनी इच्छा और पसन्द से कुछ लोगों को परामर्श-दाता नियुक्त कर लिया और अब उन सब प्रान्तों में गवर्नरों का ही शासन चल रहा है।

युद्ध आरम्भ होने पर जब सरकार के सामने लोगों की ओर से और विशेषतः कांग्रेस की ओर से यह माँग रखी जाने लगी कि यदि युद्ध में हमारा सहयोग अपेक्षित हो तो हमें उसके लिए उपयुक्त अधिकार भी मिलने चाहिएँ; और सरकार ने भी अच्छी तरह देख लिया कि नये एक्ट की संघवाली योजना देश में किसी को सन्तुष्ट नहीं कर सकी, तब भारत के बड़े लाट ने यह घोषणा कर दी कि हम अभी नये एक्ट की संघवाली योजना स्थगित करते हैं; और जब युद्ध समाप्त हो जायगा, तब इस विधान को कोई नया और सर्वसम्मत रूप देने का फिर से प्रयत्न किया जायगा। साथ ही इस समय सब दलों का सहयोग प्राप्त करने के लिए और सबके मत जानने के लिए बड़े लाट की काउन्सिल में कुछ और मेम्बर बढ़ाये जायेंगे और युद्ध-सम्बन्धी प्रयत्नों में परामर्श लेने के लिए केन्द्र में भी और प्रान्तों में भी सब दलों में से कुछ लोगों की एक कमेटी बनाई जायगी। इधर

महीनों से बड़े लाट प्रयत्न में लगे हुए हैं कि सब दल इस प्रस्ताव से सहमत हो जायँ और हम सब खास-खास दलों में से कुछ आदमियों को लेकर युद्ध का काम ठीक तरह से चलावें, और सारे संसार को यह दिखला दे कि भारतवासी हर तरह से इस युद्ध में हमारे साथ हैं। इसके लिए बड़े लाट ने, अनेक बार महात्मा गान्धी और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं के साथ भी और मुस्लिम लीग, हिन्दू-महासभा, लिबरल दल और सिक्खों आदि के प्रमुख नेताओं से बहुत सी बातें की हैं। परन्तु अभी तक कोई निश्चय नहीं हो सका है। अनेक दलों की और विशेषतः मुस्लिम लीग की माँगें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि वे किसी तरह पूरी ही नहीं की जा सकतीं।

युद्ध के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति स्पष्टरूप से यह है कि ब्रिटिश सरकार को जहाँ तक हो सके, इस विकट समय में तंग नहीं करना चाहिए। ऐसी अवस्था में जबकि ब्रिटेन एक ऐसे भीषण युद्ध में लगा है, जिसके साथ उसके जीवन और मरण का प्रश्न सम्बद्ध है, कांग्रेस को उसके सामने कोई नई अड़चन नहीं खड़ी करनी चाहिए। पर हाँ, साथ ही ब्रिटिश सरकार को भी स्वतन्त्रता-प्रेमी भारत-वासियों के मनोभावों पर किसी प्रकार का आघात नहीं करना चाहिए। इधर जब से युद्ध आरम्भ हुआ है, तबसे भारत-रक्षा कानून के अनुसार सारे देश में सैकड़ों-हजारों कांग्रेसी गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गये हैं और भाषण तथा लेखन-स्वातन्त्र्य का पूरा-पूरा अपहरण हो चुका है। महात्मा गांधी कहते हैं कि यदि सचमुच ब्रिटिश सरकार प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए लड़ रही है, तो भारत में उसे प्रजातन्त्र के मूल सिद्धान्तों की रक्षा करने के लिए यहाँ भी सब को भाषण और लेखन की पूरी स्वतन्त्रता देनी चाहिए, और जिन लोगों को उसने राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार किया

है, उन्हें छोड़ देना चाहिए। इससे अधिक अभी कांग्रेस की तरफ से कोई माँग नहीं है। हाँ, जब युद्ध समाप्त हो जाय, तब भारत को पूरी स्वतन्त्रता मिल जानी चाहिए और उसके भावी संघटन का निश्चय विधान-सम्मेलन के द्वारा होना चाहिए। जो कुछ निश्चय हो, वह प्रजा के प्रतिनिधियों का किया हुआ हो, उन लोगों का न हो जिन्हें सरकार अपनी तरफ से और मनमाने तौर पर इस काम के लिए निमन्त्रित करे। पर सरकार ने कांग्रेस की यह माँग भी मंजूर नहीं की और वह भारतवासियों को युद्ध-काल में भाषण-स्वातन्त्र्य देने को तैयार नहीं है।

लेकिन मुस्लिम लीग का हक कुछ और ही है। पहले तो जब कांग्रेसी मन्त्री-मंडलों ने पद-त्याग किया, तब उसकी तरफ से कुछ स्थानों में मुक्ति-दिवस मना कर तुच्छ मनोवृत्ति का परिचय दिया गया। इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की गई कि सात प्रान्तों में कांग्रेसी अधिकार उठ गया और फिर सारा अधिकार गवर्नरों के हाथ में चला गया। अवश्य ही मुक्ति-दिवस केवल कांग्रेस को नीचा दिखाने, मुसलमानों के मन में उसके प्रति विद्वेष उत्पन्न करने और उन्हें और भी अधिक संख्या में लीग की तरफ आकृष्ट करने के लिए मनाया गया था। यद्यपि देश के प्रायः सभी समझदारों ने लीग के इस निश्चय की घोर निन्दा की; परन्तु लीग ने मुक्ति-दिवस मनाकर ही छोड़ा, फिर चाहे वह दिवस बहुत ही थोड़े स्थानों में और बहुत ही थोड़े मुसलमानों ने मनाया हो।

इस बीच में लीग ने दूसरा अनुचित काम यह किया कि अपनी लाहौरवाली अन्तिम बैठक में पाकिस्तानवाला प्रस्ताव स्वीकृत किया। अब लीगी नेता इस बात पर अड़े हैं कि भारत के दो टुकड़े कर दिये जायँ और मुसलमानों के पान्त अलग और स्वतन्त्र रहे। बहुत से समझदार और

देश-भक्त मुसलमानों को लीग का यह रुख बहुत ह-
 खटका और उन्होंने दिल्ली में एक बहुत बड़ी अखिल
 भारतीय सभा करके लीग के इस निश्चय की निन्दा की।
 यह महासभा देशभक्त और राष्ट्रवादी मुसलमानों की सात-आठ
 बड़ी-बड़ी संस्थाओं के प्रयत्न से हुई थी; और अब इस महासभा
 की ओर से समस्त राष्ट्रवादी और देश-प्रेमी मुसलमानों का एक
 जबरदस्त संघटन करने का प्रयत्न हो रहा है। लेकिन फिर भी
 इधर दो-तीन बार भारत सरकार ने भी और भारत-मन्त्री ने भी
 मौके-बे-मौके मुस्लिम लीग की ही पीठ ठोकी और प्रकारान्तर
 से उनकी पाकिस्तानी योजना को युक्ति-संगत बतलाया। इसका
 पूरा-पूरा दुष्परिणाम अब इस रूप में दिखाई दिया है कि
 मुस्लिम लीग चाहती है कि बड़े लाट की एक्जिक्यूटिव काउन्सिल
 में जो नई जगहें बड़े, उनमें से आधी लीग के बतलाये हुए
 आदमियों को मिले और दूसरी जगहें भी उन्हीं लोगों को दी
 जायें जिन्हें लीग मंजर करे। साथ ही एक्जिक्यूटिव काउन्सिल
 के सदस्यों में कार्य और अधिकार आदि का जो विभाग हो, वह
 भी मुस्लिम लीग की स्वीकृति से ही हो। मुस्लिम लीग की यह
 नीति कुछ एंग्लो-इंडियन समाचारपत्रों को भी इतनी बुरी लगी
 है कि उन्होंने इसकी ओर निन्दा की है। और इन में से कुछ
 समाचारपत्र ऐसे भी हैं जो प्रायः समय-समय पर मुस्लिम लीग
 के देशद्रोही प्रयत्नों की प्रशंसा करते रहे हैं।

तो भी मुस्लिम लीग जानती है कि इस समय सरकार को
 मुसलमानों की सहायता और सहानुभूति की बहुत बड़ी
 आवश्यकता है। और इसी लिए वह ब्रिटिश सरकार से उसका
 पूरा-पूरा दाम भी वसूल करना चाहती है। बड़े लाट मुस्लिम लीग
 को अधिक-से-अधिक जो कुछ देना चाहते थे या दे सकते थे,
 उसे भी लीग ने ठुकरा दिया है। तो भी आशा की जाती है कि

बड़े लाट की ओर से एक बार फिर लीग को मिलाने का प्रयत्न किया जायगा। अभी बात-चीत चल रही है और निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि ऊँट किस करवट बैठेगा।

लिबरल दल, हिन्दू महासभा, सिक्ख तथा और कई दल तथा वर्ग भी किसी-न-किसी रूप में सरकार को सहायता करने के लिए तैयार है। पर सभी की कुछ-न-कुछ माँगें भी हैं। जो हो, अभी भारत की अवस्था बहुत ही डॉवाडोल है। कई दिशाओं से उस पर आक्रमणों की सम्भावना बतलाई जाती है। सारा देश नितान्त अरक्षित अवस्था में पड़ा है और तिस पर घर की जवरदस्त फूट है। यह फूट कुछ तो स्वार्थ के कारण है, कुछ बहकावे में आने के कारण और कुछ हाथ रँगने की डच्छा से। सारा संसार जिस भीषण संकट में पड़ा है, उसी में भारत भी पड़ा है। संसार की आँखें तो खुल रही हैं, पर दुःख है कि भारत की आँखें नहीं खुल रही हैं। सारे संसार की तरह भारत का भी ईश्वर ही रक्षक है। और नहीं तो सब की तरह हमें भी बुरे दिन ही सामने दिखाई दे रहे हैं।

पुनश्च—जब पूर्ण प्रयत्न करने के बाद भी सरकार ने कांग्रेस की भाषण-स्वातन्त्र्य की माँग को स्वीकार नहीं किया तो इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने युद्धघोषणा कर दी। महात्मा गांधी ने श्री विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना और गत १७ अक्टूबर को उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया। श्री विनोबा भावे वर्धा में महात्मा गांधी के श्रेष्ठतम अनुयायियों में से हैं। अहिंसा पर उनका पूर्ण विश्वास है। सरकार ने विनोबा को गिरफ्तार कर लिया और ३ महीने की सजा दी। पं० जवाहरलाल नेहरू वर्धा से लौटते हुए छिवकी स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हें ४ साल की सख्त सजा दे दी गई।

भविष्य में घटनायें क्या रंग लाती हैं कौन जानता है ?

सस्ता साहित्य मण्डल की

सर्वोदय साहित्य माला के प्रकाशन

[नोट—*चिन्हित पुस्तकें अप्राप्य हैं]

- | | | | |
|--------------------------|-------|-----------------------------|----------|
| १. दिव्य-जीवन | I=) | २४. हमारे जमाने की गुलामी* | II) |
| २. जीवन-साहित्य | १I) | २५. स्त्री और पुरुष | II) |
| ३. तामिल वेद | III) | २६. सफाई | I=) |
| ४. भारत में व्यसन | | २७. क्या करें ? | १) |
| और व्यभिचार | III=) | २८ हाथ की कतारई-बुनाई* | II-) |
| ५. सामाजिक कुरीतियाँ* | III) | २९. आत्मोपदेश* | I) |
| ६. भारत के स्त्री-रत्न | ३) | ३०. यथाथं आदर्श जीवन* | III-) |
| ७. अनोखा* | १I=) | ३१. [देखो नवजीवन माला]* | |
| ८ ब्रह्मचर्य-विज्ञान | III=) | ३२. गंगा गोविन्दसिंह* | II=) |
| ९. यूरोप का इतिहास | २) | ३३. श्री रामचरित्र | १I) |
| १०. समाज-विज्ञान | III) | ३४. आश्रम-हरिणी* | I) |
| ११. खहर का | | ३५. हिंदी मराठी कोष | २) |
| सपत्ति-शास्त्र* | III=) | ३६. स्वाधीनता के सिद्धान्त* | II) |
| १२. गुरो का प्रभुत्व* | III=) | ३७. महान् मातृत्व की ओर | III=) |
| १३. चीन की आवाज* | I-) | ३८ शिवाजी की योग्यता | I=) |
| १४. द. अ. का सत्याग्रह | १I) | ३९. तरंगित हृदय* | II) |
| १५. विजयी बारडोली* | २) | ४०. हालैण्ड की राज्यक्रांति | १II) |
| १६. अनीति की राह पर | II=) | ४१ दुखी दुनिया | I=) |
| १७. सीता की अग्निपरीक्षा | I-) | ४२. ज़िन्दा लाश* | II) |
| १८. कन्या-शिक्षा | I) | ४३ आत्मकथा | १), १II) |
| १९ कर्म योग | I=) | „ [संक्षिप्त संस्करण] | II) |
| २०. कलवार की करतूत | =) | ४४. जव अंग्रेज आये* | १I=) |
| २१. व्यावहारिक सभ्यता | II) | ४५ जीवन-विकास | १I) |
| २२. अंधेरे में उजाला | II) | ४६. किसानों का बिगुल* | =) |
| २३ स्वामी जी का बलिदान* | I-) | ४७. फाँसी | I=) |

४८ [देखो नवजीवन माला]	७६ नया शासन विधान	॥१)
४९. स्वर्ण विहान *	७७ [१] हमारे गाँव की कहानी	॥)
५०. मराठों का उत्थान	७८. [२] महाभारत के पात्र	१)
और पतन	७९. गाँवों का सुधार संगठन	१)
५१. भाई के पत्र	८०. [३] सन्तवाणी	॥)
५२. स्वगत	८१. विनाश या इलाज ?	॥१)
५३. युग धर्म *	८२. [४] अंग्रेजी राज्य में	
५४ स्त्री-समस्या	हमारी दशा	॥)
५५ विदेशी कपड़े का	८३. [५] लोक-जीवन	॥)
मुकाबिला	८४. गीता-मथन	१॥)
५६ चित्रपट	८५. [६] राजनीति प्रवेशिका	॥)
५७. राष्ट्रवाणी *	८६. [७] हमारे अधिकार	
५८. इंग्लैंड में महात्मा जी	और कतव्य	॥)
५९. भावी क्रांति का संगठन ('रोटी	८७. गांधीवाद. समाजवाद	॥१)
के सवाल' का नया संस्करण) ॥१)	८८. स्वदेशी : ग्रामोद्योग	॥)
६०. दैवी संपद्	८९. [८] सुगम चिकित्सा	॥)
६१. जीवन-सूत्र	९०. प्रेम में भगवान्	॥)
६२. हमारा कलंक	९१. महात्मा गांधी	॥)
६३. बुद्बुद्	९२. [१०] गांव और किसान	॥)
६४. सघर्ष या सहयोग ?	९३. ब्रह्मचर्य	॥)
६५. गांधी-विचार-दोहन	९४. गांधी-अभिनन्दन-ग्रन्थ	२)
६६. एशिया की क्रांति *	९५. हिन्दुस्तान की समस्याएँ	१)
६७. हमारे राष्ट्र निर्माता	९६. जीवन सदेश	॥)
६८. स्वतंत्रता की ओर	९७. समन्वय	२)
६९. आगे बढ़ो	९८. समाजवाद : पूँजीवाद	॥१)
७०. बुद्धवाणी	९९. मेरी मुक्ति की कहानी	॥)
७१. कांग्रेस का इतिहास २॥१) ॥१)	१००. खादी मोमांसा	१॥)
७२. हमारे राष्ट्रपति	१०१. बापू	॥१)
७३. मेरी कहानी	१०२. दुनिया की शासन-	
७४. भूलक	प्रणालियाँ	१॥)
७५. हमारी पुत्रियाँ कैसी हों ? ॥)		

‘नवजीवनमाला’ की पुस्तकें

१ गीताबोध—महात्मा गांधी-कृत गीता का सरल तात्पर्य—
(दूसरी बार) —)॥

२ मंगल प्रभात—महात्मा गांधी के जेल से लिखे सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों पर प्रवचन (चौथी बार) —)

३ अनासक्तियोग—महात्मा गांधी-कृत गीता की टीका (सातवीं बार) =), (=), 1)

४. सर्वोदय—रस्किन के ‘Unto This Last’ का गांधीजी द्वारा किया गया रूपान्तर (तीसरी बार) —)

५. नवयुवकों से दो बातें—प्रस क्रोपाटकिन के ‘A word to youngmen’ का अनुवाद (तीसरी बार) —)

६. हिन्द-स्वराज—महात्मा गान्धी की भारत की मौजूदा समस्याओं पर लिखी गई प्राचीन पुस्तक, जो आज भी ताज़ी है—
(दूसरी बार) (=)

७ गांधीजी का मार्ग—आचार्य कृपालानी ने इस पुस्तिका में बड़ी सरलता से बताया है कि आज के कशमकश के ज़माने में हमें गांधीजी के बताये रास्ते से ही आजादी मिल सकती है —)

८. किसानों का सवाल—डा० अहमद की इस छोटी-सी पुस्तिका में भारत के इन गरीब प्रतिनिधियों के सवाल पर बड़ी सुन्दरता से विचार किया गया है। (तीसरी बार) =)

९. ग्राम सेवा—ग्राम-सेवा के रूप, साधन और प्रकार पर महात्मा गांधी ने इसमें विशद प्रकाश डाला है। (दूसरी बार) =)

१०. खादी और गादी की लड़ाई—आचार्य विनोबा के खादी और समाज-सेवा-सम्बन्धी लेख और व्याख्यानों का संग्रह =)

११. मधुमक्खी-पालन—श्री चित्रे ने इस पुस्तक में मधुमक्खियों के पालने के बारे में प्रकाश डाला है और बताया है कि किस प्रकार हम इस आमोयोग के द्वारा बेकारों को काम दे सकते हैं (=)

१२. गांवों का आर्थिक सवाल—गाँवों के आर्थिक प्रश्नों तथा उनको हल करने की योजनाओं का ग्राम-सेवक विद्यालय के अध्यापक श्री भवेरभाई पटेल ने इस पुस्तक में संग्रह किया है ॥

१३. राष्ट्रीय गायन—देश-भक्तिपूर्ण राष्ट्रीय गायनों का संग्रह (दूसरी बार)

१४. खादी का महत्व—श्री गुलजारीलाल नन्दा-द्वारा लिखा खादी-विषयक प्रामाणिक और खादी की महत्ता और उपयोगिता बताने वाला निबंध ।

१५. जब अंग्रेज़ नहीं आये थे—अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत की दशा ।

सामयिक साहित्य माला की पुस्तकें

१. कांग्रेस का इतिहास (१९३५-३६)
२. दुनिया का रंगमंच (जवाहरलाल नेहरू)
३. हम कहाँ हैं ? " "
४. युद्ध-संकट और भारत (संकलन)
५. सत्याग्रह : क्यों, कब, कैसे ? (गांधीजी)
६. राष्ट्रीय-पंचायत—(संग्रह)

बाल साहित्य माला की पुस्तकें

१. सीख की कहानियाँ—१
२. कथा-कहानी—१
३. शिवाजी चरित्र
४. देश-प्रेम की कहानियाँ—१
५. सीख की कहानियाँ—२

सस्ता साहित्य-मण्डल से प्रकाशित

जीवन-साहित्य

[सम्पादक—श्री हरिभाऊ उपाध्याय]

में प्रति मास आपको क्या मिलेगा ?

- ★ जीवन को ऊँचा उठाने के लिए लिखेगये लेख
- ★ जीवन की जटिल समस्याओं के हल
- ★ जीवन-दायिनी कविताये और सत्य कथार्ये
- ★ साहित्य की निष्पक्ष समालोचना और समीक्षा
- ★ साहित्य-सेवियों के रेखा-चित्र और साहित्यिक संस्थाओं के सजीव परिचय
- ★ साहित्यिक प्रश्न और चर्चार्ये
- ★ साहित्य-समाचार और हलचलें

जीवन-साहित्य ही सत्साहित्य है !

अपने साहित्य-जीवन में

क्या आप

‘मण्डल’ से प्रकाशित तथा दूसरे जीवनोपयोगी साहित्य की जानकारी के लिए

‘जीवन-साहित्य’ से दूर रहेंगे ?

वार्षिक मूल्य मंडल के ग्राहको से नमूने की प्रति
२) १) २)

‘जीवन-साहित्य’

सस्ता साहित्य-मण्डल, नई दिल्ली

शाखाये:—दिल्ली, लखनऊ, इन्दौर

